वार्षिक रिपोर्ट

2005 – 2006

विदेश मंत्रालय

भारत सरकार

द्वारा प्रकाशित:
अपर सचिव, नीति नियोजन और अनुसंधान, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

यह वार्षिक रिपोर्ट इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:
www.meaindia.nic.in

आवरण:
श्री काशी नाथ दास द्वारा पानी के रंगों से चित्रित केन्द्रीय सचिवालय के भवन

रूपरेखा एवं मुद्रण:
साइबरआर्ट इनफारमेशंस प्रा. लि.
कनु चेम्बर्स, सी-2, सांवल नगर, नई दिल्ली 110 049
टेलीफैक्स: 26256148/26250700
ईमेल: cyberart@vsnl.com
वैबसाइट: www.cyberartinformations.com

विषय सूची

प्राक्कथन

1	भारत के पड़ोसी देश	1
2	दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत	21
3	पूर्वी एशिया	33
4	यूरेशिया	39
5	खाड़ी, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका	46
6	अफ्रीका (सहारा से दक्षिण)	58
7	यूरोप	73
8	अमरीका	89
9	संयुक्त राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन	99
10	बहुपक्षीय आर्थिक संबंध	114
11	तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग और विकास सहभागिता	120
12	निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन	122
13	नीति नियोजन और अनुसंधान	123
14	प्रोतोकोल	124
15	पासपोर्ट, वीजा और कोंसली सेवा	131
16	प्रशासन और स्थापना	134
17	समन्वय	138
18	सूचना का अधिकार प्रभाग	140
19	विदेश प्रचार	141
20	विदेश सेवा संस्थान	146
21	राजभाषा नीति का अनुपालन तथा विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार	148
22	सांस्कृतिक संबंध	149
23	इंडिया काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स	154
24	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली	156
25	पुस्तकालय	161

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	वर्ष 2005-06 के दौरान मुख्यालयों और विदेश में मिशनों/पदों में संवर्ग की संख्या (इनमें वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए पद और आस्थगित/वाह्य-संवर्ग के पर भी शामिल हैं)	165
परिशिष्ट II	अप्रैल से नवम्बर, 2005 तक विदेश मंत्रालय में विभिन्न समूहों में की गई भर्ती और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी की आरक्षित पदों पर भर्ती	166
परिशिष्ट III	30 नवम्बर, 2005 को अधिकारियों (भा. वि. से के कनिष्ठ वेतनमान का ग्रेड I भाषा-वार ब्यौरा)	166
परिशिष्ट IV	1 जनवरी, 2005 से 31 दिसंबर, 2005 तक प्राप्त आवेदनों और तत्काल स्कीम सहित जारी पासपोर्ट, प्राप्त विविध आवेदन एवं प्रदत्त सेवाओं की संख्या के साथ-साथ पासपोर्ट कार्यालयों का राजस्व (तत्काल स्कीम के तहत प्राप्त राजस्व सहित) और व्यय के आकड़ों को दर्शानेवाला विवरण।	167
परिशिष्ट V	वर्ष 2005-06 में विदेश मंत्रालय का वित्त	168
परिशिष्ट VI	2005-06 के बजट में क्षेत्र-वार आबंटन	168
परिशिष्ट VII	भारत के सहायता कार्यक्रम के प्रमुख गंतव्य	169
परिशिष्ट VIII	विदेश मंत्रालय के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	170
परिशिष्ट IX	भारत द्वारा देशों के साथ संपन्न अथवा नवीकृत संधियों/अभिसमय/समझौते	171
परिशिष्ट X	1 जनवरी, 2005 से दिसंबर, 2005 के दौरान जारी की गई पूर्ण शक्तियों के विवरण	184
परिशिष्ट XI	1 जनवरी, 2005 से दिसंबर, 2005 के दौरन जारी किए गए अनुसमर्थन/सहमति के लिखत	186
परिशिष्ट XII	संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित/किए जाने वाले सम्मेलन/सेमिनार/अध्ययन परियोजनाएं, जिनका आंशिक वित्तपोषण, नीतिगत नियोजन और अनुसंधान प्रभाग द्वारा किया गया।	188
परिशिष्ट XIII	अप्रैल, 2005 से जनवरी, 2006 तक की अवधि के लिए व्यय का विवरण (आईटैक एवं स्कैप कार्यक्रम)	191
परिशिष्ट XIV	भारत स्थित आइटेक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची	192
परिशिष्ट XV	आईटैक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिविलियन प्रशिक्षण स्लॉट (आबंटित/प्रयुक्त)	194
परिशिष्ट XVI	वर्ष 2005-06 की अवधि के दौरान विभिन्न देशों को आबंटित सैन्य प्रशिक्षण स्लॉट की संख्या आईटैक/सैप के अन्तर्गत	197
परिशिष्ट XVII	नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में तैनात आईटैक विशेषज्ञों की सूची	198
परिशिष्ट XVIII	लिंग से संबंधित आंकड़े	200
परिशिष्ट XIX	आई सी डब्ल्यू ए द्वारा 01.04.2005 से 30.11.2005 के दौरान आयोजित संगोष्ठियां/सम्मेलन/गोल मेज वार्त्ता	201
परिशिष्ट XX	आर आई एस द्वारा आयोजित सम्मेलन	203
	संक्षिप्त रूप	205

प्राक्कथन

वर्ष 2005-06, राष्ट्रमण्डली में भारत की उभरती हुई भूमिका और प्रतिष्ठा के लिए घटनाओं से भरा रहा। भारत की विदेशी नीति को जहां एक तरफ तेजी से बदल रहे वैश्विक वातावरण के अनुकूल करना पड़ा वहीं साथ ही दूसरी तरफ स्वयं भारत के अंदर हो रहे असाधारण परिवर्तनों के साथ उसे संबद्ध करना पड़ा। शेष विश्व समुदाय के साथ भारत की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है क्योंकि शांतिपूर्ण और समर्थक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, एक ऐसा वातावरण जो भारत के विकास लक्ष्यों में योगदान करता है, सुनिश्चित करने के लिए भारत सदैव महत्वपूर्ण हुआ है।

भारत की विदेश नीति की सफलता, भारत की परिवर्तनों के अनुकूल समायोजित करने की सुस्पष्ट योग्यता के अनुसार एक साथ मिलकर चलने की रही है; ये परिवर्तन हैं- निरंतर गतिशीलता और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रौद्योगिकीय परिष्करण में अंतनिर्हित परिवर्तन; एक जिम्मेदार नाभिकीय हथियार संपन्न राज्य के रूप में भारत के उभरकर आने में अंतनिर्हित परिवर्तन; क्षेत्रीय और वैश्विक जिम्मेदारियों को वहन करने में भारत की क्षमता में अंतनिर्हित परिवर्तन और इनके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका की वैश्विक अपेक्षाओं में परिवर्तन।

इस सुनिश्चित रूप से बदल रहे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धान्त ने अपनी अनिवार्य मान्यता को बनाए रखा, यथा; निर्णय लेने में स्वायत्ता, सभी देशों के साथ पंचशील अथवा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मैत्री और सहयोगी संबंध, बातचीत और शांतिपूर्ण साधनों के जरिए विवादों का समाधान और अंतराष्ट्रीय संबंधों के संचालन में समानता के प्रति वचनबद्धता। यूपीए सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम से इन मूल सिद्धांतों की पुनः पुष्टि हुई है।

भारत का ध्यान विदेशी मसलों पर काफी अधिक केंद्रित हुआ है जो कि आज की चुनौतियों में प्राथमिकता पर हैं, चाहे वह आतंकवाद हो या सामूहिक नरसंहार हो, का प्रसार, देशव्यापी महामारी हो या पर्यावरणीय क्षति हो या आपदा प्रबंधन। सक्रिय और सुस्पष्ट राजनयिक प्रयासों के जरिए भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट करने तथा अपने हित संवर्द्धन में समर्थ रहा है।

अपनी आर्थिक वृद्धि और तकनीकी विकास के अनुरूप भारत ने विकसित राष्ट्रों के साथ अपनी भागीदारी को सुदृढ़ और विस्तृत किया है तथा साथ ही अपने साथी विकासशील देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग में विस्तार किया है जिसमें उन देशों के साथ भारत की राजनीतिक एकात्मकता पर जोर दिया गया है। विकास और मानवीय सहायता से संबद्ध दक्षिण कोष तथा गरीबी और भूख उपशमन से संबद्ध भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका सुविधा केंद्र के लिए भारत का योगदान दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए उल्लेखनीय पहल है। ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने बहुपक्षवाद और वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भूमिका की पुनःपुष्टि की।

यह मानकर कि वैश्विक परस्पर निर्भरता के प्रबंधन के लिए मजबूत, प्रातिनिधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और नियम आधारित बहुपक्षीय प्रणाली की आवश्यकता है, भारत ने यूएन सुधार के लिए श्रमशील दबाव बनाया है और विवेचनात्मक रूप से स्थायी और अस्थायी श्रेणी दोनों की सदस्यता में यूएनएससी के विस्तार पर जोर दिया है ताकि इसकी संरचना और निर्णायक प्रक्रिया में समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकता परिलक्षित हो।

भारत ने समकालीन विश्व के प्रसंग में सहयोग का नया प्रतिमान विकसित करने की आवश्यकता का समर्थन किया है जिसमें वैश्विक खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया जरूरी होती है और बहुपक्षवाद वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मात्र प्रभावी औजार बन जाता है।

भारत की विदेश नीति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ सामरिक भागीदारी का विकास करने में हुई प्रगति है। भारत ने अमरीका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ साथ सामरिक भागीदारी की स्थापना की है और चीन के साथ सामरिक सहयोग को आगे बढ़ा रहा है जिससे भारत की नीति प्राथमिकताओं और विकास विकल्पों का विस्तार हो रहा है। आईबीएसए मंच के जरिए ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसी दो प्रमुख उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत ने उपयोगी क्रियाकलाप किया।

एशियाई महाद्वीप की भू-राजनीति में भारत की भौगोलिक अवस्थिति विलक्षण है क्योंकि इसके हित और चिंताएं इस उप क्षेत्र से आगे यानि पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया अथवा दक्षिण पूर्व एशिया तक हैं। इस भू-राजनैतिक यर्थाथ और भारत का यह विश्वास कि संवर्द्धित क्षेत्रीय सहयोग आपसी लाभकारी है, के आधार पर ही भारत सार्क, आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और शंघाई सहयोग संगठन में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।

पड़ोसी देश

भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ राजनैतिक, आर्थिक और अन्य संबंधों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। भारत दक्षिण एशिया को ऐतिहासिक विभाजन से अलग हट कर देखता है और शांति और समृद्धि के मार्ग पर सब को साथ लेकर चलने को इच्छुक है। अफगानिस्तान के सार्क में शामिल होने के साथ ही यह क्षेत्र पूर्ण क्षेत्रीय पहचान हासिल कर लेगा। भारत सार्क प्रक्रिया को दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते जैसी पहल के माध्यम से सार्क अंतर-संपर्कों को सुद्ढ़ करने हेतु एक प्रेरक तत्व के रूप में देखता है। इस प्रक्रिया में आर्थिक रूप से सक्रिय भारत अपने सभी सदस्यों के लिए परिसंपत्ति और अवसर के तौर पर है।

भारत अपने सबसे बड़े पड़ोसी चीन के साथ अपने संबंधों को संवर्द्धित करने के पक्ष में है। अनेक वार्ता प्रक्रियाओं से गुजरते हुए भारत और चीन एक दूसरे का दृष्टिकोण समझने लगे हैं और अनसुलझे मुद्दों का निवारण कर पा रहे हैं।

अफगानिस्तानः वर्ष के दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में पर्याप्त इजाफा हुआ है। राष्ट्रपति करजई ने 23-25 फरवरी, 2005 के बीच भारत की यात्रा की और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 से 29 अगस्त, 2005 के बीच अफगानिस्तान की यात्रा की।

प्रधानमंत्री ने अखण्ड, स्थिर और समृद्ध अफगानिस्तान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के सहयोग की पुनःपुष्टि की। बुनियादी संरचना, संस्थागत और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए भारत का 550 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान भारत के साथ अफगानिस्तान की भागीदारी का द्योतक है। सीमा सड़क संगठन के अधिकर्मी मनियप्पन रमन कुट्टी की दुर्भाग्यवश हुई हत्या के बावजूद भारत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंकाः भारत बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को सुदृढ़ करने और उसके संवर्द्धन करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। भारत उनके साथ गहन ऐतिहासक और सांस्कृतिक संबंधों का भागीदार है। भारत का सदा यह प्रयास रहा है कि वह एक दूसरे के हितों के लिए पारस्परिक सद्भावना और समादर के आधार पर इस क्षेत्र में समान समृद्धि, स्थायित्व, सुरक्षा, ठोस विश्वास और आपसी समझ का माहौल बनाए। उच्च स्तरीय आदान-प्रदानों से संपर्क सुदृढ़ हुआ है। संवर्द्धित आर्थिक और वाणिज्यिक आदान-प्रदानों से जनता का जनता से संपर्क और विकास परियोजनाओं में सहयोग से इन देशों के साथ भारत का संपर्क सुदृढ़ हुआ है।

बांग्लादेश के साथ भारत का संपर्क बहु-आयामी और सार्थक रहा है। इसके साथ-साथ हिंसा और आतंकवाद और बांग्लादेश की जमीन से भारत के विरूद्ध जारी कार्यवाही चिंता का विषय है।

म्यांमार के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। सीमा पार बुनियादी संरचना के विकास के माध्यम से पश्चिमी म्यांमार के साथ लगे भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास और सार्क एकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक और सीमा प्रबंधन आयाम भारत-म्यांमार संबंधों के महत्वपूर्ण घटक हैं। 8-10 मार्च, 2006 के लिए निर्धारित म्यांमार में राष्ट्रपति की आधिकारिक यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।

श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपक्षे से 27-30 दिसम्बर, 2005 के बीच भारत यात्रा से पहले से आ रहे द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। भारत ने श्रीलंका को कुल 381 मिलियन अमेरिकी डालर के मौजूदा रूप से प्रचालनीय तीन ऋण पत्र जारी किए हैं।

भूटानः भारत और भूटान के बीच परस्पर विश्वास, समझबूझ और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उच्चस्तरीय यात्राओं ने दोनों देशों के बीच विद्यमान विशेष संबंधों को और अधिक गहन बनाने में योगदान दिया। भूटान नरेश जिग्मे सिंग्मे वांग्चुक ने 1-4 अगस्त, 2005 तक भारत की यात्रा की। वर्ष के दौरान जल-विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ हुआ।

नेपालः नेपाल में राजनैतिक अस्थिरता और प्रतिकूल सुरक्षा स्थिति के प्रति भारत को निरंतर गहरी चिंता बनी हुई है। यह निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है कि संवैधानिक ताकतें नेपाल को पेश आ रही समस्याओं के राजनैतिक समाधान जो कि राष्ट्रीय मतैक्य पर आधारित है,की दिशा में मिलकर कार्य करें। नेपाल का घनिष्ठ और मित्र पड़ोसी होने के नाते भारत को आशा है कि नेपाल में शांति और स्थिरता तथा आर्थिक विकास शीघ्र ही बहाल होगा। नेपाल जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनके शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने के सभी प्रयासों में सहायता देने के लिए भारत सदैव तत्पर है।

पाकिस्तानः भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों की स्थापना के लिए रचनात्मक क्रिया-कलापों की नीति का अनुपालन किया। वार्ता की जिस प्रक्रिया में भारत संलग्न है वह 6 जनवरी 2004 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा इस्लामाबाद में अभिव्यक्त की गई वचनबद्धता पर आधारित है कि पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन किसी भी भू-प्रदेश को आतंकवाद के समर्थन के लिए उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ष के दौरान, समग्र वार्ता, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलू और मसले शामिल हैं, ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है और इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के साथ दो महत्वपूर्ण करार संपन्न किए गए, एक तो बैलिस्टिक मिसाइलों के उडान परीक्षण की पूर्व अधिसूचना के संबंध में और दूसरा भारत के तटरक्षक और पाकिस्तान को मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बीच संचार संपर्क की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।

अप्रैल 2005 में राष्ट्रपति मुशर्रफ की भारत यात्रा, सितंबर में न्यूयार्क में प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच बातचीत, और अक्तूबर में विदेश मंत्री की इस्लामाबाद यात्रा ने चल रही द्विपक्षीय वार्ता को आवश्यक गति प्रदान किया।

सभी अनसुलझे मसलों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के प्रति वचनबद्धता की सितंबर, 2005 में न्यूयार्क में प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच हुई बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य के जरिए पुनः पुष्टि की गई। भारत का तत्परता से राहत सहायता भेजना, 25 मिलियन अमरीकी डालर देने का वायदा, लोगों की आवाजाही के लिए नियंत्रण रेखा पर पांच स्थलों को खोलना और राहत सामग्री भारत द्वारा सद्भावना की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति थी। अगस्त, 2005 में हुई एक सहमति के अनुसरण में पाकिस्तान ने 435 भारतीय कैदियों को रिहा किया, जिनमें 371 मछुआरे शामिल थे। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा 7 अप्रैल, 2005 को और अमृतसर-लाहौर बस सेवा 20 जनवरी, 2006 को शुरू हुई। तथापि, महती चुनौती अभी शेष है, कि हिंसा और आतंकवाद से मुक्त वातावरण में ही द्विपक्षीय संबंध पुष्पित -पल्लवित हो सकते हैं।

चीनः वर्ष 2005 भारत और चीन के बीच राजनयिक की स्थापना की 55वीं जयंती का वर्ष था। भारत और चीन परस्पर ऐसा समझते हैं कि उनके संबंध द्विपक्षीय मसलों से कहीं बढ़कर हैं और उन्हें सार्वभौम और नीतिगत महत्व प्राप्त है।

चीन के साथ भारत एक नीतिगत एवं सहयोगात्मक भागीदारी को आगे बढ़ा रहा है। चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओं की यात्रा के दौरान अप्रैल, 2005 में राजनैतिक तौर-तरीकों और दिशा-निर्देशक सिद्धांतों पर करार संपन्न किया गया जिससे सीमा के प्रश्न पर द्विपक्षीय वार्ता में एक ठोस प्रगति हुई। दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार काफी मात्रा में बढ़ा है। दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य में द्विपक्षीय संबंधों के भावी विकास के लिए संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की है।

दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशान्त

एक दशक से अधिक समय पूर्व प्रवर्तित "पूर्वोन्मुखी नीति" आज भारत की विदेश नीति का अनिवार्य तत्व बन चुकी है। भारत इस बात का कायल है कि दीर्घकालीन सुरक्षा और स्थिर संतुलन बनाए रखने का मूलमंत्र एशिया में एक-दूसरे के साथ पारस्परिक आर्थिक साझेदारी के लिए एशियाई देशां की सामूहिक क्षमता में ही निहित है।

भारत की पूर्वोन्मुखी नीति, आसियान के साथ इसकी भागीदारी, बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी संबंधी पहल ये सब दक्षिण-पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था के एकीकरण की अपरिवर्तनीय प्रक्रिया के भाग हैं।) दिसम्बर, 2005 में क्वालालम्पुर में चतुर्थ भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी से विकासशील सार्वभौम अर्थव्यवस्था के साथ भारत की बढ़ती भूमिका और एकरूपता को सार्थकता प्रदान की।

इस परिवर्तनशील क्षेत्र के साथ सुस्पष्ट घनिष्ठतर अंर्तसंबंध बनाने के लिए सिंगापुर के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार संपन्न किया गया और थाईलैंड के साथ भी समान रूपरेखा पर करार तैयार किया जा रहा है और मलेशिया तथा

इंडोनेशिया के साथ मुक्त व्यापार करार संपन्न करने हेतु संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत के देशों के साथ भारत के संबंध निरंतर व्यापक और गहन होते रहे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, फिजी सिंगापुर और थाईलैंड के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह एशियाई-अफ्रीकी शिखर सम्मेलन और बांडुंग सम्मेलन के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया गए। राष्ट्रपति डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम की फिलिपीन्स और सिंगापुर की राजकीय यात्राओं ने इस क्षेत्र के महत्व को अंकित किया।

पूर्व एशिया

जापानः जापान के साथ भारत के संबंध सार्थक तौर पर और नीतिगत विशिष्टताओं के साथ उन्नत हो रहे हैं। और विशेष रूप से भारत के बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से निपटने में प्रासंगिक है। अप्रैल, 2005 में जापान के प्रधानमंत्री जुनिचिरों कोइजुमी की भारत यात्रा से जापान के साथ सार्वभौमिक भागीदारी का पर्याप्त संवर्धन हुआ। द्विपक्षीय सहयोग में आठगुणा पहल और एशिया में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि बनाए रखने में घनिष्ठ योगदान पर करार से निश्चित तौर पर दोनों में अपेक्षाकृत अधिक गहन संबंध बनेंगे।

कोरिया गणराज्यः अक्तूबर, 2004 में राष्ट्रप्रति रोह मू-ह्यून की भारत यात्रा के दौरान शुरू की गई "शांति और समृद्धि के लिए दीर्घावधि सहयोगात्मक भागीदारी" के बाद से भारत और कोरिया गणराज्य के बीच संबंध सुदृढ़ हुए हैं। उन्होंने तेजी से प्रगति की है। राष्ट्रपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम की कोरिया गणराज्य की यात्रा ने मजबूत बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढता प्रदान की।

अगस्त, 2005 में भारत-कोरिया संयुक्त आयोग की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक से द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहभागिता तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को सशक्त गति प्रदान की।

यूरेशिया

परम्परागत रूप से घनिष्ठ और व्यापक संपर्क ही रूस और अन्य सीआईएस देशों के साथ भारत के संबंधों की पहचान है। उच्चस्तरीय यात्राओं का नियमित आदान-प्रदानों ने व्यापार एवं आर्थिक सहयोग का संवर्द्धन किया, सांस्कृतिक मंडलियों की यात्राओं और लोगों से लोगों के बीच बढ़ते संपर्कों ने इस निकटवर्ती महत्वपूर्ण क्षेत्र के भारत के संबंधों को सशक्त बनाया।

रूसः अपनी पारंपरिक नीतिगत भागीदारी पर आधारित अपने बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रति भारत और रूस वचनबद्ध हैं। मई, 2005 में राष्ट्रपति डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम द्वारा रूस की राजकीय यात्रा और 9 मई के विजय दिवस समारोहों में भागीदारी के लिए रूस यात्रा और दिसंबर, 2005 में वार्षिक शिखर सम्मेलन में पुनः प्रधानमंत्री की दोनों देशों के बीच व्यापक संबंधों को पुनः स्थापित की प्रक्रिया का एक भाग थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति पुतिन भारत-रूस संबंधों के महत्व की पुनःपुष्टि की और एक व्यावहारिक एवं निष्पाद्य कार्यसूची तैयार की जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग, रक्षा और सुरक्षा शामिल हैं।

खाड़ी, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

खाड़ीः भारत ने इस क्षेत्र जो कि भारत के लिए निर्णायक महत्व का है, के साथ परंपरागत और ऐतिहासिक संबंध बनाने के लिए अपनी पर्याप्त शक्ति लगाई है। "पश्चिमोन्मुखी" नीति, जो भारत द्वारा प्रारंभ की गई, वह इन तथ्यों पर आधारित है कि खाड़ी प्रदेश एक प्रमुख आर्थिक भागीदार, 4 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासियों का मेजबान और भारतीय ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत होने के नाते भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2005-06 में इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण विकास हुआ। गणतंत्र दिवस-2006 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सऊदी अरब के शाह महामहिम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज द्वारा और अप्रैल 2005 में कतर के अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी की भारत की यात्रा से भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच भागीदारी के पर्याप्त संवर्द्धन के प्रति नेताओं की वचनबद्धता की पुष्टि की।

भारत इराक के आर्थिक पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए वचनबद्ध है। भारत में इराक में जारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वागत किया जिससे इराकी जनता अपने राष्ट्र की नियति के पूर्ण-संप्रभु नियंत्रक बन सकेंगे।

ईरान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध और भी गहन तथा सारगर्भित हुए हैं। संयुक्त आयोग की बैठकों, सुरक्षा वार्ता और कार्यकारी दल की बैठकों जैसे नियमित संस्थागत आदान-प्रदान से ऊर्जा क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य, सूचना

प्रौद्योगिकी और पारगमन तथा सुरक्षा के महत्वपूर्ण मसलों पर पर्याप्त सहयोग संभव हो पाया है। दोनों देश आपसी समृद्धि और शांति तथा इस क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए मैत्री संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध हैं।

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (वाना): इस वर्ष के दौरान पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ भरत के संबंधों में महत्वपूर्ण विकास हुआ। फिलीस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकार के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और जोर्डन के राजकुमार हसन की यात्राओं से भारत और इस क्षेत्र के बीच मजबूत संबंधों की पुनःपुष्टि हुई। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। सूडान, मिस्र, लीबिया और सीरिया में तेल दोहन के क्षेत्र में भारत की पर्याप्त हिस्सेदारी है। पिछले वर्षों के दौरान इन देशों के साथ शिक्षा, सुरक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण, रक्षा सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, भेषज, वस्त्र और ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में हमारा सहयोग संवर्द्धित और विधिधतापूर्ण हुआ है।

मार्च, 2005 में अल्जीयर्स में आयोजित अरब लीग शिखर सम्मेलन में पहली बार पर्यवेक्षक के रूप में भारत की उपस्थिति इस क्षेत्र के साथ भारत के बढ़ते क्रियाकलाप का सूचक है। भारत फिलीस्तीनी जनता के समक्ष आ रही समस्याओं का न्यायोचित और स्थायी समाधान पाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। ताकि उन्हें अपना राज्य मिल सके। साथ ही भारत इजराइल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को संवर्द्धित और विविधतापूर्ण करने को महत्वपूर्ण मानता है।

अफ्रीका

भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप सहारा से दक्षिण के राष्ट्रों के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को सक्रिय करने को उच्च प्राथमिकता दी। इस वर्ष भारत और अफ्रीका के बीच हुई अनेक उच्च-स्तरीय यात्राओं से हमारी भागीदारी को संवर्द्धित करने की दोनों पक्षों की वचनबद्धता परिलक्षित हुई। भारत ने अफ्रीकी देशों के इस दृष्टिकोण की व्यापक तौर पर सराहना की कि भारत उन्हें प्रगति और समृद्धि के मार्ग में भागीदार बना सकता है।

पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क, जिसके लिए भारत और अफ्रीकी यूनियन के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया था, का उद्देश्य अफ्रीका में डिजिटल डिवाइड को पाटने में सहायता करना है। इसमें आईटी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में दूरवर्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकें। इसमें एक ऐसा नेटवर्क भी बनाया जाएगा जिससे अफ्रीका राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों वीडियो कांफ्रेंसिंग और वीओआईपी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी।

भारत ने अनेक अफ्रीकी देशों को एक बिलियन डालर से अधिक का रियायती ऋण दिया है जो सड़क और रेल परिवहन, कृषि मशीनरी और खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए थीं। अफ्रीकी विकास के लिए नई भागीदारी (एनईपीएडी) और टीम-9 पहल, जो भारत और पश्चिम अफ्रीका के नौ देशों के बीच एक तकनीकी-आर्थिक सहयोग उपक्रम है, से सहारा से दक्षिण के देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए आवश्यक गति मिली है।

भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा मार्च और नवम्बर में आयोजित भारत-अफ्रीकी परियोजना भागीदारी बैठक में मंत्रालय की सक्रिय भागीदारी से अफ्रीकी सरकारों और व्यावसायियों की व्यापक भागीदारी जुटाने में सहायता मिली और इससे पर्याप्त व्यावसायिक रूचि जागी जिसके फलस्वरूप ठोस पूछताछ और द्विपक्षीय परियोजनाओं के लिए वास्तविक संपर्क संभव हुआ।

भारत ने अफ्रीका के विभिन्न भागों में शांतिरक्षा मिशनों का लगातार समर्थन किया है। अभी भारतीय सैनिक बुरूंडी, कोटडी आयवरी, कांगों लोकतांत्रिक गणराज्य, इथोरिया और एरीट्रिया, सियरालियोन और सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में कार्य कर रहे हैं। लाभार्थी देशों द्वारा भारतीय सैनिकों और कार्मिकों की सेवाओं को ऊंचे स्तर पर रखा जाता है और इनकी सराहना की जाती है।

आइटेक कार्यक्रम और अफ्रीका कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता (स्कैप) का अफ्रीकी देशों ने व्यापक रूप से उपयोग किया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अभी एक हजार से अधिक अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार अनेक अफ्रीकी राष्ट्रों के राजनयिक विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से लाभ उठा रहे हैं।

यूरोप

भारतीय विदेश संबंधों में यूरोप का स्थान प्रमुख है। भारत यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को महत्वपूर्ण मानता है।

साझे मूल्य ओर लोकतंत्र, मानवाधिकार, बहुवाद, स्वतंत्र

मीडिया और विधिसम्मत शासन में विश्वास भारत और यूरोपीय संघ को स्वाभाविक रूप से भागीदार बनाते हैं। वर्ष 2004 में आयोजित 5वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन का उन्नयन करके इसे सामरिक भागीदारी स्तर तक लाया गया। यूरोपीय संघ की यू0के0 की अध्यक्षता के अंतर्गत सितम्बर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में राजनैतिक वार्ता और सहयोग को संवर्द्धित करने तथा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त कार्य-योजना को स्वीकार किया। भारत ने यू0के0, फ्रांस और जर्मनी के साथ अलग से सामरिक भगीदारी की स्थपना की है। सितम्बर, 2005 में प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा और फरवरी, 2006 में फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा से भारत-फ्रांस सामरिक भागीदारी में मील का पत्थर हैं। ई0यू0 अभी भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस वर्ष आस्ट्रिया, इटली और चेक गणराज्य के राष्ट्रपति तथा आयरलैण्ड, नीदरलैण्ड नार्वे और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आये जिससे इन देशों के साथ भारत के संबंधों को नयी शक्ति मिली।

अमेरिका

भारत के राजनयिक संपर्कों में भारत-अमरीकी संबंधों में बदलाव अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना रही है। द्विपक्षीय संबंध साझे मूल्यों और साझे हितों पर आधारित हैं।

जुलाई, 2005 में प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा, 18 जुलाई का संयुक्त वक्तव्य, अक्तूबर, 2005 का विज्ञान और प्रौद्योगिकी रूपरेखा करार, जून, 2005 की रक्षा संबंधों पर नयी रूपरेखा और मई, 2005 में पहल की गयी भारत अमरीकी ऊर्जा वार्ता में भारत-अमरीका संबंधों को मौखिक रूप से परिभाषित करने की संभवनाएं हैं। पूर्ण असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग करने का दोनों सरकारों का निर्णय हमारे संबंधों के विश्वास और सद्भावना का सूचक है। सामूहिक विनाश के हथियारों से संबद्ध अधिनियम का अधिनियमन, असैनिक और असैनिक नाभिकीय संयंत्रों के पृथक्करण और राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूचियों के उन्नयन का उद्देश्य भारत को दोहरे उपयोग की उच्च प्रौद्योगिकियों का व्यवहार्य गंतव्य बनाना है।

इस वर्ष के दौरान भारत और अमरीका ने निरंतर बढ़ते अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक भागीदारी स्तर तक हो जाने की वचनबद्धता व्यक्त की। राजनैतिक और आधिकारिक स्तर पर बार-बार होने वाले संपर्क इस भागीदारी की विशेषता है। वर्ष 2005 में आपसी हित के वैश्विक, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर दोनों देशों के विचारों में समानता आयी। इन क्रियाकलापों में सामरिक और सुरक्षा मसलों, रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, प्रसार का मुकाबला, व्यापार और निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण पर बल दिया गया।

कनाडाः बढ़ती समझबूझ, सद्भावना और सहयोग भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता रही। वर्ष 2005 के आरंभ में कनाडा के प्रधानमंत्री श्री पाउल मार्टिन की यात्रा के बाद दोनों पक्षों से हुई अनेक यात्राओं से द्विपक्षीय संबंधों को नयी गति मिली। इस वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच असैनिक नाभिकीय सहयोग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में दो करार संपन्न किए गये।

सितम्बर, 2005 में विदेश मंत्री द्वारा तथा नवम्बर, 2005 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा की गई कनाडा की यात्रा तथा अप्रैल और सितम्बर, 2005 में कनाडा की यात्रा तथा अप्रैल और सितम्बर, 2005 में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री द्वारा की गई भारत की यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को विशेष रूप से, उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

लातीन अमरीका एवं कैरेबियाई देश (एलएसी)

भारत ने लातीन अमरीका तथा कैरिबियाई देशों के साथ अपने सहयोग को और गहन बनाया है तथा उनके साथ अपने व्यापार एवं निवेश को बढ़ाया है। ब्राजील के साथ, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय (आईबीएसए) तथा बहुपक्षीय (जी-4 और जी-20) सामरिक साझेदारी को परस्पर मान्यता देने के संदर्भ में, हमारे संबंध और गहरे हुए हैं। वर्ष के दौरान संयुक्त आयोग की बैठक और दौरों के आदान-प्रदान के माध्यम से मैक्सिकों के साथ हमारे संबंधों में एक नया मोड़ आया है। भारत ने इन देशों के साथ जो ठोस संबंध बनाए हैं, उसके परिणामस्वरूप चिली और वेनेजुएला के राष्ट्रपति सहित लातीन अमरीकी देशों के कई विदेश मंत्रियों ने वर्ष 2005 में भारत की यात्रा की है।

मध्य अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्र के देशों के साथ वार्ता और सहयोग शुरू करने की भारत के पहल के रूप में आठ मध्य अमरीकी देशों, भारत-एसआईसीए, और 14 कैरिबियाई समुदाय के देश, भारत-कारिकोम के साथ पहली बार मंत्री स्तरीय तालमेल स्थापित हुए।

एलएसी क्षेत्र को भारतीय निर्यात वर्ष 2004 के दो बिलियन डालर से बढ़कर वर्ष 2005 में 3 बिलियन डालर हो गया।

ओएनजीसी विदेश लि0 (ओवीएल) ने भारत के ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करते हुए वेनेजुएला में एक बड़ा तेल क्षेत्र का अधिग्रहण किया। मर्कोसुर (ब्राजील, अर्जेंटीना, उरूग्वे तथा परागुवे) एवं चिली के साथ अधिमानी व्यापार व्यवस्थाएं इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ बढ़ते व्यापार के कदम हैं।

मौजूदा संबंधों को मजबूत एवं व्यापक बनाना, राजनीतिक वार्ता तथा सहयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करना और व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ाना इस क्षेत्र के लिए भारतीय नीति का मुख्य केन्द्र बिंदु रहा है। वर्ष के दौरान मर्कोसुर, कान (एंडियन समुदाय) कारीकोम और मध्य अमरीकी समूह के देशों (सीका) जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ फ्रेमवर्क करार प्रवृत्त/अनुमान किए गए हैं जिससे कि इन प्रगतिशील महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों में वृद्धि हुई हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 60वें सत्र का मुख्य केन्द्र बिन्दु वर्ष 2005 में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन करना था। इस शिखर बैठक के निष्कर्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुधार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और विकास संबंधी मुद्दों पर आगे कार्रवाई करने के लिए रोडमैप निर्धारित किया है।

प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 60वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वर्ष 2000 में अंगीकार किए गए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने आवश्यक संसाधनों को गतिशील बनाने और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता जतायी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र सुधारों और उसके पुनरूद्धार की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण मसलों पर विचार-विमर्श में सकारात्मक भूमिका निभायी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भागीदारी करना जारी रखा।

यह सहज लोकतंत्र के रूप में भारत की एक विशिष्ट पहचान ही थी कि जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव द्वारा संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष शुरू किए जाने के अवसर पर, अन्य नेताओं के साथ-साथ भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया और जिसमें भारत ने 10 मिलियन डालर का प्रारंभिक अंशदान किया। लोकतांत्रिक समुदाय में भारत की सक्रिय साझेदारी और वैश्विक लोकतांत्रिक पहलों में इसकी संलग्नता ने भारत को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जिस पर कि भारत अपने मूल्यों, अनुभवों, सांस्थनिक क्षमताओं और प्रशिक्षण के आधारभूत ढांचों को उन देशों के साथ बांटा है जो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को भारत के साथ बाटतें हैं।

भेदभाव रहित एवं सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण तथा जनसंहार के सभी हथियारों को पूरे विश्व से समाप्त करने की भारतीय प्रतिबद्धता उसकी नीति घोषणा एवं राजनयिक पहलों में स्पष्ट हुई है।

अप्रसार एवं निरस्त्रीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय चिन्ताओं के साथ भारत की राष्ट्रीय अनिवार्यताएं एवं सुरक्षा दायित्वों के समन्वयन पर वर्ष के दौरान काफी प्रगति हुई है। संवेदनशील सामग्री एवं प्रौद्योगिकियों जिनका कि जन संहार के हथियारों अथवा उनके छोड़े जाने के साधनों के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है, के निर्यात पर भारत नियंत्रण रख रहा है। जन संहार के हथियारों एवं उसकी सुपुर्दगी प्रणाली (विधिविरूद्ध क्रियाकलापों का निषेध) अधिनियम का जून, 2005 में अधिनियमन, वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के उद्देश्य के लिए योगदान करने की भारतीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

क्षेत्रीय स्तर पर एशियाई, क्षेत्रीय मंच और एशिया में तालमेल तथा विश्वासोत्पादक उपायों पर सम्मेलन (सीका) के अंतर्गत विश्वास एवं सुरक्षा उत्पादक प्रक्रिया एवं संरचना में भारत की भागीदारी तेजी से बढ़ी है।

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

भारत की आर्थिक कूटनीति विश्व अर्थव्यवस्था के साथ विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां कि प्राकृतिक समानताएं पायी जाती हैं, अपने एकीकरण को और व्यापक बनाने की आवश्यकता होते हुए भी भारत की आन्तरिक क्षमताओं को बढ़ाने के प्रति केंद्रित रही है। इस दिशा में एशियन, मेकाँग-गंगा सहयोग, बिमस्टेक, इब्सा, जी-15 और आईओसी-एआरसी जैसी क्षेत्रीय आर्थिक समूहों के साथ भारत को तेजी से तालमेल बैठाने की आवश्यकता है।

दिसम्बर, 2005 में क्वालालम्पुर में आयोजित चतुर्थ भारत एशियान शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया जिसमें इस बात पर सहमति हुई कि भारत-आसियान एफटीए पर बातचीत जून, 2006 तक पूरा कर लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने क्वालालम्पुर में आयोजित पूर्व एशिया शिखर बैठक के उद्घाटन सत्र में भी भाग लिया जिसमे कि इस क्षेत्र में विकास एवं व्यापक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने की सहभागी देशों की प्रतिबद्धता संबंधी

घोषणा को मंजूरी दी गई। भारत विकासशील देशों के हितों की देखभाल के लिए वचनबद्ध है और उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन जैसे महत्वपूर्ण संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा है।

भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आईटेक) कार्यक्रम एवं विकास सहभागिता (डीपी)

भारत को सह विकासशील देशों के निकट लाने, इन देशों के साथ भारतीय तकनीकी एवं वैज्ञानिक विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने और विकासशील देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आइटेक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। वर्तमान में एशिया अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, लातीन अमरीका, पैसीफिक तथा लघु द्वीप समूह वाले देशों के ऐसे 156 देश हैं जो आइटेक कार्यक्रम के तहत कवर होते हैं। आइटेक कार्यक्रम के मुख्य घटक है : (क) नागरिक एवं सैन्य प्रशिक्षण, (ख) विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति (ग) अध्ययन दौरे (घ) कलपुर्जे एवं यंत्रों को भेंट करना (ड.) परियोजनाएं एवं सुसाध्यता अध्ययन और परामर्शी सेवा जैसी परियोजना से संबंधित कार्यकलाप, और (च) आपदा राहत हेतु सहायता। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के अनुरूप विकासशील देशों के साथ भारत की तकनीकी एवं अन्य विकासोन्मुख सहयोग को बढ़ाने और विस्तार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। भारत के विकास परियोजना सहयोग को और बेहतर बनाने के लिए आइटेक कार्यक्रम की देखरेख कर रहे तकनीकी सहयोग (टीसी) प्रभाग के अलावा मंत्रालय में एक नया 'विकास सहभागिता प्रभाग' बनाया गया है।

निवेश तथ प्रौद्योगिकी संवर्धन (आईटीपी)

भारत में निवेश तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना भारतीय आर्थिक कूटनीति का केंद्र बिन्दु रहा है। देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साझेदारी तथा एफडीआई प्रवाह और तकनीकी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ मिलकर कार्य किया है। बाह्य व्यापारों का संवर्धन एवं बढ़ावा देना तथा ऊर्जा सुरक्षा का उच्च स्तर सुनिश्चित करना भी मंत्रालय के आर्थिक कार्यों के महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं।

नीति नियोजन एवं अनुसंधान (पीपीआर)

मंत्रालय का पीपीआर प्रभाग नीति अनुसंधान में लगी संस्थाओं के साथ गहन संबंध बनाए रखा है और भारत की विदेशी नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सीधे प्रभाव डालने वाली विषयों का विश्लेषण करता रहा है। यह मंत्रालय की विदेश नीति के नियोजन, आरेखन तथा कार्यन्वयन प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों का चयन करने के उद्देश्य से सेमिनार आयोजित करने तथा अनुसंधान कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2005 के दौरान इस प्रभाग ने ऐसे 29 सेमिनार एवं अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित किया है। मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पीपीआर प्रभाग करता है।

प्रोटोकोल

प्रोटोकोल प्रभाग बड़ी संख्या में होने वाले अन्दरूनी और बाहरी उच्च-स्तरीय दौरों, सम्मेलनों, प्रत्यय पत्र समारोहों, सहकारी मेजबानी और अन्य विविध कार्यों में पूर्णतः संलग्न रहा। विदेशी हस्तियों की बड़ी संख्या में परिचर्चा करने की इसकी क्षमता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की संवर्द्धित छवि को बढ़ाया है। वर्ष के दौरान अधिकृत विदेशी मिशनों, राजनयिकों और कौंसल अधिकारियों के लिए वैट वापसी तंत्र को कार्यान्वित किया गया है।

कौंसली, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं

मंत्रालय का सीपीवी प्रभाग केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन और विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं पोस्टों के माध्यम से भारतीय नागरिकों तथा आप्रवासी भारतीयों का पासपोर्ट एवं कौंसली सेवाएं और विदेशी राष्ट्रिकों को कौंसली एवं वीजा सेवाएं प्रदान करता है। भारत में 30 पासपोर्ट कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है तथा मशीन से पढ़े जाने योग्य पासपोर्टों को जारी करने से संबंधित समस्त नियमित कार्यों को इलेक्ट्रानिक ढंग से किया जा रहा है। आवेदकों की सहायता करने तथा शिकायतों/परेशानियों की शीघ्र सुनवाई करने के लिए प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में सुविधा-केन्द्र एवं सहायता डेस्कों की स्थापना की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में किए गए प्रावधान के अनुसार, मंत्रालय ने केन्द्र में एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं समस्त पासपोर्ट कार्यालयों में सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है।

प्रशासन

मंत्रालय ने मुख्यालयों में और विदेश स्थित 164 भारतीय मिशनों/पोस्टों में बेहतर कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का उद्देश्य बनाए रखा है। कुशल कार्मिकों की उपयुक्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए समस्त पदोन्नति पैनलों को समय

पर लागू किया गया था। नियमित संपर्कों के माध्यम से कर्मचारी पक्ष के साथ संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र को और अधिक सक्रिय बनाया गया था। कुछ सचिवालयी सहायता कार्य को रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारी की भर्ती लंबित होने के कारण अस्थायी तौर पर बाहरी स्रोतों से करवाया गया था। विभिन्न मिशनों का निरीक्षण हाल में गठित निरीक्षण महानिदेशालय द्वारा किया गया था। करांची में भारतीय महाकौंसलावास को फिर से चालू करने की प्रक्रिया चलाई गई थी। अधिकारियों के वेतन के संवितरण को इलेक्ट्रॉनिक निपटान व्यवस्थातंत्र के उपयोग से स्वचालित कर दिया गया। नाम आधारित/पदनाम-आधारित ई-मेल पहचानों का बेहतर उपयोग किया गया था। मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए सरकार के विशेष भर्ती अभियान को तत्परता से लागू किया।

हिन्दी का प्रचार और प्रसार करने की सरकार की नीति पर कायम रहते हुए, विदेश मंत्रालय हिन्दी के समर्थन के लिए विशेष प्रयास करता रहा है। द्विपक्षीय संधियों, समझौता ज्ञापनों, प्रत्यय-पत्रों, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के भाषणों, मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट और संसद प्रश्नों जैसे समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया गया था। विदेश स्थित अधिकांश भारतीय मिशनों/पोस्टों में कंप्यूटर अब द्विभाषी हैं। सभी मिशन विभिन्न योजनों के माध्यम से हिन्दी की शिक्षा देने और इसका प्रसार करने में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। संयुक्त राष्ट्र में एक भाषा के रूप में हिन्दी को सुस्थापित कराने के लिए राज्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था। हिन्दी विदेश सेवा संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक अभिन्न हिस्सा है।

मंत्रालय अपनी कार्यप्रणाली के समस्त दायरे में पुरूष-महिला समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और चुनौतीपूर्ण एवं प्रतिष्ठापूर्ण पदों पर जाने हेतु महिला अधिकारियों को समान अवसर प्रदान करता है। मुख्यालयों और विदेश स्थित मिशनों/पोस्टों दोनों में महिला अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं।

समन्वय

मंत्रालय का समन्वय प्रभाग विदेश मंत्रालय के संसद से संबंधित समस्त कार्यों और मंत्रियों, विधायकों तथा सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरों की स्वीकृति के प्रस्तावों की जांच के लिए कार्य करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की स्वीकृति भी देता है। इस प्रभाग का छात्र प्रकोष्ठ देश में मेडिकल एवं इंजीनियरी संस्थाओं में आरक्षित सीटों पर विदेशी स्व-वित्तपोषित छात्रों के चयन, नामांकन और दाखिले का कार्य भी करता है।

बाहरी प्रचार

सूचना प्रसार के लिए विदेश मंत्रालय के नोडल स्रोत के रूप में बाहरी प्रचार-प्रभाग ने नियमित प्रेस विज्ञप्तियों, वक्तव्यों, प्रैस रिलीजों और अन्य संचार माध्यमों से महत्वपूर्ण मामलों एवं घटनाओं पर भारत के दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया। मंत्रालय का वेबसाईट इस संबंध में मूल्यवान स्रोत साबित हुआ। विश्व की बड़ी ताकतों, पड़ोसियों और शेष विश्व के साथ भारत के बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संबंधों को यथोचित ढंग से प्रचारित किया गया था। आतंकवाद, लोकतंत्र, प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, निरस्त्रीकरण एवं संयुक्त राष्ट्र सुधारों सहित समस्त संगत मामलों पर भारत की भूमिका की विभिन्न मंचों पर सराहना की गई। विदेश स्थित भारतीय मिशनों को विदेश में भारत की छवि को प्रदर्शित करने और बढ़ाने के लिए फिल्में, वृत्तचित्रें, अन्य श्रृव्य-दृश्य सामानों और प्रकाशनों/पुस्तकों के साथ-साथ मंत्रालय की अपनी मासिक पत्रिका इण्डिया पर्सपेक्टिव्स प्रदान की गईं।

विदेश सेवा संस्थान

विदेश सेवा संस्थान ने मंत्रालय के आईएफएस परिवीक्षार्थियों एवं अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ विदेशी राजनयिकों हेतु अपने राजनय और विदेश नीति कार्यक्रमों को जारी रखा। 2004 बैच के आईएफएस परिवीक्षार्थियों को वर्ष भर एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत रखा गया, जिससे उन्हें अपने पेशेवर जीवन के लिए तैयार किया जा सके और इसके बाद उन्हें जनवरी, 2006 में मंत्रालय में वापस कर दिया गया। विदेशी राजनयिकों हेतु तीन पेशेवर पाठ्यक्रम, विदेशी राजनयिकों हेतु एशिया संबंधी एक उन्नत पाठ्यक्रम और वियतनामी एवं सूडानी राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों में शामिल थे। संस्थान ने अन्य देशों में अपने प्रतिपक्षों के साथ संस्थागत संपर्कों को बनाए रखा।

सांस्कृतिक संबंध

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विश्व के देशों और लोगों

के साथ भारत के सांस्कृतिक संपर्कों को सुदृढ़ बनाने संबंधी प्राथमिक भूमिका को पूरा करता है। विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों और भारतीय अध्ययन पीठों के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत और इसकी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता लाने में सहायता प्रदान करता है और इस प्रकार द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अतिरिक्त, परिषद भारत/विदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है इसमें सहायता करता है, विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता लाने के लिए अपनी स्वयं की पत्रिका भी प्रकाशित करता है।

भारतीय विदेश मामले परिषद (आईसीडब्ल्यूए)

भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1943 में स्थापित भारतीय विदेश मामले परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में अपने आप को सुस्थापित कर लिया है। भारतीय विदेश मामले परिषद अधिनियम, 2001 द्वारा राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था के रूप में घोषित, इस परिषद ने संगोष्ठियों/सेमिनारों/सम्मेलनों के रूप में गतिविधियों के एक जोरदार कार्यक्रम को अपने अधिदेश के अनुसरण में आयोजित करना जारी रखा। विशिष्ट पुस्तकालय के अतिरिक्त, परिषद इण्डिया क्वार्टरली एंड फॉरेन अफेयर्स रिपोर्ट जैसी अपनी स्वयं की पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है।

विकासशील देशों हेतु अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआइएस)

एक स्वायत्तशासी नीति विचार-तंत्र के रूप में आरआईएस ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों संबंधी नीति अनुसंधान को जारी रखा तथा आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, डब्ल्यूटीओ की हांगकांग शासकी सम्मेलन, सार्क शिखर सम्मेलन, कोरिया, जापान, मलेशिया ओर पाकिस्तान के साथ व्यापक आर्थिक वार्ता संबंधी द्विपक्षीय संयुक्त अध्ययन दलों, ईबसा वार्ता, जीएसटीपी समझौतों और एफटीए समझौतों जैसे अन्य महत्वपूर्ण समझौतों तथा बड़े शिखर सम्मलनों की तैयारी में विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान किया। आरआईएस के पास अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले एवं विकास सहयोग संबंधी क्षमता का निर्माण करने और नीति में सामंजस्य लाने के लिए अन्य देशों के विचार-तंत्रों के साथ गहन तारतम्य है।

■■

भारत के पड़ोसी देश 1

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान में सितम्बर, 2005 में संसदीय और प्रांतीय परिषदों का चुनाव संपन्न होने के साथ ही वहां वर्ष 2005 में बॉन समझौता संपन्न होता दिखा। अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर पारस्परिक प्रभाव पड़ा। अफगान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने 23-25 फरवरी, 2005 को भारत का आधिकारिक दौरा किया और बदले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 28-29 अगस्त, 2005 को काबुल का दौरा किया। दोनों देशों के बीच नियमित राजनीतिक चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए अपने सहायता कार्यक्रम को जारी रखा।

वर्ष 2005 में अफगानिस्तान के राजनैतिक परिदृश्यों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक परिवर्तन था वहां सितम्बर, 2005 में संसदीय और 34 प्रांतीय परिषदों का चुनाव होना। बाद में नवनिर्मित अफगान नेशनल एसेम्बली की 19 दिसम्बर, 2005 को बैठक बुलाई गई। तथापि, तालिबान, अल-कैदा और हिज्ब-ए-इस्लामी जैसे तत्वों द्वारा बाहरी मदद से अफगानिस्तान में बारंबार हिंसा की घटना से वहां से शांति और स्थिरता का पलायन हो चुका था। 2001 में तालिबानी शासन के अंत से लेकर अब तक, वर्ष, 2005 अफगानिस्तान का सबसे खूनी वर्ष था, जब 1500 से अधिक अफगानी नागरिक मारे गए। इसके अलावा, खेती, उत्पादन, मादक द्रव्यों की तस्करी की समस्या बनी रही, जिसके कारण अफगानिस्तान के राजनैतिक और आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य प्रभावित हुआ।

अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति दुष्कर होने के बावजूद, भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्ष, 2005 में उच्चतम स्तर पर सबसे पहली द्विपक्षीय प्रगति 23-25 फरवरी, 2005 से राष्ट्रपति करजई द्वारा भारत का कामकाजी दौरा था, उनके साथ 8 कैबिनेट मंत्री भी दौरे पर आए थे। दौरे के दौरान नागरिक उड्डयन और मीडिया एवं सूचना के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में दो समझौता ज्ञापन संपन्न हुए थे।

विदेश मंत्री ने 15 फरवरी, 2005 को काबुल का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति करजई, बाबा-ए-मिल्लत और पूर्व राजा जहीर शाह से मुलाकात की और विदेश मंत्री डा0 अब्दुल्ला से बाचचीत की। उन्होंने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के नए सर्जिकल ब्लॉक का उद्घाटन किया, जिसे भारत की सहायता से फिर से बनाया गया था। अफगानी विदेशी मंत्री, डा0 अब्दुल्ला ने 3-4 जुलाई, 2005 को भारत का दौरा किया।

द्विपक्षीय संबंध तब और भी सुदृढ़ हुए जब प्रधानमंत्री ने 28-29 अगस्त, 2005 को अफगानिस्तान का सरकारी दौरा किया था। दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि उत्तम, स्थिर, लोकतांत्रिक और समृद्ध अफगानिस्तान की स्थापना क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अनिवार्य है। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद को प्रजातंत्र के लिए एक खतरा माना और यह घोषणा की कि जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के प्रति भारत की सतत् प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की और 50 मिलियन डालर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। दौरे के दौरान, भारत के सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए जाने वाले अफगानिस्तान के नए संसद भवन की आधारशिला भी रखी गई। तीन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें लघु विकास परियोजनाओं पर एक समझौता ज्ञापन, स्वास्थ्य सुविधा और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर एक करार और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन शामिल था। वर्ष के दौरान एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया गया।

भारत ने सार्क की सदस्यता पाने के अफगानिस्तान के निर्णय का स्वागत किया। ढाका में 13 नवम्बर, 2005 को हुए 13वें सार्क शिखर सम्मेलन के अंतिम घोषणा-पत्र में अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य बनने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया।

अफगानिस्तान को भारत की सहायता

वर्ष 2002-2010 में भारत की मौजूदा प्रतिबद्धता 550 मिलियन यू0एस0 डालर तक बनती है। अफगानिस्तान में वर्ष 2005 में भारत द्वारा की गई कुछ प्रमुख प्रतिबद्धताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- उजबेकिस्तान से काबुल तक बिजली लाने के लिए 111 मिलियन यू0एस0 डालर की अनुमानित लागत से पुल-ए-खुमरी से काबुल तक 220 कि0वा0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और अफगानिस्तान के काबुल में 220/110/20 कि0वा0 सब-स्टेशन के निर्माण के लिए वित्त-पोषण और कार्यनिष्पादन।
- 67 मिलियन यू0एस0 डालर की अनुमानित लागत से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अफगानिस्तान के नए संसद भवन का निर्माण, जिसके 2010 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- वर्ष 2006 के बाद से भारत में युनिवर्सिटी शिक्षा के लिए अफगान छात्रों के लिए 500 छात्रवृति और अफगानी प्रशिक्षार्थियों के लिए लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 500 छात्रवृति शुरू करना।

अफगानिस्तान में भारत के सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही अन्य परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- विश्व खाद्य कार्यक्रम के तत्वावधान में अफगानिस्तान में विद्यालय भोजन कार्यक्रम के लिए बिस्कुट की आपूर्ति।
- बोर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 84 मिलियन यू0एस0 डालर की अनुमानित लागत से अफगानिस्तान में जारंग-देलाराम रोड की मरम्मत/पुनःनिर्माण, जिसे 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- वाटर एवं पावर कंस्लटेंसी सर्विसेज इण्डिया लि0 द्वारा 77 मिलियन यू0एस0 डालर की अनुमानित लागत से अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में सलमा बांध विद्युत परियोजना का पुनर्निर्माण और समापन, जो जनवरी, 2009 तक पूरी हो जाएगी।
- वर्ष 2005-06 तक विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित अफगान पुनर्निर्माण ट्रस्ट कोष के लिए चार वर्षों के लिए प्रति वर्ष 200,000 यू0एस0 डालर का अंशदान।
- काबुल, मजार-ए-शरीफ, जलालाबाद, हेरात और कंधार में इंडियन मेडिकल मिशनों को औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति।
- सेंट्रल वायर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा कंधार में 5000 टन की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण पूरा करना।
- हबीबिया स्कूल और बाल स्वास्थ्य हॉस्पिटल के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट की पुनः स्थापना।
- काबुल के पुल-ए-चरखी में आम सुविधा और टूल रूप सेंटर का निर्माण और उद्घाटन।
- 11 प्रांतीय राजधानियों में बुनियादी दूरसंचार नेटवर्क बहाल करना।
- फरयाब प्रांत में पावर ट्रांसमिशन लाइन और सब-स्टेशन उपकरण की आपूर्ति।
- भारत की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में 250 से अधिक अफगानवासियों का क्षमता निर्माण।
- अफगान नेशनल आर्मी को 300 वाहनों की आपूर्ति।
- प्रिंटिंग प्रेस, 100 कि0वा0-एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर, 10 टीवी स्टेशनों के लिए टी0वी0 सैटेलाईट अपलिंकिंग/डाउनलिंकिग सुविधा की स्थापना सहित सूचना व्यवस्था को फिर से बहाल करना/पुनः सक्रिय बनाना।
- अफगानिस्तान के गांवों में अफगानी महिला संगठनों को 1000 सिलाई मशीनों की आपूर्ति।
- सिग्नान में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के सौर विद्युतीकरण की चालू परियोजना।
- अमीर गाजी करगाह रिजर्वायर डैम को फिर से चालू करने का कार्य सितम्बर, 2005 में शुरू किया गया, जो दिसम्बर, 2006 तक पूरा हो जाएगा।

एक दुर्भाग्यशाली घटनाक्रम में, बोर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी, श्री मणियप्पन रमन कुट्टी, जो जारंग-देलाराम सड़क परियोजना में कार्य कर रहा था, का संदिग्ध तालिबानी आतंकवादियों ने 19 नवम्बर, 2005 को अपहरण कर लिया और 22 नवम्बर, 2005 को उसकी हत्या कर दी। भारत सरकार ने अफगानी अधिकारियों की मदद से अपहृत की सुरक्षित रिहाई का हरसंभ्व प्रयास किया था। इस रूकावट के बावजूद, भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

बांग्लादेश

बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की विशेषता उनके घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से बताई जाती है। विस्तृत दौर की चर्चा और सार्क शिखर सम्मेलन के मौके पर सर्वोच्च राजनैतिक स्तर के दौरों सहित राजनैतिक और सरकारी

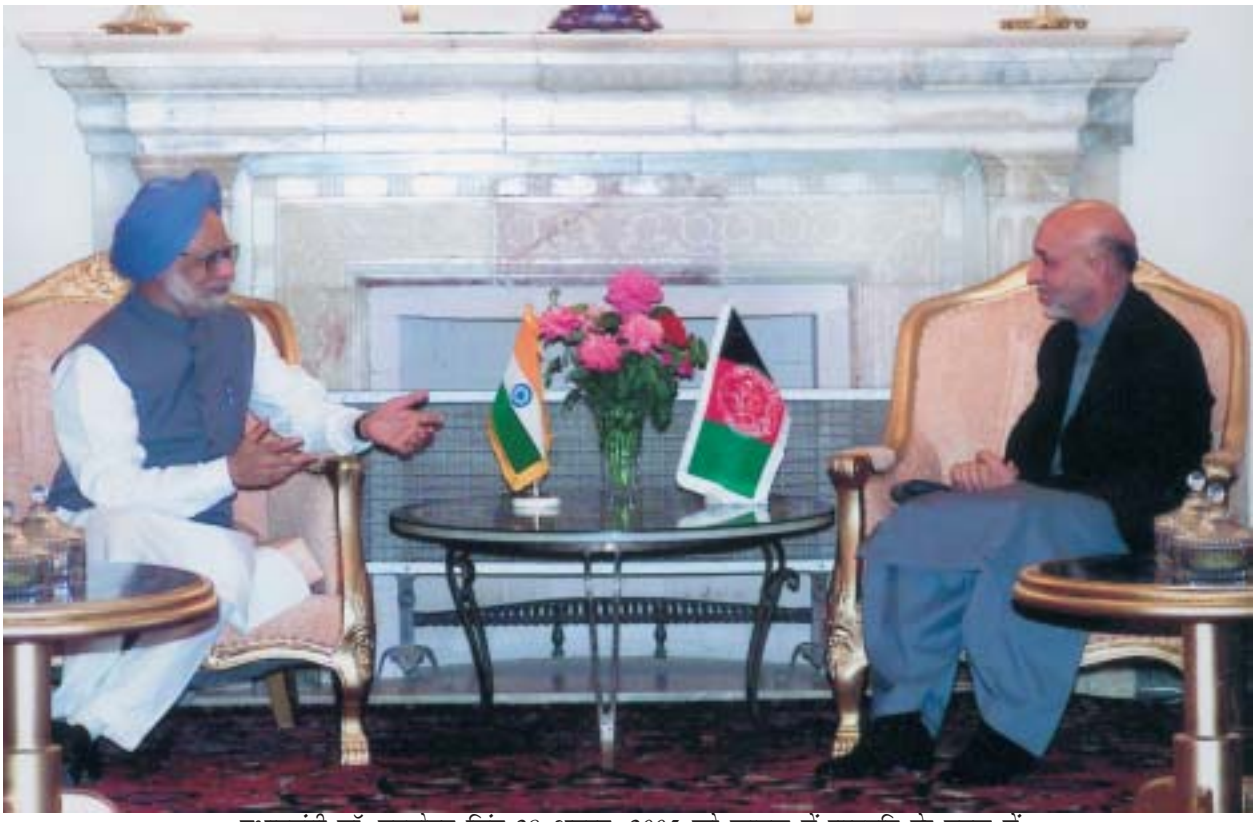

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 28 अगस्त, 2005 को काबुल में राष्ट्रपति के महल में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री हमीद करजाई के साथ।

भूटान नरेश महामहिम जिग्मे सिंग्ये वाडचुक 2 अगस्त, 2005 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ।

स्तर के दौरों के जरिए बांग्लादेश के साथ संबंध और सुदृढ़ हुए। हाल ही के वर्षों में, अनेक ऐसी पहलकदमियां रही हैं जिसने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ किया है, हालांकि, सुरक्षा संबंधी मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में हमेशा से ही अड़चन रही है। ये मुद्दे बांग्लादेश की भूमि पर भारत के पूर्वोत्तर से भारतीय विद्रोही समूहों और उनके नेताओं की मौजूदगी और क्रियाकलापों, अतिवादी इस्लामिक राजनैतिक पार्टियों और संगठनों तथा गैर-कानूनी घुसपैठियों सहित रूढ़िवादी उन्मुखीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव से संबंधित हैं।

प्रधानमंत्री ने ढाका में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बांग्लादेश का दौरा किया जहां उन्होंने शिखर सम्मेलन की उपजीविका के संबंध में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक में भारतीय विद्रोही समूहों, पारगमन, ऊर्जा और जल संसाधनों पर चर्चा हुई थी।

बांग्लादेश ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री खालिदा जिया के भारत दौरे के लिए मार्च, 2006 के उत्तरार्द्ध की तारीख का प्रस्ताव किया है।

विदेशी मंत्री ने 6-8 अगस्त, 2005 को बांग्लादेश का दौरा किया। यह संप्रग सरकार के किसी मंत्री के लिए बांग्लादेश का पहला दौरा था और बांग्लादेश में उनका भव्य स्वागत हुआ। दौरे के दौरान सुरक्षा, गैर-कानूनी आप्रवास, सीमा पर बाड़ लगाने, व्यापार और वाणिज्य, निवेश, दोनों देशों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने, जल संसाधनों के वहन, म्यांनमार-बांग्लादेश-भारत गैस पाइपलाईन और संयुक्त राष्ट्र सुधार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई थी। ईएएम ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री का एक पत्र भी दिया जिसमें उन्हें भारत दौरे के लिए आमंत्रित किया गया था। अपने दौरे के दौरान ईएएम ने बांग्लादेश के लिए 100 अतिरिक्त आईटीईसी स्लॉट, सूचना प्रौद्योगिकी में 600 बांग्लादेशी शिक्षकों के प्रशिक्षण, 620 कम्प्यूटर उपहारस्वरूप देने और बांग्लादेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की।

दो वर्ष के अंतराल के बाद ढाका में 18-21 सितम्बर, 2005 को भारत-बांग्लादेश ज्वायंट रिवर्स कमीशन की 36वीं बैठक हुई। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री पी0आर0 दासमुंशी, जल ससांधन मंत्री ने किया था। ज्वायंट रिवर्स कमीशन की इस बैठक ने दोनां पक्षों को दोनों देशों के बीच जल संसाधन के बंटवारे से संबंधित मुद्दे पर द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। बाढ़ की भविष्यवाणी, आर्सेनिक को दूर करने, भारत के नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना और तिमाईमुख बांध से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने म्यांनमार-बांग्लादेश-भारत त्रिपार्श्विक गैस पाईपलाईन के संबंध में 4-6 सितम्बर को ढाका का दौरा किया।

बांग्लादेश की ओर से, मि0 खांडाकेर मुशर्रफ हुसैन, बांग्लादेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने भारत सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 7-9 अप्रैल, 2005 को आयोजित 'मातृत्व, जन्मजात और बाल स्वास्थ्य' पर हुई एक बैठक में अपने शिष्टमंडल के नेता के रूप में भारत का दौरा किया।

लगभग 4 वर्षों के बाद 20-23 जून, 2005 को नई दिल्ली में विदेशी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी। दो विदेश सचिवों ने सुरक्षा, सीमाओं की शांतिपूर्ण देख-रेख, लोगों का एक-दूसरे के देशों में गैर-कानूनी घुसपैठ, जल संसाधन में सहयोग, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, निवेश को बढ़ावा देने, विज्ञान-प्रौद्योगिकी और कृषि में सहयोग, रक्षा आदान-प्रदान और सांस्कृतिक संबंध से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। आम हित के मामले पर एक दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुक्त और स्पष्ट चर्चा हुई थी, जो द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है।

भारत और बांग्लादेश के बीच गृह सचिव स्तर के छठे दौर की बातचीत नई दिल्ली में 27-28 अक्तूबर, 2005 को हुई। वार्ता के दौरान, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, गैर-कानूनी आप्रवास, संयुक्त सीमा, लंबित पड़े समझौते और कॉन्सुलर मिलों पर चर्चा हुई थी।

नौ-सेना के प्रमुख एडमिरल अरूण प्रकाश ने 17-20 दिसम्बर, 2005 को बांग्लादेश का दौरा किया। उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की।

महानिदेशक के स्तर पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बांग्लादेश राईफल्स (बीडीआर) जैसे रक्षा बलों की सीमा पर तैनाती से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर संस्थगत चर्चा भी हुई। 12-17 अप्रैल, 2005 और 26 सितम्बर-1 अक्तूबर, 2005 को दो बैठकें हुई थीं। इनमें सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। दोनों बलों ने अपनी आपसी सूझ-बूझ बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की ताकि उनका विश्वास एक-दूसरे पर बना रहे।

व्यापार संबंधी संयुक्त कार्यसमूह की तीसरी बैठक ढाका में 1-2 अगस्त, 2005 को हुई। टैरिफ बैरियर्स, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता और द्विपक्षीय व्यापार समझौते में संशोधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

संयुक्त सीमा कार्य दल की ढाका में फरवरी 2006 में होने

वाली बैठक के बाद पुनः अपना कार्य प्रारंभ करने की आशा है।

आधारभूत सुविधा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को 150 मिलियन डालर का ऋण देने के लिए वार्ता का दूसरा दौर नई दिल्ली में 22-23 अगस्त, 2005 को संपन्न हुआ। ऋण और शर्तों के दायरे में वित्त पोषण के लिए शामिल की जाने वाली परियोजनाओं की सूची पर आगे भी चर्चा होने की संभावना है।

सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान बढ़ते रहे हैं। दोनों देशों के बीच अगस्त, 2005 में 2005-08 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भूटान

भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ और दोस्ताना संबंध हैं जो आपसी विश्वास, समझदारी और सद्भाव पर आधारित हैं। वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों में ये संबंध और भी मजबूत हुए थे।

जनवरी, 2005 में अपने भारत दौरे के बाद, भूटान नरेश, जिग्मेसिंगे वांगचुक ने 1-4 अगस्त, 2005 को भारत का दौरा किया जसके दौरान उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ विस्तृत दौर की चर्चा की। इस दौरे से इन दोनों देशों के बीच के संबंध और भी प्रगाढ़ हुए।

प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह की भूटान के प्रधानमंत्री ल्योंपो सांगे नेदूप के साथ 12-13 नवम्बर, 2005 को ढाका में सार्क शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी। तत्कालीन विदेश मंत्री, श्री के0 नटवर सिंह ने अक्तूबर, 2005 में, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन राज्य मंत्री, कुमारी शैलजा ने जून, 2005 में संसदीय मामले और रक्षा राज्य मंत्री, श्री बी0 के0 हांडिक ने जुलाई, 2005 में, पर्यावरण और वन राज्य मंत्री, श्री नोमो नारायण मीणा ने अगस्त, 2005 में भूटान का दौरा किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस आर0सी0 लाहौटी ने मुख्य न्यायाधीशों के 8वें सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भूटान का दौरा किया। भूटान से वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ल्योंपो टोसे जिम्बा और उप-पर्यावरण मंत्री दाशों नादों रंचेन ने अक्टूबर/नवम्बर, 2005 में भारत का दौरा किया। विदेशी मंत्री ल्योंपो खांडू वांग्चुक ने 16 जनवरी, 2006 को भारत का दौरा किया और विदेश राज्य मंत्री, राव इंदरजीत सिंह और विदेश सचिव से मुलाकात की।

द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौते को नवीकृत करने पर चर्चा हुई थी और 10 वर्षों के लिए व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौते को नवीकृत करने पर सहमति हुई थी; नवम्बर, 2005 में विद्युत सचिव के भूटान दौरे के दौरान भूटान में विद्युत परियोजनाओं पर एक अम्ब्रेला करार को अंतिम रूप दिया गया था; प्रति सप्ताह उड़ान की संख्या को 12 से बढ़ाकर 47 करने के लिए नागरिक उड्डयन वार्ता के दौरान वायु सेवा करार पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ था; और आपसी सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए यूपीएससी और भूटान के रॉयल सिविल सेवा आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ था।

भूटान-भारत फाउंडेशन की बैठक अक्तूबर, 2005 में थिम्फू में हुई थी। इंडो-भूटान फ्रेंडशिप एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के शिष्टमंडलों का दौरा भी हुआ था। मणिपुरी और पंजाबी लोकनृत्य मंडली ने भूटान में अपना प्रदर्शन किया। "भारत-भूटान; दोस्ती की राह पर" एक फोटो प्रदर्शनी दिल्ली में दिसम्बर, 2005 में आयोजित की गई थी।

भारत हमेशा से ही भूटान का व्यापार और विकास में सबसे बड़ा साझेदार रहा है। द्विपक्षीय विकास सहयोग में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पुल, विद्युत, वाणिज्य और उद्योग, नागरिक उड्डयन, संस्कृति, शहरी विकास और आवास, न्याय क्षेत्र, मीडिया, मानव संसाधन विकास, आईटी और दूरसंचार जैसे विविध क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल थीं। भूटान की 9वीं योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए मंजूर की गई परियोजनाएं सफलतापूर्वक प्रगति पर हैं। भारत-भूटान विकास सहयोग की समीक्षा करने के लिए अधिकारी स्तर की वार्ता 12-13 जनवरी, 2006 को हुई थी। जल-विद्युत क्षेत्र इन दोनों देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना है। 1020 मेगावाट की ताला पनबिजली परियोजना वर्ष 2006 के मध्य तक शुरू होने की संभवना है। पुनात्सांग्चु-I पनबिजली परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के वर्ष 2006 में तैयार होने की संभावना है और उसके बाद 9वीं योजनावधि में पुनात्सांगचु-II के साथ मांगदेचु पनबिजली परियाजनाओं का डीपीआर तैयार किया जाएगा।

मई, 2005 में तृतीय भूटान-भारत व्यापार मेलों और सितम्बर, 2005 में थिंफू में दूसरे निर्माण एक्सपो में अनेक अग्रणी भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया।

वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा के लिए भारतीय संस्थानों में अध्ययन के लिए आए 50 भूटानी छात्रों को भारतीय छात्रवृत्ति दी गई। ये छात्रवृत्तियां आईटीईसी/कोलंबो प्लान स्कीम की तकनीकी सहयोग योजना के अंतर्गत दी गई सुविधा के अतिरिक्त थीं। इसके अलावा, बहुत अधिक संख्या में भूटानी छात्र भारत के विद्यालयों और कालेजों में अध्ययन करते हैं।

केन्द्र स्तर पर संयुक्त कार्यसमूह के जरिए और राज्य स्तरों पर राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग बैठकों के माध्यम से सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में भूटान के साथ सहयोग और अधिक बढ़ा था। दोनों देशों के सुरक्षा बलों द्वारा नियमित समन्वित पेट्रोलिंग की गई और दोनों सरकारों के बीच जानकारी की समय पर आदान-प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी।

चीन

वर्ष 2005, भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 55वां वर्ष था। इस वर्ष के दौरान, कार्यात्मक सहयोग के साथ उच्च स्तर पर राजनैतिक चर्चाओं से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ।

चीनी प्रधानमंत्री वेन जिआबाओं ने 9-12 अप्रैल, 2005 को भारत का दौरा किया जो द्विपक्षीय संबंधों की प्रगाढ़ता को दर्शाता है। इस दौरे के नतीजे भी काफी महत्वपूर्ण रहे। ग्यारह समझौते/समझौता ज्ञापन संपन्न हुए। दोनों प्रधानमंत्रियों को भारत-चीन व्यापार और आर्थिक संबंधों की भावी दिशा पर संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

दोनों पक्षों ने सामान्य चिंता के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत सर्वसम्मति जताई। हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करके दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि भारत-चीन संबंध व्यापक विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। भारत-चीन संबंध को "शांति और समृद्धि के लिए सामरिक, नीतिगत और सहयोगात्मक भागीदारी" तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने 11 अप्रैल, 2005 को एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त वक्तव्य में इस सर्वसम्मति को दर्शाया गया कि भारत-चीन संबंध द्विपक्षीय मुद्दों से बढ़कर है और अब इसका वैश्विक और कार्यनीतिगत महत्व है। इस संदर्भ में, द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक विकसित एवं विविधिकृत करने एवं संबंधों के सतत् सुधार के मार्ग में मतभेदों को लाए बिना सक्रिय तरीके से इन लंबित मतभेदों को सुलझाने पर सहमति हुई थी। वर्ष 2006 को "भारत-चीन मित्रता के वर्ष" के रूप में घोषित किया गया है।

दौरे के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा विवाद पर अपने-अपने राय दिए और समान तथा सौहार्दपूर्ण विचार-विमर्श के जरिए एवं द्विपक्षीय संबंधों के समग्र हितों को जारी रखते हुए एक उचित, स्पष्ट और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हल ढूंढ़ने की अपनी तत्परता दिखाई। इस दौरे का एक महत्वपूर्ण नतीजा "राजनैतिक मानदण्डों और भारत-चीन सीमा विवाद के समाधान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत पर करार" संपन्न होना था। इसने उन विशेष प्रतिनिधियों के कार्य के प्रथम चरण के सफल समापन को दर्शाया, जिन्हें समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में सीमा विवाद का निपटान करने के लिए, फ्रेमवर्क तलाशने का कार्य सौंपा गया था। उनके कार्यों के दूसरे चरण में, राजनैतिक फ्रेमवर्क और राजनैतिक मानदण्डों एवं मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर करार के आधार पर सीमा विवाद के निपटारे के लिए दोनों रक्षों द्वारा किए जाने वाले समायोजनों की तलाश करने के लिए दो विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई थी। अंतिम चरण में दोनों तरफ से सिविल, मिलिटरी और सर्वे कर्मचारियों द्वारा नक्शे और जमीन पर सीमाओं का वास्तविक चित्रण और सीमांकन शामिल होगा।

दौरे के दौरान "भारतीय चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर प्रोटोकोल" भी संपन्न हुआ था। इस बात को दोहराया गया था कि अंतिम समाधान को एक ओर रखकर, दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल रखने के लिए अपने संयुक्त प्रयासों को जारी रखेंगे। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत थे कि यह महत्वपूर्ण है कि संयुक्त कार्यसमूह वास्तविक नियंत्रण रेखा की जल्द से जल्द पुष्टि एवं स्पष्ट करने के लिए अपने कार्यों को जारी रखें।

प्रधानमंत्री वेन के दौरे में व्यापार और आर्थिक विकास के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया था। दोंनों पक्ष वर्ष 2008 तक 20 मिलियन या उससे अधिक बिलियन डालर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत थे। दोनों प्रधानमंत्रियों को दिए गए संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) की रिपोर्ट में सामग्रियों, सेवाओं के व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों से संबंधित उपायों का उल्लेख किया गया था और इसमें भारत और चीन के बीच बढ़े हुए आर्थिक सहयोग को आसान बनाने एवं इसमें आने वाली अड़चनों को दूर करने की सिफारिश की गई थी ताकि उन उपायों को शीघ्र कार्यान्वित किया जा सके। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इन सिफारिशों पर विचार करने और इनके कार्यान्वयन में सहयोग करने का काम मंत्रालय स्तरीय भारत-चीन संयुक्त आर्थिक समूह (जेईजी) को सौंप दिया। जेएसजी ने सामग्रियों और सेवाओं के व्यापार, निवेश, व्यापार निवेश को प्रोत्साहित करने एवं इसमें मदद करने और निर्धारित क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों वाले भारत-चीन क्षेत्रीय व्यापार करार की भी

सिफारिश की है। दोनों प्रधानमंत्री एक संयुक्त कार्यबल की नियुक्ति करने पर सहमत थे जो भारत-चीन क्षेत्रीय व्यापार करार की व्यवहार्यता और उससे मिलने वाले लाभों का विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसकी विषय-वस्तु के संबंध में अपनी सिफारिशें देंगे। दोनों पक्षों ने भारत और चीन के बीच वित्तीय वार्ता तंत्र बनाने के लिए एक करार भी किया।

प्रधानमंत्री वेन के दौरे के बाद भी उच्च स्तरीय वार्ता जारी रही। प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह 23 अप्रैल को जकार्ता में एफ्रो-एशियन सम्मेलन के दौरान और फिर 9 मई को मास्को में विजय दिवस के दौरान चीन के राष्ट्रपति हु-जिंताओं से मिले। बाद में, 7 जुलाई को सेनेगल्स, यू0के0 में जी 8+5 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन और फिर 14 सितम्बर को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय मानीटरी बैठक के अंतिम दिन प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति हु-जिंताओं से वार्ता हुई। प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री वेन जिआबाओ 14 दिसम्बर को प्रथम पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के समापन पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी मिले।

कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ चाईना (सीपीसी) के साथ शुरू की गई वार्ता, जो 2004 में शुरू हुई थी, को और अधिक आगे बढ़ाया गया। हरियाणा सरकार के आग्रह पर क्विंघई प्रांत के पार्टी सचिव मि0 झो लेजी ने सितंबर 2005 को भारत का दौरा किया। तत्कालीन संस्कृति और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री जयपाल रेड्डी के आमंत्रण पर सीपीसी पोलित ब्यूरो सदस्य और सीपीसी के प्रचार विभाग के मंत्री, मि0 लिअ युनशान ने अक्तूबर, 2005 में भारत का दौरा किया। मि0 वांग झागुओ, सीपीसी पोलित ब्यूरो सदस्य और चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के स्थायी समिति के उपाध्यक्ष ने नवंबर 2005 में भारत का दौरा किया। प्रांतीय स्तर पर, जिर्यागसु पार्टी सचिव, मि0 ली युआंचावो ने सितंबर 2005 में, जबकि जीलिन पार्टी सचिव, मि0 वांग युंकून ने दिसंबर 2005 में भारत का दौरा किया।

सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों-श्री एम0 के0 नारायण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और मि0 दाई बिंगुओ, चीन के कार्यकारी उप-विदेश मंत्री के बीच बातचीत का छठा दौर 26-28 सितंबर, 2005 को संपन्न हुआ, जो कि बातचीत के दूसरे चरण की शुरूआत थी। वार्ता का अगला दौर भविष्य में नई दिल्ली में होगा।

विदेश सचिव, श्री श्याम शरण और चीन के उप विदेश मंत्री, मि0 वु0 दवेई के बीच भारत-चीन सामरिक नीति संबंधी वार्ता का दूसरा दौर 9-10 जनवरी, 2006 को बीजिंग में संपन्न हुआ। सामरिक नीति संबंधी वार्ता का पहला दौर 24 जनवरी, 2005 को दिल्ली में संपन्न हुआ था।

भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में लगातार सुधार रक्षा के क्षेत्र में और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं संयुक्त क्रियाकलापों में एक दूसरे की बढ़ती हुई भागीदारी से सुस्पष्ट था। वर्ष 2005 में भारत की ओर से चीन के प्रमुख उच्च स्तरीय दौरे में से कुछ इस प्रकार थेः नौसेना स्टाफ के वाईस चीफ, वाइस एडमिरल यशवंत प्रसाद ने अप्रैल में; मिलिटरी इंट्रेलीजेंस के महानिदेशक, लेफ्टि0 जनरल डी0एच0 सुमनवार ने मई में; सैन्य संचालन के महानिदेशक, लेफ्टि0 जनरल मदन गोपाल ने सितंबर में; राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से एक शिष्टमंडल ने मई में; चीन में एकेडमिक सेमिनार में भाग लेने के वाइस एडमिरल रमनपुरी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने जून में 1 भारतीय शिष्टमंडल ने अगस्त, 2005 में चीन-रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास "पीस मिशन 2005" में और बाद में सितंबर 2005 में चीन के सैन्य अभ्यास "नॉर्थर्न स्वोर्ड 2005" में एक पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। चीन की ओर से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जनरल लियांग गुआंग्ली ने मई 2005 में भारत का दौरा किया। रियर एडमिरल झांग योग्यी के नेतृत्व में पीएलए सैन्य शिष्टमंडल ने अक्तूबर, 2005 में भारत का दौरा किया। इसके अलावा, चीन के सेंट्रल मिलिटरी कमीशन के जनरल ऑफिस के डिप्टी चीफ के नेतृत्व में एक सात-सदस्यीय शिष्टमंडल ने जुलाई-अगस्त, 2005 को भारत का दौरा किया। पीएसए के तीन अधिकारियों ने नवंबर, 2005 में भारतीय सैन्य अभ्यास "डिजर्ट स्ट्राइक" में पर्यवेक्षकों के रूप में हिस्सा लिया। पीएलए नौ सेना से दो पोतों के कार्यबलों ने 28 नवंबर से 1 दिसंबर 05 तक भारत का दौरा किया और कोच्ची के समुद्र तट पर भारतीय नौसेना के साथ तलाशी एवं बचाव कार्य का अभ्यास किया। रक्षा मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी का चीन दौरा मार्च, 2006 में तय है।

आतंकवाद रोकने और लोक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत-चीन सहयोग गृहमंत्री श्री शिवराज पाटील के 7-11 सितंबर 2005 के चीन दौरे से व्यक्त होता है। दौरे के दौरान, भारत के गृह मंत्रालय और चीन के लोक सुरक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, देशपार के अपराध जिसमें हवाला, मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों का अवैध व्यापार, जाली पासपोर्ट और बीजा और साईबर क्राईम शामिल हैं, का सामना करने के लिए सहयोग; कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण; और

पारस्परिक लाभदायक ढंग से राष्ट्रीय इंटरपोल एजेंसियों के बीच सहयोग का प्रावधान किया गया था।

भारत और चीन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों में भी लगातार सुधार जारी रहा था। चीनी आंकड़े के अनुसार नवंबर, 2005 तक दोनों ओर से मिलाकर व्यापार 16-97 बिलियन यू0एस0 डालर तक पहुंच चुका था, जो 39.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। जनवरी-नवंबर, 2005 के दौरान भारत से चीन को किया गया कुल निर्यात 8.96 बिलियन यू0एस0 डालर का था जबकि भारत में चीन से होने वाला आयात 8.01 बिलियन यू0एस0 डॉलर तक पहुंच गया था, जो कि 2004 की संबद्ध अवधि में क्रमशः 30 प्रतिशत और 58 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। भारत से चीन को मुख्य रूप से लौह अयस्क, लौह व इस्पात, प्लास्टिक, कीमती पत्थर एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनों का निर्यात किया गया। भारत में चीन से होने वाले निर्यात में मुख्य रूप से मशीन, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, खनिज ईंधन (कोल व कोक), सूती वस्त्र, लौह-इस्पात और लौह-स्टील के उत्पाद शामिल थे।

चीन में जुलाई, 2005 को हुई डब्ल्यू टी ओ लघु-मंत्रीस्तर की बैठक के समापन के अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ की चीन के वाणिज्य मंत्री, मि0 बो जिलाई के साथ हुई वार्ता के दौरान बढ़े हुए द्विपक्षीय कार्य को आसान बनाने के भारत-चीन संयुक्त अध्ययन समूह द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं को दोहराया गया। वित्त मंत्री, श्री पी0 चिदंबरम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, श्री वाई0वी0आर0 रेड्डी ने भी जी-20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 14-16 अक्तूबर, 2005 को चीन का दौरा किया जहां उन्होंने अपने साथियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्ष आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में भारत-चीन सहयोग को बढ़ाने और हाल ही में गठित इंडिया-चाइना फाइनेंशियल डायलॉग की जल्द से जल्द बैठक बुलाने पर सहमत थे।

भारत और चीन में बढ़ती हुई वैश्विक दिलचस्पी तथा उनके आर्थिक सहयोग को "चीन और भारत का बदलता हुआ आर्थिक स्वरूप : घरेलू और क्षेत्रीय अड़चनें" नामक उच्चस्तरीय सम्मेलन में दर्शाया गया था, जिसका आयोजन बीजिंग में अक्तूबर, 2005 को इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड द्वारा किया गया थें । भारत की ओर से भाग लेने वालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर डा0 राकेश कुमार और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अशोक लाहिड़ी भी शामिल थे। चीन, थाइलैण्ड, सिंगापुर और हांग-कांग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था।

सतलज नदी के मामले में बाढ़ के मौसम के दौरान हाइड्रोलाजिक आंकड़ों के आदान प्रदान के संबंध में एक समझौता ज्ञापन संपन्न होने से जल संसाधन के क्षेत्र में भी भारत चीन सहयोग जारी रहा। समझौते में दोनों पक्षों के लिए द्विपक्षीय चर्चा को जारी रखने की भी व्यवस्था की गई थी ताकि तिब्बत से भारत में बहने वाली दो अन्य नदियों-पर्लुंग जंगबो और लोहित/जायु क्यू नदियां- के जल्द ही ऐसे किसी करार को अंतिम रूप देने के लिए द्विपक्षीय चर्चा को जारी रखा जा सके। भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र के लिए हाइड्रोलाजिक आंकड़ों के आदान प्रदान के संबंध में ऐसा ही एक समझौता ज्ञापन पहले ही संपन्न हो चुका है।

ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की तलाश करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री मणिशंकर अय्यर के नेतृत्व में सरकार एवं तेल कंपनियों के अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने 11-13 जनवरी, 2006 को चीन का दौरा किया। दौरे के दौरान भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के बीच तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों में एक समझौता करार भी हुआ।

सांस्कृतिक क्षेत्र में, भारत-चीन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (2003-05) में विभिन्न चर्चाओं एवं क्रियाकलापों, जिनमें नृत्य, थियेटर, पेंटिंग, फोटोग्राफिक प्रदर्शनियां, फिल्में, साहित्यिक चर्चा और सांस्कृतिक पुनः स्थापन शामिल थे, के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना जारी रखा गया। अप्रैल, 2005 में प्रधानमंत्री वेन जिआबाओ के भारत दौरे के दौरान, भारत में चीन का सांस्कृतिक माह और चीन में भारत का सांस्कृतिक माह आयोजित करने पर सहमति हुई थी। चीन के लुओयांग में ह्वाईट हौर्स टेम्पल के निकट भारतीय शैली में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन भी संपन्न हुआ था। प्रधानमंत्री द्वारा गठित सलाहकार समिति ने डिजाइन और परियोजना के लिए आर्किटेक्ट का चयन किया है। चीन की तरफ से वर्ष 2006 में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

जन संचार, युवा मामले और खेल के क्षेत्र में भी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। वेन जियाबाओ के भारत दौरे के दौरान भारत-चीन फिल्म कारपोरेशन कमीशन पर एक प्रोटोकोल संपन्न हुआ था। चीन की फिल्मों को गोआ के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में और नवंबर, 2005 में हैदराबाद में गोल्डन एलिफैन्ट बाल

चीन के प्रधानमंत्री श्री वेन जियाबाओ 11 अप्रैल, 2005 को महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करते हुए।

विदेश सचिव श्री श्याम सरन इस्लामाबाद में 1 सितम्बर, 2005 को पाकिस्तान के विदेश सचिव श्री रियाज मोहम्मद खान के साथ।

फिल्मोत्सव में दिखाया गया। चीन के खेल मंत्री मि0 लियुपेंग के जुलाई, 2005 में भारत दौरे के दौरान, दोनों पक्षों में खेल के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ।

शैक्षिक आदान प्रदान में भी विस्तार हुआ है। गैर-सरकारी आंकलनों के अनुसार, चीन में इस समय मेडिकल के लगभग 1000 भारतीय छात्र है।

अप्रैल-नवम्बर, 2005 की अवधि के लिए भारतीय दूतावास, बीजिंग में वर्ष 2004 में उसी अवधि के दौरान जारी किए गए 6,359 बीजा के एवज में 10,347 वीजा जारी किए गए। भारतीय महावाणिज्य दूतावास, शंघाई में अप्रैल-नवम्बर 2005 के दौरान 7,479 वीजा जारी किए गए। चीन के सरकारी आंकड़े के अनुसार, चीन में इस समय पंजीकृत भारतीय नागरिकों की संख्या 4,717 है जो चीन के अलग-अलग प्रांतों और शहरों में रह रहे हैं।

मंत्रीस्तर पर विचार विमर्शों का आदान प्रदान

- कृषि मंत्री श्री शरद पवार, ने मार्च-अप्रैल, 2005 में चीन का दौरा किया और अपने चीनी प्रतिपक्ष मंत्री दु किंग्लिन के साथ चर्चा की।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डा0 अंबुमणिदास रामदोस ने 14-20 नवंबर, 2005 को चीन का दौरा किया और चीन के स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय आबादी और परिवार नियोजन आयोग मंत्री और पारंपरिक चीन औषधि के राज्य प्रशासन के प्रमुख से मुलाकात की।
- पर्यटन मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी ने बीजिंग में महिलाओं पर चौथे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन की 10 वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने के लिए 31 अगस्त-2 सितंबर 2005 को चीन का दौरा किया।
- वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री ई.वी.के.एस. इलानगोवन ने बैंकॉक समझौते के मंत्री परिषद के पहले सत्र में भाग लेने के लिए 1-2 नवंबर 2005 को चीन का दौरा किया।
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, श्री रमन सिंह ने 24 नवंबर-1 दिसंबर 2005 के दौरान चीन का दौरा किया।
- छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे, मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री ईश्वर दास रोहानी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरमोहिन्दर सिंह चडढा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री जी0आर0 मुसाफिर, तमिलनाडु विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री ए0 अरूणाचलम ने अध्ययन दौरे के एक हिस्से के रूप में अगस्त-सितंबर 2005 के दौरान चीन का दौरा किया और चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के साथ विचार विमर्श किया।
- श्री रघुबर दास, वित्त और शहरी विकास मंत्री, झारखंड सरकार ने अक्तूबर, 2005 में चीन का दौरा किया।
- श्री निरूपम सेन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री प0 बंगाल सरकार ने चीन आर्थिक सहयोग केंद्र के आंमत्रण पर चीन का दौरा किया।
- चीन के भूमि एवं संसाधन मंत्री, मि0 सुनबेंसेंग ने खान मंत्री के आग्रह पर सितंबर 2005 में भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान, खनन के क्षेत्र में भारत-चीन द्विपक्षीय सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ था।

इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच कई कार्यात्मक स्तर के शिष्टमंडलों के दौरे हुए थे जिससे द्विपक्षीय सहयोग के काफी अधिक क्षेत्रों पर काम किया जा सके।

हांगकांग

हांगकांग के आंकड़े के अनुसार जनवरी-नवंबर 2005 की अवधि के दौरान दोनों देशों का व्यापार 6.89 बिलियन यू0एस0 डालर तक पहुंच गया था, जो वर्ष 2004 में उसी अवधि से 27 प्रतिशत अधिक है। भारत से हांगकांग को हुआ निर्यात 4.29 बिलियन यू0एस0 डालर (22 प्रतिशत की वृद्धि) और भारत में हांगकांग से आयात 2.59 बिलियन यू0एस0 डालर (37 प्रतिशत की वृद्धि) का था।

श्री कमलनाथ, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने विभिन्न सरकारी विभागों और औद्योगिक निकायों के प्रतिनिधियों के साथ हांगकांग में छठे डब्ल्यू टी ओ मंत्री स्तरीय मम्मेलन में भाग लेने के लिए 13-18 दिसंबर 2005 को हांगकांग का दौरा किया।

वर्ष 2005 में दोनों पक्षों ने भारत और हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बातचीत की ओर एक करार को अंतिम रूप दिया गया। जिस पर दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 2006 में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होने की संभावना है।

मालदीव

भारत और मालदीव के बीच काफी अरसे से निकट और मित्रवत संबंध रहे हैं। उच्चस्तरीय चर्चा के जरिए इस संबंध की

प्रगाठता बनी रही। माननीय श्री मौमून अब्दुल गयूम, मालदीव रिपब्लिक के राष्ट्रपति ने 27 मार्च-1 अप्रैल 2005 तक भारत का सरकारी दौरा किया। वे भारत के राष्ट्रपति से मिले और प्रधानमंत्री से चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मामले पर अपने अपने विचार रखे।

दोनों देशों के बीच घनिष्ट द्विपक्षीय राजनैतिक समझ को दर्शाते हुए, डा. अहमद शहीद,मालदीव के विदेशी मंत्री ने जुलाई, 2004 में अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद, 11-14 अगस्त, 2005 को भारत का दौरा किया। विदेश मंत्रियों की बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हित के मामले पर अपने अपने विचार रखे। उन्होंने 12 अगस्त, 2005 को प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की।

डा0 शहीद के साथ मि0 ग्रासीम इब्राहीम, मालदीव के वित्त और ट्रेजरी मंत्री ने फिर 6-8 सितंबर 2005 को भारत का दौरा किया। मंत्रियों ने 8 सितंबर 2005 को वित्त मंत्री से मुलाकात की।

मि0 इस्माइल शेफुई, मालदीव के रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने 24-28 सितंबर 2005 को भारत का दौरा किया। वे 27 सितंबर 2005 को रक्षा मंत्री से मिले और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की।

नौसेना प्रमुख, एडमिरल अरूण प्रकाश ने 20-23 नवंबर 2005 को मालदीव का दौरा किया। मालदीव के रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री के साथ वार्ता करने के अलावा, उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।

नवंबर 2005 में ढाका में हुए सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई।

वर्ष 2005-06 के दौरान, भारत ने अपने एड सहायता कार्यक्रम के तहत रक्षा, पुलिस और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में मालदीव वासियों को प्रशिक्षण सुविधा देना जारी रखा।

मि0 मोह0 जमील अहमद, मालदीव के न्याय मंत्री ने 16-20 जनवरी 2006 को भारत का दौरा किया। उन्होंने मालदीव में विधिक संस्थागत फ्रेमवर्क बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री से विचार विमर्श किया।

भारत-मालदीव संयुक्त तटरक्षा सैन्य अभ्यास, दोस्ती VIII माले के समुद्र तट पर 20-25 दिसंबर 2005 को कराया गया था। इन सैन्य अभ्यासों की देखरेख करने के लिए वाईस एडमिरल ए0के0 सिंह ने मालदीव का दौरा किया। 21 दिसंबर 2005 को रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री से वार्ता करने के अलावा, उन्होंने 22 दिसंबर 2005 को मालदीव के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की।

विदेश सचिव ने द्विपक्षीय परामर्श के लिए 10-12 फरवरी 2006 को मालदीव का दौरा किया।

म्यांमार

भारत-म्यांमार संबंध दोनों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों की लगभग 1650 कि0मी0 लंबी भूमि सीमा और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा है। चार पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार से मिलती है। म्यांमार में भारतीय मूल की लगभग 2.5 मिलियन आबादी है। भू-सामरिक नीतिगत घटक भारत और म्यांमार के बीच घनिष्ट संबंध रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत-म्यांमार संबंध दोनों देशों की एक दूसरे के साथ सहयोग करने की एक जैसी इच्छा को दर्शाता है ताकि उनकी सीमाओं में शांति और स्थिरता बनी रहे, स्थायी आर्थिक विकास दर हासिल हो सके, उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सर्वमान्य लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कार्य और लोगों के पारस्परिक संपर्क में तेजी लाई जा सके। हाल ही के वर्षों में अनेक क्षेत्रों में विनिमयों में लगातार वृद्धि देखी गई है जिसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ एवं विस्तृत हुए हैं।

उच्च स्तरीय दौरे की गति को जारी रखते हुए, तत्कालीन विदेश मंत्री श्री के0 नटवर सिंह ने म्यांमार के विदेश मंत्री यू न्यान विन के आमंत्रण पर 24-27 मार्च, 2005 को म्यांमार का सरकारी दौरा किया था। दौरे के दौरान, विदेश मंत्री ने राज्य शांति और विकास परिषद के अध्यक्ष, सीनियर जनरल थान स्वे और प्रधानमंत्री लेफटि0 जनरल सो विन से मुलाकात की और विदेश मंत्री न्यान विन के साथ व्यापक विचार विमर्श भी किया। जनरल थान स्वे ने अक्तूबर 2004 में भारत का दौरा किया और दोनों देशों के बीच दौरे के बाद से अब तक अधिकारियों द्वारा की गई बाद की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत एक "उपयोगी पड़ोसी के रूप में म्यांमार के अपने संबंधों को बहुत अधिक प्राथमिकता देता है"। दोनों पक्ष इस बात से सहमत थे कि आतंकवाद को रोकने संबंधी वार्ता और समेकित सहयोग और अधिक मजबूत होगा एवं विभिन्न विकास परियोजनाओं से संबंधित सहयोग बढेगा और इसकी निगरानी की जाएगी। भारत और म्यांमार

के बीच वर्ष 2003 में एक करार हुआ जिसमें 15 मार्च 2005 से राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों को वीजा की जरूरत से मुक्त रखा गया था।

विदेश मंत्री के दौरे के बाद, म्यांमार ऊर्जा मंत्री, ब्रिगेडियर जनरल लुथवी ने दो बार भारत का दौरा किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के आमंत्रण पर 5-7 जुलाई को अपने पहले दौरे के दौरान, बिग्रे0 जन0 लुन थि ने यथाशीघ्र भारत को गैस निर्यात करने की अपनी इच्छा दोहराई। म्यांमार से भारत तक गैस लाने के विभिन्न विकल्पों पर दोनों पक्षों में चर्चा हुई। म्यांमार में थनलीन रिफाइनरी को फिर से चालू करने लिए भारत सरकार ने 20 मिलि0 यू0एस0 डालर ऋण की भी घोषणा की। म्यांमार के ऊर्जा मंत्री ने म्यांमार शिष्टमंडल के नेता के रूप में बिम्सटेक ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए निर्धारित 3-4 अक्तूबर, 2005 को फिर से नई दिल्ली का दौरा किया। 8-10 मार्च, 2006 को राष्ट्रपति जी द्वारा म्यामांर के राजकीय दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

भारत ने नई दिल्ली में 18-21 अक्तूबर 2005 को वरि0 अधिकारी स्तर पर म्यांमार के साथ वार्षिक फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन्स के नवें चक्र की मेजबानी की। शिष्टमंडल ने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की और इस संबंध को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अधिक गतिमान और कार्योन्मुख दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में कार्य किया।

म्यांमार और भारत के बीच 11वीं राष्ट्र स्तरीय बैठक 13-17 अक्तूबर, 2005 को यांगून में हुई थी। गृह सचिव ने भारतीय शिष्टमंडल का और उप-गृहमंत्री ब्रिग0 जन0 फोने स्वे ने म्यांमार शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। विचार विमर्शों में सुरक्षा मुद्दों, संयुक्त निरीक्षण और बाउंड्री पिलर्स का रखरखाव, सीमा व्यापार और सीमापार की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।

थल सेना के चीफ प्रमुख (सीओएएफ) जनरल जे.जे. सिंह ने राज्य शांति और विकास परिषद के उपाध्यक्ष वाइस सीनियर जनरल मौंग अये के निमंत्रण पर 29 अक्तूबर-2 नवंबर, 2005 को म्यांमार का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान, सीओएएस ने पीन ओ ल्वीन, मंडाले और बगान में रक्षा सेवा प्रौद्योगिकी एकेडमी का भी दौरा किया।

जनरल ऑफिसर कमांडिंग 3 कॉर्प्स, ले0 जनरल दलजीत सिंह के नेतृत्व में थलसेना शिष्टमंडल ने 5-9 मई 2005 को और समेकित रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख लेफ्टि0 जन0 आर0एल0 कपूर ने 5-11 दिसंबर 2005 को म्यांमार का दौरा किया। छठे ईंडो-म्यांमार स्पोट्स मीट में भाग लेने के लिए दि इंडियन आर्मी फुटबाल एंड वॉलीवॉल दलों ने 26 मई-2 जून 2005 को म्यांमार का दौरा किया।

म्यांमार नौसेना के चीफ वाइस एडमिरल सू थाने ने मार्च 2005 में भारत का दौरा किया। इसके बाद पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल आर पी सुल्तान ने 30 अप्रैल-3 मई 2005 को चांगून का दौरा किया जो कि समुद्र पार दो भारतीय नौसेना पोत, आईएसएस वेला (सबमैरीन) और आईएनएसएल-34 की नियुक्त के संबंध में था। रियर एडमिरल संजीव भसीन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इस्टर्न फ्लीट ने भी समुद्रपार दो पोतों आईएनएस रंजीत और आईएनएस कथुर की नियुक्ति के संबंध में 22-26 दिसंबर 2005 को म्यांमार का दौरा किया। म्यांमार नौसेना दल ने जुलाई-अगस्त 2005 में प्रशिक्षण के लिए आईएनएस सतवहन, विशाखापत्तनम और सितंबर 2005 में दिल्ली और कोच्ची का दौरा किया। म्यांमार नौसेनापोत यूएमएस अनौरहता ने जनवरी 2006 में पोर्टब्लेयर में मिलन 2006 में हिस्सा लिया। नौसेना के चीफ एडमिरल अरूण प्रकाश ने 19-22 जनवरी 2006 को म्यांमार का दौरा किया।

म्यांमार के संबंध में भारतीय नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू सीमापार आधारभूत सुविधा विकास परियोजनाएं कार्यान्वित करके प0 म्यांमार के साथ अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र का समेकन और बेहतर विकास का लक्ष्य हासिल करना है। महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाओं में सीमा की सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना, हाइडल पावर का विकास, शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदान प्रदान तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट फैसिलीटी का खास ही महत्व है जो बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर मार्ग प्रदान करने की कोशिश करता है। वर्ष 2005-06 में परियोजना संबंधी कानूनी कार्रवाई पूरी होती दिखी। म्यांमार में चिंदबिन नदी पर एक संयुक्त परियोजना के रूप में विकसित किए जाने के लिए तमांथी हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत परियोजना की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की गई थी और इसे स्वीकार भी किया गया था और दोनों पक्ष अब इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आगे के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। मिजोरम क्षेत्र में रि-तिद्विम और रि-फालम सड़कों की मरम्मत के संबंध में बार्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम शुरू किया गया था और पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा दावी को एक गहरे समुद्री बंदरगाह के रूप में विकसित करने संबंधी प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट

तैयार की गई थी और इसे विचारार्थ म्यांमार को प्रस्तुत किया गया था। यांगोन-मंडाले रेलवे लाइन की मरम्मत के संबंध में एक तकनीकी रिपोर्ट और भारत-म्यांमार रेल लिंक पर राईट्स द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट भी अक्तूबर 2005 में म्यांमार को सौंप दी गई थी।

आर्थिक क्षेत्र में भी भारत द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2006 तक 1 बिलियन यू0एस0 डालर करने के पारस्परिक रूप से सहमत लक्ष्य को हासिल करने के प्रति वचनबद्ध रहा है। वर्ष 2004-05 के दौरान, भारत से म्यांमार को 84 मिलि0 यू0एस0 डालर का निर्यात हुआ जबकि भारत में म्यांमार से 341 मिलि0 यू0एस0 डालर की सामग्रियां आयात की गई। चैन्नई और यांगून के बीच एक डायरेक्ट कंटेनर सेवा 13 मार्च 2005 को शुरू की गई। पीएचडीसीसीआई शिष्टमंडल ने 26 मई 2005 में म्यांमार का और वाणिज्य एवं उद्योग इंडो-म्यांमार चैम्बर्स के एक 15 सदस्ययीय शिष्टमंडल ने 23-27 मई 2005 का यांगून का दौरा किया। इस प्रकार, व्यावसायिक चैम्बर्स के बीच भी विचार विमर्श जारी रहा। भारत सरकार ने म्यांमार सरकार को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भी उपहार स्वरूप दिया था जिसकी घोषणा संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक के दौरान की गई थी।

ओएनजीसी विदेश लि0 और गेल ने साउथ कोरिया की कंपनी डेबू के साथ राखीन तटक्षेत्र से AIII ब्लॉक में प्राकृतिक गैस के अन्वेषण में भाग लेने के लिए करार किए हैं। ऐसा ही करार वर्ष 2004 में AI ब्लॉक के लिए किया गया था। एस्सार आयल लि0 ने AII ब्लॉक और आन-शोर L ब्लॉक के लिए 7 मई 2005 को उत्पादन साझेदारी करार किया है। म्यांमार से भारत तक गैस लाने के संबंध में दोनों पक्षों के बीच पूर्वोत्तर भारत से होकर एक पाइप लाइन सहित विभिन्न निकायों और संपीड़ित एवं द्रवित प्राकृतिक गैस कके आयात पर चर्चा हो रही है। म्यांमार में थानलीन रिफाइनरी को पुनः चालू करने के लिए जुलाई, 2005 में 20 मि0 यू0एस0 डालर का ऋण भी दिया गया है।

भारत म्यांमार की उसकी महाद्वीपीय सीमा निर्धारण में सहायता कर रहा है और इसके लिए गोआ में 24-28 अक्तूबर 2005 को राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं सागर अनुसंधान केंद्र में म्यांमार के वैज्ञानिकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके बाद, एनसीएओआर, गोआ में आगे का अध्ययन किया जाएगा। इसी बीच समुद्र विज्ञान पर तीसरी भारत-म्यांमार संयुक्त कार्यशाला यांगून में 16-24 दिसंबर 2005 को आयोजित की गई।

भारत ने कोलंबो प्लान और आइटेक कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2005-06 में म्यांमार को 142 स्लॉट प्रदान किया। विशेषज्ञों के आदान प्रदान संबंधी समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पीएचडी कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों के अनेक विशेषज्ञों को युनिवर्सिटी ऑफ यांगून में नियुक्त किया गया। यांगून विश्वविद्यालय की भौतिकी, जैव-प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं को अद्यतन बनाने के लिए विश्वविद्यालय को उपकरण भी उपहार स्वरूप दिए गए।

इंडिया-एशिया मीडिया विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत भारत से एक 11-सदस्यीय मीडिया शिष्टमंडल ने 22-25 मई 2005 को यांगून का दौरा किया। विख्यात भरतनाट्यम भाष्यकार श्री जनक खेंद्री ने 25 मई 2005 को युनिवर्सिटी ऑफ कल्चर यांगून में आयोजित व्याख्यान-सह-प्रदर्शन कार्यशाला में हिस्सा लिया। श्याम बेनेगल ने "नेताजी सुभाषचंद्र बोस-द अनफॉरगोटेन हीरो" नामक फिल्म की शूटिंग म्यांमार में की थी और 15-16 अगस्त 2005 को इसे यांगून में पर्दे पर दिखाया गया। भारत की ओर से समसामयिक कला प्रदर्शनी का आयोजन 18-25 नवंबर को यांगून के राष्ट्रीय संग्रहालय में किया गया था। हैदराबाद से श्री इकबाल हुसैन की अगुवाई में एक 7 सदस्यीय कब्वाली दल ने 23-24 दिसंबर 2005 को म्यांमार का दौरा किया और वार्षिक उर्स समारोह पर पंज-पीर दरगाह पर और शासक बहादुर शाह जफर की मजार पर अपना प्रदर्शन किया।

बिनय के0 बहल द्वारा बौद्ध संपदा पर "करूणा का मार्ग" नाम से 82 फोटोग्राफों का प्रदर्शन दिसंबर 2004 में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। भारत सरकार ने स्वेदागोन पगोडा ट्रस्ट को ये फोटोग्राफ स्थायी प्रदर्शन के लिए उपहार स्वरूप दे दिए। नालंदा, वाराणसी, आगरा, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद में बौद्ध विश्वविद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली शैक्षिक और अनुसंधान पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए म्यांमार से धार्मिक अधिकारियों एवं साधुओं के एक तीन-सदस्यीय शिष्टमंडल ने 24 नवंबर-8 दिसंबर 2005 को भारत का दौरा किया।

नेपाल

निकट पड़ोसी के रूप में भारत और नेपाल के बीच घनिष्ट मित्रता और सहयोग है जो सांस्कृतिक एवं व्यापक वाणिज्यिक एवं आर्थिक संपर्कों से जकड़ा हुआ है। नेपाल से सटी हुई भारत की 1850 कि0 मी0 सीमा खुली हुई है। सीमा के आर-पार लोगों के आने जाने की परंपरा काफी पुरानी है।

वर्ष के दौरान नेपाल में राजनैतिक अस्थिरता और प्रतिकूल

सुरक्षा स्थिति भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय था। विशेष रूप से सात दलों के गठबंधन और माओवादियों के बीच नवंबर 2005 में हुए 12-सूत्री समझौते के बाद राजतंत्र और राजनैतिक पार्टियों के बीच की दूरी अधिक बढ़ गई। माओवादियों द्वारा 2 जनवरी 2006 को लिए गए चार महीने पुराने एक पक्षीय युद्धविराम को स्थगित करने का निर्णय एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। भारत ने नेपाल में राजतंत्र और राजनैतिक दलों सहित संवैधानिक बलों के साथ अपनी नियमित चर्चा जारी रखी थी। प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह 22 अप्रैल 2005 को जकार्ता में एफ्रो-एशियाई शिखर सम्मेलन के मौके पर नेपाल के शासक राजा ज्ञानेंद्र से मिले। दोनों नेता 13 नवंबर 2005 को ढ़ाका में हुए सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर फिर से मिले। विदेश राज्य मंत्री, राव इंदरजीत सिंह ने 21-23 जुलाई 2005 को काठमांडू का दौरा किया। विदेश सचिव, श्री श्याम शरण ने 11-13 दिसंबर 2005 को नेपाल का दौरा किया। भारत ने दोहराया कि बहु-दलीय प्रजातंत्र, जैसा कि नेपाल के 1990 के संविधान में उल्लिखित है, बहाल होना चाहिए और संवैधानिक बल, जिसमें राजतंत्र की संस्थाएं और राजनैतिक दल दोनों शामिल हैं, को माओवादी बागियों सहित नेपाल की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।

नेपाल में चुनिंदा नदियों पर तटबंध के निर्माण और बाढ़ नियंत्रण एवं आम नदियों के प्रबंधन पर संयुक्त प्रयासों की व्यापक लघुआवधिक एवं दीर्घावधिक कार्यनीति तैयार करने में चल रहे सहयोग पर चर्चा करने के लिए दोनों सरकारों के अधिकारियों की मई, 2005 में बैठक हुई थी। नेपाल में बनाए जाने वाले सप्त कोशी उच्च बांध और सुनकोशी डाइवर्शन योजना पर विशेषज्ञों के संयुक्त दल की बैठक जून 2005 में हुई थी ताकि भारतीय सहायता से 30 माह की अवधि के लिए अगस्त 2004 में नेपाल में स्थापित संयुक्त परियोजना कार्यालय द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए क्षेत्रीय अन्वेषणों की समीक्षा की जा सके।

भारत और नेपाल ने रूपाईदीहा (जिला-बहराईच, उत्तर प्रदेश)-नेपालगंज (जिला-बांके, नेपाल) चेकपोस्टों पर 1 नवंबर 2005 से सीमा पार गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत इस चेक पोस्ट से सीमा पार करने वाले भारतीय एवं नेपाली नागरिकों के पास उनकी पहचान के लिए दस्तावेजों की जरूरत होगी, जैसा कि दोनों सरकारों ने इस पर आपसी सहमति दे दी है।

भारत-नेपाल द्विपक्षीय व्यापार 14.4 प्रतिशत तक बढ़ गया है। नेपाली वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक भारत के 1.8 बिलियन यूएस डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। जो नेपाल के कुल विदेशी व्यापार का 65.8 प्रतिशत है। नेपाली आयात में भारत की हिस्सेदारी 64.9 प्रतिशत थी। दूसरी ओर भारत में 67.7 प्रतिशत नेपाली सामग्रियों का खपत हुआ था। भारत-नेपाल पारगमन संधि पत्र के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए, जो कि 5 जनवरी, 2006 को समाप्त होने वाला है, नेपाल एवं भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक काठमांडू (2-3 दिसंबर, 2005) में हुई थी। भारत ने पारगमन संधिपत्र के प्रोटोकॉल और ज्ञापन में निहित पारगमन के तौर-तरीकों, मार्गों, शर्तों और कस्टम व्यवस्थाओं के लिए 3 माह की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि दोनों सरकारों को समीक्षा प्रक्रिया पूरा करने का समय मिल सके।

भारतीय संयुक्त निवेश, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 35 प्रतिशत है, से माओवादी विद्रोहियों की गतिविधियों के बावजूद अच्छे कार्यनिष्पादन की जानकारी मिली है। विनियामक कठिनाईयों और बाजार प्रतिबंधों से कुछेक भारतीय संयुक्त निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा है। वर्ष के दौरान किसी नए निवेश की जानकारी नहीं मिली है।

नेपाल के लिए भारतीय सहायता पैकेज की लागत वार्षिक औसतन 60 करोड़ से 75 करोड़ रूपए के बीच है। खास लघु विकास परियोजना स्कीम में भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम ने सफलता पूर्वक काम किया जिसमें तीन क्षेत्रों-शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधा विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्तमान में, लघु विकस परियोजना स्कीम के अंतर्गत नेपाल के 61 जिलों को कवर करते हुए 115 छोटी और बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं।

प्रमुख परियोजनाएं समाप्ति की अवस्था में हैं। इनमें बीर हॉस्पिटल ट्रौमा सेंटर, मनमोहन अधिकारी पोलीटेक्निक और अन्य बोर्डर आधारभूत सुविधा विकास परियोजनाएं शामिल हैं। भारत से आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति के जरिए ग्वाईटर रोग का उन्मूलन कर दिया गया है।

भारत एक वर्ष में विभिन्न पाठयक्रमों में लगभग 1000 नेपाली छात्रों को छात्रवृत्ति देता है। इसके अलावा, अनेक छात्र अपने स्वयं के खर्च से भारत में अध्ययन के लिए आते हैं।

पाकिस्तान

इस अवधि के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध हिंसा और आतंकवाद मुक्त माहौल में उनकी वार्ता को आगे बढ़ाने की इच्छा से जाहिर होता था, यद्यपि भारत ने इस संबंध

में अपनी चिंता को व्यक्त करना जारी रखा था। नियंत्रण रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वास्तविक भूमि स्थिति रेखा (सियाचीन), जो 25 नवंबर 2003 से लागू है, पर कुछेक छोटी-मोटी घटनाओं को छोड़कर युद्धविराम जारी था।

लोगों का एक दूसरे के साथ बढ़ता हुआ संपर्क

8 प्रमुख विषयों पर संयुक्त वार्ता ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ और विस्तृत करने के लिए, जो 2004 के बाद से सुधर रहा है, एक संरचनात्मक आधार दिया। वर्ष के दौरान संयुक्त वार्ता के दूसरे दौर, जो दिसंबर 2004 में विदेश सचिवों की बैठकों के साथ शुरू हुआ था, में अनेक उपलब्धियां हासिल हुई। नियंत्रण रेखा के आर-पार 7 अप्रैल 2005 को श्रीगनर-मुज्जफराबाद बस सेवा शुरू हुई जिससे लोगों को एक देश से दूसरे देश जाने और अपने विभाजित परिवारों से मिलने का मौका मिला। नियंत्रण रेखा के एक ओर से दूसरी ओर पूंछ-रावलकोट को बस से जोड़ने का और श्रीनगर-मुजफ्फराबाद मार्ग पर ट्रक सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया था। दोनों देशों ने अमृतसर-लाहौर के बीच बस सेवा शुरू की जबकि अमृतसर-ननकाना साहिब के बीच फरवरी में बस सेवा शुरू हो जाने की संभावना है। राजस्थान में मुनाबाओ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खोखरापार के बीच रेल सेवा भी फरवरी 2006 में शुरू हो जाएगी। दोनों सरकारें 1974 में संपन्न हुए प्रोटोकॉल को संशोधित करते हुए तीर्थ स्थलों की सूची विस्तृत करने और तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने पर भी सिद्धांततः सहमत थे। जैसा की सहमति दी गई थी संयुक्त वार्ता का तीसरा दौर जनवरी 2006 में शुरू हुआ था।

बंदियों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण

वार्ता प्रक्रिया की दूसरी अन्य उपलब्धि दोनों सरकारों द्वारा 12 सितंबर 2005 को 371 मछुआरों सहित 435 भारतीय बंदियों और 51 मछुआरों सहित 148 पाक बंदियों की रिहाई थी। यह रिहाई 30 अगस्त 2005 को हुई गृह सचिव स्तर की बैठक के दौरान किए गए करार पर आधारित थी। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि बंदियों के मुद्दे को मानवतावादी तरीके से हल किया जाएगा, बंदी बनाए जाने की तत्काल सूचना दी जाएगी, तीन माह के भीतर कांसुलर पहुंच मुहैया कराया जाएगा और जैसे ही बंदीकरण की अवधि समाप्त होगी बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारत ने भी अपनी ओर से 18 नवंबर 2005 को 26 अन्य बंदियों को रिहा कि। बंदियों के इस मानवतावादी मुद्दे के प्रति सद्भाव दृष्टिकोण जारी रखने की प्रतिबद्धता थी।

प्रमुख समझौते

दो प्रमुख समझौते संपन्न हुए थेः बैलिस्टिक मिसाइलों के उड़ान परीक्षणों की पूर्व सूचना पर समझौता और भारतीय तटरक्षक तथा पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्यूरिटी एजेंसी (पीएमएसए) के बीच संचार संपर्क के लिए समझौता ज्ञापन। पहला समझौता विश्वास बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय था जबकि दूसरे समझौते से तट की रक्षा करने वाली समुद्रवर्ती एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग मिलने की संभावना है। इसके अलावा, मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर सैद्धान्तिक सहमति बनी थी और यह करार जल्द ही संपन्न हो जाएगा। वीजा और कांसुलर करार/प्रोटोकॉल की समीक्षा की जा रही थी, जबकि 1972 के शिपिंग प्रोटोकॉल को संशोधित करने की चर्चा चल रही थी। 1988 के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम को भी संशोधित किया जा रहा था।

वाणिज्य और व्यापार

वर्ष 2005-06 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में पर्याप्त बढ़ोत्तरी नजर आई, जो पिछले वित्तीय वर्ष अप्रैल-अगस्त के दौरान 240 मिलियन यू0एस0 डालर की तुलना में वर्ष 2005-06 में उसी अवधि के दौरान बढ़कर 299 मिलियन यू0एस0 डालर हो गया, अर्थात इसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पाकिस्तान से निर्यात 93 प्रतिशत बढ़ा है जबकि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा था। पाकिस्तान ने भारतीय सामग्रियों के आयात को 773 तक बढ़ाते हुए अपनी विधिकृत सूची को बढ़ाया था, जबकि प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन और मांस जैसी वस्तुओं का चयन करने के लए उसने पाकिस्तान बाघा बार्डर खोल दिया। जुलाई, 2005 में अपनी व्यापार नीति की घोषणा करते समय पाकिस्तान ने भारत से आयातित वस्तु की सूची बढ़ाने के लिए इसमें तीन वस्तुओं - चीनी, जौ और मुलायम स्टील को जोड़ दिया था। तथापि, भारत अभी तक पाकिस्तान द्वारा मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिए जाने का इंतजार कर रहा था, जबकि भारत ने पहले ही पाकिस्तान को यह दर्जा दे दिया है। दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों की बैठक अगस्त 2005 में हुई थी और वे एक-दूसरे के देश में बैंक शाखा खोलने पर सहमत थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसके पाकिस्तानी प्रतिपक्ष ने यह घोषणा की कि प्रत्येक पक्ष की तरफ से दो शाखा खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण प्रगति

सियाचिन और सर क्रीक जैसे मुद्दों पर आगे की चर्चा हुई। संयुक्त वार्ता के दूसरे दौर में इस बात पर सहमति हुई थी कि सर क्रीक पर एक संयुक्त सर्वेक्षण किया जाएगा। बगलिहार पनबिजली परियोजना संबंधी मतभेद एक तटस्थ विशेषज्ञ के हवाले कर दिया गया था जो दोनों पक्षों के साथ अब तक

दो बैठकें कर चुके थे और तीसरी बैठक के फरवरी 2006 में होने की आशा है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भी सहयोग देखा गया और दोनों पक्ष पहुंच, बारंबारता और नामित एयरलाईंसों की संख्या बढ़ाने पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत थे। इस लोचनीयता का मुख्य कारण लोगों को यात्रा के लिए अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने की मंशा थी। इसी भावना ने दोनों सरकारों को करांची और मुम्बई में अपने-अपने वाणिज्य दूतावासों को फिर से खोलने पर सहमत किया।

उच्च स्तरीय संपर्क

वर्ष 2005-06 में अनेक उच्च स्तरीय संपर्क दिखे। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अप्रैल 2005 में भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री मनमोहन संह और राष्ट्रपति मुशर्रफ द्वारा जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में वार्ता प्रक्रिया के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। संयुक्त वार्ता के दूसरे दौर की समीक्षा करने के लिए विदेश सचिव ने 31 अगस्त-2 सितंबर 2005 को इस्लामाबाद का दौरा किया। विदेश सचिव के दौरे के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह ने संयुक्त वार्ता के पहले दो चक्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने और 16 वर्ष के अंतराल के बाद संयुक्त आयोग को पुनःसक्रिय बनाने के लिए 2-5 अक्तूबर 2005 को इस्लामाबाद का दौरा किया। संयुक्त आयोग को पुनः सक्रिय बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो स्थायी आधार पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक संस्थागत आधार उपलब्ध कराने के दोनों देशों की इच्छा का परिचायक थी।

14 सितंबर 2005 को भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बैठक के अवसर पर न्यूयार्क में पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि वे शांति प्रक्रिया में आतंकवाद को बाधा बनने नही देंगे।

जनवरी 2006 में पाकिस्तानी विदेश सचिव ने अपने भारतीय प्रतिपक्ष से वार्ता करने और संयुक्त वार्ता का तीसरा दौर शुरू करने के लिए भारत का दौरा किया। उन्होंने सीबीएम और जम्मू-कश्मीर सहित शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर भी वार्ता की। संयुक्त वार्ता का तीसरा दौर जुलाई/अगस्त 2006 में संपन्न होने की संभावना है।

भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता

भूकंप पीड़ितों के लिए भारत में काफी अधिक सहानुभूति थी। प्रधानमंत्री ने उसी दिन 8 अक्तूबर 2005 को राष्ट्रपति मुशर्रफ से टेलीफोन पर बातचीत की जब इस विनाशकारी भूकंप ने दक्षिणी एशिया के उत्तरी हिस्सों को हिलाकर रख दिया था जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में 80,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत द्वारा वहां तत्काल राहत सामग्री भेजी गई और आकस्मिक राहत के लिए यूएन समन्वयक द्वारा जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 25 मिलियन यू0एस0 डालर की सहायता की घोषणा की गई। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2005 में इस्लामाबाद में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश राज्यमंत्री को भेजा और स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पुनर्निर्माण परियोजनाएं शुरू करने का और उस राशि से, जिसकी घोषणा जेनेवा में की गई थी, निर्माण सामग्री का प्रबंध करने का प्रस्ताव रखा। भारत सरकार ने 1300 टन से अधिक राहत सामग्रियां दी जिसमें नियंत्रण रेखा के पार लोगों की दी गई सामग्री भी शामिल थीं। इसके अलावा, निजी एजेंसियों द्वारा भी सैकड़ों टन राहत सामग्रियां दानस्वरूप दी गई थीं। सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से पाकिस्तान में भेजी गई राहत सामग्री का कुल मूल्य 69 करोड़ रूपए या 15.5 मिलि0 यू0एस0 डालर था। पाकिस्तान के उच्चायोग को आपूर्ति की सोर्सिंग कराने और भारतीयों से नकद डोनेशन प्राप्त करने के लिए एक बैंक खाता खोलने की भी अनुमति दी गई थी।

अन्य देशों के राहत वायुयानों के लिए शीघ्र ओवर फ्लाईट मंजूरी दी गई थी। एक विशेष चेष्टा के रूप में, पाकिस्तान के बचाव हेलीकॉप्टरों को अनुमति के साथ एलओसी के निकट "नो-फ्लाई" जोन में उड़ने की मंजूरी दी गई थी। भारतीयों द्वारा पाकिस्तान/पीओके में उनके संबंधियों को फोन करने में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से एलओसी के भारतीय हिस्से में विशेष टेलीफोन केंद्र खोले गए थे। विदेशी संगठनों को भारत से आपूर्ति की सोर्सिंग करने की अनुमति दी गई थी। भारत ने लोगों एवं राहत सामग्रियों को लाने-ले-जाने के लिए एलओसी पर 5 क्रौसिंग प्वांईंट भी खोल दिया। 16 नवंबर 2005 तक 5 क्रॉसिंग खोले गए थे। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि दोनों तरफ के लोगों के मिलने-जुलने के लिए एलओसी पर दो मिलन स्थल खोले जाएंगे।

तथापि, पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर, राहतकैंप, एलओसी के आर-पार संयुक्त राहत कार्य, चिकित्सा राहत दल और टेलीकॉम सुविधा की मरम्मत के प्रस्तावों को ठुकरा दिया।

सीमा पर आतंकवाद

भारत सीमा-पार घुसपैठ और इससे जुड़ी आतंकवादी हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करता रहा था। पाकिस्तान के इस आश्वासन के बावजूद कि ऐसे घुसपैठों को रोकने के

मालदीव के राष्ट्रपति श्री मौमून अब्दुल गयूम नई दिल्ली में 28 मार्च, 2005 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ।

राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 28 दिसम्बर, 2005 को राष्ट्रपति भवन में श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपक्षे का स्वागत करते हुए।

प्रयास किए जाएंगे, घुसपैठ और हिंसक घटनाओं में कोई पर्याप्त कमी नहीं हुई है। भारत ने यह आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान इस संबंध में ठोस कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान ने अपनी इस वचनबद्धता को पूरा करने के महत्व को बारंबार दोहराया जो 6 जनवरी, 2004 के संयुक्त प्रेस वक्तव्य में दिया गया था जिसमें कहा गया था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह से उसके नियंत्रणाधीन क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि संपूर्ण वार्ता प्रक्रिया हिंसा और आतंकमुक्त, विश्वास और भरोसे के माहौल पर निर्भर है।

श्रीलंका

इस अवधि के दौरान भारत-श्रीलंका संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता एवं सुदृढ़ता नजर आई। अनेक उच्च स्तरीय दौरों का आदान-प्रदान हुआ था; संबंधों के संस्थागत फ्रेमवर्क का भी विस्तार हुआ था; व्यापार और वाणिज्यिक संपर्कों में पर्याप्त वृद्धि जारी रही; और रक्षा सहयोग भी जारी रहा। द्विपक्षीय मुद्दों और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में विचार-विमर्श करने और द्विपक्षीय संबंधों को अधिक विस्तृत करने की दिशा में कार्य करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और विपक्ष के नेताओं ने इस अवधि के दौरान भारत का दौरा किया। द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा करने के लिए मई 2005 में आयोजित विदेशी परामर्श को विदेश मंत्री और श्रीलंका के विदेश मंत्री की सह-अध्यक्षता में कोलंबो में जून 2005 को आयोजित भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की छठी बैठक द्वारा सफल बनाया गया था।

श्रीलंका में नवंबर 2005 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्से के अधीन नई सरकार ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्से ने 27-30 दिसंबर 2005 को भारत का दौरा किया। इसके पहले, विदेश मंत्री मंगला समर सीरा ने नवंबर 2005 में भारत का दौरा किया। श्रीलंका के तत्कालीन विदेशी मंत्री अनूरा भंडारनायके ने भी 25-26 अगस्त 2005 को भारत का दौरा किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा ने 2-4 जून 2005 को भारत का दौरा किया था और विपक्ष के नेता रानिल विक्रमसिंघे 6-9 अप्रैल 2005 के पहले 16-18 अगस्त 2004 को भारत में थे। अध्यक्ष डब्ल्यूजेएम लोकाबंदुरा ने 27 अप्रैल-1 मई 2005 को भारत का दौरा किया। भारत की ओर से विदेश मंत्री ने 9-11 जून 2005 को कोलंबो का दौरा किया। उन्होंने मारे गए एक श्रीलंकाई विदेश मंत्री लक्ष्मण कादीरगमर के दाह-संस्कार में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री के साथ भी 15 अगस्त 2005 को कोलंबो का दौरा किया। विदेश सचिव, श्याम शरण ने 30 अप्रैल-2 मई 2005 को श्रीलंका का दौरा किया।

भारत का दौरा करने वाले श्रीलंकाई नेताओं ने श्रीलंका में शांति प्रक्रिया से संबंधित विकासों की भारत को जानकारी दी। भारत फिर से हिंसा आरंभ होने का विरोध करता है और राजनैतिक हल पर बातचीत करने के पक्ष में है जो सभी समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा करता हो। भारत की श्रीलंका की सुरक्षा में स्थायी दिलचस्पी है और यह श्रीलंका की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता के प्रति वचनबद्ध है। भारत श्रीलंका के पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्रों में पुनर्वास के प्रति भी वचनबद्ध है। भारत ने श्रीलंकाई विदेश मंत्री लक्ष्मण कादिरगमर की हत्या की कड़ी निंदा की।

भारत और श्रीलंका के बीच मानव उपचार और उन मछुआरों, जो समुद्री सीमा रेखा के पार भटक गए थे, के जल्द रिहाई के संबंध में मौजूदा सुलहनामा आगे भी जारी रहा था। श्रीलंकाई अधिकारी इस समस्या के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं।

मत्स्य उद्योग पर हाल ही में बनाए गए संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में, जो मछुआरों के भटक जाने संबंधी मुद्दों से संबंधित है, उनके खिलाफ बलों के प्रयोग को रोकने और जब्त किए गए बोटों को जल्द से जल्द छोड़ने और अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में लाइसेंसीकृत मछुवाही के लिए हुए द्विपक्षीय समझौते के लिए कामकाज की संभावनाओं की तलाश करने के लिए तौर-तरीके प्रस्तुत किए जाएंगे।

अनेक श्रीलंकाई सैनिकों, नाविकों और वायुसैनिकों ने भारतीय रक्षा स्थापनाओं में प्रशिक्षण लेना जारी रखा है।

विभिन्न भारतीय पुलिस स्थापनाओं में 450 श्रीलंकाई पुलिस अधिकारियों के लिए 5 दिसंबर 2005 को उन्नत पुलिसिंग तकनीकों पर एक तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था।

वर्ष के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक संबंध अधिक सुदृढ़ होता दिखा। तकनीकी स्तर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) पर वार्ता का छठा दौर संपन्न हुआ जो सेवाओं और निवेशों में व्यापार सहित एफटीए को और अधिक विस्तृत बनाएगा।

आज भारत श्रीलंका में चौथा सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक है। श्रीलंका निवेश बोर्ड ने 450 मिलियन यू0एस0 डालर की कुल एफडीआई वाली 147 भारतीय परियोजनाओं

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 12 नवम्बर, 2005 को ढाका में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 13 दिसम्बर, 2005 को कुआलालम्पुर में चतुर्थ आसियान शिखर सममेलन में राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के साथ।

को मंजूरी दी है। भारतीय तेल निगम ने 300 करोड़ रूपए से अधिक राशि का निवेश किया है जबकि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा 300 मेगावाट कोयला या एलएनजी आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना वाली प्रमुख विद्युत परियोजना पर विचार चल रहा है।

भारत ने श्रीलंका को अनेक ऋण दिए हैं। इनमें से तीन पर इस समय अभी काम चल रहा है। यह पूंजीगत सामग्री, उपभोक्त सामग्रियों, परामर्शदात्री सेवाओं और खाद्य सामग्रियों के लिए 100 मिलियन यू0एस0 डालर का ऋण, श्रीलंका को गेहूँ की आपूर्ति के लिए 31 मिलियन यू0एस0 डालर का ऋण और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 150 मिलियन यू0एस0 डालर का ऋण है। सुनामी के बाद, श्रीलंका सरकार ने जून 2004 में श्रीलंका में दक्षिणी रेलवे के लिए दिए गए अन्य 100 मिलियन यू0एस0 डालर का उपयोग ग्रामीण आधारभूत परियोजनाओं के लिए करने की मांग की थी। इस पर सहमति दे दी गई है। इस प्रकार श्रीलंका सरकार को लगभग कुल 381 मिलियन यू0एस0 डालर का ऋण (लगभग 1700 करोड़ रूपए) उपलब्ध कराया जा रहा है।

भारत श्रीलंका के साथ विकास सहयोग को एक प्राथमिक क्षेत्र के रूप में मानता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस समय चलाई जाने वाली परियोजनाओं में डिकोयो में 150 बेड वाले अस्पताल का निर्माण, त्रिंकोमाली में अस्तपाल की मरम्मत और कैंसर अस्पताल बनाने के लिए 75 मिलियन यू0एस0 डालर का अनुदान शामिल है। शिक्षा क्षेत्र के लिए विचार विमर्श की जाने वाली परियोजनाओं में केंद्रीय प्रांत में विद्यालयों में शैक्षिक आधारभूत सुविधा को अद्यतन बनाना, श्रीलंका में (+2 छात्रों के लिए)छात्रवृत्ति योजना और दो व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। हाल ही में कार्यान्वित हो चुकी परियोजनाओं में, केन्द्रीय प्रांत में 30 विद्यालयों को अद्यतन बनाने के लिए 1 करोड़ रूपए का अनुदान, प्वांइट पेडू के अस्पताल में दवाओं एवं उपकरणों का दान, हम्बांहोटा के अस्पताल को उपकरण मुहैया कराना, 4 एम्बूलेंसों की आपूर्ति, 1500 लोगों के लिए कैटरेक्ट आई सर्जरी प्रोग्राम और अनेक विश्वविद्यालयों को उपकरण और आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराना शामिल है।

26 जनवरी, 2004 के बाद से भारत हमेशा से ही श्रीलंका के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। भारतीय सहायता, केंकेसंथुराई बंदरगाह में बचाव कार्य, नेगोम्बो-कोलंबो-मतारा रेलवे लाइन की मरम्मत करना, हम्बांटोरा, जाफना और ट्रिन्कोमाली में बेस अस्पतालों की मरम्मत करना, अनुभव कार्यों का आदान-प्रदान और तीन से पांच वर्षों की अवधि के लिए ऋण माफ करने नामक परियोजनाओं पर केंद्रित है।

सेतुसमुद्रम मुद्दे पर जानकारी का आदान-प्रदान जारी रहा था। विचार विमर्श का दूसरा दौर 1 अगस्त 2005 को संपन्न हुआ और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट और परियोजना की हाइड्रोडायनेमिक मोडलिंग के ब्यौरों की प्रति भी सौंपी गई थी।

■■

दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत 2

दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ अपने एतिहासिक और सांस्कृतिक संपर्कों को आधार बनाते हुए भारत ने अपनी पूर्वोन्नमुख नीति के अनुसरण में दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास जारी रखा। भारत की पूर्वान्नमुख नीति को विस्तारित कर इसमें दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ - साथ प्रशांत क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। द्विपक्षीय स्तर पर और क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर नियमित आदान-प्रदान किये जाने से उन देशों के साथ भारत के संबंधों को नयी गति मिली है। एशियाई - अफ्रीकी शिखर सम्मेलन और बांडुंग सम्मेलन के स्वर्ण जयंती समारोहों, जिसमें प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह से एशिया की ओर से संबोधन करने का अनुरोध किया गया, में भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री की जर्काता, इन्डोनेशिया की यात्रा और 13 तथा 14 दिसम्बर, 2005 तक आयोजित चौथे भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के लिए प्रधान मंत्री की क्वालालंपुर की यात्रा इस क्षेत्र के साथ भारत के क्रियाकलापों की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डा. सुसिलो बाम्बैंग युधोयोनो तथा फिजी, सिंगापुर और थाइलैंड के प्रधान मंत्रियों ने भारत का दौरा किया। इस अवधि के दौरान होने वाली अनेक मंत्रिस्तरीय यात्राओं से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिली।

भारत ने अक्टूबर,2005 में पोर्ट मोर्सबी में आयोजित प्रशांत द्वीप मंच (पी आई एफ) की बैठक में पश्च मंच वार्ता में तीसरी बार भागीदारी की। इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबध और सुदृढ़ तथा संवर्द्वित हुए। भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को महत्व देना जारी रखा।

ब्रुनेई दारूस्सलाम

ब्रुनेई दारूस्सलाम के साथ द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे। क्रियाकलाप के मुख्य क्षेत्र राजनैतिक और तेल के व्यापार सहित अन्य व्यवसाय थे।

भारत- ब्रुनेई संयुक्त समिति की पाचवीं वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय बैठक 28 मई, 2005 को हुई। बैठक के दौरान सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की गयी। ब्रुनेई शेल पेट्रोलियम बरहार्ड (बी एस पी) और भारत पेट्रोलियम निगम लि. (बी पी सी एल) के बीच जून, 2005 में 1.8 मि. बैरल सेरिया लाइट एक्सपोर्ट ब्लैंड की आपूर्ति के लिए एक अवधि करार किया गया।

आसियान-भारत मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय मीडिया के उस प्रतिनिधियों के एक समूह ने अक्टूबर, 2005 में ब्रुनेई का दौरा किया।

कंबोडिया

वर्ष के दौरान भारत कंबोडिया के बीच संबंधों में और अधिक सुदृढ़ता आई। भारत कंबोडिया संयुक्त कार्यदल की द्वितीय बैठक सियेम रीप में 10 जनवरी, 2006 को हुई। कंबोडिया में खमेर रूप ट्रिब्यूनल केलिए भारत ने एक मिलियन अमरीकी डालर देने का वायदा किया।

इंडोनेशिया

दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे बड़े देश, और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी, जिसके साथ भारत की समुद्री सीमा मिलती है, इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंधों में समझबूझ और सहयोग जारी रहा।

इंडोनेशिया ने जकार्ता में एशियाई - अफ्रीकी शिखर सम्मेलन और 22-24 अप्रैल, 2005 तक बांडुंग सम्मेलन 1955 की स्वर्ण जयंती समरोहों की मेजबानी की। 23 अप्रैल, 2005 को एक नए एशियाई - अफ्रीकी सामारिक भागीदारी का शुभारंभ किया गया।

इस वर्ष अनेक मंत्रिस्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान किया गया जो द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दोनों देशों की ईच्छाओं का द्योतक थी। इंडोनेशिया के विदेश, व्यापार, पर्यटन और संस्कृति, कृषि और स्वास्थ्य मंत्री ने भारत का दौरा किया। विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कृषि और स्वास्थ्य मंत्री ने विदेश राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री भी वहाँ का दौरा किया। ने पश्चिम बंगाल के मुख्य-मंत्री

ने अगस्त, 2005 में इंडोनेशिया की यात्रा की। जर्कार्ता के गवर्नर ने सितम्बर, 2005 में भारत का दौरा किया।

भारत - इंडोनेशिया संयुक्त परामर्शी मंच की बैठक 27-29 सितम्बर, 2005 तक योग्याकार्ता में हुई।

इस वर्ष की मुख्य बात 21-24 नवम्बर, 2005 तक राष्ट्रपति सुसीलो बाम्बांग युधोयोनो की भारत की राजकीय यात्रा रही। एक विशाल सरकारी शिष्टमण्डल, जिसमें अर्थव्यवस्था के समन्वयक मंत्री, रक्षा मंत्री, व्यापार मंत्री उद्योग मंत्री, स्टेट सेक्रेटरी, तीन सांसद, वायु सेना प्रमुख और कादिन के अध्यक्ष शामिल थे, भी राष्ट्रपति सुसीला वाम्बांग युधोयोनो के साथ आया।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने 23 नवम्बर, 2005 को सर्वोच्च चैम्बरों द्वारा आयोजित भारत-इन्डोनेशि वाणिज्य शिखर-सम्मेलन को संबोधित किया।

द्विपक्षीय बातचीत के पश्चात प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति सुसीलो बाम्बांग युधोयोनो ने एक संयुक्त घोषणा संपन्न की जिसके जरिए बहुवादी लोकतंत्रों के साझे मूल्यों के आधार पर नई सामरिक भागीदारी की स्थापना की जाएगी। नई सामरिक भागीदारी का उद्देश्य घनिष्ठ राजनयिक समन्वय, मजबूत रक्षा संबंधों, संवर्द्धित आर्थिक संबंधों, बेहतर प्रोद्योगिक सहयोग और गहन सांस्कृतिक संपर्कों तथा शैक्षिक संपर्कों के जरिए दोनों देशों के दीर्घावधिक हितों का सम्मान करना है।

यात्रा के दौरान तीन समझौता ज्ञापन भी संपन्न किये गये जिसमें अपने-अपने विदेश सेवा संस्थानों के बीच सहयोग, समुद्री और मत्सिकी सहयोग तथा एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीका) संपन्न करने की संभावना पर विचार करने के लिए संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना करना शामिल है।

नई सामरिक भागीदारी में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया गया है। वार्षिक भारत - इंडोनेशिया सामरिक वार्ता आरंभ की जानी है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग को तेज किया जाएगा। दोनों पक्ष वर्ष 2010 तक द्विपक्षीय व्यापार को तीन गुणा करने के लिए कदम उठायेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाना है। दोनों देश हिंद महासागर में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली के क्षेत्र में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। भारत इंडोनेशिया में द्वितीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करेगा जो असेह में अवस्थित होगा।

प्रदान मंत्री और राष्ट्रपति सुसीलो बाम्बांग युधोयोनो के बीच संपन्न संयुक्त घोषणा में दोनों देशों ने 16 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में पूर्वी एशियाई समुदाय के एक साझे विजन के लिए पूर्णतः भागीदारी करने और योगदान देने की आवश्यकता की पुष्टि की जिससे घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

नौसेना प्रमुख और स्टाफ समिति के प्रमुखों के अध्यक्ष एडमिरल अरूण प्रकाश ने 27-31 जुलाई, 2005 तक इंडोनेशिया का दौरा किया। आई एन एस विराट के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पांच पोत स्क्वाड्रन ने 28 जुलाई से 1 अगस्त, 2005 तक जकार्ता का दौरा किया। यात्रा के दौरान आई एन एस विराट पर भारतीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की गयी जिसमें एच ए एल के ध्रुब हेलीकॉप्टर द्वारा उड़ान प्रदर्शन भी किये गये। दोनों नौसेनाओं द्वारा एक माह की द्विपर्षीय समन्वित गश्त सितम्बर और नवम्बर, 2005 में आयोजित की गयी।

आइटेक वित्तपोषण के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र के लिए एक व्यावसायिक केन्द्र की स्थापना जर्कार्ता में 3.08 करोड़ रू. की लागत से की गयी। वर्ष 2005-2006 के लिए आइटेक, कोलंबो योजना और जी सी एस एस योजनाओं के अंतर्गत इंडोनेशिया को कुल 147 प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति स्लाट्स आबंटित किये गये।

वर्ष 2005 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में 30 प्रतिशत की वृद्धि होकर 4 बिलियन अमरीकी डालर होने की संभावना थी। एक विशेष भारतीय प्रदर्शनी "इन्डियाटेक 2005" ई ई पी सी और दूतावास द्वारा सफलतापूवर्क आयोजित की गयी।

अंतरिक्ष सहयोग भारत - इंडोनेशिया द्विपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की मुख्य बात रही। इसरो ने द्वितीय टेलीमेट्री, ट्रेकिंग एण्ड कमांड ग्राउंड स्टेशन का निर्माण करके इंडोनेशिया के पपुआ प्रांत के बियाक में अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया। इसरो वर्ष 2006 के आरंभ में इंडोनेशिया के टुबसैट माइक्रो सेटेलाइट का मॉडल लांच करने के लिए भी सहमत हुआ।

इंडोनेशिया (जकार्ता और बाली) में दो भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों ने नियमित कक्षाएं चलाने के अतिरिक्त 30 मार्च और 23 सितम्बर, 2005 को "इंडोनेशिया और भारत के बीच सांस्कृतिक संपर्क" पर संगोष्ठियाँ आयोजित की; दोनों सांस्कृतिक केन्द्रों में तीन संकाय सदस्यों के साथ कार्मिकों की संख्या पूर्ण है।

राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 23 नवम्बर, 2005 को राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉ. सुसीलो बांबाग युधोयोनो और श्रीमती बांबाग युधोयोनो का स्वागत करते हुए।

4 फरवरी, 2005 को मालाकानांग महल में फिनीपींस की राष्ट्रपति मादाम ग्लोरिया मकापगल एरोयो राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम का स्वागत करते हुए।

लाओ पी डी आर

वर्ष के दौरान भारत और लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच संबध निरंती सुदृढ बने रहे। 12 दिसंबर, 2005 से 7 जनवरी, 2006 तक लाओ सेना के 32 कार्मिक अध्ययन दौरे पर भारत आए।

मलेशिया

वर्ष के दौरान मलेशिया के साथ भारत के संबंध और अधिक सुदृढ़ हुए। दिसंबर, 2004 में हुई प्रधान मंत्री अब्दुल्लाह अहमद बदावी की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप व्यापक आर्थिक सहयोग करार की व्यवहार्यता जांच हेतु गठित किए गए संयुक्त अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट पूर्ण की। मलेशिया के निर्माण मंत्री दातो सेरी एस - सामी वेलू अप्रैल, 2005 तथा अगस्त, 2005 में भारत की यात्रा पर आए। नौसेनाध्यक्ष एडमिरल अरूण प्रकाश जुलाई, 2005 में मलेशिया गए उसी समय नौसेना पांच पोत भी मलेशिया की यात्रा पर गए थे जिनका नेतृत्व विमान वाहक आई एन एस विराट ने किया।

मलेशिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष तान श्री दातो सेरी दि राजा रामली नगाह तालिब संसदीय शिष्टमंडल के साथ 25-29 जुलाई, 2005 तक भारत की यात्रा पर आए। राज्य सभा के उपसभापति सितंबर, 2005 में अध्ययन दौरे पर मलेशिया गए।

मलेशिया के साथ प्रथम विदेश कार्यालय परामर्श वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर 20 अक्तूबर, 2005 को पुतराज्य में हुआ। द्विपक्षीय, क्षेत्रिय और बहुपक्षीय महत्व के मसलों पर इस बैठक में चर्चा हुई।

विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद 5-8 सितंबर , 2005 तक क्वालालम्पुर की यात्रा पर गए।

फिलीपींस

फिलीपींस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबध निरंतर व्यापक और मजबूत हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के नेतृत्व में आठ सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल अंतर्संसदीय संघ की सभा में भाग लेने के लिए 3-8 अप्रैल, 2005 तक फिलीपींस की यात्रा पर गया। विदेश कार्यालय परामर्श का आठवां दौर नई दिल्ली में 7 जुलाई, 2005 को हुआ तथा द्वितीय भारत-फिलीपींस सुरक्षा वार्ता 8 जुलाई, 2005 को हुई। विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 8-10 सितंबर, 2005 तक मनीला की सद्भावना यात्रा की।

फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति श्री फिडेल वी. रामोस 19-20 जनवरी, 2006 तक दिल्ली आए। उनके प्रवास के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबधों खासतौर पर आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने हेतु विभिन्न् मंत्रियों से मुलाकात की। फिलीपींस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर हमारे राष्ट्रपति 3-6 फरवरी, 2006 तक फिलीपींस की यात्रा पर गए। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हुई। राष्ट्रपति ने फिलीपींस की नेशनल असेम्बली को संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान कृषि में सहयोग पर एक करार संपन्न किया गया।

दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच जारी रहने वाले क्रियाकलापों के भाग के रूप में वायुसेनाध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल एस पी त्यागी 21-25 अगस्त, 2005 तक फिलीपींस की यात्रा पर गए।

द्विपक्षीय व्यापार जो 2003-04 में 443.64 मिलियन अमरीकी डालर था 2004-2005 में बढ़कर 577.08 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। जबकि भारत से निर्यात 321.53 मिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 395.16 मिलियन अमरीकी डालर हो गया; फिलीपींस से आयात भी बढ़कर 122.11 मिलियन अमरीकी डालर के स्थान पर 181.92 मिलियन अमरीकी डालर हो गया।

भारत और फिलीपींस के नागर विमानन शिष्टमंडलों की बैठक 20-21 जुलाई, 2005 तक नई दिल्ली में हुई। एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। भारत-फिलीपींस संयुक्त कार्यदल की नौवीं बैठक 1-2 सितंबर, 2005 को मनीला में हुई।

व्यापारिक और वाणिज्यिक शिष्टमंडलों की अनेक यात्राएं हुईं : सी ए पी ई एक्स सी आइ एल द्वारा प्रायोजित 10 सदस्यीय शिष्टमंडल 5-9 अगस्त, 2005 तक मनीला की यात्रा पर गया; सी आई आई (गोवा परिषद) द्वारा प्रायोजित 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 8-10 अगस्त, 2005 तक मनीला की यात्रा पर गया; फिलीपींस के तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने 13-17 अक्तूबर, 2005 तक नई दिल्ली में हस्तशिल्प एवं उपहार मेले में भाग लिया और फिलीपींस का तीन सदस्यीय शिष्टमंडल भारत-अफ्रीका-जीसीसी आसियान फार्मा एवं स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने 1-2 दिसंबर, 2005 तक हैदराबाद की यात्रा पर आया।

2005-06 के दौरान आईटैक, कोलंबो प्लान के तहत फिलीपींस को 68स्लॉट आवंटित किए गए और तीन छात्रवृत्तियां सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत प्रदान की गईं। आईटैक,

29 जून, 2005 को सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री सैन लूंग प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ नई दिल्ली में।

3 जून, 2005 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्री थाक्षिन शिनावात्रा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ नई दिल्ली में।

कोलंबो प्लान के अंतर्गत 2005 - 06 के दौरान आवंटित 68 स्लाटों में से 57 का उपयोग अभी तक कर लिया गया है।

सिंगापुर

भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबध निरंतर विस्तारित और गहन हुए। उच्चस्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान और आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों में ठोस वृद्धि द्वारा घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबध चिह्नित हुए।

सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री श्री टी. आर. बालू 7-9 सितंबर, 2005 तक सिंगापुर की यात्रा पर गए। उन्होंने भारत में संभारतंत्रीय अवसरों का प्रवेश द्वार पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अंबुमणि रामदास ने 24 अक्तूबर को स्वास्थ्य मंत्री श्री खाव बून वान के साथ बातचीत की।

भारत-सिंगापुर संसदीय मंच के तत्वावधान में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल 3-5 अक्तूबर, 2005 तक सिंगापुर की यात्रा पर गया।

लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी 9-11 अप्रैल, 2005 तक सिंगापुर की यात्रा पर गए।

भारत-सिंगापुर वायुसेवा वार्ता 23 और 24 अगस्त, 2005 को नई दिल्ली में हुई। दोनों देशों के बीच वायुसेवाओं का संवर्धन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। भारत और सिंगापुर के बीच वायु ट्रैफिक में काफी वृद्धि होती रही है और 2005 में भारत और सिंगापुर के बीच भारत से दो नई एयरलाइन - जेट एयर वेज (अप्रैल, 2005) और एयर सहारा (मई, 2005) चालू हो गई हैं।

ए पी ई डी ए के सहयोग से 9-15 जून, 2005 तक सिंगापुर में भारतीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौड 26 मई, 2005 को सिंगापुर गए और निवेश संवर्धन गोष्ठी को संबोधित किया। केरल के उद्योग एवं सामाजिक कल्याण मंत्री श्री इब्राहीम कुंजू, तमिलनाडु के विधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री डी. जय कुमार और आंध्र प्रदेश की चीनी, बडे उद्योग एवं निर्यात संवर्धन मंत्री डॉ. (श्रीमती) जे गीता रेड्डी निवेश, पर्यटन एवं सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग संवर्धन करने के लिए वर्ष के दौरान सिंगापुर गई।

वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर विदेश कार्यालय परामर्श का सातवां दौर नई दिल्ली में 26 सितंबर, 2005 को हुआ।

सिंगापुर सरकार के निवेश स्कंध, तेमासेक होल्डिंग्स ने 2004 में मुंबई में कार्यालय की स्थापना करने के बाद एफ आई के जरिए 1 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया।

रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री श्री बी. के. हांडीक अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम रक्षा प्रदर्शनी 2005 में भाग लेने के लिए 16-20 मई, 2005 को सिंगापुर गए। भारतीय नौसेनाध्यक्ष और सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष एडमिरल अरूण प्रकाश इमडेक्स 2005 में भाग लेने सिंगापुर गए और उन्होंने दसवीं नेवल प्लेटफार्म टेक्नोलोजी गोष्ठी में मुख्य भाषण दिया। 16-22 मई, 2005 तक सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम मैसूर तथा आई एन एस तारासा और भारतीय तट रक्षक पोत सागर शामिल हुए।

भारतीय नौसेना के पूर्वी बेडे से भारतीय नौसेना के चार अन्य पोतों के साथ भारतीय विमान वाहक विराट ने 19-22 जुलाई, 2005 तक सिंगापुर की यात्रा की। विमान वाहक के साथ गए भारतीय नौसेना बैंड ने विक्टोरिया कंसर्ट हॉल में अपनी कला का प्रदर्शन किया।

भारत-आसियान मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई, 2005 में 10 भारतीय पत्रकारों का एक शिष्टमंडल सिंगापुर की यात्रा पर गया। भारतीय सांस्कृतिक संबध परिषद द्वारा प्रायोजित बांसुरी वादक श्री रोहित आनंद ने सिंगापुर में 20 मई, 2005 को अपनी कला का प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री श्री ली साएन लूंग 28-30 जुलाई, 2005 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। उनके साथ विदेश मंत्री श्री जॉर्ज योंग यो, व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री लिम हंग कियांग और सामुदायिक विकास, युवा एवं खेल मंत्री श्री विवियन बालकृष्णन तथा संसद सदस्य भी भारत की यात्रा पर आए। यात्रा के दौरान दो करारों पर हस्ताक्षर हुए - व्यापक आर्थिक सहयोग करार और आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी संधि। व्यापक आर्थिक सहयोग करार एक ऐसा समग्र पैकेज है जिसमें मुक्त व्यापार व्यवस्था, निवेश संवर्धन एवं संरक्षण पर द्विपक्षीय करार, उन्नत दोहरे कराधान के परिहार से संबद्ध करार और स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा, मीडिया एवं पर्यटन में सहयोग का कार्यक्रम शामिल है। यात्रा के दौरान भारत - सिंगापुर मंच की शुरूआत की गई। प्रधान मंत्री ली ने मध्याह्न भोज के समय "दक्षिण - पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंध" विषय पर भाषण दिया।

मंत्री मेंटोर श्री ली कुआन 18-23 नवंबर, 2005 तक भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने नई दिल्ली में "एशियाई नवचेतना में भारत" नामक जवाहरलाल नेहरू स्मारक व्याख्यान दिया।

शिक्षा मंत्री श्री थर्मन षण्मुगारत्नम् 11-15 सितंबर, 2005 तक चेन्नई तथा नई दिल्ली की यात्रा पर आए। चेन्नई में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय विकास राज्य मंत्री श्री सेड्रिक फू चेन्नई और बंगलौर में सिंगापुर की कंपनियों की परियोजना के संबंध में 10-15 अप्रैल, 2005 तक इन शहरों की यात्रा पर आए।

सिंगापुर के सेनाध्यक्ष मेजर जनरल डेसमंड कुएक 20-22 जून, 2005 तक भारत की यात्रा पर आए।

राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे अब्दुल कलाम 31 जनवरी से 3 फरवरी, 2006 तक सिंगापुर की यात्रा पर गए। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए।

थाईलैंड

उच्चस्तरीय यात्राओं के साथ और आर्थिक एवं व्यापारिक संपर्कों को मजबूत बनाते हुए थाईलैंड के साथ भारत के संबंध गहन और व्यापक होते रहे। प्रधानमंत्री डॉ. थाक्षिन शिनावात्रा एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल के साथ 3 जून, 2005 को कार्य यात्रा पर भारत आए, विदेश मंत्री कांताथी सुपामोंखोन और विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्री श्री कोर्न थप्पारांसी उनके साथ आए थे। परम मान्य राजकुमारी महा चक्री सिरीधोर्न विकास के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार ग्रहण करने के लिए 18-23 नवंबर, 2005 तक भारत की यात्रा पर आई। परम मान्य राजकुमारी चुलाभोर्न महीडोल एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेने 21-29नवंबर, 2005 तक बंगलौर की यात्रा पर आई।

थाईलैंड से भारत को हुई अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रथम उपाध्यक्ष श्री सुचार्ट तंजारोएन, 12-18 सितंबर, 2005; बिम्सटेक के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए ऊर्जा मंत्री श्री विसेट चूपीबान की 3 और 4 अक्तूबर, 2005 की भारत यात्रा शामिल हैं।

भारत से थाईलैंड की यात्राओं में निम्नलिखित यात्राएं शामिल हैं 12-18 मई, 2005 तक बैंकाक में यूनेस्कैप के 61 वें वार्षिक सत्र में भाग लेने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री ई वी के एस इलंगोवन; नौसेनाध्यक्ष एडमिरल अरूण प्रकाश, 19-20 मई, 2005; पोर्ट ब्लेयर और फुकेट के बीच सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने हेतु अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लेफ्टीनेंट गवर्नर प्रो. राम कापसे, 29 जून से 2 जुलाई, 2005; 29 जून, 2005 को आंध्र प्रदेश पर्यटन द्वारा बैंकाक में आयोजित पर्यटन लक्ष्य संवर्धन शो में भाग लेने के लिए आंध्र प्रदेश की पर्यटन मंत्री डॉ. जे गीता रेड्डी; श्री बी. के. हांडीक, संसदीय कार्य एवं रक्षा राज्य मंत्री 12-15 जुलाई बिम्सटेक लोगों से लोगों के संपर्क कार्यक्रम का एक भाग; 25 अगस्त, 2005 को आसियान-भारत एस ओएम के लिए वाणिज्य सचिव एस एन मेनन की बैंकाक यात्रा; 25-28 अगस्त, 2005 तक बैंकाक में बौद्ध महोत्सव में भाग लेने के लिए उड़ीसा के पर्यटन मंत्री श्री सूर्य नारायण पात्र तथा उड़ीसा के संस्कृति मंत्री डॉ. दामोदर राउत और 1-5 अगस्त, 2005 तक बैंकाक में एशिया पैसिफिक सेनाध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए उप सेनाध्यक्ष लेफ्टीनेंट जनरल बी. एस. ठाकुर की यात्रा।

भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त कार्यदल की प्रथम बैठक 9 और 10 जनवरी, 2006 को बैंकाक में हुई। कृषि, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, निवेश, नागर विमानन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने दक्षिण एशिया में और पड़ोसी देशों में राजनीतिक स्थिति पर आदान-प्रदान किया। सहयोग के सहमत क्षेत्रों में की गई प्रगति पर निगाह रखने हेतु एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई।

सुरक्षा पर संयुक्त कार्यदल की चतुर्थ बैठक 13-14 अक्तूबर, 2005 को नई दिल्ली में हुई।

द्विपक्षीय रक्षा सहयोग सुदृढ़ हुआ। समन्वित समुद्री गश्त पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। पहली समुद्री गश्त शाही थाई नौसेना तथा भारतीय नौसेना द्वारा 15-23 सितंबर, 2005 तक की गई। भारतीय नौसेना के दो जहाजों - आइ एन एस वेला तथा आइ एन एस लक एल - 34 ने 21-24 अप्रैल, 2005 तक फुकेट की यात्रा की।

एशियाई रक्षा प्रदर्शनी 2-5 नवंबर, 2005 तक बैंकाक में हुई। इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए चार सदस्यों का एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल बैंकाक की यात्रा पर गया। दो भारतीय फर्मों - भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ब्रह्मोस ने प्रदर्शनी में भाग लिया और अपने उत्पाद प्रदर्शित किए।

द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि हुई। द्विपक्षीय मुक्त व्यापार व्यवस्था के लिए रूपरेखा करार के अंतर्गत 'अर्ली हार्वेस्ट स्कीम' जिसमें 82 मदें (6 - अंकीय एच एस कोड स्तर) शामिल हैं, 1 सितंबर, 2004 से चल रही है। जनवरी से अक्तूबर, 2005 के दौरान भारत का थाईलैंड को निर्यात 1075.1 मिलियन अमरीकी डालर का था जो विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए निर्यात की तुलना में 9% अधिक था। थाईलैंड से भारत को निर्यात इस अवधि के दौरान

1228.6 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गयाजो विगत वर्ष से 63% अधिक था।

अप्रैल से अक्तूबर, 2005 के दौरान भारत से थाईलैंड जाने वाले प्रमुख व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में निम्नलिखित शामिल हैं - (i) अप्रैल, 2005 में भारतीय वस्त्र उपांग एवं मशीनरी निर्माता संघ के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा; (ii) भारतीय निर्यात संगठन परिमंडल से एक प्रतिनिधिमंडल; (iii) अगस्त, 2005 में चेन्नई में कॅपेक्सिल द्वारा प्रायोजित कागज एवं कागज उत्पादों से संबधित प्रतिनिधिमंडल की यात्रा; (iv) अगस्त, 2005 में भारतीय सोल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स से प्रतिनिधमंडल की यात्रा; (v) अक्तूबर, 2005 में महरत्ता वाणिज्य, उद्योग एवं कृषि चेंबर से प्रतिनिधिमंडल की यात्रा।

महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटनाओं में ये शामिल हैं - (i) 23-26 जून, 2005 तक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन, और (ii) बैंकाक नृत्य एवं संगीत महोत्सव के एक भाग के रूप में 2 अक्तूबर, 2005 को कलाक्षेत्र द्वारा रामायण की प्रस्तुति।

2005 के दौरान भारत ने थाई राष्ट्रिकों को 104 छात्रवृत्तियां प्रदान की जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पी एच डी पाठ्यक्रमों के लिए 16 दीर्घकालीन विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियां थीं।

वियतनाम

भारत और वियतनाम के बीच गहन और घनिष्ठ संबंध बने रहे।

वियतनाम के विदेश मंत्री श्री गुयेन दी नियन 31 मार्च से 4 अप्रैल, 2005 तक भारत की यात्रा पर आए। प्रतिनिधिमंडल स्तर की यात्राओं के अलावा उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री के. नटवर सिंह से बातचीत की और राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ से और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री एल. के. अड़वानी से भी मुलाकात की।

1955 के बांडुंग सम्मेलन की 50वी जयंती के दौरान मई, 2005 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति ट्रान डुक लुओंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने 22 सितंबर, 2005 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 60 वें सत्र के दौरान वियतनाम के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की।

वियतनाम के रक्षामंत्री श्री फाम वान ट्रा 5-7 मार्च, 2005 तक भारत यात्रा पर आए और उन्होंने रक्षा मंत्री के साथ विचार विमर्श किया। आईटैक कार्यक्रम के अंतर्गत वियतनामी रक्षा बलों के अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहा। भारतीय नौसेना पोत आई एन एस मगर ने 9-13 जून, 2005 तक वियतनाम की यात्रा की। एन सी सी के 13 कैडटों और 2 अधिकारियों के एक दल ने 15-24 नवंबर, 2005 तक वियतनाम की यात्रा की।

वियतनाम के मात्स्यिकी मंत्री श्री ता कुआंग डोक 20-23 मार्च, 2005 तक भारत की यात्रा पर आए। वियतनाम की राष्ट्रीय असेंबली की बजटीय एवं आर्थिक समिति के उपाध्यक्ष श्री ट्रिंह हुय क्वाश के नेतृत्व में एक वियतनामी प्रतिनिधिमंडल 18-20 सितंबर, 2005 तक भारत की यात्रा पर आया।

वियतनाम फादरलैंड फ्रंट के अध्यक्ष श्री फाम द दुयेत के नेतृत्व में 11-16 अक्तूबर, 2005 तक एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया। वियतनामी प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की। में गुंयेन थी होआय थु के नेतृत्व में वियतनामी संसदीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें आठ सांसद थे, वियतनामी संसद की सोशल कमिटी के सांसद और अध्यक्ष 8-11 जनवरी, 2006 तक बंगलौर और केरल की यात्रा पर आए ताकि घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक नीति तथा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से उत्प्रवासियों के लिए सामाजिक नीति का अध्ययन कर सकें।

वियतनाम के साथ द्विपक्षीय व्यापार निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर रहा। जनवरी-सितंबर, 2005 की अवधि के दौरान भारत का वियतनाम को निर्यात 440 मिलियन अमरीकी डालर का रहा है और वियतनाम से आयात 71.09 मिलियन अमरीकी डालर का रहा। वियतनाम के आयोजना एवं निवेश मंत्रालय ने 10-17 अप्रैल, 2005 तक एक निवेश संवर्धन प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजा।

विश्व व्यापार संगठन में वियतनाम के सम्मिलन पर भारत और वियतनाम ने अगस्त, 2005 में एक करार संपन्न किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-वियतनाम संयुक्त समिति की बैठक 20 मई, 2005 को नई दिल्ली में हुई। वियतनाम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपमंत्री डॉ. ली दिंह टियन ने किया। इस बात पर सहमति हुई कि बायोटेक्नोलोजी एवं स्वास्थ्य रक्षा, विज्ञान प्रबंधन एवं इंडिकेटर्स, नई सामग्री और जलवायु अनुसंधान के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष दो संयुक्त कार्यशालाएं एक भारत में, एक वियतनाम में की जाएंगी।

2005-06 के लिए पर्यटन सहयोग योजना पर 14 अक्तूबर, 2005 को हनोई में हस्ताक्षर हुए।

सतम्बर 2005 में सुवा, फिजी में 51वें सी पी ए सम्मेलन के दौरान फिजी के प्रधानमंत्री श्री लाइसेनिया करासे से मुलाकात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी।

9 जून 2005 को नई दिल्ली में आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री श्री अलेक्जेंडर डाउनर से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह।

23 अगस्त - 1 सितंबर, 2005 तक वियतनाम से 13 सदस्यीय वियत बैक पारंपरिक कलाकार मंडली भारत आई।"वियतनामीज फेसँ शीर्षक से एक फोटो प्रदर्शनी भी इस अवसर पर आयोजित की गई।

आस्ट्रेलिया

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हुए अनेक राजनैतिक - स्तरीय द्विपक्षीय दौरों और द्विपक्षीय बैठकों के साथ भारत-आस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों में संवर्द्धन जारी रहा।

भारत - आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक मई, 2005 में सिडनी में हुई। भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री श्री कमल नाथ और आष्ट्रेलियाई शिष्टण्डल का नेतृत्व श्री मार्क वेले ने किया। उसी समय संयुक्त वाणिज्यिक परिषद की बैठक भी हुई।

खान मंत्री श्री शीश राम ओला ने उड़ीसा, झारखण्ड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के एक शिष्टमण्डल के साथ 23-21 मई, 2005 तक आस्ट्रेलिया का दौरा किया। मंत्री महोदय ने आस्ट्रेलिया के उद्योग, पर्यटन और संसाधन मंत्री, प्रांतीय मंत्रियों और खनन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री सुरेश पचौरी लोक सेवा से संबंधित अध्ययन के लिए 21-18 मई, 2005 तक एक शिष्टमण्डल के प्रमुख के रूप में आस्ट्रेलिया गये। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. एम.एस. अहलूवालिया ने मेलर्बोन विश्वविघालय में वार्षिक डेविड फिंच व्याख्यान देने के लिए 19-23 सितम्बर, 2005 तक आस्ट्रेलिया का दौरा किया। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (आई सी) श्री विलास मुत्तेमवार ने 3-8 नवम्बर, 2005 तक आस्ट्रेलिया का दौरा किया। उन्हें विश्व पवन ऊर्जा संघ से एक पुरस्कार प्राप्त हुआ और उन्होंने मेलर्बोन में वार्षिक विश्व पवन ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित किया।

आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री श्री अलेक्जेन्डर डॉवनर ने भारत-आस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता के लिए भारत का दौरा किया।

आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री जॉन हॉवर्ड 6 मार्च, 2006 को भारत आने वाले हैं। उनकी यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उनकी यात्रा से पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों/नीतिगत वार्ताएं 14-16 फरवरी, 2006 तक नई दिल्ली में होनी हैं जिनमें द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा की जाएगी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राज्य स्तर पर पर्याप्त क्रियाकलाप हुए। कर्नाटक के उद्योग एवं अवसंरचना मंत्री श्री पी.जी. आर सिंधिया के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने 26 अप्रैल - 2 मई, 2005 तक क्वींसलैंड और विक्टोरिया का दौरा किया। विक्टोरिया के प्रधान मंत्री श्री स्टीव ब्लैक्स के नेतृत्व में एक वाणिज्यिक शिष्टमण्डल 12-17 अप्रैल, 2005 तक भारत आया। विक्टोरिया राज्य ने नवम्बर में नवम्बर में बंगलौर में एक व्यापक और निवेश कार्यालय खोला जिसका उद्घाटन विक्टोरिया के सूचना प्रोद्योणिकी मंत्री सुश्री मार्शी थॉमसन ने किया। पश्चिमी आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री डा. ज्योफ गैलोप 30 सितम्बर, 2005 से 10 दिनों के लिए भारत यात्रा पर आये। दो शिष्टमण्डलों ने जैव-प्रोद्योगिकी तथा ऊर्जा की पहचान की।

भारत-आस्ट्रेलिया ट्रैक-II राजनय की चौथी गोलमेज बैठक 11 और 12 अप्रैल, 2005 को कैनबरा में हुई।

भारत-आस्ट्रेलिया व्यापार संबंधों में इस वर्ष लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2004-2005 (जुलाई, 2004 - जून, 2005) में द्विपक्षीय व्यापार 7.3 बि. आस्ट्रेलियाई डालरों का हुआ। अनेक आस्ट्रेलियाई कंपनियों ने भारत में कार्यालय स्थापित किये।

रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि होती रही। आस्ट्रेलियाई वायु सेना के प्रमुख एअर मार्शल ज्योफ शेफर्ड ने 23-29 सितम्बर, 2005 तक भारत का दौरा किया। सेना प्रमुख जे. जे. सिंह ने 23-28 अक्टूबर, 2005 तक आस्ट्रेलिया का दौरा किया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आस्ट्रेलिया ने शांति, मैत्री और सहयोग से संबद्ध आसियान संधि पर हस्ताक्षर किया और इसे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एक भागीदार के रूप में शामिल किया गया। आस्ट्रेलिया स्वच्छ विकास एवं जलवायु से संबद्ध एशिया प्रशांत भागीदारी का सदस्य भी है जिसमें चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और अमरीका भी शामिल है। इनसे बहुपक्षीय मंचों पर आस्ट्रेलिया के साथ भारतीय क्रियाकलाप के लिए अतिरिक्त अवसर मिले।

फिजी द्वीपसमूह

अनेक जारी पहलकदमियों के कारण भारत-फिजी द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय विकास हुआ।

भारत और फिजी के बीच पहले दौर के विदेश कार्यालय परामर्श जो 14 और 15 जुलाई, 2005 को वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर आयोजित किये गये, में कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, जल संसाधन विकास, पर्यटन और दूर संवेदन

जैसे विविध क्षेत्रों में फिजी को दी जानी वाली संवर्द्धित सहायता सहित भारत-फिजी द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गयी। भारतीय शिष्टमण्डल ने जी - 4 प्रस्ताव को सह-प्रायोजित करने के लिए फिजी सरकार को धन्यवाद दिया। प्रधान मंत्री करासे को भारत यात्रा का नियंत्रण भी दिया गया।

भारत और फिजी के बीच खेल संपर्क पुनः जीवीत हो उठे जब भारतीय राष्ट्रीय फुटबाल टीम ने अगस्त, 2005 में फिजी का दौरा किया।

लोक सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने, जिसमें राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष, सांसद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, राष्ट्रकुल संसद संघ सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1-10 सितम्बर, 2005 तक फिजी का दौरा किया। सम्मेलन के दौरान पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष श्री हाशिम अब्दुल हसीम को भारी अंतर से सी पी ए कार्यकारी समिति का अध्यक्ष चुना गया। लोक सभाध्यक्ष ने अपनी यात्रा के दौरान लाउटोका में भारतीय संस्कृतिक केन्द्र के उप-केन्द्र का उद्घाटन किया।

विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधान मंत्री श्री महेन्द्र चौधरी ने 8-18 सितम्बर, 2005 तक भारत का दौरा किया और उन्होंने प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मुलाकात की।

8-15 अक्टूबर, 2005 तक फिजी के माननीय प्रधान मंत्री लायसेनिया करासे की राजकीय यात्रा भारत - फिजी द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यात्रा के दौरान भारत और फिजी ने स्वास्थ्य एवं पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर करार तथा एक संयुक्त व्यापार समिति की स्थापना और सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन संपन्न किये। प्रधान मंत्री करासे ने फिजी के विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। शिष्टमण्डल ने नारियल उघोग, सूचना प्रौद्योगिकी और फिल्म निर्माण के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए क्रमशः कोच्ची, बंगलौर और मुम्बई का दौरा किया।

भारतीय उच्चायोग, कैनबरा में रक्षा सलाहकार को फिजी द्वीपसमूह गणराज्य के लिए सह प्रत्यायित किया गया। इस वर्ष नई दिल्ली में फिजी सेना के दो आधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

फिजी के चीनी उद्योग के प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए रियायती दर पर 50.40 मि. अमरीकी डालरों की ऋण श्रृंखला से संबद्ध करार भारतीय एक्जिम बैंक और सूवा के फिजी चीनी निगम के बीच नवम्बर, 2005 को संपन्न किया गया।

न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के शिक्षा मंत्री श्री त्रेवोर मलार्ड 17-22 अप्रैल, 2005 तक भारत यात्रा पर आए। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर करार संपन्न हुआ।

दस सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य मंडली और दस सदस्यीय कठपुतली मंडली 21-31 अक्तूबर, 2005 तक न्यूजीलैंड के यात्रा पर गईं।

पपुआ न्यू गिनी, सोलामन द्वीप एवं वनुआतु

अप्रैल, 1996 में पोर्ट मोर्सबी में भारत का आवासी मिशन खुल जाने के बाद पपुआ न्यू गिनी के साथ भारत के संबंध घनिष्ठ हुए हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी उम्मीदवारी के लिए भारत को पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और वनआतु से समर्थन मिलता रहा है। पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और वनुआतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थक हैं।

पपुआ न्यू गिनी को आइटैक के 15 स्लाट और वनुआतु तथा सोलोमन द्वीप के लिए प्रत्येक को आठ-आठ स्लाट आवंटित किए गए थे। इसके अतिरिक्त वनुआत और सोलोमन द्वीप समूह से एक - एक अधिकारी ने विदेशी राजनयिकों के लिए विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग लिया। एच आई वी/एड्स संसाधन केंद्र की स्थापना के लिए भारत के अंतर्गत पपुआ न्यू गिनी को 10 लाख रुपए का अनुदान देगा।

लघु द्वीप विकासशील राज्यों को सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने पपुआ न्यू गिनि, सोलोमन द्वीप समूह और वनुआतु को सूचना प्रौद्योगिक उपकरण प्रदान किए हैं।

पश्च पैसिफिक द्वीपसमूह मंच वार्ता में भाग लेने के लिए दो सदस्यीय शिष्टमंडल 28-30 अक्तूबर, 2005 तक पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गया। पैसिफिस द्वीप समूह मंच में भारत वार्ता भागीदार है।

16 मिलियन अमरीकी डालर के भारतीय निर्यात के साथ पपुआ न्यु गिनी के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है।

तिमोर - लेस्ते

तिमारे लेस्ते में राष्ट्र और संस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई। अप्रैल, 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूनोटिल की स्थापना का अनुमोदन कर दिया जो एक-वर्षीय विशेष राजनैतिक मिशन है और जो मई 2006 तक देश में रहेगा।

उच्च - स्तरीय दौरों के आदान-प्रदान से तिमोर लेस्ते और इंडोनेशिया के बीच संबंधों में और सुधार आया। मार्च, 2005 में दोनों देशों ने 1999 में हुए मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने के लिए सत्य और मैत्री आयोग का गठन किया। एक दस सदस्यीय सी टी एफ ने अगस्त, 2005 में अपना कार्य आंरभ किया। सी टी एफ की अनुशंसाएं बाध्य नहीं होगी।

भारत ने तिमोर लेस्ते के साथ अपना घनिष्ठ संबंध बनाये रखा और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना सहयोग दिया। वर्ष 2005-2006 के दौरान तिमोर लेस्ते को 10 आइटेक प्रशिक्षण स्लाट और 10 जी सी एस एस स्लाट आबंटित किये गये। आइटेक के अंतर्गत तिमोर लेस्ते के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण परिणेजना पर विचार किया जा रहा है।

टोंगा

भारतीय उच्चायोग कैनबरा के रक्षा परामर्शदाता को टोंगा गणराज्य के लिए सहप्रत्यापित किया गया। टोंगा के दो अधिकारियों ने इस वर्ष नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा पठ्यक्रमों में भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर विदेश मंत्री के विशेष दूत डा. अतुल खरे ने जुलाई/अगस्त, 2005 में टोंगा का दौरा किया और उन्होंने टोंगा के विदेश मंत्री से मुलाकात की और आपसी हित के मामलों पर बातचीत की।

तुवालु

संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर विदेश मंत्री के विशेष दूत डा. अतुल खरे ने जुलाई/अगस्त, 2005 में तुवालु के प्रधान मंत्री से मुलाकात की और आपसी हित के मामलों पर चर्चा की।

■■

पूर्वी एशिया 3

जापान

भारत जापान के साथ अपने घनिष्ठ, सहयोगी एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों का आदर करता है। अगस्त, 2000 में भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित 21वीं शताब्दी के लिए, वैश्विक साझेदारी ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक बनाने तथा गहरा करने में तथा एशिया एवं विश्व की संपन्नता एवं स्थिरता में योगदान दिया है। घरेलू आदर्शों एवं मूल्यों, आर्थिक समादरताओं तथा रणनीतियों समाभिरूपताओं के प्रति अपनी-अपनी प्रतिबद्धता का दोनों देशों में साझी मान्यता ने सहयोग के बहुआयामी संबंध के लिए लचीली नींव प्रदान की है।

28 से 30 अप्रैल, 2005 के दौरान प्रधानमंत्री जूनिचिरो कोइजुमी की भारत यात्रा से भारत-जापान के द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ोत्तरी के एक नए दौर की शुरूआत हुई। श्री कोईजुमी और प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने यात्रा के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर साझेदारी को सुदृढ़ करने वाला एक संयुक्त बयान जारी किया। अपने वैश्विक संबंध की पूर्ण शक्यता का दोहन करने के लिए दोनों नेताओं ने आठ-सूत्रीय पहल का निर्णय किया जिनमें अंतःक्रिया के 8 मुख्य क्षेत्रों में सहयोग के उपाय शामिल हैं जो इस प्रकार हैं- (i) उच्च स्तरीय विनियमों के मोमेंटम का सुदृढ़ीकरण सहित परिवर्तित एवं स्तरोन्नत वार्ता संरचना, उच्चस्तरीय सामरिक बातचीत आरंभ करना और विद्यमान वार्ता तंत्र का पूरा उपयोग; (ii) माल एवं सेवाओं में व्यापार के विस्तार, निवेश प्रवाह और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों, तथा भारत-जापान आर्थिक साझेदारी करार के माध्यम से व्यापक आर्थिक विनियोजन; (iii) परिवर्धित सुरक्षा वार्ता और सहयोग; (iv) खाद्यान्न एवं प्रौद्योगिकी पहल; (v) सांस्कृतिक एवं शैक्षिक पहल तथा एक देश की दृश्यता और प्रोफाइल को दूसरे देश में बढ़ाने के लिए जन-दर-जन संपर्कों का सुदृढ़ीकरण (vi) एक नया एशियाई युग लाने में सहयोग; (vii) संयुक्त राष्ट्र सुधार खासकर सुरक्षा संबंधी सुधार को जल्दी मूर्तरूप देने के लिए सहयोग सहित संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग और (viii) वैश्विक चुनौतियों एवं अवसरों का प्रत्युत्तर देने में सहयोग।

वर्ष के दौरान जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री (एमईटीआई) श्री शोइची नाकागावा ने 6 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में ऊर्जा सुरक्षा पर आयोजित पहले गोलमेज में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। जापान के वित्त मंत्री श्री साडाकाजू तानिमाकी ने 12 से 14 जनवरी, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया। आर्थिक और राजकोषीय मंत्री श्री हीजो टाकेनाश ने 12-13 जनवरी को भारत का दौरा किया। कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी के वरिष्ठ उप मंत्री श्री टाकापोशी सुनेडा ने 11-13 जनवरी, 2005 को भारत का दौरा किया। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन ने 17 से 19 जनवरी, 2005 के दौरान जापान का दौरा किया।

जापान-भारत संबंध पर एक संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए मार्च, 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री योशिरो मोरी ने भारत का दौरा किया। सत्ता पक्ष लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के महासचिव श्री शिंजा एबे ने मार्च, 2005 में भारत का दौरा किया। व्यापक सूचना वार्ता के तीसरे चक्र का आयोजन 23 मार्च, 2005 को हुआ जिसके बाद 24 मार्च, 2005 को टोकियो में सैन्य-दर-सैन्य बातचीत का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के विशेष सुरक्षा सलाहकार और पूर्व विदेश मंत्री सुश्री यूरिको कावागुची ने अप्रैल, 2005 में भारत का दौरा किया। वाणिज्य मंत्री श्री कमलनाथ ने भारत-जापान निवेश वार्ता के चौथे चक्र में हिस्सा लेने के लिए अप्रैल, 2005 में जापान का दौरा किया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने मई, 2005 में निहोन केइजई शिंबून द्वारा आयोजित सम्मेलन 'एशिया का भविष्य' में भाग लिया। जापान प्रतिरक्षा एजेंसी के वरिष्ठ उपमंत्री श्री हिरोशी इमाजू ने मई, 2005 में भारत का दौरा किया। भारत पैवेलियन खड़ा करके तथा आईसीसीआर की सांस्कृतिक मंडलियों के कला-प्रदर्शन की व्यवस्था करके मार्च-सितम्बर, 2005 में आयोजित 2005 विश्व प्रदर्शनी, एइची, जापान में भारत ने हिस्सा लिया। वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री श्री ई. वी. के. एस. एलानगोवन ने 20 जुलाई, 2005 को एइची टोक्यो में भारत राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए 19 से 21 जुलाई, 2005 के दौरान जापान का दौरा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह

हुड्डा ने नवम्बर में जापान का दौरा किया तथा हरियाणा में जापानी निवेश आकृष्ट करने के लिए, जापानी व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। विदेशी मंत्री श्री तारो आशे ने 3-4 जनवरी, 2006 को भारत का दौरा किया। दोनों पक्ष अब से सामयिक परिप्रेक्ष्य के साथ विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता और निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार पर संयुक्त सचिव/ महानिदेशक स्तरीय वार्षिक परामर्श के आयोजन पर सहमत हुए। वित्त मंत्री श्री पी0 चिदम्बरम ने 17-19 जनवरी को जापान का दौरा किया।

श्री टारो आशो, जो उस समय आंतरिक मामलों और संचार के जापानी मंत्री थे, ने आईसीटी मंच की प्रथम बैठक के लिए अगस्त 2005 में भारत आए एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। भारत और जापान के आईटी एवं संचार उद्योग के सीईओ से बने इस मंच ने ब्राडबैंड, मोबाइल संचार, ई-गवर्नेंस, सूचना सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा सर्वगत नेटवर्क के क्षेत्रों में भारी सहयोग का रास्ता तय करने के लिए 6 कार्य समूहों का गठन करने का निर्णय लिया। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी, सी-डाक (उन्नत संगठन विकास केंद्र) और सी-डाट (टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र) ने अपने हित के क्षेत्रों में आरएंडडी सहयोग हेतु एनआईसीटी (राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रोद्योगिकी संस्थान, जापान) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने सितम्बर, 2005 में जब जापान का दौरा किया तब ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण सहित भावी द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करते हुए संयुक्त बयान जारी किया गया। जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ उपमंत्री श्री अकीरा निशीना ने मध्य और उत्तरी एशिया के प्रधान प्रदायकों तथा एशिया के प्रधान क्रेताओं के मंत्री स्तरीय गोलमेज में भाग लेने के लिए 25-26 नवम्बर, 2005 को भारत का दौरा किया।

अप्रैल, 2005 में प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोईजुमी की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसरण में भारत-जापान संयुक्त अध्ययन समूह को व्यापक ढंग से भावी भारत-जापान आर्थिक विनियोजन के लिए रोडमैप तैयार करने का कर्य सौंपा गया। जेएसजी की पहली बैठक नई दिल्ली में 18-19 जुलाई, 2005 को तथा दूसरी बैठक टोकियो में 15-16 नवम्बर, 2005 को हुई। जेएसजी की तीसरी बैठक 1 और 2 फरवरी, 2006 को हुई। जेएसजी द्वारा व्यापक आर्थिक साझेदारी करार की संभाव्यता की भी जांच की जाएगी।

वाणिज्य विभाग और एमईटीआई के बीच नीति वार्ता की पहली बैठक दिल्ली में अप्रैल, 2005 में हुई। इस क्रियाविधि के तहत कार्य समूह, जिसे विशेष रूप से व्यापार एवं निवेश बाधाओं की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है, की पहली बैठक टोकियो में 26 और 27 अक्तूबर, 2005 को हुई।

निप्पन कोडानरेन के अध्यक्ष के नेतृत्व में जापानी व्यवसाय शिष्ट मंडल ने वनम्बर, 2005 में भारत का दौरा किया।

भारत-जापान विज्ञान परिषद की बैठक जापान में 28-29 जनवरी, 2005 को हुई। अप्रैल, 2005 में जापानी प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में व्यापक सहयोग का पता लगाने के लिए एक नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल आरंभ करने पर सहमति हुई थी। और प्रौद्योगिकी में भारत-जापान सहयोग संबंधी संयुक्त समिति की बैठक 3 नवम्बर, 2005 को हुई जिसमें इस प्रकार की पहल के घटकों एवं क्रियान्वयन विधि पर बातचीत हुई।

ज्वाइंट स्टाफ कांउसिल आफ जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के अध्यक्ष जनरल हाजिमे मसाकी ने सितम्बर, 2005 में भारत का दौरा किया। भारतीय तटरक्षक पोत 'समर' ने नवम्बर, 2005 में जापान में छठें द्विपक्षीय तटरक्षक अभ्यास में भाग लिया। दोनों तटरक्षक बलों के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन विचाराधीन है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ने इस अवसर पर जापान का दौरा किया।

पर्यटन राज्य मंत्री सुश्री रेणुका चौधरी ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु टोकियो में आयोजित रोड शो में भाग लेने के लिए 2 से 16 अक्तूबर, 2005 के दौरान जापान का दौरा किया। आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित भारत की अनेक सांस्कृतिक मंडलियों ने एइची एक्सपो के अलावा जापान के विभिन्न भागों में अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। जापान से दूरदर्शन की 32 टीमों ने डाक्यूमेंटरी फिल्मों की शूटिंग करने के लिए अप्रैल से नवम्बर, 2005 की अवधि में भारत का दौरा किया।

2003-04 में दोतरफा व्यापार बढ़कर 4.356 बिलियन अमरीकी डालर हो गया(भारतीय निर्यात 1.714 बिलियन अमरीकी डालर और आयात 2.642 बिलियन अमरीकी डालर)। 2004-05 में जापान को निर्यात 15 प्रतिशत बढकर 1.978 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया तथा जापान से आयात भी 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3.006 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया। जापान भारत में चौथा सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक है। लगभग 265 जापानी कंपनियों ने 1991 से जून, 2005 की अवधि में 1.944 बिलियन अमरीकी डालर का

29 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री श्री जुनिचिरो कोईजुमी के साथ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह।

7 फरवरी 2006 को प्रेसिडेन्सियल पैलेस में राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का स्वागत करते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति श्री रोह मू-ह्यून।

वास्तविक निवेश किया। भारत में जापानी एफआईआई मात्रात्मक उछाल का साक्षी है क्योंकि भारतीय पूंजी बाजार में पोर्टफोलियो निवेश में 10 भारत केंद्रित निधियों ने लगभग 4 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है।

कार्यात्मक स्तर पर भारी संख्या में शिष्टमंडलों द्वारा यात्राओं का दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान हुआ जिससे सहयोग का द्विपक्षीय एजेंडा सक्रियता से आगे बढ़ रहा है।

कोरिया गणतंत्र

भारत और कोरिया गणतंत्र (आरओके) के संबंधों में वर्ष 2005 के दौरान उल्लेखनीय एवं निरंतर प्रगति हुई। उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान, बढ़ती आर्थिक एवं वाणिज्यिक संहलग्नता, बढ़ते दोतरफे निवेश प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परिवर्धित कार्यात्मक विनिमयों एवं सहयोग ने इस संबंध को और गति दी। पहले, अक्त्बर, 2004 में राष्ट्रपति रोह मू-हून के "भारत दौरे के दौरान दोनों ने शांति एवं समृद्धि के लिए दीर्घकालीन सहयोगी साझेदारी" स्थापित करने का निर्णय लिया था। भारत और आरओके अपने संबंध पर दीर्घकालीन एवं समारिक नजरिया अपना रहे हैं।

राष्ट्रपति रोह-मूहून के निमंत्रण पर राष्ट्रपति ने 6 से 9 फरवरी, 2006 के दौरान आरओके का राजकीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान सीमाशुल्क में सहयोग एवं परस्पर सहायता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग तथा व्यापक आर्थिक साझेदारी करार विकसित करने के वास्ते संयुक्त कार्यबल गठित करने के करार हस्ताक्षरित किए गए।

द्विपक्षीय सहयोग पर भारत-कोरिया संयुक्त आयोग का चौथा अधिवेशन नई दिल्ली में 1 अगस्त, 2005 से आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता दोनों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से की। व्यापार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई। राजनयिक और आफिशियल पासपोर्ट धारकों द्वारा बीजा मुक्त यात्रा पर करार तथा रक्षा उद्योग एवं संभारतंत्रीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री सुरेश पचौरी ने रिइनवेंटिंग गवर्नमेंट पर छठें ग्लोबल फोरम में हिस्सा लेने के लिए 23 से 26 मई, 2005 के दौरान सिओल का दौरा किया। संसद सदस्य श्री सैफुद्दीन सोज ने 25 से 27 मई 2005 के दौरान सिओल में आयोजित एशियाई राजनीतिक दलों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थाई समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सिओल में अपने ट्रांजिट हाल्ट के दौरान 1 जून, 2005 को आरओके के विदेश एवं व्यापार मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दिल्ली के मेयर श्री सतबीर सिंह ने 29 सितम्बर से 3 अक्तूबर, 2005 के दौरान आयोजित सिओल विश्व मेयर सम्मेलन में हिस्सा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा ने नवम्बर, 2005 में आरओ" के का दौरा किया तथा अपने राज्य में कोरियाई निवेश आकृष्ट करने के लिए कोरियाई व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

राष्ट्रीय रक्षा कालेज के पद्रंह सदस्यीय शिष्टमंडल ने 16 से 22 मई, 2005 के दौरान आरओके का दौरा किया।

आरओके के अधिग्रहण उपमंत्री के भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली में 13 सितम्बर, 2005 को रक्षा उद्योग और संभार तंत्रीय सहयोग पर आरओके के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय और भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय तट रक्षक पोत "समर" ने 21 से 24 अक्तूबर के दौरा बुसान का दौरान किया तथा कोरियाई तट रक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास किया। इन अभ्यासों में चोरी से घुसने वाले वाहकों का संयुक्त अवरोधन, तलाशी एवं बचाव मिशन तथा महासागर में जाने वाले पोतों पर अग्निशमन शामिल था।

आरओके के सबसे बड़े इस्पात निर्माण पोस्को ने उड़ीसा में एक समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए 22 जून, 2005 को उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के मुताबिक पोस्को कच्चे लोहे की खदाने विकासित करने, इस्पात संयंत्र स्थापित करने, पारादीन में पत्तन सुविधाएं विकसित करने तथा हर वर्ष 12 मिलियन टन इस्पात निर्मित करने के लिए संचयी रूप से 12 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करेगा।

भारत-आरओके नागरिक उड्डयन वार्ता 13 से 16 जुलाई, 2005 के दौरान सिओल में आयोजित की गई। एयर इंडिया ने अपनी सिओल सेवा 8 जुलाई, 2005 से फिर से शुरू कर दी। अब यह सिओल - नई दिल्ली -मुबंई के बीच हर सप्ताह चार सेवाएं संचालित करता है।

भारत-कोरिया संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की पहली बैठक सिओल में 31 अगस्त, 2005 को हुई। संयुक्त समिति ने सहयोग के एक एजेंडे पर निर्णय लिया जिनमें तकनीकी मिशनों का पारस्परिक दौरा, शैक्षिक सेमिनार/ कार्यशाला/फोरम का आयोजन तथा संयुक्त अनुसंधान का

संचालन शामिल है। इस बात पर भी सहमति हुई कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास की संयुक्त परियोजनाओं को सहायता देने के वास्ते प्रत्येक पक्ष हर वर्ष 300000 अमरीकी डालर का बजटीय निधियन आवंटित करेगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर ने 2 और 3 अक्तूबर, 2005 को सिओल का दौरा किया तथा 25 नवम्बर, 2005 को प्रधान एशियाई तेल प्रदायकों एवं क्रेताओं के गोल मेज सम्मेलन में पीओके की भागीदारी सहित ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर वाणिज्य, उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री श्री ही विओम ली के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। 3 अक्तूबर, 2005 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने सिओल में ब्लाक ए-3 के लिए समनुदेशन करार (म्यांमार में) के हस्ताक्षर समारोह में भी हिस्सा लिया। देबू इंटरनेशनल कार्पोरेशन, जिसके ए-3 ब्लाक में 100% शेयर हैं, ने 20% शेयर ओएनजीसी विदेश लि0 को और 10% गेल (इंडिया) लि0 को दिया। आरओके के वाणिज्य, उद्योग और ऊर्जा मंत्री श्री ही-विओम ली ने मध्य और उत्तरी एशिया के प्रधान संघटकों तथा एशिया के प्रधान क्रेताओं के मंत्री स्तरीय गोल मेज में हिस्सा लेने के लिए 25 एवं 26 नवम्बर, 2005 को भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान भारत और आरओके ने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग के लिए 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः- भारत और कोरिया के बीच हाइड्रोकार्बन सहयोग पर करार और रणनीतिक भूमिगत पेट्रोलियम भंडारण सुविधा, गैस हाइड्रेट से संबंधित तकनीकी सहयोग, हाइड्रोजन और संपींडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), हाइड्रोजन और ईंधन सेल तथा सामरिक गठजोड़े की स्थापना पर पांच समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

पर्यटन राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी ने आरओके से भारत विशेषकर बौद्ध सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित रोड शो में हिस्सा लेने हेतु 11 और 12 अक्तूबर, 2005 को सिओल का दौरा किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा0 अंबुमणि रामदास ने डेइगू में परंपरागत औषधि पर आयोजित एक सेमिनार में भाग लेने के लिए 19 से 22 अक्तूबर, 2005 के दौरान आरओके का दौरा किया। डा0 रामदास ने कोरियाई आहार एवं प्रशासन से पंजीकरण में भारतीय कंपनियों के सामने आ रही कठिनाइयों पर आरओके के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री श्री किम जिऊन-तेई के साथ विचार-विमर्श किया।

2004-05 में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा 29% बढ़कर 4.157 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गई (निर्यात 963 मिलियन अमरीकी डालर और आयात 3.194 बिलियन अमरीकी डालर)। 1991 से लेकर सितम्बर, 2005 की अवधि में कोरिया से एफडीआई का वास्तविक प्रवाह 698 मिलियन अमरीकी डालर है। भारत-आरओके संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) की अंतिम बैठक 6 जनवरी, 2006 को हुई तथा इसने माल एवं सेवाओं में द्वापक्षीय व्यापार, निवेश प्रवाह और अन्य आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए उपायों की सिफारिश करने के साथ अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। जेएसजी की रिपोर्ट ने यह भी सिफारिश की कि दोनों देश व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर वार्ता करने के लिए एक संयुक्त कार्यबल आरंभ करें।

कार्यात्मक स्तर पर आयोजित यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैंः- 30 मई से 4 जून, 2005 की अवधि में सिओल में आयोजित एशिया-प्रशांत पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) के नौवे कांग्रेस में हिस्सा लेने हेतु सचिव, डाकतार विभाग का दौरा; कच्चे तेल के भंडारण तथा भूमिगत टैंक के संबंध में कोरियाई राष्ट्रीय तेल निगम के साथ विचार-विमर्श करने के लिए 16 से 18 मई 2005 की अवधि में संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा दौरा; 19 और 20 मई 2005 को सिओल में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी पर संयुक्त अध्ययन समूह की दूसरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा दौरा; और 6 जनवरी, 2006 को सिओल में आयोजित संयुक्त अध्ययन समूह की चौथी एवं अंतिम बैठक में हिस्सा लेने के लिए वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल का दौरा।

महाराष्ट्र सरकार में उद्योग मंत्री श्री अशोक चव्हाण के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने व्यापार को बढ़ावा देने, सूचना के आदान-प्रदान एवं संयुक्त उद्यम एवं निवेश पर विचार-विमर्श करने के लिए 27 से 30 सितम्बर, 2005 के दौरान आरओके का दौरा किया।

कोरिया प्रजातांत्रिक जन गणतंत्र

इस अवधि के दौरान भारत और कोरिया प्रजातांत्रिक जन गणतंत्र (डीपीआरके) के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और मंत्री पूर्ण बने रहे। सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय और डीपीआरके उप विदेश मंत्री के स्तर पर दोनों के बीच विदेश मंत्रालयीन परामर्श का आयोजन पौगयांग में 14-15 जून 2005 को हुआ। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में डीपीआरके को 2000 टन चावल भेजे। आईटीईसी कार्यक्रम के तहत डीपीआरके अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, व्यावसायिकों के लिए

अंग्रेजी भाषा मं पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में प्रशिक्षण दिया गया। डीपीआरके के राजनयिकों ने विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित विदेशी राजनयिकों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) में हिस्सा लिया।

23वें अप्रैल स्प्रिंग फ्रेंडशिप आर्ट फेस्टिबल में भाग लेने के लिए अप्रैल 2005 में 13 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य मंडली ने पोंगयांग का दौरा किया। भारतीय मुक्केबाजी टीम ने 18 से 23 जुलाई, 2005 के दौरान आयोजित पोंगयांग अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया।

मंगोलिया

भारत और मंगोलिया के बीच परंपरागत रूप से घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध इस वर्ष के दौरान और मजबूत हुए, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने का 15वां वर्ष गांठ था।

विदेश राज्य मंत्री श्री ई0 अहमद ने राष्ट्रपति एन0 खवयार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 23 से 25 जून 2005 के दौरान उलनवाटर का दौरा किया।

मांगोलिया के विदेश मंत्री श्री मून्ह-ओरजिल ने 22 से 27 दिसम्बर, 2005 की अवधि में भारत का राजकीय दौरा किया। उनका दौरा भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर था। इसके दौरान नीचे उल्लिखित करार हस्ताक्षरित किए गएः- राजनयिक एवं शासकीय पासपोर्ट घारकों के लिए बीजा अपेक्षाओं में परस्पर छूट देने पर करार; वर्ष 2006-08 के लिए संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम; डरखान उल ऐमाग, मंगोलिया में भारत-मंगोलिया मैत्री एग्रोपार्क स्थापित करने के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन; और उलानवटार में भारतीय चांसरी परिसरों के पट्टाकरण पर करार। यात्रा के दौरान दोनों पक्ष राजनयिक संबंध स्थापित होने की 15वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंगोलिया में टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसीन हेतु उपग्रह आधारित ई-नेटवर्क स्थापित करने के वास्ते एक नई पहल आरंभ करने पर सिद्धांततः सहमत हुए।

दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच सहयोग और विनिमय पर विचार-विमर्श करने के लिए पांच सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने 8 से 14 मई 2005 के दौरान मंगोलिया का दौरा किया। मंगोलियाई रक्षा मंत्री श्री शरवदोरजे ने 5 से 11 दिसम्बर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया तथा रक्षा मंत्री के साथ बातचीत की। यात्रा के दौरान उन्होंने मिजोरम में संचालित द्वितीय भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया।

अंग्रेजी भाषा, गणित और सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ाने के लिए पांच भारतीय शिक्षक भारत-मंगोलिया संयुक्त विद्यालय में प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र के विस्तार के अंग के रूप में भारत सुखवातर, डोरनोड,, खोबसगोल, बुलजान और खारखोरी के प्रांतों में नए सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है। मंगोलिया में पांच नए सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने के सिलसिले में नवम्बर, 2005 में राष्ट्रीय सूचना विकास केन्द्र के चार सदस्यीय शिष्टमंडल ने उलानवटार का दौरा किया।

बौद्ध पांडुलिपियों के डिजटलीकरण से संबंधित परियोजना पर विचार-विमर्श करने के लिए 16 से 20 नवम्बर 2005 के दौरान तीन सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने उलानवटार का दौरा किया।

भारत मंगोलिया के खेनट्टी ऐमाग के दादलसोडम गांव में प्रायोगिक सौर विद्युतीकरण परियोजना शुरू कर रहा है।

■■

यूरेशिया 4

रूस और अन्य सी आई एस देशों के साथ भारत के संबध परंपरागत घनिष्ठ एवं व्यापक कार्य-कलापों द्वारा चिह्नित हुए। सरकारी, संसदीय और वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडलों और सांस्कृतिक मंडलियों के आदान-प्रदान के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं महत्वपूर्ण रहीं। फिल्म महोत्सवों, गोष्ठियों, सम्मेलनों और व्यापार प्रदर्शनियों का आयोजन नियमित रूप से किया गया; विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय करार संपन्न किए गए; आईटैक कार्यक्रमों के मानदण्डों के भीतर तथा अन्य माध्यमों के जरिए कतिपय सी आई एस देशों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए गए और उन्हें सहायता मुहैया कराई गई।

रूस

इस अवधि के दौरान गहन द्विपक्षीय राजनैतिक संपर्क हुए, इनमें उच्चतम राजनैतिक स्तर के संपर्क भी शामिल हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की 60वीं जयंती के अवसर पर विजय दिवस 9 मई के समारोहों में भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री मास्को गए। इसी माह के दौरान राष्ट्रपति रूस की राजकीय यात्रा पर गए। राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर यू पी ए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जून में रूस की यात्रा पर गई। जुलाई 2005 में ग्लेनीगल्स जी - 8 की बैठक के दौरान तथा सितंबर में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की।

जून के शुरू में विदेश मंत्री स्तर की त्रिपक्षीय (भारत-रूस-चीन) बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री ब्लादीवोस्तोक गए। विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री लावरोव से भी द्विपक्षीय बैठक की। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूसी अंतर सरकारी आयोग के 11 वें सत्र की सहअध्यक्षता करने के लिए विदेश मंत्री अक्तूबर में पुनः मास्को गए। विदेश मंत्री ने मास्को में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत - रूसी अंतर सरकारी आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए रूस की यात्रा की। इससे पूर्व अक्तूबर में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई इवानोव भारत में संयुक्त सैनिक अभ्यास के सिलसिले में भारत आए। रक्षा सचिव अप्रैल में मास्को गए। रूस के ऊर्जा एवं उद्योग मंत्री विक्तोर खिस्तेन्को उत्तर एवं मध्य एशियाई तेल उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए नवंबर में नई दिल्ली आए। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर फरवरी में रूस गए और सितंबर-अक्तूबर में साखालिन 1 परियोजना के प्रथम उत्पादन के अवसर पर समारोह में भाग लेने पुनः रूस गए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री कपिल सिबल सितंबर में रूस की यात्रा पर गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम के नारायणन मई में और सितंबर में, दो बार मास्को गए और उन्होंने रूसी रक्षा मंत्री तथा रूसी रक्षा परिषद के सचिव के साथ बैठकें की। रूसी रक्षा परिषद के सचिव अक्तूबर में दिल्ली आए।

26 सितंबर से 4 अक्तूबर, 2005 तक मास्को में "रूस में भारतीय दिवस" का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण तथा संस्कृति मंत्री ने और रूस के संस्कृति मंत्री ने किया।

वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक, जिसकी शुरूआत वर्ष 2000 से हुई थी, में भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री 4-7 दिसंबर, 2005 तक रूस की यात्रा पर गए। 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने पहले तो प्रतिबंधित बैठक में तथा उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन से विस्तार से वार्ता की। उन्होंने रूसी परिसंघ के रक्षा, ऊर्जा और उद्योग मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें की। उनके दौरे के कार्यक्रमों में मास्को राजकीय विश्वविद्यालय में भाषण देना भी शामिल था। राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर स्तरीय बैठकों के बाद जो तीन करार संपन्न किए गए वे इस पुकार हैं : (i) सैन्य-तकनीकी सहयोग पर करार, (ii) शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ग्लोनास प्रणाली के संयुक्त विकास, संचालन और उपयोग के क्षेत्र में दीर्घावधि सहयोग को क्रियान्वित करते हुए सुरक्षोपाय प्रौद्योगिकियों पर करार, (iii) कोरोनास-फोटोन परियोजना की रूपरेखा के भीतर सौर भौतिकी और सौर पृथ्वी संबंधों के क्षेत्र में सहयोग पर इसरो और रूसी परिसंघ के परिसंघीय अंतरिक्ष अभिकरण के बीच करार।

हाल ही में हुई प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा के समय की गई वचनबद्धता के अनुसार विश्व व्यापार संगठन पर रूस के साथ करार पर चल रही बातचीत को अन्तिम रूप देने के लिए वाणिज्य सचिव 20-24 जनवरी, 2006 तक रूस की यात्रा पर गए।

रूस के व्यापार एवं आर्थिक विकास मंत्री श्री जर्मन ग्रेफ 4-7 फरवरी, 2006 तक भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान विश्व व्यापार संगठन संबंधी करार संपन्न हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी पर दोनों देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ बनाने की संभावनाओं की खोज करने हेतु श्री ग्रेफ बंगलौर भी गए।

भारतीय संसद के निमंत्रण पर रूसी डूमा के अपर हाऊस के अध्यक्ष श्री मिरोनोव 26 फरवरी से 1 मार्च, 2006 तक भारत यात्रा पर आएंगे।

प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर रूस के प्रधान मंत्री श्री फ्रादकोव 16-17 मार्च, 2006 तक भारत यात्रा पर आएंगे।

रूस के उप विदेश मंत्री श्री किस्ल्याक भी फरवरी के अंत अथवा मार्च, 2006 के शुरू में भारत आएंगे।

भारत, रूस और चीन के व्यापार समुदायों के बीच त्रिपक्षीय बैठक के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं जैसा कि विदेश मंत्री स्तर की त्रिपक्षीय बैठक में निर्णय लिया गया था यह बैठक मार्च, 2006 के अंत तक होगी।

अर्मेनिया

अर्मेनिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में अक्तूबर में हुई उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शोखावत की यात्रा के साथ और अधिक मजबूती आई। उपराष्ट्रपति ने अर्मेनिया के प्रधानमंत्री को 60 सोनालिका भारतीय ट्रेक्टरों (300 टैक्टरों के कुल उपहार पैकेज में से) शिपिंग दस्तावेज प्रदान किया। यात्रा के दौरान दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए; एक तो मैत्री और सहयोग की द्विपक्षीय संधि के अनुसमर्थन दस्तावेज के आदान-प्रदान का प्रोतोकोल तथा दूसरा दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

मानव संसाधन विकास मंत्री के निमंत्रण पर अर्मेनिया गणराज्य के विज्ञान एवं शिक्षा मंत्री श्री सेर्गो येरित्स्यान 3-12 दिसंबर, 2005 तक भारत यात्रा पर आए।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग पर भारत अर्मेनिया संयुक्त आयोग की बैठक शीघ्र ही होनी है।

अज़रबैजान

भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर जून, 2005 में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बाकू गए। श्री अय्यर 12 वें कैस्पियन अंतराष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन के प्रथम प्लेनरी सत्र में अतिथि वक्ता थे। भेषजों और फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात संवर्धन के लिए नवंबर में एक फार्माक्सिल प्रतिनिधिमंडल बाकू गया। वायु-संपर्क स्थापित होने के बाद से अज़रबैजान एयरलाइन अब बाकू-दिल्ली के बीच सप्ताह में दो उडानों का संचालन करती है।

सांस्कृतिक क्षेत्र में मणिपुरी पुंग ढोल चोलम नृत्य मंडली ने सितंबर में अज़रबैजान के विभिन्न शहरों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। बाकू में हिंदी फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया गया। बाकू में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष नवंबर में "भारत-यूरेशिया आगे का मार्ग" पर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भारत आए और उन्होंने चंडीगढ़ में कौकेशियन अध्ययन केंद्र में व्याख्यान दिया।

अजरबैजान के वित्त मंत्री श्री अवाज अलाकबरोव, अजरबैजान के उप वित्तमंत्री श्री अजेर बायरामोव के साथ 9-12जनवरी, 2006 तक भारत की यात्रा पर आए। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री तथा वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

भारत और अजरबैजान के बीच व्यापार, आर्थिक एवं वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग पर संयुक्त आयोग से संबंधित करार पर हस्ताक्षर करने तथा आयोग की प्रथम बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए वाणिज्य राज्य मंत्री श्री ई वी के एस इलंगोवन मध्य मार्च में अजरबैजान जाएंगे, उनकी यात्रा की तैयारी चल रही है।

बेलारूस

भारत और बेलारूस ने हार्दिक और घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखा। लोकसभा उपाध्यक्ष श्री चरणजीत अटवाल 12 सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने 23-28 मई, 2005 तक बेलारूस की यात्रा पर गए। उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत राष्ट्रपति अलेक्सांदेर लुकाशेंको के साथ बातचीत करने बेलारूस गए। दोनों पक्षों ने आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता पर एक संधि संपन्न की। सी आई आई ने 26-30 अगस्त, 2005 तक मिंस्क में "उद्यम भारत" नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। अप्रैल में मिंस्क में "भारत के भिन्न-भिन्न रंग" विषय पर भारतीय फिल्म और फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बेलारूस की संगीत

6 दिसम्बर, 2005 को मास्को में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतीन।

अक्टूबर 2005 में येरेवन में उप-राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत का स्वागत करते हुए अर्मेनिया के राष्ट्रपति श्री रॉबर्ट कोचारियां।

अकादमी को भां. सां. सं. प. द्वारा प्रायोजित 18 भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों का एक सेट भेंट किया गया।

व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्राद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-बेलारूस संयुक्त आयोग का तृतीय सत्र शीघ्र ही मिंस्क में होने की उम्मीद है।

जॉर्जिया

जॉर्जिया के साथ भारत के संबंध घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण बने रहे। अप्रैल में सी आई आई ने त्बिलिसी में "उद्यम भारत 2005 प्रदर्शनी" का आयोजन किया। भारतीय फार्मास्यूटिकल्स निर्यात संवर्धन परिषद से एक प्रतिनिधिमंडल त्बिलिसी गया और उत्पादक एवं सफल व्यापार बैठक में भाग लिया जिसका उद्घाटन जॉर्जिया के उप स्वास्थ्य मंत्री ने किया था।

कजाकस्तान

फरवरी, 2005 में भारत-कजाख संयुक्त आयोग के एक निर्णय के परिणामस्वरूप गठित हाइड्रोकार्बन पर भारत-कजाकस्तान संयुक्त कार्यदल की प्रथम बैठक अप्रैल में अस्ताना में हुई। के एम जी ने कैस्पियन सागर में दो महत्वपूर्ण तटीय तेल भंडारों पर ओ वी एल को आंकडे प्रस्तुत किए। राष्ट्रपति नजरबायेव और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बीच पहली मुलाकात 8 मई, 2005 को मास्को में, विजय दिवस की 60 वीं जयंती के समारोहों के अवसर पर हुई। जुलाई में अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत को एस सी ओ के पर्यवेक्षक के रूप स्वीकार किया गया। शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री ने भारत और मध्य एशिया के बीच अधिक घनिष्ठ आर्थिक सहयोग की स्थापना के महत्व पर बल दिया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर अपने कजाक समकक्ष से मिलने अक्तूबर में अल्माती गए जिनके साथ उन्होंने 13 वीं कजाकस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस प्रदर्शनी "किओजे 2005" का उद्घाटन किया। उन्होंने तेल एवं सम्मेलन, जिसमें ओ एन जी सी ने भाग लिया था में भाषण भी दिया। एशिया में अंतः क्रिया एवं विश्वासोत्पादक उपाय सम्मेलन के विशेष कार्यदल की बैठक अगस्त में अलमाती में हुई जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की बैठक हुई।

भारत से राष्ट्रीय रक्षा कालेज का 16 सदस्यीय दल मई में कजाकस्तान की यात्रा पर गया। वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर विदेश कार्यालय परामर्श अस्ताना में अगस्त में हुए। भारतीय पक्ष का नेतृत्व सचिव (पूर्व) ने किया और कजाक पक्ष का नेतृत्व उप विदेश मंत्री ने किया। यात्रा के दौरान सचिव (पूर्व) ने अल्माती में कजाकस्तान राष्ट्रीय ग्रंथागार में भारत अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया।

भारतीय भोजन महोत्सव, जो अवधी भोजन पर केंद्रित था, मई में अलमाती में हयात रीजेंसी होटल में आयोजित किया गया, इसके साथ फोटो प्रदर्शनी, भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों की प्रदर्शनी वेशभूषा तथा हस्तकला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। 1955 में हुई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अल्माती यात्रा की 50 वी जयंती का आयोजन राजदूतावास ने 17 जून को किया इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन कजाकस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा किया गया और अल्माती के राष्ट्रीय ग्रंथागार में एक फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस अवसर की यादगार के लिए कजाक डाक ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया।

जून में अल्माती में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के दौरान सी आई आई और काजीन्वेस्ट ने दोनों संगठनों के बीच द्विपक्षीय वाणिज्यिक एवं व्यापार सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर भारत कजाकस्तान संयुक्त कार्यदल की द्वितीय बैठक 20-21 मार्च, 2006 को नई दिल्ली में होगी।

किर्गीजस्तान

किर्गीजस्तान के साथ संबंध घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण बने रहे। भारत ने नई सरकार का स्वागत किया जिसने राष्ट्रपति कुर्मान्बेक बाकीव के नेतृत्व में भारत के साथ सहयोग को मजबूत बनाने में रूचि अभिव्यक्त की। सितंबर में भारत ने किर्गीजस्तान में घटित प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी। नवंबर में किर्गीज रक्षा मंत्री की भारत यात्रा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए वार्ता प्रारंभ करने में सफल रही।

द्विपक्षीय व्यापार सीमित है लेकिन 49.31 मिलियन अमरीकी डालर के वार्षिक टर्नओवर के साथ बढ़ रहा है। परिधान और वस्त्र मुख्य रूप से किर्गीज़स्तान को भारतीय निर्यात किए गए। एक कैमेक्सिल प्रतिनिधिमंडल जुलाई में किर्गीजस्तान गया और क्रेता - विक्रेता सम्मेलन में भाग लिया। असैनिक प्रशिक्षण के लिए आईटेक स्लाटों का पूर्ण रूपेण उपयोग किया गया। सांस्कृतिक क्षेत्र में, दो भारतीय फिल्म महोत्सवों का आयोजन किया गया, पहला बिश्केक में सितंबर में तथा दूसरा तालास में नवंबर में।

5 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रपति भवन में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आई.ए. कस्मिोव और श्रीमती करिमोव का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह।

4 अक्टूबर, 2005 को मिस्क में उप-राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत का स्वागत करते हुए कौंसिल ऑफ दी रिपब्लिक ऑफ दी नेशनल असेम्बली ऑफ बेलारूस के अध्यक्ष।

ताजिकिस्तान

भारत और ताजिकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध निरंतर प्रगति के पक्ष पर अग्रसर रहे। 2003 में प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान संपन्न राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा पर द्विपक्षीय करार 1 जुलाई, 2005 को प्रभावी हुआ। व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत - ताजिक संयुक्त आयोग का दूसरा सत्र दुशान्बे में जुलाई में हुआ जिसकी सह अध्यक्षता भारतीय वाणिज्य सचिव और ताजिक आर्थिक और व्यापार मंत्री ने की। द्विपक्षीय व्यापार करार के अंतर्गत भारत सरकार से 0.6 मिलियन अमरीकी डालर द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित फलों के रस के प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन अप्रैल में हुआ। एन डी ए खडकवासला में प्रवेश के लिए ताजिक कैडेटों को प्रशिक्षित करने हेतु पिछले दल के स्थान पर अगस्त में नया सैन्य प्रशिक्षण दल भेजा गया। वरिष्ठ ताजिक सैन्य अधिकारियों ने भी आईटैक कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पावधि पाठ्यक्रम में भाग लिया।

हिमाचल प्रदेश वन एवं वन्यजीवन विभाग ने कई जंगली जानवर दुशान्बे प्राणिउद्यान को उपहार में दिए।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत-ताजिकिस्तान संयुक्त कार्य दल की प्रथम बैठक 9-10 जनवरी, 2006 को दुशान्बे में हुई। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व अपर सचिव (अंतर्राष्ट्रीय संगठन) ने किया जबकि ताजिक पक्ष का नेतृत्व उनके उप विदेश मंत्री ने किया। बैठक के अंत में समान हितों और सहमत बिंदुओं से युक्त एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए।

तुर्कमेनिस्तान

1 अक्तूबर, 2005 को अश्गाबात में मार्गस्थ विराम के दौरान उपराष्ट्रपति श्री भैरौसिंह शेखावत और उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल ने तुर्कमेनिस्तान की संसद के प्रधान तथा वहां के विदेश मंत्री से संक्षिप्त बातचीत की। सचिव (पूर्व) 16-18 अक्तूबर, 2005 तक विदेश कार्यालय परामर्शों के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अश्गाबात गए। तुर्कमेनिस्तान के तेल एवं गैस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा विदेश मंत्रियों के साथ वार्ताएं हुई और तेल एवं गैस, टी ए पी गैस पाइप - लाइन परियोजना, ऊर्जा पर संयुक्त कार्य दल, संयुक्त आयोग की बहाली, ऋण, श्रृंखला, अजंता फार्मा का संयुक्त उद्यम (तुर्कमेनिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ), नागर विमानन, वीजा व्यवस्था, त्रिपक्षीय पारगमन करार, बी आई पी पी ए का आई आर, आईटैक कार्यक्रम, पी सी एफ डी, भा. सां. सं. प. की छात्रवृत्ति योजना और भारत में उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक बातचीत की गई। भा. सां. सं. प. द्वारा प्रायोजित दस सदस्यीय भंगड़ा और गिद्दा नृत्य मंडली ने स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान कला की प्रस्तुति की। इस अवसर पर कई गणमान्य तुर्कमान अतिथि भी मौजूद थे। सूचना प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी भाषा में अल्पावधि आईटैक कार्यक्रम के तहत 26 तुर्कमान राष्ट्रिक भारत आए।

तुर्कमेनबाशी आयल रिफाइनरी के प्रमुख श्री ए. के. पुडाकोव और तुर्कमेनिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री 25 नवंबर, 2005 को एशियाई तेल मंत्रियों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भारत आए।

उक्रेन

भारत और उक्रेन के बीच विदेश कार्यालय परामर्श कीव में मई में हुए इनमें सचिव (पूर्व) की अध्यक्षता में तथा उक्रेनी उप विदेश मंत्री के नेतृत्व में, दो शिष्टमंडलों ने भाग लिया। राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम ने जून, 2005 में उक्रेन की राजकीय यात्रा की। उक्रेनी पक्ष के साथ व्यापार, आर्थिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग का संवर्धन करने पर बातचीत हुई। मानकीरण और मापविज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग पर दो करार संपन्न हुए। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने उक्रेन के विद्वानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की और प्रनिप्रोपेट्रोबस्क शहर में यूजोव के सैटेलाइट डिजाइन कार्यालय में गए।

दस्तकारी निर्यात संवर्धन परिषद ने उक्रेनी आयातकों के साथ सितंबर, 2005 में एक क्रेता - विक्रेता मेले का आयोजन किया। नवंबर, 2005 में फूड एक्सपो में भारतीय टी बोर्ड ने भाग लिया। भारत-उक्रेन अंतर्सरकारी आयोग के व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर कार्य दल की बैठक दिल्ली में 13 फरवरी, 2006 को हुई।

उजबेकिस्तान

भारत और उजबेकिस्तान के संबध परंपरागत हार्दिकता से पूर्ण रहे। उजबेक राष्ट्रपति अप्रैल में भारत की राजकीय यात्रा पर आए, उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में आर्थिक मामले, विदेशी मामले, उच्चतर शिक्षा एवं सामाजिक मामलों के प्रभारी उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री भी आए थे। द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित वार्ताओं में तेल एवं गैस और फार्मास्यूटिकल्स

और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, अंतर संसदीय संबंधों में घटनाक्रम, अतंर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय गतिविधियों के बीच सैन्य और सैन्य तकनीकी क्षेत्र, संस्कृति, लघु एवं निजी उद्यम का समर्थन, शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदान कार्यक्रम पर करार संपन्न किए गए। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के अन्य क्षेत्रों में आठ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया जिसमें उजबेकिस्तान ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करने की अभिव्यक्ति की। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की रोकथाम पर संयुक्त कार्य दल की द्वितीय बैठक 31 अक्तूबर, 2005 को नई दिल्ली में हुई। उजबेक लेजिस्लेटिव चेंबर (लोअर हाउस) के अध्यक्ष के नेतृत्व में छह सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल नवंबर, 2005 में भारत यात्रा पर आया।

द्वितीय भारत व्यापार प्रदर्शनी ताशकंद में सितम्बर 2005 में हुई। इस अवधि के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री उजबेकिस्तान गए। आइटैक कार्यक्रम के अंतर्गत उजबेकिस्तान को 90 स्लॉट आवंटित किए गए।

भा. सां. सं. प. द्वारा प्रायोजित गणमान्य अतिथि कार्यक्रम के तहत लाल बहादुर शास्त्री जन्म शताब्दी के दौरान शास्त्री स्कूल आफ ताशकंद से छह सदस्यीय दल भारत यात्रा पर आया। लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फार इंडियन कल्चर, ताशकंद द्वारा नियमित नृत्य संगीत, योग, भाषा एवं भारतीय अध्ययनों की कक्षाएं आयोजित की गई। भारतीय विश्व विद्यालयों में उच्चतर अध्ययनों के लिए सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उजबेक विद्यार्थियों को अठारह छात्रवृत्रियां प्रदान की गई।

■■

5 खाड़ी, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका

खाड़ी क्षेत्र

खाड़ी क्षेत्र को एक प्रमुख आर्थिक भागीदार के रूप में उभरने, 40 लाख भारतीयों द्वारा वहां जाकर बसने और तेल एवं गैस का एक प्रमुख स्रोत होने के तथ्य को स्वीकार करते हुए सरकार ने "पश्चिमोन्मुख" नीति का अनुगमन किया है। यह वर्ष बढ़ते तालमेल, व्यापार एवं आर्थिक संबंधों और जी सी सी देशों के साथ एफ टी ए के लिए बातचीत शुरू करने के लिए स्मरण किया जाएगा। खाड़ी देशों से इस वर्ष दो महत्वपूर्ण यात्राएं हुई। अप्रैल, 2005 में कतर के अमीर ने महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, ने भारत का दौरा किया तथा दो पवित्र मस्जिदों के अभिरक्षक एवं सऊदी अरब के शाह महामहिम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज अल सउद वर्ष 2006 के गणतंत्र दिवस समारोहों के मुख्य अतिथि रहे। कई अन्य उच्च स्तरीय दौरों का आदान-प्रदान भी हुआ। दिसंबर, 2005 में ओमान के साथ रक्षा सहयोगों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए; अगस्त, 2005 में कुवैत के साथ न्यायिक सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर हुए; अप्रैल, 2005 में कतर के साथ वायु सेवा के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और जुलाई, 2005 में बहरीन के साथ तथा सितम्बर, 2005 में ओमान के साथ प्रत्यर्पण संधियों के अनुसमर्थन-दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया। तृतीय भारत-जीसीसी राजनीतिक वार्त्ता सितम्बर, 2005 में न्यूयार्क में संपन्न हुई। भारत - जी सी सी औद्योगिक संगोष्ठी मार्च, 2006 के दौरान मस्कट में आयोजित करने की योजना है। सरकार, क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए खाड़ी देशों के साथ सहयोग करने को इच्छुक है। इसने खाड़ी और पश्चिमी एशिया के लिए एक विशेष दूत नियुक्त किया है। सरकार इराक में हो रही घटनाओं पर सावधानीपूर्वक नजर रख रही है और आशा करती है कि आ रही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इराकी जनता अपनी नियति अपने ही हाथों में अत्यधिक नियंत्रण में रखने में सफल होगी। सरकार ईराक के पुनर्निर्माण में सहायता करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

हाल के समय में, भारत का ईरान के साथ संबंधों में सामरिक आयाम भी जुड़ा है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री के स्तरों पर उच्च स्तरीय तालमेल, ऊर्जा क्षेत्रों में सुरक्षा एवं सामरिक क्षेत्रों में आदान-प्रदान, अफगानिस्तान के लिए पारगमन में सहयोग और व्यापार के खुलते नए क्षेत्र - इन सभी ने द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत किया है।

बहरीन

लोगों का लोगों के साथ संपर्कों के जरिए तथा व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्रों में और अधिक आदान-प्रदान होने के साथ भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं।

प्रत्यर्पण संधि पर भारत और बहरीन के बीच 16 जुलाई, 2005 को अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ; आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता के करार; और सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक सहयोग के करार पर दोनों देशों द्वारा जनवरी, 2004 में हस्ताक्षर किए गए।

ईरान

ईरान के तत्कालीन विदेश मंत्री डा. सैयद कमाल करजई ने संयुक्त आयोग की बैठक में सह-अध्यक्षता करने के लिए फरवरी, 2005 में भारत की यात्रा की।

ईरान के विदेश मंत्री मनुचेहर मोत्ताकी के आमंत्रण पर हमारे विदेश राज्य मंत्री ने 2-4 सितंबर, 2005 तक ईरान का दौरा किया। इस दौरे के दौरान, विदेश राज्य मंत्री ने राष्ट्रपति महमूद अहमदी - नेजाद से भेंट की और ईरानी मजलिस के सभापति डा. गुलाम अली हदाद-अदेल, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव डा. अली लारीजानी तथा विदेश मंत्री मोत्ताकी के साथ बैठकें कीं। द्विपक्षीय वार्त्ताओं में द्रवित प्राकृतिक गैस करार पर विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान भी शामिल था।

संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ईरानी मजलिस के सभापति डा. गुलाम अली हदाद-अदेल ने 28 फरवरी-4 मार्च, 2005 तक भारत का दौरा किया।

संयुक्त आयोग बैठक

भारत-ईरान संयुक्त आयोग के 14 वें सत्र की बैठक नई

दिल्ली में 21 ओर 22 फरवरी, 2005 को आयोजित की गई। ईरान के विदेश मंत्री डा. कमाल करजई और भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री के. नटवर सिंह ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, व्यापार, परिवहन और संचार,उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण-विकास, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; सूचना प्रौद्योगिकी तथा कोंसुली विषयों से संबंधित संयुक्त आयोग द्वारा स्थापित सात उप-समितियों में सहयोग के लिए व्यापक विचार-विमर्श किए गए। फिक्की और ईरानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 14 वें संयुक्त आयोग की बैठक के तर्ज पर संयुक्त व्यापार परिषद आयोजित की।

15 वें भारत-ईरान संयुक्त आयोग की बैठक 11-12 मार्च, 2006 को तेहरान में होनी निश्चित है। ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन एवं संचार, उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण विकास; संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और कोंसुली विषयों के क्षेत्र में दोनों देश विचार विमर्श करेंगे।

सुरक्षा एवं सामरिक परामर्श

दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् निकायों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सामरिक परामर्शों के ढांचे के अन्दर सांस्थानिक बनाया गया है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सचिव डा. अली लारीजानी ने 30-31 अगस्त, 2005 को भारत की एक कार्यविशेष यात्रा की। डा. लारिजानी ने श्री एम. के. नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से और प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री से भेंट की। भारत और ईरान के बीच सामरिक वार्त्ता का चतुर्थ दौर 1 मई, 2005 को आयोजित किया गया।

द्विपक्षीय व्यापार

पिछले वर्ष (2003-04 में 2.9 बिलियन डालर) की अपेक्षा 43.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराते हुए वर्ष 2004-05 में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 4.13 बिलियन अमरीकी डालर की हुई। द्विपक्षीय व्यापार में सर्वाधिक बड़ा मद ईरानी क्रूड तेल (वर्ष 2004-05 में 2.47 बिलियन अमरीकी डालर) के आयात का रहा। गत चार वर्षों के दौरान ईरान के लिए भारत के निर्यातों में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 के 700मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर तेल के अलावा व्यापार 970 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है। तेल को छोड़कर ईरानी निर्यात लगभग 410 मिलियन अमरीकी डालर रहा। वर्ष 2004-05 के दौरान ईरान को कुल भारतीय निर्यात 1.24 बिलियन अमरीकी डालर के निकट रहा जिसमें गैसोलिन और पैट्रो-केमिकल्स निर्यात लगभग 680 मिलियन अमरीकी डालर का शामिल है।

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग

द्विपक्षीय संबंधों में ऊर्जा क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में रेखांकित करते हुए वर्ष 2003 में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच ईरान से एल एन जी की खरीद करने और प्रस्तावित ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन की रूप-रेखा पर विचार-विमर्श जारी है।

नई दिल्ली में 6 जनवरी, 2005 को आयोजित तेल एवं गैस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग पर एशियाई मंत्रियों की प्रथम गोलमेज संगोष्ठी में ईरान के भूतपूर्व पैट्रोलियम मंत्री डा. बिजान जांगानेह ने भाग लिया। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के पैकेज पर दोनों देश सहमत हुए।

वर्ष 2009 से शुरू हो कर अगले 25 वर्षों की अवधि के लिए 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष एल एन जी आयात करने के समझौते को अन्तिम रूप देने के लिए पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस-मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर ने जून, 2005 में ईरान की यात्रा की।

ईरान - पाकिस्तान - भारत गैस पाइपलाइन पर भारत-ईरान तृतीय विशेष संयुक्त कार्य दल की बैठक 28-29 दिसंबर, 2005 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। परियोजना की संरचना, गैस-मूल्यांकन और अगली बैठकों की अनुसूची पर विचार-विमर्श किये गए।

भारत और ईरान, अफगानिस्तान के लिए समुद्र से होकर एक वैकल्पिक प्रवेश मार्ग को विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं जो कि अफगानिस्तान को मेलाक - जरांज - डेलाराम सड़क मार्ग हो कर जोड़ते हुए ईरान के चाह्बहार बंदरगाह से होकर है। अफगानिस्तान में भारत का सड़क निर्माण परियोजना प्रगति पर है जिसके लिए ईरान कार्य कर रहे लोगों को वीजा प्रदान कर, ईरान से कच्ची सामग्री के स्रोत का पता कर, बंदरगाह और पारगमन प्रदान कर रहा है।

इराक

30 जनवरी को हुए चुनावों और मई, 2005 में बनी संक्रमणकालीन सरकार के पश्चात, संविधान का प्रारूप तैयार कर 15 अक्तूबर, 2005 को हुए जनमत-संग्रह में उसका अनुसमर्थन और 15 दिसंबर, 2005 को हुआ संसदीय चुनाव-इराक की महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं। भारत इन सभी घटनाक्रमों का स्वागत करता है।

प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने इराक के राजनीतिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण में भारत की प्रतिबद्धता दुहराते हुए

संक्रमणकालीन सरकार के प्रमुख, प्रधान मंत्री डा. इब्राहिम अल-जाफरी को बधाई संदेश भेजा। पश्चिमी एशिया के लिए विशेष दूत श्री सी. आर. गरेखान ने 22-25 मई, 2005 तक इराक की यात्रा की और प्रधान मंत्री से भेंट की और ईरान सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मिले। भारत ने जुलाई, 2005 में जार्डन में आयोजित बहुपक्षीय दाता समिति के बैठक में भाग लिया। ई यू/यू एस द्वारा ब्रसेल्स में 21-22 जून, 2005 को इराक पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह ने भाग लिया और इराक के पुनर्निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दुहरायी। वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व बैंक के तत्वावधान में संचालित दो इराकी न्यास कोषों के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर के भारतीय अंशदान का शेष 5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का भुगतान किया गया। डब्ल्यू एफ पी के सहयोग से इराकी स्कूली बच्चों को बिस्कूट देने की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में इराकी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कुवैत

प्रवासी भारतीय मामलों के राज्य मंत्री श्री जगदीश टाईटलर ने 12-13 अप्रैल, 2005 को कुवैत की यात्रा की। उन्होंने कुवैत में आयोजित श्रम अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों तथा व्यापारियों से भेंट की। उन्होंने कुवैती प्राधिकारियों से भी भेंट की।

पश्चिमी एशिया तथा मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के विशेष दूत श्री सी. आर. गरेखान ने 17-18 जून, 2005 तक कुवैत की यात्रा की और वहां के विदेश मंत्री डा. मोहम्मद सबाह अल-सलेम अल-सबाह से भेंट की।

कुवैत के न्याय मंत्री श्री अहमद याकूब बकर ने 15-17 अगस्त, 2005 तक भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के साथ बैठकें कीं। इस यात्रा के दौरान भारत और कुवैत के बीच सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक सहयोग के एक करार पर हस्ताक्षर किये गए।

कुवैत के अमीर महामहिम शेख जबर अल अहमद अल जबर अल-सबाह, जिनकी 15 जनवरी, 2006 को मृत्यु हो गई, की स्मृति में भारत सरकार ने 16 जनवरी, 2006 को राष्ट्रीय शोक घोषित किया। राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री ने कुवैत सरकार तथा लोगों को संवेदना संदेश भेजा। पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री मणिशंकर अय्यर संवेदना प्रकट करने के लिए 16 जनवरी, 2006 को कुवैत गए।

भारतीय निर्वासितों के लिए मुआवजे

1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान जिन भारतीय नागरिकों को जान एवं माल की हानियां हुई थी उन्हें मुआवजे का भुगतान करने के लिए 1991 में विशेष कुवैत कक्ष की स्थापना की गई थी। मुआवजे का भुगतान संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग, जिनेवा द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से प्राप्त मुआवजे की राशि का वितरण इस प्रयोजन के लिए नामित चार राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से किया जा रहा है।

दावे के आवेदनपत्रों की जांच करना और प्रत्येक मामले में भुगतान की मात्रा तथा भुगतान की समय-सीमा निर्धारित करना (अथवा किसी दावे को पूरी तरह अस्वीकार करना) पूर्णतया संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग की शासी परिषद, आयोग द्वारा अपनाई गई मुआवजा प्रक्रिया के अनन्तिम नियमों के अनुच्छेद 40(4) के तहत संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के निर्णय अन्तिम होते हैं तथा तात्विक, प्रक्रियात्मक अथवा किसी अन्य आधार पर पुनरीक्षा अथवा अपील के अध्यधीन नहीं होते।

1 अप्रैल 2005 से 10 जनवरी, 2006 तक की अवधि के बीच संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने व्यक्तिगत दावों की श्रेणी में लगभग 538 दावों के लिए 2729675.50 अमरीकी डॉलर की राशि अन्तरित की है। पिछले वर्ष में प्राप्त राशि, जो विभिन्न कारणों से असंवितरित पड़ी रही, इस अवधि के दौरान संवितरित की जाती रही। चार नामित बैंकों द्वारा 542 दावेदारों को कुल 3825874.24 अमरीकी डॉलर की राशि संवितरित की गई। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

श्रेणी	**दावों की संख्या**	**भुगतान की गई राशि (अमरीकी डॉलर में)**
क	342	650,500.00
ग	182	963950.05
घ	18	2211424.19
कुल	**542**	**3825874.24**

मई, 2005 में भारत से गए एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने जेनेवा में यू एन सी सी के अधिकारियों से भेंट की और मुआवजे के लिए दावे प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी, 1996 को बढ़ाने की मांग की। किन्तु चूंकि आयोग को

सितम्बर, 2006 तक अपना कार्य समाप्त कर लेना था अतः अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना संभव नहीं हो सका। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यू एन सी सी से क और ग श्रेणी के अन्तर्गत मुआवजे के असंवितरीत दावे और पता न लग सकने वाले दावों की समेकित सूची मांगी और प्राप्त की। अब मंत्रालय मुआवजा प्रक्रिया समाप्त करने की प्रक्रिया में है।

ओमान

भारत और ओमान सल्तनत के बीच संबंधों में निरन्तर प्रगति हुई है। वर्ष 2005 भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ थी। इसे समारोहपूर्वक मनाने के लिए मस्कट स्थित भारतीय दूतावास द्वारा तथा नई दिल्ली स्थित ओमान दूतावास द्वारा कई समारोह आयोजित किये गए।

1 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश से बनने वाला ओमान - भारत उर्वरक परियोजना (ओमिफ्को) का जनवरी, 2006 में उद्घाटन किये जाने की आशा है। ओमान के रक्षा मंत्री श्री सय्यीद बदर बिन सउद बिन हरेब अल बुसैदी ने 5-7 दिसंबर, 2005 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

दिसंबर 2004 में हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन - दस्तावेजों का औपचारिक रूप से नई दिल्ली में 14 सितम्बर, 2005 को आदान-प्रदान किया गया।

कतर

कतर राज्य के अमीर शेख, हमद बिन खलीफा अल थानी द्वारा प्रथम उप प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री तथा वित्त मंत्री के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 13-15 अप्रैल, 2005 को भारत के किए गए शासकीय दौरे ने द्विपक्षीय संबंधों में एक नया आयाम दिया।

द्विपक्षीय वार्त्ता में तेल एवं गैस, नागर विमानन, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और रक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस यात्रा के दौरान दोनों के बीच एक वायु सेवा करार पर हस्ताक्षर किए गए।

कतर के विदेश राज्य मंत्री श्री अहमद बिन अब्दुल्लाह अल - महमूद के नेतृत्व में एक बहु-क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल ने 19-24 जून, 2005 तक भारत का दौरा किया। द्विपक्षीय विचार-विमर्श व्यापार, औद्योगिक निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग करने पर केंद्रित थी।

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 20 और 21 नवंबर, 2005 को दोहा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पैट्रोलियम टेक्नोलॉजी कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए कतर का दौरा किया।

कतर राज्य की प्रथम महिला मोहतरमा शिखा मोजाह बिन्त नस्र अल-मिस्नेद ने 6-9 फरवरी, 2006 को भारत की यात्रा की।

सऊदी अरब

संयुक्त आयोग के छठे सत्र की बैठक (जे सी एम) 12 अप्रैल, 2005 को रियाद में संपन्न हुई। संयुक्त आयोग की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने की। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर ने अप्रैल, 2005 तथा नवंबर, 2005 में रियाद का दौरा किया।

दो पवित्र मस्जिदों के अभिरक्षक, महाराज फहद बिन अब्दुल अजीज अल सउद की मृत्यु पर भारत ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया और संसद के दोनों सदनों में उनके निधन पर संवेदना प्रकट की गई। राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री ने संवेदना संदेश भेजा। भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री स्व. पी. एम. सईद ने उनकी अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

दो पवित्र मस्जिदों के अभिरक्षक शाह अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज अल सउद ने 24-27 जनवरी, 2006 तक भारत की यात्रा की। उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी था जिसमें विदेश मंत्री, वित्त, पैट्रोलियम, श्रम एवं सांस्कृतिक और सूचना मंत्री शामिल थे। इस यात्रा के दौरान - द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं सुरक्षा करार, दोहरा कराधान से बचने पर करार, युवा एवं खेल-कूद के क्षेत्र में सहयोग पर करार और अपराध का मुकाबला करने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। महामहिम शाह अब्दुल्लाह और प्रधान मंत्री द्वारा एक दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया जिसमें भावी सहयोग के लिए एक कार्यसूची और भारत और सऊदी अरब के बीच भागीदारी की कल्पना की गई है।

महामहिम शाह गणतंत्र दिवस समारोहों के मुख्य अतिथि थें। यात्रा के दौरान, जामिया मिलिया इस्लामिया ने उन्हें मानद डाक्ट्रेट की उपाधि से विभूषित किया।

हज

हज, 2006 के लिए हज समिति तीर्थयात्रियों का कोटा 82,000 से बढ़ा कर 1,00,000 कर दिया गया। निजी टूर

आपरेटरों के माध्यम से अन्य 47,000 (लगभग) यात्रियों ने भी हज की यात्रा की जिससे हज, 2006 की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों की कुल संख्या बढ़ कर 1,47,000 हो गई, जो कि भारत के लिए हज तीर्थयात्रियों का पूर्ण अनुज्ञेय कोटा था। राज्य सभा के उप सभापति श्री के. रहमान खान और एक 23 सदस्यीय हज सद्भावना प्रतिनिधिमंडल जिसने 5-23 जनवरी, 2006 तक सऊदी अरब की यात्रा की थी, महामहिम शाह अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज अल - सउद से भेंट की। इससे पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 15-17 मई, 2005 तक सऊदी अरब की यात्रा की और हज - 2006 के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये।

हज 2006 के अंतिम दिन 12 जनवरी, 2006 को हुई भगदड़ में 56 भारतीय तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। मृतक के निकटतम संबंधियों को सऊदी अरब जाने और शवों को दफनाने की व्यवस्था करने के लिए हर संभव सहायता दी गई।

तत्कालीन विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह ने 6 जून, 2005 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय वार्षिक हज सम्मेलन का उद्घाटन किया।

निजी टूर संचालकों के पंजीकरण की पद्धति जो कि हज 2003 से शुरू हुई थी हज 2006 के लिए भी जारी रही।

संयुक्त अरब अमीरात

संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध घने और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। 29 अप्रैल, 2005 को तिरूवनन्तपुरम से एयर-इंडिया एक्सप्रेस के उद्घाटन के अवसर पर नागर विमानन राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल तथा केरल के मुख्य मंत्री श्री ओमेन चांडी ने आबु - धाबी की यात्रा की। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10-12 जुलाई, 2005 को संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। इसी प्रकार उत्तरांचल के मुख्यमंत्री श्री एन. डी. तिवारी ने 12-15 सितम्बर, 2005 को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। दिसंबर, 2005 में दुबई में आयोजित आई एम सी प्रायोजित भारतीय व्यापार शिखर सम्मेलन का भारतीय प्रवासी मामलों के मंत्री ऑस्कर फर्नान्डीज ने उद्घाटन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात का दिसम्बर, 2005 में दौरा किया। दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने "ग्लोबल विलेज, दुबई" के दिल्ली दिवस में भाग लेने के लिए 3-6 जनवरी, 2006 तक दुबई की यात्रा की।

शिक्षा मंत्री शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान ने निवेश के अवसरों को ढूंढ़ने के लिए अगस्त, 2005 में भारत की यात्रा की।

शेख मखतोउम, उप राष्ट्रपति तथा संयुक्त अरब अमीरात के प्रधान मंत्री तथा दुबई के शासक का 4 जनवरी, 2006 को देहावसान हो जाने पर भारत ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। राष्ट्रपति जी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति एवं आबु-धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जयेद अल नहयान को संवेदना संदेश भेजा। भारत के लोगों और सरकार की ओर से संवेदना प्रकट करने के लिए उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत विदेश राज्य मंत्री के साथ दुबई गए।

खाड़ी सहयोग परिषद

मंत्रिमंडल की व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति ने 27 जुलाई, 2005 को हुई अपनी बैठक में खाड़ी सहयोग परिषद (जी सी सी) के साथ भारत के कारोबार को बढ़ाने का निर्णय लिया।

22 सितम्बर, 2005 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 60 वें सत्र के समय तीसरी भारत-जी सी सी राजनीतिक वार्त्ता संपन्न हुई। जी सी सी पक्ष का नेतृत्व जी सी सी के अध्यक्ष के रूप में बहरीन के उप प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन मुबारक अल खलीफा ने किया जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व तत्कालीन विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह ने किया। जी सी सी के महासचिव ने बैठक में भाग लिया। वित्त, व्यापार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत - जी सी सी सांस्थानिक सहयोगों को बढ़ाने पर सहमति हुई। भारत और जी सी सी के बीच निजी क्षेत्र के पहल वाली आर्थिक वार्त्ता जारी रही। दूसरा भारत - जी सी सी औद्योगिक सम्मेलन मार्च, 2006 में मस्कट में होने की संभावना है।

पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका

वर्ष के दौरान, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ भारत के संबंध में आई महत्वपूर्ण प्रगति निरन्तर जारी है। कई उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान हुए हैं। इन देशों के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निवेश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इन देशों से आयात में भी वृद्धि हुई है। इस वर्ष इन देशों के लिए सांस्कृतिक दलों के दौरों की संख्या में भी पहले से वृद्धि हुई है।

अल्जीरिया

अल्जीरिया के साथ हमारे संबंध पारंपरिक रूप से घनिष्ठ एवं

26 जनवरी, 2006 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सऊदी अरब के बादशाह अबदुल्लाह बिन अब्दुल अजीज अल-सौद और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह। बादशाह इसके मुख्य अतिथि थे।

14 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर शहंशाह शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह।

सौहार्दपूर्ण बने रहे। एयर मार्शल पी. पी. राजकुमार, ए वी एस एम के नेतृत्व में नेशनल डिफेन्स कॉलेज का एक 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 15-20 मई, 2005 तक अल्जीरिया का अध्ययन दौरा किया।

संयुक्त राष्ट्र व्यापक सुधारों तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के मुद्दे पर अल्जीरिया के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए विशेष दूत श्री सैयद शहाबुद्दीन ने 26-28 जून, 2005 तक अल्जीरिया का दौरा किया।

कई भारतीय कंपनियों को अल्जीरिया में ठेके मिले हैं। 120 कि.मी. लंबी विद्युत संचरण लाइन का निर्माण 30 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से करने की एक महत्वपूर्ण परियोजना कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लि. ने हासिल की; 163 कि. मी. लंबी 3 एल पी ई कोटेड ऑनशोर पाइपलाइन्स की आपूर्ति 75 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से करने का ठेका वेलस्पन-गुजरात को मिला; 51.210 मिलियन अमरीकी डालर की कुल लागत से ट्रांसमिशन लाइन (400 के वी एकल सर्किट का) के निर्माण की दो परियोजनाएं मेसर्स के ई सी इंटरनेशनल लि. को दिया गया और शोधन के लिए नेशनल ऑयल कंपनी की तेल रिफाइनरी का आधुनिकीकरण, पुनर्निर्माण एवं उन्नयन के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर का ठेका इंजीनियर्स इंडिया लि. (ई आई एल) को दिया गया। अल्जीरिया में रिफाइनरियों का पुनर्निर्माण एवं बदलाव के लिए 3 मिलियन डालर की लागत का ठेका ई आइ एल को मिला।

आईटेक कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्जीरिया को 9 स्लाट आवंटित किये गए।

जिबूती

जिबूती के साथ द्विपक्षीय संबंध मित्रतापूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बने रहे। भारत के लिए जिबूती के प्रथम आवासी राजदूत के रूप में श्री युसुफ उमर दोउलेह को प्रत्यायित किया गया। जिबूती विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय उम्मीदवारी को समर्थन देना जारी रखा।

मिस्र

भारत और मिस्र के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों में प्रगति हुई है। मिस्र के एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री श्री एज्जाद साद ने 17 मई 2005 को नई दिल्ली में आयोजित फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन्स (एफ ओ सी) के पाचवें दौर में भाग लेने के लिए मिस्र के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। पश्चिमी एशिया तथा मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए भारत के विशेष दूत श्री सी. आर. गरेखान ने 20-22 नवम्बर, 2005 को मिस्र की यात्रा की और विदेश मंत्री श्री अबैल अल घीत तथा अरब लीग के महासचिव श्री आमरी मुसा के साथ वार्त्ता की।

रक्षा सचिव ने 2-4 जुलाई, 2005 के मिस्र का दौरा किया और पारस्परिक सहयोग के मुद्दों पर मिस्र के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया।

थल सेनाध्यक्ष ने 2-6 दिसम्बर, 2005 तक मिस्र की यात्रा की।

इस अवधि के दौरान वाना क्षेत्र में मिस्त्र भारत का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक एवं आर्थिक भागीदार बना रहा।

विभिन्न क्षेत्रों में भारत का मिस्र में 400 मिलियन डालर से अधिक का निवेश हुआ। अपर मिस्र में स्थित कारखाने में फॉस्फोरिक एसिड का उत्पादन करने के लिए भारतीय कृषक खाद सहकारी लि. (इफ्को) ने नवंबर, 2005 में 76 प्रतिशत इक्विटी की भागीदारी के साथ इंडो-इजिप्सीयन कंपनी बनाया। इसके लिए 325 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश की आवश्यकता है। पिछले वर्ष 432 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय निर्यात में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मिस्र को निर्यात किये गए थोक सामग्रियों में इंजीनियरी सामान जिसमें डीजल इंजन, पंप तथा वाहन शामिल हैं, टेक्सटाइल्स फाइबर एवं यार्न, प्लास्टिक्स एवं रबर की वस्तुओं के साथ - साथ रसायन तथा खाद भी शामिल है।

इजरायल

इजरायल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ एवं विकसित होते रहे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने 28-31 मई, 2005 तक इजरायल का दौरा किया। उन्होंने इजरायल के उप प्रधान-मंत्री श्री एहद ओलमर्ट के साथ भेंट की और एक संयुक्त अनुसंधान एवं विकास कोष (भारत-इजरायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पहल) बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत दोनों देशों की कंपनियों द्वारा संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु दोनों देश 1-1 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करेगा। दोनों पक्षों के बीच यह भी सहमति हुई कि नैनोप्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष तथा वैमानिकी, गैर परंपरागत ऊर्जा एवं जल के

क्षेत्रों में और अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त दल बनाया जाए।

वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर भारत-इजरायल विदेश कार्यालय परामर्श का 9 वां दौर 28 अगस्त, 2005 को जेरूसलम में संपन्न हुई। सचिव (पूर्वी) ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तथा इजरायल के उप प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री श्री सिल्वान शालोम से भी भेंट की।

शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री, कुमारी शैलजा ने "सहस्राब्दि के विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत लिंग तथा प्रवासन पर महिला नेताओं के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन" में भाग लेने के लिए 24-27 सितम्बर, 2005 तक इजरायल की यात्रा की।

प्रधान मंत्रियों की आर्थिक संगोष्ठी में शामिल होने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने 9-11 नवंबर, 2005 तक इजरायल का दौरा किया। श्री कमलनाथ ने अपने इजरायली समकक्ष उद्योग, व्यापार एवं श्रम मंत्री श्री एहद ऑल्मर्ट तथा वहां के वित्त मंत्री से मुलाकात की। उन लोगों ने द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक बढ़ावा देने की प्रणाली की रूपरेखा और भावी सहयोग क्षेत्रों को चिन्हित करने वाली संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट को स्वीकार कर जारी किया। 9 नवम्बर, 2005 को आयोजित प्रदर्शनी-इजरायल गेटवे 2005 में भारत ने भाग लिया।

जनवरी से अक्तूबर, 2005 के बीच समान अवधि में वर्ष 2004 की तुलना में 18.21% की वृद्धि दर्ज कर 2135.4 मिलियन अमरीकी डालर तक जा पहुंचा। कई इजरायली कंपनियों ने निर्माण और अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं भारत में स्थापित की। भारतीय कंपनियों ने भी इजरायल में अपना व्यापार स्थापित किया। भारतीय स्टेट बैंक को अपनी एक शाखा इजरायल में खोलने की अनुमति दी गई और वह वहां अपना कार्य आरंभ करने की प्रक्रिया में है।

कृषि, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री शरद पवार ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री इजाक राबिन की 10वीं पूण्यतिथि के स्मरणोत्सव के राज्य समारोह में भाग लेने के लिए 13-16 नवम्बर, 2005 तक इजरायल की यात्रा की। उन्होंने प्रधान मंत्री श्री एरीयल शेरान से मुलाकात की और इजरायल के कृषि मंत्री श्री इसरायल काट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

इजरायल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री एहुद बराक ने हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप इनीशियेटिव कांफ्रेंस को 16 नवम्बर को संबोधित किया और भारत में अपने प्रवास के दौरान प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की।

12 सितम्बर, 2005 को जारी वक्तव्य में भारत ने गाजा पट्टी से इजरायल की वापसी तथा सकारात्मक विकास के रूप में नार्दर्न वेस्ट बैंक के चार अधिवास तथा एक ऐसी प्रक्रिया आरम्भ होने का स्वागत किया जो संगत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों और रोडमैप के अनुसरण में परस्पर स्वीकार्य, तथा बात-चीत के जरिए समाधान ढूंढ़ने की पराकाष्ठा पर समाप्त होगी।

विशेष दूत, राजदूत सी. आर. गरेखान ने 14-16 नवंबर, 2005 को इजरायल की यात्रा की और इजरायल के कई नेताओं से मिले। 15 नवंबर, 2005 को जारी वक्तव्य में राफाह सीमा पर आवाजाही को खोलने, गाजा और वेस्ट बैंक के बीच यात्रा करने और गाजा पट्टी में एक समुद्री बंदरगाह का निर्माण करने से संबंधित फिलीस्तीनी प्राधिकारियों और इजरायल के बीच संपन्न आवागमन एवं पहुंच के करार का भारत ने स्वागत किया।

भारत, एम ई पी पी के सभी पहलुओं के संकल्प और "दी रोडमैप" का समर्थन करता है।

जार्डन

भारत और जार्डन के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे।

श्री सामी खासावनेह के नेतृत्व में जार्डन के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 19-23 अप्रैल, 2005 को भारत का दौरा किया और राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा लोक सभा अध्यक्ष से मुलाकात की।

मई, 2005 को जार्डन के प्रिंस हसन और दक्षिण आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव श्री बुतरस घाली ने लोकतांत्रिक मंच को संबोधित करने के लिए भारत की यात्रा की और प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री से भेंट की। नई दिल्ली में आयोजित "ससटेनेबल डिवलपमेंट" शिखर बैठक में भाग लेने के लिए प्रिंस अल हसन बिन तलाल ने 1-6 फरवरी, 2006 को भारत की यात्रा की।

भारत जार्डन के पोटाश और फास्फेट का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश बना रहा। भारत के लिए जार्डन से आयात की मुख्य वस्तुओं में खाद, फास्फेट और फास्फोरिक एसिड है।

169.5 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से शुरू होने वाला संयुक्त - उपक्रम फास्फोरिक एसिड कारखाना मेसर्स भारत-जार्डन केमिकल्स कंपनी भारत-जार्डन व्यापार सहयोग

में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह जार्डन का सबसे बड़ा संयुक्त-उपक्रम भी है। यह 15.4 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजना लागत से अबदून केबल स्टे ब्रिज का निर्माण के लिए ग्रेटर अम्मान की नगरपालिका ने मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो को ठेका दिया है।

लेबनान

विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 27 सितंबर-1 अक्तूबर, 2005 तक लेबनान की यात्रा की और राष्ट्रपति जनरल एमिले लाहुद, प्रधान मंत्री फुआद सिनिओरा और विदेश एवं कृषि मंत्रियों से भेंट की। इस दौरे का मकसद पूर्व प्रधान मंत्री रफीक हारिरी की बम विस्फोट में फरवरी, 2005 में मृत्यु हो जाने के पश्चात लेबनान में हुए राजनीतिक बदलाव के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों की महत्ता को रेखांकित करना था। आइटेक कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन के विकास के माध्यम से लेबनान को सहायता करने में भारतीय तैयारी से विदेश राज्य मंत्री ने लेबनान को अवगत भी कराया।

लेबनान में भारतीय शांति रक्षक सैनिक संयुक्त राष्ट्र के अन्तरिम बल का अंग है। लेबनान के प्राधिकारियों के लिए उनकी सेवाएं काफी महत्व रखती हैं।

लीबिया

एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 26-29 मई, 2005 को लीबिया का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री ने प्रधान मंत्री शुकरी धानेम, जनशक्ति, प्रशिक्षण और रोजगार मंत्री मातुग मोहम्मद मातुग, लीबिया की संसद के विदेश समिति के अध्यक्ष श्री शाहोमी और विदेश कार्यालय में अफ्रीकी मामलों के राज्य मंत्री श्री त्रीकी से भेंट की। उन्होंने लीबिया रक्षा प्रापण के प्रमुख जनरल अहमद महमूद तथा नेशनल आयल कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री बादरी से भी मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री ने ऊर्जा मंत्री डा. फाथी उमर बेन शतवान तथा लीबिया के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के अध्यक्ष उमरान अबु क्रा के साथ भी बैठक कीं।

विदेश राज्य मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह ने सीर्त में आयोजित ए यू शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 1-5 जुलाई, 2005 को लीबिया की यात्रा की। विदेश राज्य मंत्री ने वहां के विदेश मंत्री शलगाम के साथ भी बैठक की।

भारतीय विश्वविद्यालयों में 319 लीबियाई छात्रों का नामांकन करने के लिए एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लि.,नई दिल्ली (एड सी आई एल) और उच्च शिक्षा मंत्रालय, लीबिया के बीच 18 सितम्बर, 2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

एन आई आई टी, भारत ने लीबिया में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए लीबिया के मेसर्स स्टाकसाइड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया। आई-फ्लेक्स सालयूशंस, सेंट्रल बैंक ऑफ लीबिया तथा अन्य पॉच बैंकों के साथ कोर बैंकिंग की एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

भेल ने 600 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कार्य पूरा कर लिया है। इसकी पहली इकाई शुरू हो गई है और नवम्बर, 2005 से बिजली पैदा कर रही है। ऑयल इंडिया तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारियों की एक टीम ऑयल इंडिया के अध्यक्ष श्री आर. के. दत्ता के साथ 3-8 दिसम्बर, 2005 को लीबिया की यात्रा की और दो ब्लॉकों में तेल निकालने के लिए लीबिया नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन (एन ओ सी) के साथ कांट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर किया।

मोरक्को

भारत और मोरक्को के बीच संबंध पहले की तरह मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तथा सहयोगात्मक बने रहे। विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 23-25 मई, 2005 को मोरक्को की यात्रा की और वहा के नेताओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। उन्होंने महामहिम राजा मोहम्मद VI के साथ और साथ ही मोरक्को के प्रधान मंत्री द्रीस जेत्तु और वहां के विदेश मामलों के मंत्री-डेलीगेट श्री तैयब फास्सी फिहरी से भी मुलाकात की।

भारत सरकार के विशेष दूत श्री सैयद शहाबुद्दीन ने 22-24 जून, 2005 को मोरक्को की यात्रा की और प्रधान मंत्री द्रीस जेत्तु और विदेश मंत्री मोहम्मद बेनाइसा के साथ विचार-विमर्श किया।

भारतीय नौसेना का जहाज "आई एन एस तरंगिनी" ने 12-15 सितम्बर, 2005 को सद्भावना यात्रा पर तांजियर्स की यात्रा की।

वर्ष के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों का निरन्तर बढ़ना जारी रहा। टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने 200 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश कर पहले से विद्यमान भारत-मोरक्को संयुक्त उपक्रम कंपनी, इमासीड में भागीदार बन गया। भारतीय सिंथेटिक एवं रेयॉन टेक्सटाइल्स निर्यात संवर्धन परिषद ने मोरक्को में 22 और 23 दिसम्बर, 2005 को

26 मई, 2005 को रबत में विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद से मुलाकात करते हुए मोरक्को के राजा बादशाह मोहम्मद VI।

19 मई, 2005 को नई दिल्ली में फिलीस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद अब्बास के साथ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह।

एक एक्सक्लूसिव भारतीय टेक्सटाइल प्रदर्शनी-सह-क्रेता-विक्रेता मिलन का आयोजन किया।

ओडिसी विजन नामक एक आई सी सी आर द्वारा प्रायोजित ओडिसी नृत्य मंडली ने 2-9 जुलाई, 2005 को मोराकेच में आयोजित 40 वें राष्ट्रीय लोकप्रिय कला महोत्सव में प्रदर्शन किया।

जुलाई, 2005 में खुरीबगा में एक भारतीय सांस्कृतिक फिल्म सप्ताह का आयोजन किया गया।

फिलिस्तीन

फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ बढ़ते तालमेल के साथ, फिलिस्तीन के साथ द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। भारत फिलिस्तीन को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने विदेश मंत्री डा. नासर अल किदवा के साथ 19 और 20 मई, 2005 को भारत का दौरा किया और भारतीय नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया। इस यात्रा के दौरान फिलिस्तीन के पुनर्निर्माण परियोजना और मानवीय सहायता के लिए भारत ने 15 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की। फिलिस्तीनी प्राधिकारियों के साथ 6 परियोजनाओं पर विचार-विमर्श चल रहा है। इसमें शामिल है - नई दिल्ली में फिलिस्तीनी राजदूतावास भवन, रमाल्लाह में प्रधान मंत्री कार्यालय, गाजा में कार्डियक केन्द्र, आबु दिस में एक स्कूल और गाजा एवं अल कुद्स विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र। सचिव (पूर्वी) ने 27 अगस्त, 2005 को फिलिस्तीन की यात्रा की और राष्ट्रपति आबु माजेन, प्रधानमंत्री आबु आला, आन्तरिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जनरल नासर युसूफ तथा उप विदेश मंत्री अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह से मुलाकात की।

पश्चिमी एशिया तथा मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए विशेष दूत श्री सी.आर. गरेखान ने 17-20 नवम्बर, 2005 को फिलिस्तीन की यात्रा की।

आइटेक कार्यक्रम के अन्तर्गत फिलिस्तीन को 30 स्लॉट आवंटित किये गए।

सोमालिया

सोमालिया में आन्तरिक अस्थिरता रहने के कारण दोनों देशों के बीच तालमेल सीमित रहा। सितंबर, 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर न्यूयार्क में सोमालिया के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से भेंट की और उन्हें सोमालिया की राजनीतिक परिस्थिति एवं आर्थिक परिदृश्यों की जानकारी दी।

सूडान

सूडान की सरकार तथा सूडान पिपुल्स लिबरेशन मूवमेंट के बीच व्यापक शांति करार पर हस्ताक्षर के समय नैरोबी में आयोजित समारोह में 9 जनवरी, 2005 को विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस करार पर हस्ताक्षर हो जाने से दो दशकों से चले आ रही गृहयुद्ध समाप्त हो गयी और शांति की शुरूआत हुई।

अप्रैल, 2005 में विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने ओस्लो में आयोजित सूडान दाता सम्मेलन में भाग लिया और 10 मिलियन अमरीकी डालर अनुदान स्वरूप देने और 100 मिलियन अमरीकी डालर का रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट का वचन दिया। यू एन पीस मॉनीटर्स के रूप में दक्षिणी सूडान में 720 भारतीय सैनिक तैनात किये गए। भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़कर 2600 की अपनी पूर्ण संख्या प्राप्त कर लेने की संभावना है।

नार्थ एवं साउथ के बीच व्यापक शांति समझौता के अन्तर्गत बनी नेशनल यूनिटी की नई सरकार के नेताओं से मिलने तथा संयुक्त उपक्रम/सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक 18 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 6-7 नवम्बर, 2005 को सूडान की यात्रा की। विदेश राज्य मंत्री ने राष्ट्रपति उमर अहमद अल बशीर से भेंट की और ऊर्जा एवं खनन, कृषि तथा पर्यावरण के मंत्रियों और सूडान के विदेश राज्य मंत्री के साथ बैठकों में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने अपने दौरे की अवधि में दो दिनों का विस्तार किया और जूबा की यात्रा कर दक्षिणी सूडान की सरकार के नेताओं के साथ भी विचार-विमर्श किया।

हमारे गृह मंत्री के निमंत्रण पर सूडान के आन्तरिक मंत्री, मेजर जनरल (पी एस सी) अब्देल रहीम मोहम्मद हुसैन ने अपने राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में जनवरी, 2005 में भारत की यात्रा की।

सूडान के विदेश मंत्री डा. मुस्तफा उस्मान इस्माइल ने 7-9 जून, 2005 को भारत की यात्रा की। उन्होंने प्रधान मंत्री से मुलाकात की और विदेश मंत्री के साथ वार्ता में भाग लिया।

भारत-सूडान द्विपक्षीय व्यापार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 1999-2000 के 309.72 करोड़ रूपये से बढ़कर सूडान को भारत का निर्यात वर्ष 2003-04 में 493.41 करोड़ रूपया हो गया है।

सीरिया

विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 26-28 सितंबर, 2005 को सीरिया की यात्रा की। उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति डा. बशर अल-असाद, विदेश मंत्री श्री फारूक अल-शारा तथा उच्च शिक्षा मंत्री डा. हनी मुर्तदा से मुलाकात की। श्री अहमद ने सीरिया के राष्ट्रपति को भारत आने का पुनः निमंत्रण दिया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने 10-16 सितम्बर, 05 को सीरिया की यात्रा की और दमिश्क में आयोजित ऐफ्रो-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन सम्मेलन के 15 वें आम सभा में भाग लिया। ऐफ्रो-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के सहायक महासचिव के पद पर भारतीय उम्मीदवार सुश्री सीमा बहुगुणा का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया।

आई सी सी आर द्वारा प्रायोजित एक "समकालीन ग्राफिक" प्रदर्शनी सीरिया में अक्तूबर, 2005 में लगाई गयी।

भारतीय कंपनियों ने मई, 2005 में दमिश्क में आयोजित मार्बलस, सेरामिक्स तथा सीमेंट उत्पादों पर "टेक्नो-स्टोन 2005" नामक चौथे अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भागीदारी की। सीरियाई तेल एवं गैस क्षेत्र में ओ एन जी सी - विदेश लि. और चीन नेशनल पैट्रोलियम कॉरपोरशन ने संयुक्त रूप से पेटर-कनाडा के शेयर के लिए बोली लगायी और शेयर प्राप्त किया (शेल संचालित अल फूरात उपक्रम की 38% हिस्सेदारी)।

पश्चिमी एशिया तथा मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के विशेष दूत श्री सी. आर. गरेखान ने 19-21 जून, 2005 को दमिश्क की यात्रा की और द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्र की नवीनतम प्रगति एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों पर सीरिया के विदेश मंत्री श्री फारूक अल-शारा तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की।

भारत-सीरिया सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2003-06 के अन्तर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम अगस्त, 2005 में दमिश्क गई।

ट्यूनीशिया

अप्रैल, 2005 में ट्यूनीश में फार्मास्यूटिकल्स पर आयोजित भारत-ट्यूनीशिया संयुक्त कार्य दल की दूसरी बैठक में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

फार्मास्यूटिकल्स पर संयुक्त कार्य दल की तीसरी बैठक नवम्बर, 2005 में नई दिल्ली में संपन्न हुई। नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ट्यूनीशिया का दौरा किया और भारत तथा टयूनीशिया के बीच वायु-सेवा के करार पर हस्ताक्षर किये। टयूनीशिया में एक उर्वरक कारखाना लगाने के लिए अन्वेषणात्मक बात - चीत करने के लिए गुजरात राज्य उर्वरक निगम के एक प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई, 2005 में ट्यूनीशिया की यात्रा की। संचार तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानीधि मारन ने इंफोर्मेशन सोसायटी के विश्व शिखर-सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16-18 नवम्बर, 2005 तक ट्यूनीशिया की यात्रा की। दिसम्बर, 2005 के दौरान सिथेंटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने ट्यूनीश में भारतीय वस्त्रों की एक एक्सक्लूसिव प्रदर्शनी लगायी।

वर्ष 2005 के पहले 8 माह के दौरान ट्यूनीशिया को भारतीय निर्यात 70.92 मिलियन अमरीकी डालर का था जबकि ट्यूनीशिया से आयात 55.30 मिलियन अमरीकी डालर का रहा।

भारत - अरब लीग संबंध

भारत, अल्जीयर्स में 22 और 23 मार्च, 2005 को आयोजित अरब लीग शिखर बैठक में पर्यवेक्षक की हैसियत से भाग लिया। 5 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री ने किया। भारत और अरब लीग के बीच एक समझौता-ज्ञापन लागू है।

■■

6 अफ्रीका (सहारा से दक्षिण)

पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध और सुदृढ़ हुए। हाल के वर्षों में आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों में विस्तार हुआ है। अधिकतर अफीकी देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार पर्याप्त मात्रा में है। इस बात को स्वीकार किया जाता है कि भारतीय उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत सामान गुणवत्ता और लागत के हिसाब से प्रतियोगी हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण माना जाता है और व्यापक रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि अफ्रीकी देशों की प्रगति और विकास के लिए भारत उपयोगी साबित हो सकता है।

अनेक अफ्रीकी देश भारत में अपने राजनयिक मिशन खोल रहे हैं। अक्टूबर, 2005 में नई दिल्ली में लेसोथो का आवासी मिशन खोला गया जिसका उद्घाटन वहाँ के विदेश मंत्री ने किया। कोमोरोस ने नई दिल्ली में मानद प्रधान कोंसल का कार्यालय खोला है।

इस वर्ष अफ्रीका और भारत के बीच हुए अनेक उच्च स्तरीय दौरों में हमारे संबंधों की घनिष्ठता परिलक्षित हुई। शेसल्स के राष्ट्रपति ने जुलाई - अगस्त में भारत का दौरा किया। मारीशस के प्रधान मंत्री ने अक्तूबर में भारत की राजकीय यात्रा की। जाम्बिया की प्रथम महिला ने भा.सां.स.प. के निमंत्रण पर अक्तूबर में भारत की यात्रा की। दक्षिण अफ्रीका के लोक सेवा और प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने नवम्बर, 2005 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। दक्षिण अफ्रीका के विदेश उप-मंत्री ने भी दिसम्बर, 2005 में भारत का दौरा किया।

भारत से प्रधान मंत्री ने मार्च-अप्रैल, 2005 में मारीशस का दौरा किया। पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष ने अगस्त में उगांडा की यात्रा की। लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री ने अप्रैल, 2005 में मारीशस की राजकीय यात्रा की। विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अप्रैल में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए द्विपक्षीय संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन भारत और अफ्रीकी देशों के बीच संबंध मजबूत करने की दिशा में अगला कदम था। इस वर्ष जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ ऐसी बैठकें की गयीं। उसी प्रकार मारीशस और दक्षिण अफ्रीका के साथ विदेश कार्यालय परामर्श किये गये।

भारत द्विपक्षीय स्तर पर और आई बी एस ए वार्ता की रूपरेखा के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका के साथ घनिष्ठ सहयोग कर रहा है। आई बी एस ए को विकासशील विश्व में सहयोग के एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। भारत - पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा) समझौता ज्ञापन में किये गये उल्लेख के अनुसार घनिष्ठ और दीर्घावधिक आर्थिक संबंध बनाने पर दोनो पक्ष सहमत हुए हैं। मार्च, 2003 में एस ए डी सी मंत्रियों की परिषद द्वारा दक्षिण अफ्रीका विकास परिषद - भारत मंच का अनुमोदन किया गया ताकि भारत और इस उप क्षेत्र के बीच बेहतर क्रियाकलाप किया जा सके।

भारतीय सैनिक टुकड़ियाँ बुरूंडी, आयवरी कोस्कट, डी और कांगो, इथोपिया ओर एरीट्रिया जैसे वभिन्न अफ्रीकी देशों में चल रही शांति रक्षा कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इथोपिया और एरीट्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन (यू एन एम ई ई) बल के भाग के रूप में इथोपिया और एरीट्रिया की सीमा पर लगभग 1500 भारतीय सैनक तैनात हैं।

मार्च, 2005 से भारत को औपचारिक रूप से अफ्रीकी संघ में प्रत्यायित किया गया है और इसने इस संगठन के साथ अपने क्रियाकलापों को बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय और अफ्रीकी यूनियन ने अफ्रीकी देशों में ई - शिक्षा और टेलीमेडिसिन के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से 27 अक्टूबर, 2005 को पैन-अफ्रीकी नेटवर्क परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया।

अफ्रीकी देशों में मानव संसाधन विकास में सहायता करने के लिए भारत आइटेक, स्कैप और भा. सां. सं. प. छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत इन देशों के द्वारा मनोनीत छात्रों के

लिए अपनी छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त अलग-अलग देशों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर समय-समय पर विशेष पाठ्यक्रम भी चलाये जाते हैं।

सी आई आई और एक्जिम बैंक ने "भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी 2005 - एक्सपैंडिंग होरायजंस" पर नई दिल्ली में 6-8 नवम्बर, 2005 तक एक बैठक का आयोजन किया। यह एक अत्यंत सफल कार्यक्रम रहा। व्यावसायिकों और उद्यमियों के अतिरिक्त अफ्रीकी देशों के अनेक नेताओं ने इसमें भाग लिया।

बोत्सवाना

जैसा कि बोत्सवाना के राष्ट्रपति श्री मोगाए ने उल्लेख किया, भारत और बोत्सवाना के बीच संबंध "उत्कृष्ट" रहे। इस वर्ष रक्षा और नागरिक मामलों में सहयोग बढ़ा। श्री फेस्टस जी मोगाए ने मुम्बई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हीरा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मई 2005 में भारत का दौरा किया।

बुरूंडी

बुरूंडी में नेशनल असेम्बली के चुनाव 4 जुलाई, 2005 को हुए। पूर्व विद्रोही गुट सी एन डी डी - एफ डी डी को बहुमत (59 सीट) मिला। इस दल के नता श्री पियरे न्युरूजिजा को 19 अगस्त 2005 को बुरूंडी का राष्ट्रपति चुना गया। नयी सरकार का शपथ ग्रहण 26 अगस्त, 2005 को हुआ।

कोमोरोस

कोमोरोस संघ के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। सद्भावना प्रदर्शन के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत त्रिशूल ने 29 मई से 1 जून, 2005 तक पोर्ट मोरोनी (कोमोरोस संघ की राजधानी) की मैत्री यात्रा की।

एरीट्रिया

भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह ने एशियाई - अफ्रीकी शिखर सम्मेलन के दौरान अवकाश के क्षणों में 22 अप्रैल, 2005 को एरीट्रिया के अपने समकक्ष श्री अली सैद अब्देला के साथ मुलाकात की। एरीट्रिया के विदेश मंत्री ने एरीट्रिया के शिक्षा क्षेत्र में भारत के योगदान, जिसके अंतर्गत 600 भारतीय शिक्षक कार्यरत हैं, की प्रशंसा की और इथोपिया तथा एरीट्रिया के लिए यू एन मिशन के तहत इथोपिया के साथ लगने वाली एरीट्रिया की सीमा पर 1400 शांति रक्षक सैनिकों के लिए धन्यवाद दिया।

आइटेक कार्यक्रम 2005-2006 के तहत एरीट्रिया को पांच स्लाट आबंटित किये गये। भारत ने एरीट्रिया के रक्षा कार्मिकों के लिए 7 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया।

इथोपिया

भारत और इथोपिया के बीच सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। आतंकवाद में दोनों देशों के समान विचार हैं। इथोपिया में 150 भारतीय कंपनियों की उपस्थिति है और 300 मि. अमरीकी डालरों के निवेश का लक्ष्य है। आदिस अबाबा अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है।

भारत - ए यू पैन अफ्रीकी ई - नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत 2 मि. अमरीकी डालरों की लागत पर चलायी जाने वाले पहली पॉयलट परियोजना के लिए इथोपिया को चुना गया है।

केन्या

भारत और केन्या के बीच द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण और सहयोगी हैं। केन्या को किये जाने वाले भारतीय निर्यात में वर्ष 2004-2005 में 83.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल द्विपक्षीय व्यापार 71% बढ़कर 455 मि. अमरीकी डालर हो गया।

योजना एवं राष्ट्रीय विकास मंत्री प्रो. पीटर अनायंग न्यांगों ने 2-4 मार्च, 2005 तक नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीकी परियोजना भागीदारी पर बैठक में भाग लिया।

राष्ट्रीय धरोहर राज्य मंत्री श्री नजीब बलाला ने 5-7 जून, 2005 तक भा.सां.सं.प. के अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया।

परिवहन मंत्री श्री क्रिस्टोफर मुरूंगारू ने विश्व के 12 प्रमुख बंदरगाहों की अध्ययन यात्रा के भाग के रूप में केन्या बंदरगाह प्राधिकार के तीन अधिकारियों के साथ 28-29 अगस्त, 2005 तक न्हावाशेवा, मुंबई में जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह का दौरा किया।

रसायन एवं संबंधित उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद ने 29-30 मार्च, 2005 तक नैरोबी में क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया।

पर्यावरण एवं राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा ने 20-25 फरवरी, 2005 तक आयोजित यू एन ई पी शासी परिषद/ वैश्विक मंत्रिस्तरीय पर्यावरण मंच के 23 वें सत्र में और 24-25 अक्तूबर, 2005 तक नौरोबी में आयोजित मरूभूमिकरण के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के उच्च-स्तरीय खण्ड में भाग लिया।

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ ने 2-4 मार्च, 2005 तक मोम्बासा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की लघु मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।

उच्चायोग ने 3 अक्तूबर, 2005 को "क्या गांधीवाद आज के संघर्षरत विश्व के लिए सही मार्ग है" विषय पर नैरोबी स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। उच्चायोग ने "नेहरू, गुट-निरपेक्ष आंदोलन और आज का विश्व" विषय पर 14 नवम्बर, 2005 को नौरोबी स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक और संगोष्ठी का आयोजन किया।

लेसोथो

लेसोथो के विदेश मंत्री श्री मोनयाने मोलेलेकी ने 14 अक्तूबर, 2005 को लेसोथो के नये उच्चायोग का उद्घाटन किया।

लेसोथो ने कृषि उपकरण की खरीद के लिए सेसोथो को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 5 मि. अमरीकी डालरों के ऋण का उपयोग किया है।

मेडागास्कर

मेडागास्कर के साथ द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। मलागेसी विदेश मंत्री ले. जनरल मारसेल रनजेवा की 21-23 मार्च, 2005 तक की भारत यात्रा से द्विपक्षीय संबंध संवर्द्धित हुए। भारत सरकार ने यात्रा पर आये मलागेसी विदेश मंत्री के जरिए मलागसी के राष्ट्रपति श्री मार्क खालोमनाना को किसी सुविधाजनक तिथि पर भारत की यात्रा करने का निमंत्रण दिया।

मलावी

भारत और मलावी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। भारत सरकार के विशेष दूत श्री वी.के. ग्रोवर ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए 4-6 मई, 2005 तक लिलोंगवे का दौरा किया।

इस वर्ष के दौरान भारत ने आइटेक कार्यक्रम के अंतर्गत मलावी को 10 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जिनका उपयोग किया जा रहा है।

मारीशस

प्रधान मंत्री ने 30 मार्च से 2 अप्रैल, 2005 तक मारीशस का राजकीय दौरा किया। यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने "सायबर टावर" का उद्घाटन किया जिसका निर्माण भारत द्वारा दिये गये 100 अमरीकी डालरों के ऋण की सहायता से किया गया है। प्रधान मंत्री ने "स्वामी विवेकानन्द अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र" का भी उद्घाटन किया जिसका निर्माण 15 मि. अमरीकी डालर की लागत से किया गया; इसमें से आधा अनुदान और आधा ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

प्रधान मंत्री ने नेशनल असेम्बली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया। उच्च-स्तरीय आधिकारिक बातचीत के दौरान मारीशस विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के सर्वेक्षण में भारतीय सहायता, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मारीशस को ज्ञान का एक केन्द्र बनाने और इसके लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र के विकास सहित द्विपक्षीय सहयोग को और संवर्द्धित करने के अनेक उपायों पर चर्चा की गयी।

इस यात्रा के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग पर एक करार, द्विपक्षीय वायु सेवा करार से संबंधित समझौता ज्ञापन, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर करार और बेई डू टोम्बेयू मल व्यवस्था परियोजना के लिए एक्जिम बैंक की ऋण श्रृंखला पर करार भी संपन्न किये गये।

लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री श्री महावीर प्रसाद ने 8-12 अप्रैल, 2005 तक मारीशस की राजकीय यात्रा की।

समुद्री मामलों पर जारी द्विपक्षीय सहयोग के भाग के रूप में आई एन एस शारदा ने 20-23 अप्रैल तक मारीशस की यात्रा की। आई एन एस दिल्ली तथा आई एन एस त्रिशूल ने भी 21-24 जून तक मारीशस का दौरा किया।

3 जुलाई को मारीशस में हुए चुनाव के उपरांत सत्ता परिवर्तन हुआ। लेबर पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने चुनाव जीता और लेबर पार्टी के नेता डा. नवीन रामगुलाम को प्रधान मंत्री की शपथ दिलाई गयी। इस चुनाव के लिए चुनाव आयुक्त श्री एन गोपालस्वामी और उप चुनाव आयुक्त आनन्द कुमार पर्यवेक्षक थे।

विदेश सचिव श्री श्याम शरण ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए नये नेतृत्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा के लिए 23-25 अगस्त, 2005 तक मारीशस का दौरा किया।

भारत और मारीशस के बीच विदेश कार्यालय परामर्शों का पहला दौर 31 अगस्त को नई दिल्ली में हुआ। विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग मंत्री मदन मुरलीधर दुल्लू ने मारीशस के शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह ने किया।

दक्षिणी सैन्स कमान के जेनरल ऑफिसर कमान्डिंग इन चीफ

1 अगस्त, 2005 को नई दिल्ली में सिसल्स के राष्ट्रपति श्री जेम्स एलिक्स माईकेल के साथ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह।

24 अक्टूबर, 2005 को नई दिल्ली में मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचन्द्र रामगुलाम के साथ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह।

ले. जेनरल बी. एस. ठाकर, पी वी एस एम, वी एस एम ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए 3-6 अक्तूबर, तक मारीशस का दौरा किया।

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने भारतीय उच्चायोग के सहयोग से मारीशस में 19-23 अक्तूबर तक "भारत मेले" का आयोजन किया।

मारीशस के प्रधान मंत्री डा. नवीनचन्द्र रामगुलाम ने 23-28 अक्तूबर, तक भारत का राजकीय दौरा किया। उनके साथ उप प्रधान मंत्री तथा वित्त एवं विकास मंत्री श्री रामकृष्ण सीतानेन और विदेश, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा सहयोग मंत्री श्री मदन मुरलीधर डुल्लू भी आये। यात्रा के दौरान आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता पर करार, सजायाफ्ता कैदियों के अंतरण पर करार, जल सर्वेक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर करार, संबंधित एजेंसियों के बीच मानकों के सुमेलन पर समझौता ज्ञापन, उपभोक्ता संरक्षण और विधिक मापविद्या के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन, आई आई पी एस और मारीशस की सरकार के बीच एक एमझौता ज्ञापन और अधिमानी व्यापार करार की स्थापना से संबद्ध समझौता ज्ञापन संपन्न किये गये।

मोजाम्बिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मोजाम्बिक के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध और सुदृढ़ हुए। वर्ष 2004-2005 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 117 मि. अमरीकी डालरों (भारत से निर्यात 77 मि. अमरीकी डालरों का और मोजाम्बिक से आयात 40 मि. अमरीकी डालरों का) का हुआ। भारत से किये जाने वाले प्रमुख निर्यात थे चावल (बासमती को छोड़कर) दवाएं और भेषज, कार्बनिक कृषि रसायन, जूते और रबर के निर्मित उत्पाद, रसायन, परिवहन उपकरण, रेशम और सूती धागे तथा मोजाम्बिक से प्रमुख आयात थे काजू, कच्चा सूती, धातु स्क्रैप तथा चाय।

इस वर्ष मोजाम्बिक को कुल 20 स्कैप छात्रवृत्तियाँ आबंटित की गयीं जिनका पूर्णतः उपयोग किया गया।

नामीबिया

भारत और नामीबिया के बीच द्विपक्षीय संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण रहे। नामीबिया ने संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का निरंतर समर्थन किया है। इस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है। उच्च-स्तरीय क्रिया कलाप बनाए रखे गए। जून, 2005 में द्वितीय शिखर सम्मेलन के दौरान दोहा में उप - प्रधान मंत्री के साथ विदेश राज्य मंत्री की बैठक हुई।

मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत के सहयोग को नामीबियाई नेतृत्व द्वारा सराहा गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 40 नामीबियाई उम्मीदवारों ने स्कैप/आईटेक की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नौ (9) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की छात्रवृत्तियों का उपयोग किया गया।

जून, 2005 में टाटा के वाहनों का एक शोरूम नामीबिया में खुला।

5 से 10 दिसम्बर, 2005 तक नामीबिया के कृषि मंत्री, डॉ. निकी इयोम्बो ने भारत का दौरा किया।

रवांडा

भारत और रवांडा के बीच द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण और सहयोगी रहे। 2 से 4 जून, 2005 तक किगाली में हुए दसवें कोमेसा शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पॉल कगामे ने कोमेसा के राष्ट्रपति का पद भार संभाला।

सेशेल्स

सेशेल्स के राष्ट्रपति श्री जेम्स एलिक्स माइकल ने 31 जुलाई से 2 अगस्त, 2005 तक भारत का राजकीय दौरा किया। उन्होंने विभिन्न भारतीय नेताओं के साथ गंभीर विचार-विमर्श किया जिसके उपरांत द्विपक्षीय सहयोग के लिए अनेक क्षेत्रों की पहचान की गई। भारत ने 13 मिलियन अमरीकी डालर के वित्तीय सहायता पैकेज के साथ उनके आर्थिक सुधार कार्यक्रम का सर्मथन करने का वायदा लिया। जिसमें भुगतान संतुलन को पनर्स्थापित करने के लिए 5 मिलियन डालर और भारत से पण्यों की खरीद के लिए भारत के एक्जिम बैंक द्वारा 8 मिलियन डालर की राशि दी गई।

सेशेल्स राष्ट्रीय दिवस (18 जून) के अवसर पर आई एन एस त्रिशूल ने समारोहों में भाग लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया का दौरा किया। दक्षिण कमान के लेफ्टिनेंट जेनरल बी. एस. ठाकर के नेतृत्व में एक भारतीय रक्षा शिष्टमंडल ने क्षेत्रीय परामर्श दौरे पर अक्तूबर में सेशेल्स का दौरा किया। सेशेल्स के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सेशेल्स के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और मैसूर विश्विद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ताज समूह ने सेशेल्स में डेनिस द्वीप रिजॉर्ट के प्रबंधन और व्यापार का अधिग्रहण किया। एयरटेल (1998 से सेशेल्स की प्रमुख

सूडान के विदेश मंत्री डॉ. मुस्तफा ओस्मान इसमाइल ने 7 जून, 2005 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की।

नोबल पुरस्कार विजेता आर्चविशप डेसमंड टुटु 14 दिसम्बर, 2005 को बिल्डिंग पीस थ्रू डॉयलाग-रिजोल्विग डिफरेंसेज विषय पर बंगलौर में भा.सां.सं.प. द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए।

दूरसंचार कंपनी) ने माहे द्वीप पर ली मेरिडियन बारबेरॉनस होटल खरीदा।

सेशेल्स ने सात अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (अन्तर्राष्ट्रीय कानून आयोग, यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड, विश्व व्यापार संगठन की कार्यकारी परिषद, खाद्य एवं कृषि संगठन, आईएम ओ परिषद और इंटरपोल (एशिया) का उपाध्यक्ष और डब्ल्यू सी ओ परिषद्) में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

दक्षिण अफ्रीका

भारत के दक्षिण अफ्रीका के साथ घनिष्ठ और व्यापक द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। यह उन अफ्रीकी देशों में से है जहाँ भारतीय मूल के लोग अधिकतम संख्या में हैं। यह बहुपक्षीय मंचों, विशेषकर द्विपक्षीय आई बी एस ए मंच पर एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

पिछले दशक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक क्रियाकलापों में कई गुणा वृद्धि हुई है। रक्षा के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग है।

विदेश राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) ने द्विपक्षीय बैठक के लिए 1 से 5 अप्रैल, 2005 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया।

वान्डुंग सम्मेलन की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर 26 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रपति मबेकी ने विदेशियों के लिए दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च सम्मान - द ऑर्डर ऑफ द कंपेनियन्स ऑफ ओ आर टैम्बो से प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू को मृत्योपरांत सम्मानित किया। स्वर्गीय प्रधान मंत्री की ओर से यह सम्मान सांसद श्री राहुल गांधी द्वारा स्वीकार किया गया।

खनिज और ऊर्जा से संबद्ध पोर्टफोलियो समिति के एक दक्षिण अफ्रीकी संसदीय शिष्टमण्डल ने 30 जुलाई से 5 अगस्त, 2005 तक भारत का दौरा किया।

भूमि और पर्यावरण मामलों से संबद्ध संसदीय चयन समिति के एक 8 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने 7-12 अगस्त, 2005, तक भारत का दौरा किया।

दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक विकास और सामुदायिक विकास से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति के 16 सदस्यी शिष्टमण्डल ने 24-28 सितम्बर, 2005 तक भारत का दौरा किया।

संचार मंत्री डा. इवी मत्सेपे - कैसबरी ने 27-29 नवम्बर, 2005 तक भारत का व्यापक दौरा किया।

लोक सेवा और प्रशासन मंत्री सुश्री जेराल्डाइन जे फ्रेसेअर - मोलेकेती के नेतृत्व में एक मंत्रिस्तरीय शिष्टमण्डल 14-17 नवम्बर 2005 में भारत आया जिसका उद्देश्य इस विषय पर चर्चा करना था कि किस प्रकार भारत कौशल और मानव संसाधन की कमी को पूरा करने में दक्षिण अफ्रीका की सहायता कर सकता है। इस शिष्टमण्डल में प्रेसिडेंसी में मंत्री डा. इसोप पहद, संचार मंत्री श्री राधाकृष्ण एल पदयाची और शिक्षा उप मंत्री श्री ई सुर्ती भी शामिल थे।

दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है। जी - 4 के साथ सर्वसम्मति बनाने के लिए भी इसने निरंतर कार्य किया है।

स्वाजीलैंड

वर्ष 2004-05 के दौरान भारत और स्वाजीलैंड के बीच 24 मि. अमरीकी डालरों का द्विपक्षीय व्यापार हुआ जिसमें भारत से 21 मि. अमरीकी डालरों का निर्यात हुआ और स्वाजीलैंड से 3 मि. अमरीकी डालरों का आयात हुआ और स्वाजीलैंड को निर्यात की गयी मुख्य मदें थी दवाएं और भेषज, रंग, समुद्री उत्पाद, चाय, जूते, रत्न एवं आभूषण।

इस वर्ष के दौरान स्कैप के अंतर्गत स्वाजीलैंड को 5 छात्रवृत्तियाँ आबंटित की गयी हैं।

तंजानियाँ

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत और तंजानियाँ के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे। हाल के वर्षों में तंजानियाँ से चिकित्सा, पर्यटन, लोगों से लोगों के बीच क्रियाकलाप का महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। 75 प्रशिक्षण स्लाट्स के आबंटन के साथ तंजानियाँ आइटेक कार्यक्रम का प्रमुख लाभार्थी है।

भारत और तंजानियाँ के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। कैलेन्डर वर्ष 2004 के दौरान वर्ष 2003 में 169 मि. अमरीकी डालरों की तुलना में तंजानियाँ को भारत द्वारा किये गये निर्यात में 29% की वृद्धि हुई और यह 218 मि. अमरीकी डालर का हो गया। तंजानियाँ से भारत को होने वाला आयात वर्ष 2003 में 73.18 मि. अमरीकी डालरों का था जो वर्ष 2004 में 39% बढ़कर 101.69 मि. हो गया।

उगांडा

भारत और उगांडा के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगी द्विपक्षीय संबंध हैं। 28 जुलाई, 2005 को उगांडा में देश व्यापी जनमत

संग्रह किया गया जिसमें उगांडा वासियों ने बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली के पक्ष में मतदान किया जो वर्ष 2006 के चुनावों से आंरभ होगा। संसद ने संवैधानिक संशोधन विधेयक का अनुमोदन कर दिया जिसमें राष्ट्रपति के दो बार के कार्यकाल की सीमा हटा दी गयी है। नवम्बर, 2005 में आयोजित एन आर एम कंवेंशन में नशनल रेसिस्टेंस मूवमेंट द्वारा राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार मनोनीत किया गया। उगांडा वर्ष 2007 में होने वाली राष्ट्रकुल शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजवानी करेगा।

भारत सरकार के विशेष दूत श्री वी.के. ग्रोवर ने 28 और 29 अप्रैल, 2005 तक उगांडा का दौरा किया। पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष श्री हशिम अब्दुल हलीम ने 9 और 10 अगस्त, 2005 को उगांडा का दौरा किया।

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा ने कम्पाला में वेटलैंड पर रमसार कंवेंशन के संविदाकारी पक्षकारों के नौंवे सम्मेलन के मंत्रिस्तरीय खण्ड में भाग लेने के लिए 11 और 12 नवम्बर, 2005 को उगांडा का दौरा किया।

उगांडा गणराज्य के उप-राष्ट्रपति प्रो. गिलबर्ट बुकेन्या ने सिपला (इन्डिया)लि. के आमंत्रण पर 8-12 अगस्त, 2005 तक भारत का निजी दौरा किया। उन्होंने उगांडा में एंटी - रेट्रोवियल दवाओं के उत्पादन के लिए मैसर्स क्वालिटी केमिकल्स के साथ एक संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए सिपला (इन्डिया) लि. के साथ एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया।

निवेश राज्य मंत्री प्रो. सेमाकुला किवानुका ने 6-8 नवम्बर, 2005 तक नई दिल्ली में भारत - अफ्रीका परियोजना भागीदारी - "एक्सपैडिंग होरायजंस" पर बैठक के लिए युगांडा के तीन सदस्यीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया।

जाम्बिया

विदेश कार्यालय परामर्शों के लिए 27 फरवरी- 1 मार्च, 2005 तक लुसाका में वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर बैठक की गयी।

जाम्बिया पक्ष की ओर से प्रथम महिला सुश्री मौरीन ग्वानावासा ने भा. सां. सं. प. के आमंत्रण पर अक्तूबर में भारत का दौरा किया। भारत-जाम्बियाई संयुक्त स्थायी आयोग की पांचवीं बैठक सितम्बर में नई दिल्ली में हुई। जाम्बिया के वित्त और राष्ट्रीय योजना मंत्री श्री न्गांडे के नेतृत्व में 10 सदस्यीय जाम्बियाई शिष्टमण्डल भारत आया। जाम्बिया के ऊर्जा और जल विकास मंत्री जार्ज पोंम्बो ने भी मार्च, 2005 में भारत का दौरा किया जबकि भूतपूर्व राष्ट्रपति केनेथ कोंडा ने मार्च, 2005 में एच आई वी एड्स से जुड़े सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्ष जाम्बिया ने अनेक सरकारी विभागों के लिए भारत से वाहनों का आयात करके 10 मि. डालरों के ऋण के बड़े भाग का उपयोग किया। दिसम्बर, 2005 में राष्ट्रपति की 2003 की यात्रा के दौरान वायदा किये गये 25 मि. रू. के दान के भाग के रूप में जाम्बिया को 8 मि. रू. के कृषि उपकरणों का दान दिया गया।

वर्ष 2004-05 में द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष के 54.5 मि. अमरीकी डालरों की तुलना में 73.9 मि. अमरीकी डालरों का हो गया। जाम्बिया ने वर्ष 2003 के करार के अंतर्गत 9.4 मि. अमरीकी डालरों के बकाये का भुगतान कर दिया। एक्जिम बैंक और जाम्बिया विकास बैंक ने मार्च में पांच वर्षीय भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किये। भारत ने जाम्बिया के लिए आइटेक स्लाट्स की संख्या को बढ़ाकर 35 से 50 कर दिया।

भा. सां. सं. प. द्वारा प्रायोजित एक 10 सदस्यीय ताल वाघ मंडली ने अक्तूबर में लुसाका में कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

जिम्बाबवे

जिम्बाबवे की स्वतंत्रता की पच्चीसवीं वर्षगांठ में भारत के साथ इसके संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। जिम्बाबवे की अर्थव्यवस्था में आयी मंदी के बावजूद जिम्बाबवे की "पूर्वान्नमुख" नीति के अनुसरण में भारत के साथ उसके व्यापार और आर्थिक संबंधों में विकास हुआ।

भारतीय कंपनियों को भेषज, सिंचाई और ग्रामीण विघुतीकरण के क्षेत्र में सफलता मिली है। अपनी उर्वर कृषि और विशाल खनिज सम्पदा और प्लेटिनम के अपने विशालतम भण्डार के कारण जिम्बाबवे साधन संपन्न राष्ट्र हैं।

एच एम टी (अंतरराष्ट्रीय) की रिपोर्ट पर एस एम ई के विकास के लिए 5 मि. अमरीकी डालरों के भारतीय ऋण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उद्योग मंत्री श्री मुम्बेनगेगवी के नेतृत्व में जिम्बाबवे के एक शिष्टमण्डल ने भारत-अफ्रीका भागीदारी परियोजना पर बैठक में भाग लिया जिसके फलस्वरूप भारतीय दूर-संचार परामर्शी निगम (टी सी आई एल) ने जिम्बाबवे के राष्ट्रीय रेलवे के साथ एक करार संपन्न किया। जिम्बाबवे के स्वास्थ्य मंत्री श्री डेविड पेरिरेनयात्वा ने भारत का दौरा किया।

भारत ने वार्षिक हरारे अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव में भाग लिया जिसमें कुचिपुड़ी नृत्य मण्डली का नेतृत्व सुश्री शैलजा ने किया। भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाबवे का दौरा किया और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट मैच खेला।

कोमेसा

भारत के पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के लिए साझे बाजार (कोमेसा) के साथ अपना क्रियाकलाप जारी रखा। सचिव (पश्चिम) श्रीमती शशि त्रिपाठी ने 28 फरवरी, 2005 को कोमेसा के महासचिव एरास्टस जे. ओ. म्वेन्चा के साथ मुलाकात की और विशेष सचिव (आर्थिक संबंध) श्री राकेश कुमार ने 28 नवम्बर, 2005 को लुसाका में कोमेसा की कार्यकारी महासचिव श्रीमती नागला अल-हुसैनी के साथ मुलाकात की जिसमें भारत कोमेसा समझौता ज्ञापन के अनुसरण में कोमेसा के साथ भारत के क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के लिए बातचीत की गयी। भारतीय जल एवं ऊर्जा परामर्शी सेवाएं लि. वॉपकोस ने जाम्बिया में विद्यमान सिंचाई सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए सितम्बर/ अक्तूबर, 2005 में वहाँ का दौरा किया। आगामी महीनों में वॉपकोस के विशेषज्ञ एरीट्रिया, उगांडा, स्वाजीलैंड और जिम्बाबवे की यात्रा पर जाएंगे।

भारत ने 30 मई से 3 जून, 2005 तक किगाली में आयोजित कोमेसा शिखर सम्मेलन में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।

एस ए डी सी

1992 में गठित दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय में 14 सदस्य देश हैं। ज्ञापन अक्तूबर, 1997 में संपन्न किया गया। मार्च, 2004 में लुआंडा में आयोजित बैठक में एस ए डी सी मंत्रियों की परिषद ने एस ए डी सी - भारत मंच को संस्थागत रूप देने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। भारत एस ए डी सी - मंच की पहली बैठक अप्रैल, 2006 में होने की संभावना है।

पश्चिम अफ्रीका

पश्चिम अफ्रीका के देशों के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंध गहन हुए हैं। टीम-9 एक नई पहल अर्थात भारत और पश्चिम अफ्रीका के 8 देशों के बीच तकनीकी - आर्थिक सहयोग ने पश्चिम अफ्रीका के कई महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के संबंधों को गहन बनाने में आवश्यक गति प्रदान की है। 3 जुलाई, 2005 को सिर्ते लीबिया में अफ्रीकी यूनियन के शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने टीम - 9 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की विदेश मंत्री ने टी - 9 के मंत्रियों से न्यूयॉर्क में 16 सितंबर, 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयार्क की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस दल में शामिल होने के नाइजर के अनुरोध को मान लिया जाए और इस समूह की कुल सदस्यता 10 की हो।

वर्ष के दौरान टीम - 9 के देशों को भारत द्वारा प्रदत्त 500 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को क्रियाशील करने का ठोस कार्य किया गया। सिर्ते में टीम - 9 देशों की बैठक के अवसर पर विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 260 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य की परियोजनाओं के अनुमोदन पत्र प्रदान किए। सड़क और रेल परिवहन, कृषि क्रियान्वयन, निर्माण, सिंचाई, विद्युतीकरण, कपास ओटाई और खाद्य प्रसंस्करण जेसे विभिन्न क्षेत्रों में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पश्चिम अफ्रीका के साथ भारत के संबंध गहन होने की उम्मीद है।

भारत ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उपकरणों की खरीद के लिए ऋण दिया है। अफ्रीकी विकास के लिए नई भागीदारी के अंतर्गत दिए गए 200 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण में से 84.3 मिलियन अमरीकी डालर का पहले ही सेनेगल, माली, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गाम्बिया और नाइजर में परियोजनाओं के लिए अनुमोदन किया जा चुका है।

वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय ने आर्थिक राजनय में एक महत्वपूर्ण पहल की जिसके तहत मार्च और नवंबर में भारतीय उद्योग परिमंडल द्वारा आयोजित भारत-अफ्रीकी परियोजना भागीदारी गुप्त वार्ता में मंत्रालय ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन वार्ताओं में मंत्री स्तरीय शिष्टमंडलों, प्रमुख वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्य चेंबरों के प्रधानों और उद्योग प्रमुखों ने भाग लिया। इन वार्ताओं ने व्यापार के प्रति प्रचुर मात्रा में रूचि जाग्रत की जिससे वास्तविक पूछताछ तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं के वास्तविक संबंधों के मार्ग प्रशस्त हुए।

अंगोला

भारत और अंगोला के बीच द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बने रहे हैं। अप्रैल, 2002 में अंगोला में गृहयुद्ध की समाप्ति की बाद अंगोला को भारत के निर्यात और निवेश में वृद्धि हुई है। फिक्की से 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 20-23 सितंबर, 2005 तक लुआंडा की यात्रा पर गया।

भारत ने रेलवे पुनर्वास परियोजना के लिए अंगोला की सरकार को 40 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया है 'राइट्स' तकनीकी सहायता दल जून, 2005 से लुबांगो में है।

उद्योग उप मंत्री श्री अब्राहाओ पिओ डोस सांतोस गोर्गल 20-

25 अगस्त, 2005 तक भारत की यात्रा पर आए। पांच एंबुलेंस अंगोला को उपहार में दी गई।

बेनिन

बेनिन गणराज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों में वर्ष 2005-06 के दौरान गति आई। विदेश मंत्रालय और अफ्रीकी इंटीग्रेशन की महासचिव श्रीमती मरियम अलादजी बोनी दियालो बेनिन के विदेश मंत्री श्री रोगेटियन बियाऊ की यात्रा की तैयारी के लिए अप्रैल, 2005 में भारत यात्रा पर आई।

अफ्रीकी देशों के कार्यक्रमों को सहायता के अंतर्गत भारत ने बेनिन की सरकार को 60 ट्रेक्टर और कलपुर्जे प्रदान किए।

बुर्किना फासो

13 नवंबर, 2005 को हुए राष्ट्रपति के चुनावों में राष्ट्रपति ब्लेज कोम्पाओर ने विजय प्राप्त की। उन्होंने बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में 20 दिसंबर, 2005 को शपथ ग्रहण की। हाल के वर्षों में भारत और बुर्किना फासो के बीच संबंध सुदृढ़ हुए हैं।

भारत ने टीम - 9 के अंतर्गत 30.97 मिलियन अमरीकी डालर की एक ऋण श्रृंखला का अनुमोदन किया है जिसमें से 30 मिलियन अमरीकी डालर कृषि परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए और 0.97 मिलियन अमरीकी डालर नेशनल पोस्ट ऑफिस को उपकरणों से सज्जित करने और आधुनिक फारेन एक्सचेंज ब्यूरो के सृजन के लिए हैं।

टीम - 9 पहल के अंतर्गत बुर्किना फासो के लिए संस्वीकृत ऋण श्रृंखला के संबंध में वित्त एवं बजट मंत्री श्री ज्यां बैपतिस्त कम्पाओरे 1-4 अगस्त, 2005 तक नई दिल्ली की यात्रा पर आए। प्रतिनिधिमंडल ने विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ विचार-विमर्श किया और वित्त मंत्री श्री पी चिदबरम से मुलाकात की।

कैमरून

भारत और कैमरून के बीच संबंध निरंतर संवर्धित होते रहे। भारत ने कैमरून की सरकार को उनके कृषि के क्षेत्र को विकसित करने में सहायता हेतु 60 ट्रैक्टर और कलपुर्जे दान स्वरूप देने की घोषणा की है।

चाड

भारत और चाड के बीच द्विपक्षीय संबंधों और भी गति प्राप्त हुई जब मार्च,2005 में चाड के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री भारतीय उद्योग परिमंडल की में सभा गुप्त वार्ता लेने भारत आए। विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जुलाई, 2005 में अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन के अवसर पर चाड के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्री नागूम यामसूम से और टीम - 9 के अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री ने टीम - 9 पहल के अंतर्गत चाड में चार परियोजनाओं के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर के भारत सरकार के अनुमोदन के आशय का एक पत्र हस्तांतरित किया; इन परियोजनाओं में बाइसिकल निर्माण संयत्र की स्थापना, ट्रैक्टरों और कलपुर्जों का निर्माण एवं संयोजन; इस्पात छड़ संयंत्र और बेलनी-मिल; और सूती धागा संयत्र शामिल हैं।

कोत द आइवर

कोत द आइवर टीम - 9 पहल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। कोत द आइवर के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक हैं। विदेश मंत्री मामादू बांबा ने मार्च, 2005 में भारतीय उद्योग परिमंडल की सभा में अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया कृषि और परिवहन क्षेत्रों के लिए कोत द आइवर को 26.08 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की ऋण श्रृंखला प्रदान की गई है।

द्विपक्षीय विचार-विमर्शों के दौरान कोत द आइबर ने कृषि, एस एम ई और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत के साथ गहन सहयोग की बलवती इच्छा की पुष्टि की।

कोत द आइवर के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर, 2005 में भारतीय उद्योग परिमंडल की गुप्त वार्ता में भाग लिया और आबिदजान में एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र की स्थापना के लिए एन आर डी सी के साथ एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया। विदेश मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है।

कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य

भारत और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डी आर कोंगो) के बीच द्विपक्षीय सबंध घनिष्ठ और सहयोगात्मक हैं। डी आर कोंगों के विदेश मंत्री श्री रमाजानी बाया की यात्रा के बाद उप राष्ट्रपति श्री ज्यां पिएरे बेंबा 2-4 मार्च, 2005 तक भारतीय उद्योग परिमंडल की सभा में भाग लेने दिल्ली आए।

नेपाड़ कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने डी आर कोंगो को चार परियोजनाओं, अर्थात् एक सीमेंट फैक्टरी की बहाली 500 बसों के अधिग्रहण, मैंगनीज खानों की बहाली और सोसायटे मिनिएरे दे बाकवांगा (मीबा) के लिए उपस्करों का अधिग्रहण, के क्रियान्वयन के लिए 33.5 मिलियन अमरीकी डालर की एक्जिम बैंक ऋण श्रृंखला का अनुमोदन किया है।

भारत ने डी आर कोंगो के विदेश मंत्री से प्राप्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए 60 ट्रेक्टर उनके अतिरिक्त पुर्जों और उपसाधनों सहित भेजे।

इक्विटोरियल गिनी

भारत ने इक्विटोरियल गिनि की साथ हार्दिक संबंध बनाए रखे हैं। इक्विटोरियल गिनी को पेयजल परियोजना के लिए 15 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की ऋण श्रृंखला प्रदान की गई है।

घाना

घाना के साथ द्विपक्षीय संबधों ने अपनी तीव्र गति बनाए रखी। आई सी टी में भारत घाना कोफी अन्नान उत्कृष्ट केंद्र जिसकी स्थापना भारत की सहायता से हुई थी अब पूर्णतः क्रियाशील है। घानावासियों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के अलावा यह अन्य इकोवास देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

द्विपक्षीय व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए घाना के लिए दो ऋण श्रृंखलाओं का अनुमोदन किया गया। 15 मिलियन अमरीकी डालर की प्रथम ऋण श्रृंखला के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए संवितरण पहले ही प्रभावी हो चुका है। 27 मिलियन अमरीकी डालर की द्वितीय ऋण श्रृंखला के लिए अगस्त, 2005 में करार संपन्न हुआ।

भारत ने टीम - 9 के अंतर्गत 60 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला का अनुमोदन किया जिसमें से 30-30 मिलियन अमरीकी डालर"ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना" और"राष्ट्रपति परिसर के निर्माण" के लिए हैं। घाना के वित्त मंत्री अगस्त, 2005 में भारत यात्रा पर आए और उन्होंने एक्जिम बैंक के साथ करार संपन्न किया।

वर्ष के दौरान बहुत से भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल घाना की यात्रा पर गए। पेट्रोलियम के क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज, विकास और उत्पादन में सहयोग पर ओ एन जी सी (विदेश) और घाना नेशनल पेट्रोलियम कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। अकरा में स्टेट बैंक की शाखा खोलने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

विधि एवं न्याय मंत्री श्री एच आर भारद्वाज के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रमंडल के विधि मंत्रियों की 13 वीं बैठक में भाग लेने के लिए 1-20 अक्तूबर, 2005 तक अकरा गए।

खाद्य एवं कृषि मंत्री श्री अर्नेस्ट देवराह अप्रैल/मई, 2005 में भारत की यात्रा पर आए। घाना के उप वित्त मंत्री ऋण श्रृंखला पर करार संपन्न करने के लिए 22-26 अगस्त, 2005 तक भारत यात्रा पर आए।"बंगलौर आई.टी. कॉम 2005" में भाग लेने के लिए संचार उप मंत्री बंगलौर आए। कासावा प्रसंस्करण एवं चीनी मिल के लिए उपस्करों के अधिग्रहण के संबंध में घाना के खाद्य एवं कृषि उप मंत्री सितंबर, 2005 में भारत यात्रा पर आए।

गिनी बिसाऊ

जुलाई, 2005 में चुनाव के बाद जोआओ बर्नार्डो वियेरा ने गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति पद का कार्य भार ग्रहण किया। राष्ट्रपति वियेरा ने नए मंत्रिमंडल की नियुक्ति नवंबर 2005 में की। भारत और गिनी बिसाऊ के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। भारत ने टीम - 9 पहल के अंतर्गत गिनी बिसाऊ को 25 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की सिद्धांत रूप में सहमति दी है।

राष्ट्रपति कार्यालय के मिनिस्टर एवं चीफ आफ स्टाफ श्री जोआओ गोम्स कार्डोसो और गिनी बिसाऊ के आर्थिक आयोजना मंत्री डॉ. यसुफ साना भारतीय उद्योग परिमंडल की सभा में भाग लेने नवंबर, 2005 में भारत आए।

माली

भारत और माली के बीच द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक रहे कृषि उपकरणों के संयोजन संयत्र तथा विद्युतीकरण परियोजना के लिए माली को दिए गए 27 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के संबध में माली का दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 7-14 अगस्त, 2005 तक भारत यात्रा पर आया इस प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख अर्थव्यवस्था तथा वित्तमंत्री श्री अबू बकर ट्राओर थे तथा इसमें कृषि एवं खान मंत्री, और ऊर्जा एव जल मंत्री और साथ ही माली के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार शामिल थे।

माली के राष्ट्रपति के विशेष दूत श्री मोदिबो सिदबे 13 मई, 2005 को भारत आए और उन्होंने विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ विचार विमर्श किया। दिसंबर में माली के खान मंत्री भारत आए और उन्होंने विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ विचार विमर्श किया।

ई ई पी सी से 7 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल नवंबर - दिसंबर, 2005 में माली की यात्रा पर गया।

मारीटानिया

मारीटानिया में 3 अगस्त, 2005 को सैन्य शासन परिवर्तन

22 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में नाईजीरिया के विदेश मंत्री राजदूत ओलू अदेनीजी विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह के साथ।

चाड के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री नोगौम योमास्सोम नई दिल्ली में 3 मार्च, 2005 को विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह के साथ।

हुआ जिसके परिणामस्वरूप नई व्यवस्था कर्नल एली आउल्ड मोहम्मद वाल के हाथ में आई।

नवंबर, 2005 में भारतीय उद्योग परिमंडल की सभा में मारीटानिया ने भागीदारी की। पेट्रोल इंडिया लिमिटेड मारीटानिया आयल रिफाइनरी सोमिर को बहाल करने का कार्य कर रहा है जबकि एक अन्य भारतीय कंपनी सी एस एल सेनेगल ने मारीटानिया में सीमेंट संयंत्र को उन्नत बनाने का कार्य शुरू कर दिया है।

नाइजर

मार्च में भारतीय उद्योग परिमंडल की सभा में भाग लेने के लिए नाइजर की विदेश मंत्री मादाम ऐशातु मिंडाउडू ऊर्जा और खनिज मंत्री के साथ भारत आने से नाइजर के साथ भारत के संबंधों को नवजीवन प्राप्त हुआ। भारत ने नाइजर की सरकार को 17 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया है ताकि वह भारत से बसें ट्रक और कृषि के उपकरण खरीद सकें। न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नाइजर के प्रधानमंत्री से मिले और देश की कृषि क्षेत्र के लिए सहायता देने का वायदा किया। न्यूयार्क में टीम-9 की बैठक में नाइजर को समूह में दाखिल करने पर सहमति हुई। 6-8 नवंबर, 2005 तक दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिमंडल की बैठक में नाइजर के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नाइजर का प्रतिनिधित्व किया।

नाइजर की सरकार से प्राप्त एक अनुरोध के प्रत्युत्तर में भारत ने अकाल से प्रभावित बच्चों के लिए बच्चों की दवाइयों की आपूर्ति की एक खेप भेजी।

नाइजीरिया

राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सघन सहयोग के साथ नाइजीरिया और भारत के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। नवंबर, 2005 में नाइजीरिया के पेट्रोलियम संसाधन मंत्रालय और ओ एन जी सी मित्तल ऊर्जा लि. के बीच समझौता ज्ञापन संपन्न होना द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। भारत को दो गहन समुद्र तटीय ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे और 120000 बैरल प्रतिदिन (6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) क्रूड आयल की दीर्घकालीन आपूर्ति की जाएगी। बदले में ओ एम ई एल नाइजीरिया में 180,000 बैरल प्रतिदिन की तेल रिफाइनरी सापित करेगा और नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था में, विद्युत एवं शोधन क्षेत्रों में, रेलवे लाइनों के निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करेगा।

नाइजीरिया से एक अंतर मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल अक्तूबर, 2005 में भारत आया जिसमें पेट्रोलियम संसाधनों के राज्य मंत्री, विद्युत एवं इस्पात मंत्री, वाणिज्य मंत्री और नाइजीरिया रेलवे कार्पोरेशन के अध्यक्ष शामिल थे। ओ एन जी सी, एन टी पी सी, राइटस और इरकॉन के साथ उनकी बैठकों तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर के साथ हुए विचार-विमर्शों के दौरान कई अवसरों की पहचान की गई।

मार्च 2005 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल नाइजीरिया की यात्रा पर गया और ऊर्जा सहयोग पर बातचीत की शुरूआत की। इसके बाद भारत से प्रतिदिन 40,000 बैरल क्रूड आयल की आपूर्ति के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन ने नाइजीरिया नेशनल पेट्रोलियम कार्पोरेशन के साथ एक दीर्घकालीन संविदा पर हस्ताक्षर किए। बाद में नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन से एक प्रतिनिधिमंडल अगस्त, 2005 में नाइजीरिया की यात्रा पर गया।

नाइजीरिया के फार्मास्यूटिकल उत्पादों के आयात का भारत सबसे बड़ा स्रोत बना रहा। जुलाई, 2005 में भारत से एक फार्मास्यूटिकल प्रतिनिधिमंडल नाइजीरिया की यात्रा पर गया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री से तथा अन्य प्रमुख अधिकारियों से बातचीत की।

वर्ष के दौरान एक अन्य गौरतलब घटना यह हुई कि 1987 में घटित नशीली दवाइयों से संबधित किसी अपराध के लिए स्थानीय न्यायालय द्वारा एयर इंडिया पर लगाए गए 31.5 मिलियन अमरीकी डालर के दंड से छूट मिल गई। नाइजीरिया के नागर विमानन मंत्री ने नाइजीरियाकी उडान के लिए एयर इंडिया का मार्ग प्रशस्त करते हुए इस छूट के विषय में 13 जून, 2005 को औपचारिक रूप से सूचना दी। नाइजीरिया और भारत के बीच सीधा हवाई संपर्क जून, 2005 में उस समय बहाल हुआ जब नाइजीरिया की बेल व्यू एयरलाइंस ने लागोस और मुंबई के बीच दो साप्ताहिक उडानें शुरू की।

नाइजीरिया के निर्माण राज्य मंत्री के नेतृत्व में 35 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मार्च, 2005 में नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका गुप्त वार्ता में भाग लेने भारत आया। द्विपक्षीय संबंधों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर विदेश मंत्री के साथ परामर्श करने हेतु नाइजीरिया के विदेश मंत्री राजदूत ओलुयेमी अदेनीजी मार्च, 2005 में नई दिल्ली आए।

वर्ष के दौरान नाइजीरिया के साथ सक्रिय रक्षा सहयोग जारी रहा। अभी नाइजीरिया की सशस्त्र सेना के 16 अधिकारी भारत में विभिन्न रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर

रहे हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल जे. जे. सिंह 27 नवंबर से 1 दिसंबर, 2005 को नाइजीरिया की यात्रा पर गए।

कोंगो गणराज्य

वाणिज्य मंत्री मादाम एडलेड माउंडेले न्गोलो 4 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ 11-18 नवंबर, 2005 तक सरकारी यात्रा पर भारत आई। उन्होंने विदेश राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ के साथ विचार-विमर्श किया। कोंगो में व्यापार एवं निवेश के अवसरों के बारे में भारतीय व्यापारियों को परिचित कराने हेतु भारतीय उद्योग परिमंडल ने मंत्री के लिए एक व्यापारिक मेल-मिलाप का आयोजन किया।

कोंगो की सरकार से प्राप्त एक अनुरोध के प्रत्युत्तर में भारत ने मलेरिया रोधी एवं अन्य औषधियों की एक खेप ब्राजाविले भेजी है।

गैबोन गणराज्य

गैबोन के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबध हैं। मई, 2005 में आयल इंडिया लिमिटेड का एक प्रतिनिधिमंडल गैबोन की यात्रा पर गया और दो तटीय ब्लाकों का प्राथमिक मूल्याकंन किया। गैबोन की सरकार भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना चाहती है।

गिनी गणराज्य

भारत ने गिनी गणराज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबध बनाए रखे हैं। सहयोग मंत्री श्री अल्हाजी थायर्नो हबीब दियालो चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 10-17 सितंबर, 2005 तक भारत की यात्रा पर आए प्रतिनिधिमंडल ने विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की और राइटस, एन एस आई सी, एन आर डी सी, बी एच ई एल और सी आइ आइ को देखने गए। मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर और भूविज्ञान डॉ. अहमद टिडियाने सौरे के नेतृत्व में पांच सदस्यीय एक और प्रतिनिधिमंडल ने 6-8 नवंबर, 2005 तक दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिमंडल की गुप्त वार्ता में गिनी गणराज्य का प्रतिनिधित्व किया।

सेनेगल

वर्ष के दौरान भारत और सेनेगल के संबधों में यथेष्ट वृद्धि हुई। तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह 25 और 26 मई, 2005 को सेनेगल की यात्रा पर गए और उन्होंने राष्ट्रपति अब्दुलाये वादे और विदेश मंत्री शेख टिडियाने गाडियो सहित विभिन्न राजनैतिक नेताओं के साथ व्यापार बातचीत की। इन विचार - विमर्शों के दौरान सहयोग के क्षेत्रों को पहचाना गया जिनमें कृषि, रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी और एस एम ई शामिल हैं। दोनों विदेश मंत्रियों ने विदेश कार्यालय परामर्शों पर एक प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए। श्री नटवर सिंह ने डकर में कोर्निश वेस्त में महात्मा गांधी प्लाजा की आधारशिला रखी राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली और सेनेगल के लघु एवं मध्यम उद्यम, महिला उद्यमी और माइक्रो वित्त मंत्रालय के बीच एक सहयोग करार भी संपन्न हुआ।

विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उन 300 बसों के औपचारिक लांच के लिए 6-7 अप्रैल, 2005 को सेनेगल गए जो 18 मिलियन अमरीकी डालर की द्विपक्षीय ऋण श्रृंखला के अंतर्गत सेनेगल द्वारा भारत से आयात की गई थी। विदेश राज्य मंत्री ने सेनेगल के राष्ट्रपति श्री अबदुलोय वाडे, प्रधानमंत्री मैकी सैन और विदेश मंत्री शेख टिडियाने गाडियो से मुलाकात की राइटस और सेनेगल की एजेंसी फार न्यू रेलवे सिस्टम के बीच प्रस्तावित डकर - टांबाकौंडा - जिंगुइनचोर का व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने टीम - 9 के कार्यक्रम के अंतर्गत बडी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 27 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया, और डकर-बामको रेलवे लाइन के लिए लोकोमोटिव्स और कोच की आपूर्ति के लिए सेनेगल और माली को संयुक्त रूप से 27.7 मिलियन अमरीकी डालर का एक और ऋण दिया।

भारत ने सितंबर में सेनेगल में असाधारण बाढ़ से प्रभावितों के लिए राहत सामग्री की एक खेप दानस्वरूप भेजी जिसमें टैंट, कंबल, वाटर पंप और दवाइयां शामिल थी।

सियरा लियोन

भारत और सियरा लियोन के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत 400 सैन्य बैरकें उपलब्ध करवा कर देश की सेना की सहायता करने पर सहमत हो गया है। इस परियोजना पर इस समय कार्य चल रहा है।

सियरा लियोन के विदेश मंत्री नवंबर, 2005 में दिल्ली में भारतीय उद्योग परिमंडल की गुप्त वार्ता में भाग लेने के लिए भारत आए।

गाम्बिया

गाम्बिया के विदेश मंत्री श्री सिडि मोरो सानेह इस वर्ष बड़े प्रतिनिधिमंडलों के साथ दो बार भारत यात्रा पर आए जिससे

भारत और गाम्बिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गति आई। भारत ने गाम्बिया को कृषि मशीनरी और ट्रैक्टर संयोजन संयत्र खरीदने के लिए 6.7 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया। भारत ने सितंबर, 2005 में गाम्बिया की सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लिए दवाइयों की एक खेप भी उपहार स्वरूप भेजी।

टोगो

पूर्ण राष्ट्रपति एयादेमा की मृत्यु के उपरांत टोगो में राष्ट्रपति के चुनाव 24 अप्रैल 2005 में हुए। श्री फाउरे ग्नासिंगबे चुनाव में विजयी रहे और 4 मई, 2005 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। भारत और टोगो के बीच द्विपक्षीय संबंध मधुर बने रहे। टोगो की सरकार से प्राप्त अनुरोध के प्रत्युत्तर में भारत ने 60 ट्रैक्टर दान स्वरूप देने का निर्णय लिया है।

इकोवास औद्योगिक विकास बैंक, जिसका मुख्यालय लोम में है, ने ई बी आई डी की पूंजी में भागीदारी और पश्चिम अफ्रीका में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता मांगी है। ई बी आई डी के अध्यक्ष मार्च और मई, 2005 में भारत यात्रा पर आए और उन्होंने वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा एक्जिम बैंक के अधिकारियों से इस संबंध में मुलाकात की।

भारत ने आइटैक/स्कैप कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देना जारी रखा। टोगो को इस वर्ष दो प्रशिक्षण स्लॉट आवंटित किए गए।

टोगो के साथ व्यापार में वृद्धि हुई है, टोगो को भारत का निर्यात 260.83 मिलियन अमरीकी डालर का रहा। टोगो से आयात 41.97 मिलियन अमरीकी डालर का रहा।

अफ्रीकी संघ

मार्च, 2005 से भारत को औपचारिक रूप से अफ्रीकी संघ में प्रत्यायित किया गया है राजनीतिक और विकासात्मक मसलों पर अफ्रीकी संघ के साथ गहन क्रिया कलाप किया गया। जुलाई में सिर्ते में आयोजित अफ्रीकी संघ असाधारण शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारत को प्रतिनिधित्व किया। सचिव (पश्चिम) अगस्त में और पुनः अक्तूबर, 2005 में आदिस अबाबा गए और उन्होंने वहां आयोजित असाधारण अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के दौरान गणमान्य लोगों से बातचीत की।

पॅन अफ्रीकी ई-नेटवर्क

सितंबर, 2004 में पॅन अफ्रीकी संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम ने घोषणा की कि अफ्रीकी संघ के सभी 53 सदस्य देशों को ई - नेटवर्क के जरिए जोडा जाएगा। प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य इसरो, एम्स और इग्नू के जरिए टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन, उपलब्ध कराना है। इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों/राज्याध्यक्षों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए टी सी आई एल को मुख्य अभिकरण के रूप में चुना गया है।

इस परियोजना पर अफ्रीकी संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए मई और जुलाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल आदिस अबाबा की यात्रा पर गए। अफ्रीकी संघ से एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल अक्तूबर में नई दिल्ली आया और इस महत्वपूर्ण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु औपचारिक रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत सरकार तथा टी सी आई एल के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न किए। टी सी आई एल और इथोपिया की सरकार के बीच संपन्न एक समझौता ज्ञापन और विदेश मंत्रालय एवं टी सी आई एल के बीच संपन्न एक अलग समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के भीतर इथोपिया में एक विशिष्ट परियोजना पर कार्य शुरू किया गया है।

इस परियोजना की लागत, विदेश मंत्रालय के 'अफ्रीका को सहायता' कार्यक्रम के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से वहन की जाएगी।

■■

यूरोप 7

भारत के विदेशी संबंधों में यूरोप प्रमुखता से उभरा है। भारत यूरोपीय संघ के सदस्य देशों तथा पूर्वी महाद्वीप के अन्य देशों के साथ भी अपने संबंध को काफी महत्व देता है। 25 सदस्यीय यूरोपीय संघ तथा व्यक्तिगत रूप से भी फ्रांस, जर्मनी और यू.के. के साथ भारत की सामरिक साझेदारी है। वर्ष के दौरान ई.यू. और यूरोप के अलग-अलग देशों के साथ भारत के सरोकार और गहन एवं विविधतापूर्ण हुए।

ईयू, यू के, फ्रांस और इटली के साथ शिखर स्तरीय बातचीत और मंत्री स्तर पर दौरों का बढ़ता विनिमय इस सामरिक क्षेत्र के साथ भारत के निरंतर बढ़ रहे सहयोग का द्योतक है।

7 सितम्बर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित छठे भारत-ई यू शिखर सम्मेलन ने विविध क्षेत्रों में भारत-ई यू पारस्परिकता के लिए रोडमैप तैयार करने वाले व्यापक संयुक्त कार्य योजना का समर्थन किया। भारत-ई यू संबंध अब सिर्फ व्यापार और आर्थिक संबंध नहीं रह गए हैं अपितु, इसके तहत व्यापक क्षेत्र शामिल हो गए हैं। शिखर सम्मेलन ने सामरिक साझेदारी पर एक राजनीतिक घोषणा पत्र भी जारी किया जिसने 1993 में दोनों पक्षों द्वारा अंगीकृत पिछले भारत-ई यू राजनीतिक बयान को अद्यतन किया।

भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंध गहरे होते रहे तथा इसमें उत्कृष्ट वृद्धि हुई।

अल्बानिया

3 जुलाई, 2005 को अल्वानिया में संसदीय चुनाव हुए। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता श्री साली बेरिशा अल्वानिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए।

आस्ट्रिया

आस्ट्रिया के राष्ट्रपति डॉ. होंजफिशर ने 16 से 21 फरवरी, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ और चिकित्सा विश्वविद्यालय, इंसब्रक के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सहयोग पर एक करार तथा सहयोग विकास पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए।

बेल्जियम

बेल्जियम यूरोपीय देशों में भारत के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर के रूप में उभरा है और इसका व्यापार कारोबार 2004 में लगभग 6.5 बिलियन यूरो था जो यू के के साथ भारत के व्यापार से थोड़ा ही कम है। द्विपक्षीय व्यापार में रत्न एवं जवाहरात का हिस्सा लगभग 75% है। बेल्जियम ने यूएनएससी पर जी-4 रूपरेखा संकल्प को सह-प्रायोजित किया।

विशाल व्यावसायिक शिष्टमंडल के मुखिया के रूप में एचआरएस क्राऊन प्रिंस पिलिप की भारत यात्रा ने द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को गति प्रदान की। तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह ने इराक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और जी-4 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए 20 और 21 जून, 2005 को ब्रुसेल्स का दौरा किया।

बोस्निया और हर्जेगोविना

29जून, 2005 को इवोमिरो जोविक ने बारिस्लाव पाराविक से अधिकारिक तौर पर बोस्निया के अध्यक्ष और हर्जेगोविना प्रेसीडेंसी के रूप में पदभार ग्रहण किया।

बुल्गारिया

अगस्त, 2005 में समाजवादियों, केंद्रवादियों और नृजातीय तुर्कों के गठबंधन का नेतृत्व करते हुए श्री सर्गेई स्टेनशेव बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने।

उप प्रधानमंत्री और शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री श्री डैनियल वाल्टचेव ने 3 से 7 दिसम्बर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल के साथ 2005-07 के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए।

क्रोएशिया

क्रोएशिया के राष्ट्रपति श्री स्त्जेपन मेजिक ने पांच वर्ष के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए फरवरी, 2005 में शपथ ग्रहण किया। यूरोपीय संघ क्रोएशिया के लिए सिंहासनारोहण वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गया क्योंकि इस बात की पुष्टि हुई

कि क्रोएशिया पिछले यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अधिकरण के साथ पूर्णतया सहयोग कर रहा है। जनरल एंटे गोटोवानिया, जिन पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना था, और जो क्रोएशिया के सिंहासनारोहण वार्ता में विलंब के मुख्य कारण थे, को केनारी द्वीपसमूह में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर आईसीटीवाई में मुकदमा चलेगा।

साइप्रस

इस वर्ष भारत और साइप्रस के संबंध सौहार्दपूर्ण और सहयोगी रहे। एक महत्वपूर्ण प्रगति के तहत अजरबेजान सरकार ने 30 जून, 2005 को यह घोषणा की कि यह तुर्की साइप्रस पासपोर्ट स्वीकार करने का कार्य शुरू करेगा। उत्तरी साइप्रस में सत्ता परिवर्तन को कुछ हद तक मान्यता देने वाले तुर्की के बाद अजरबेजान दूसरा देश होगा।

चेक गणराज्य

राष्ट्रपति वाकलाव क्लौस (पीके) ने 6-12 नवम्बर, 2005 के दौरान भारत का राजकीय दौरा किया। दिल्ली के अलावा वे कोलकाता, गोवा, बंगलोर और औरंगाबाद भी गए। उनकी यात्रा से मैत्री संबंध तथा बढ़ते व्यापार एवं निवेश संबंध और मजबूत हुए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने देश के समर्थन का उल्लेख किया।

नए चेक प्रधानमंत्री श्री जिरी पारोउबेक, जिन्होंने स्टानिस्लाव ग्रास के बाद अप्रैल, 2005 में पदभार ग्रहण किया, 17 से 19 जनवरी, 2006 के दौरान भारत का दौरा किया तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, भारी उद्योग मंत्री से मुलाकातें की।

उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री श्री मिलन सिमोनोक्सी ने 8 से 12 फरवरी, 2005 के दौरान भारत की यात्रा की।

स्कोडा ऑटो जिसने 2000 में औरंगाबाद में भारतीय बाजार में प्रवेश किया, ने अगले वर्ष औरंगाबाद स्थित अपने दफ्तर में एक नए मॉडल श्स्कोडा फाबिया सेडन' कार बनाने की योजना बनाई है। अपने बाजार को बढ़ाकर दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को भी शामिल करने की इसकी योजना है।

डेनमार्क

प्रधानमंत्री श्री एंडर्स फोग रासमूसेन 3 से 6 अप्रैल, 2006 के दौरान भारत के दौरे पर आने वाले हैं। संसदीय व्यापार और उद्योग समिति ने 11 से 18 फरवरी, 2006 के दौरान भारत का दौरा किया।

फिनलैंड

फिनलैंड के विदेश मंत्री श्री एरक्की टूमिओजा हेलसिंकी प्रक्रिया बैठक में भाग लेने के लिए 6 से 10 फरवरी, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया तथा विदेश मंत्री के साथ वार्ता की। फिनलैंड के व्यापार और उद्योग मंत्री ने 15 से 19 जनवरी, 2006 के दौरान भारत का दौरा किया तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मट्टी वानहानेन 13 और 14 मार्च, 2006 को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। फिनलैंड के प्रधान मंत्री का दौरा इस बात को देखते हुए महत्वपूर्ण है कि 2006 के उत्तरार्ध में फिनलैंड संघ का अध्यक्ष बन जाएगा तथा 7वां वार्षिक भारत-ईयू शिखर सम्मेलन हेलसिंकी में अक्तूबर, 2006 में होने वाला है।

फ्रांस

भारत और फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी है जिसकी शुरूआत जनवरी, 1998 में राष्ट्रपति चिराक की भारत यात्रा के दौरान हुई। नागरिक न्यूक्लियर ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की इसकी योजना है। यूएनएससी के सुधार पर जी-4 संरचना निकाय का फ्रांस सह-प्रायोजक है।

राष्ट्रपति चिराक के आमंत्रण पर प्रधान मंत्री ने 11 से 13 सितम्बर, 2005 के दौरान फ्रांस का दौरा किया। दोनों पक्षों ने भारत और फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी की पुनर्पुष्टि की तथा संबंध को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई। यात्रा के दौरान भारत ने फ्रांस से 6 स्कोर्पीन पनडुब्बियां खरीदने के अपने निर्णय की घोषणा की।

दोनों पक्षों ने माना कि नाभिकीय ऊर्जा सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत है तथा यह कि शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए नाभिकीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करने की आवश्यकता है। फ्रांस ने भारत के साथ पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नागरिक नाभिकीय सहयोग की आवश्यकता को अभिस्वीकार किया तथा अन्य देशों एवं एनएसजी के साथ काम करते हुए तथा द्विपक्षीय सहयोग को गहन बनाकर इस दिशा में कार्य करने पर सहमत हुआ। फ्रांस ने डब्ल्यू एम डी का प्रसार रोकने के प्रति भारत की वचनबद्धता तथा इस संबंध में उसके चल रहे प्रयासों की सराहना की। दोनों देश द्विपक्षीय न्यूक्लियर सहयोग करार तथा रक्षा सहयोग पर संरचना करार स्थापित करने तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य करने पर सहमत हुए।

आस्ट्रिया के राष्ट्रपति श्री हंज फिशर 17 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ।

राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 7 नवम्बर, 2005 को राष्ट्रपति भवन में चेक गणराज्य के राष्ट्रपति श्री बाक्लाव क्लाउस और श्रीमती लिविया क्लाउस की आगवानी करते हुए।

दोनों पक्ष निम्नलिखित अग्रता क्षेत्रों में व्यवसाय साझेदारी गठित करने पर भी सहमत हुए :- अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, भेषज उद्योग, पर्यावरण, उन्नत एवं नई प्रौद्योगिकी, आहार प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल्स और एरोनाटिक्स। 1991 से अब तक भारत में फ्रांसीसी एफ डी आई का वास्तविक प्रवाह लगभग 760 मिलियन यूरो है।

फ्रांस ने फांसीसी विश्वविद्यालयों तथा श्ग्रेंडेस इक्लोस' में और अधिक भारतीय छात्रों का स्वागत करने की इच्छा व्यक्त की। सांस्कृतिक क्षेत्र में गुप्त काल से कला प्रदर्शनी 2007 में ग्रैंड पेलियास में आयोजित की जाएगी।

भारत-फ्रांस फोरम की 10वीं बैठक श्री जियान फ्रांसोइस-पांसेट और श्री एम. रासगोत्रा की सह-अध्यक्षता में 7 अक्तूबर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

एन एस ए और श्री मौरिस गौरडौल्ट मेंटाग्ने, राजनयिक सलाहकार और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि के बीच सामरिक वार्ता का 14वां चक्र पेरिस में 2 सितम्बर, 2005 को आयोजित हुआ।

अन्य उच्च स्तरीय दौरों के सतत विनिमय के क्रम में एक विशाल शिष्टमंडल के साथ फ्रांस के रीन-आल्पस क्षेत्र के राष्ट्रपति श्री जीन जैर क्वैरेनी ने 22 से 28 अक्तूबर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया। फ्रांसीसी सीनेटर श्री माइकल गेरी ने 1 से 9 नवम्बर, 2005 की अवधि में भारत का दौरा किया। इससे पूर्व राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार श्री जेरोम मोनोड ने अक्तूबर, 2005 में भारत का दौरा किया। फ्रांस का दौरा करने वालों में निम्नलिखित शामिल हैं:- सूचना और प्रसारण मंत्री श्री जयपाल रेड्डी (मई), रेल राज्य मंत्री श्री आर. वेलू (मई), वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री कमलनाथ (मई में डब्ल्यू टी ओ/ओईसीडी की बैठकों के लिए), और पीएमओ में राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान (मई में स्थायी विकास पर ओ ई सी डी की बैठक के लिए)। सचिव, शहरी विकास ने शहरी विकास पर जे डब्ल्यू जी की मध्यवर्ती तकनीकी बैठक के लिए जून, 2005 में फ्रांस का दौरा किया।

फ्रांस के अवसंरचना, परिवहन, स्थलीय आयोजना, पर्यटन और सागर मंत्री श्री गिल्स डे रोबिन ने सड़क पर जे डब्ल्यू जी के लिए अप्रैल में भारत का दौरा किया। फ्रांस के कृषि, मत्स्यपालन और ग्रामीण कार्य राज्य मंत्री श्री निकोलस फोरिसियर ने कृषि पर जे डब्ल्यू जी की पहली बैठक के लिए अप्रैल में भारत का दौरा किया।

1998 में गठित भारत-फ्रांस उच्च स्तरीय रक्षा समिति की 8वीं बैठक नई दिल्ली में 8 और 9 दिसम्बर, 2005 को आयोजित की गई। फ्रांसीसी शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री थियरी वोर्जा डे मोजोटा ने किया जबकि भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव ने किया।

ऊर्जा और खनिज अन्वेषण एवं विकास पर जे डब्ल्यू जी की बैठक क्रमशः 29 और 30 नवम्बर, 2005 को हुई। कृषि पर गठित जे डब्ल्यू जी की पहली बैठक नई दिल्ली में अप्रैल में हुई। शहरी विकास पर गठित जे डब्ल्यू जी की मध्यवर्ती तकनीकी समूह बैठक नई दिल्ली में जून, 2005 में हुई। रेल संचालन समिति का दूसरा सत्र नई दिल्ली में मई, 2005 में आयोजित हुआ।

उन्नत अनुसंधान संवर्धन संबंधी भारत-फ्रांस फोरम के शासी निकाय की 18वीं बैठक नई दिल्ली में 14 नवम्बर, 2005 को हुई।

राष्ट्रपति जैक शिराक ने 19 और 20 फरवरी, 2006 को भारत का राजकीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान राजनैतिक, आर्थिक, रक्षा, अंतरिक्ष और असैनिक नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी सामरिक भागीदारी को दृढ़ता से आगे बढ़ाने की भारतीय और फ्रंटधच वचनबद्धता पर जोर दिया।

यात्रा के दौरान सम्पन्न किये गये करारों में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय ऊर्जा के विकास पर एक घोषणा और रक्षा सहयोग पर करार सबसे महत्वपूर्ण थे। भारत ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पूर्ण असैनिक ऊर्जा सहयोग स्थापित करने के लिए फ्रांस के समर्थन की सराहना की।

जर्मनी

भारत और जर्मनी के बीच सामरिक साझेदारी 2001 से है। जर्मनी भारत का महत्वपूर्ण व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदार है। भारत और जर्मनी ने यू एन एस सी के सुधार पर जी-4 रूपरेखा संकल्प के संदर्भ में निकटता से सहयोग किया।

औद्योगिक और आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-जर्मनी संयुक्त आयोग का 15वां सत्र नई दिल्ली में अप्रैल, 2005 में आयोजित हुआ। जर्मनी के अर्थ-व्यवस्था और श्रम मंत्री श्री वालफांग क्लीमेंट तथा वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने सत्र की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की।

वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने 6 से 9 जून, 2005 के दौरान ड्यूसेलडोफ और बर्लिन का दौरा किया। बर्लिन में वित्त मंत्री जर्मनी के अर्थव्यवस्था और श्रम मंत्री श्री वालफांग क्लीमेंट,

7 सितम्बर, 2005 को नई दिल्ली में भारत ई यू शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री जोस मैनुएल बरासो।

12 सितम्बर, 2005 को पेरिस में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का स्वागत करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति श्री जैक शिराक।

आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री सुश्री हीदेमारी विकजोरेक-जियूल तथा अपने समकक्षी जर्मन वित्त मंत्री श्री हंस इचेल से मिले। बर्लिन में वित्त मंत्री ने 'भूमंडलीकरणशील विश्व में भारत' पर अर्थशास्त्रियों और व्यवसाय अग्रणियों को सम्बोधित किया।

आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत की तरक्की को दर्शाने वाले भारत-सप्ताह का आयोजन अक्तूबर, 2005 में बावरिया राज्य में किया गया। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री ई वी के एस इवानगोवन ने इसमें भाग लिया।

व्यवसाय, व्यापार और निवेश पर गठित भारत-जर्मनी परामर्शी समूह की 14वीं बैठक चेन्नई में 4 से 6 नवम्बर, 2005 के दौरान हुई।

भारत अप्रैल में आयोजित होने वाले हनोवर व्यापार मेला 2006 का साझेदार देश है। भारत ने अक्तूबर, 2006 में आयोजित होने वाले फ्रैंकफ र्ट पुस्तक मेला-2006 के लिए श्गेस्ट आफ आनर' देश बनने के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया है।

जर्मनी भारत का यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर है। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है तथा 2004 में 6.3 विलियन यूरो पर पहुंच गया। जर्मनी भारत में निवेश करने वाले प्रमुख देशों में भी है (2004 में 160 मिलियन यूरो)। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग भी है।

बुंडेस्टाग की उपाध्यक्ष और भारत-जर्मनी संसदीय समूह की सदस्या डॉ. (श्रीमती) एंटजे वोल्मर ने अगस्त, 2005 में भारत का दौरा किया।

वर्ष के दौरान जर्मनी में सत्ता परिवर्तन हुआ तथा सी डी यू-सी एस यू और एस पी डी के गठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में सी डी यू की सुश्री अंजीला मार्केल ने जर्मनी के नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया।

ग्रीस

भारत और ग्रीस के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है। मार्च, 2005 में श्री कारोलोस पापोलियास हेलेनिक गणराज्य के छठें राष्ट्रपति बने। ग्रीस के प्रधान मंत्री कोस्टास करमालिस और तुर्की के प्रधानमंत्री रेसेप तय्यीय इरडोगन ने 3 जुलाई, 2005 को दोनों देशों को जोड़ने वाली प्राकृतिक गैस पाइप लाइन निर्मित करने की परियोजना का उद्घाटन किया जिसे आगे चलकर इटली तक बढ़ाया जाएगा जिससे मध्य-पूर्व के गैस उत्पादक क्षेत्र यूरोपीय बाजार से जुड़ जाएंगे।

होली सी

जनजातीय कार्य मंत्री और कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं सांख्यिकीय राज्य मंत्री के साहचर्य में उप राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत ने पोप जान पौल रूरू के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए 8 अप्रैल, 2005 को वेटिकन का दौरा किया।

हंगरी

डॉ. लास्जलो सोलियोम हंगरी के नए राष्ट्रपति चुने गए।

तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह ने जून, 2005 में हंगरी का सरकारी दौरा किया। इस दौरान आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए। वालटोनफुरेड में गुरूदेव रवींद्र नाथ टैगोर का एक बुत लगाया गया। हंगरी के संस्कृति मंत्री श्री अंद्रास बोजोकी ने 14 से 20 जनवरी, 2006 के दौरान भारत का दौरा किया तथा हंगरी के सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। हंगरी के संसदीय सावना शिष्टमंडल ने भी 17 से 22 जनवरी, 2006 के दौरान भारत का दौरा किया तथा संसदीय कार्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री से मिला।

आईसलैंड

आईसलैंड के राष्ट्रपति श्री ओलाफुर रगनार ग्रिमसन ने टी ई आर आई द्वारा आयोजित दिल्ली स्थायी विकास शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 से 9 फरवरी, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया।

राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम ने मई, 2005 में आइसलैंड का राजकीय दौरा किया। उनकी यह यात्रा मार्गदर्शक थी तथा भूकंप पूर्वानुमान अध्ययन, ऊर्जा, मछली पालन, भेषज उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग की नई संभावनाएं खुलीं।

आइसलैंड के विदेश मंत्री गियर एच. हार्ड 26 से 28 फरवरी, 2006 के दौरान भारत आएंगे। इस यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली में आइसलैंड के नए दूतावास का उद्घाटन करेंगे। इस यात्रा के दौरान हवाई सेवाओं पर एक करार भी हस्ताक्षरित होना प्रस्तावित है।

आयरलैंड

राज्य मंत्री (पी एम ओ) श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अहाकिस्टा, काउंटी कोर्क में एयर इंडिया के 'कनिष्क' विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की त्रासदी की 20वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए जून, 2005 में आयरलैंड का दौरा किया। भारतीय शिष्टमंडल में

24 नवम्बर, 2005 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम स्वीडन के सम्राट महामहिम कार्ल XVI गुस्ताफ और रॉयल टेक्नॉलोजी मिशन का स्वागत करते हुए।

8 दिसम्बर, 2005 को नई दिल्ली में नार्वे के प्रधानमंत्री श्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ।

पंजाब सरकार के लोक निर्माण और संस्कृति मंत्री श्री प्रताप सिंह वाजवा शामिल थे।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री घनश्याम तिवारी ने जी ई एस सी आई के अंग के रूप में आयोजित मल्टी स्टेकहोल्डर एप्रोचः शिक्षा के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का दोहन पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक मंच में भाग लेने के लिए 12 से 17 अप्रैल, 2005 के दौरान डवलिन का दौरा किया।

आयरलैंड के प्रधान मंत्री श्री बेरटी अहेर्न ने 16-21 जनवरी, 2006 तक भारत का राजकीय दौरा किया। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक सहयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर करार सम्पन्न किए गए। यात्रा से साफ्टवेयर सेवाओं, शिक्षा, इंजीनियरिडग, स्वास्थ्य, खाद्य और विनिर्माण जैसे विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय क्रियाकलाप सुदृढ़ हुए।

वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 250 मिलियन यूरो का है।

इटली

इटली के राष्ट्रपति श्री कार्लो एजेगलिओ कैंपी की फरवरी, 2005 में भारत यात्रा के बाद इटली के साथ भारत के संबंधों में नई ताजगी आई।

जनवरी-सितम्बर, 2005 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में 22% की वृद्धि हुई (2004 में 3.3 विलियन यूरो)। इटली भारत का ई यू में चौथा सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर है।

तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह ने इटली के विदेश मंत्री के निमंत्रण पर 20 से 22 जून, 2005 के दौरान रोम का दौरा किया।

विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने व्यावसायिक तालमेल को बढ़ावा देने के लिए 23 से 27 मई, 2005 के दौरान मिलान का दौरा किया। उन्होंने बेरोना में सी ई ओ की एक सभा को तथा मिलान में एन आर आई व्यापारियों को संम्बोधित किया।

राजस्थान सरकार में उद्योग मंत्री श्री नरपत सिंह राजवी ने करारा में करारामार्मोटेक मेला में भाग लेने के लिए 1 से 4 जून, 2005 के दौरान इटली का दौरा किया।

भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री संतोष मोहन देव ने जून, 2005 में इटली का दौरा किया और इटली में फियट, इवेको, वियोगो सहित आटोमोबाइल क्षेत्र के अग्रणी व्यवसायियों तथा उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों से मिले। मंत्री ने संयुक्त अनुसंधान केद्र इस्प्रा और डिजाइन सेंटर, तूरीन और पिसा के पास पियागो संस्था का दौरा किया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने एम्ब्रुसेट्टी फोरम में भाग लेने के लिए 1 से 4 सितम्बर, 2005 के दौरान इटली का दौरा किया। वे इटली के रचनात्मक क्रियाकलाप मंत्री डॉ. क्लौदियो स्काजोला से मिले।

कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने 33वें द्विवार्षिक एफ ए ओ सम्मेलन और 130वें एफ ए ओ परिषद में भाग लेने के लिए 16 से 21 नवम्बर, 2005 के दौरान इटली का दौरा किया। यात्रा के दौरान श्री शरद पवार ने अपने इतावली समकक्षी श्री गिओवानी एलीमात्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन राज्य मंत्री कुमारी शैलजा के नेतृत्व में 26 से 28 मई, 2005 के दौरान चार सदस्यीय शिष्टमंडल ने इटली का दौरा किया तथा फ्लोरेंस में तोस्काना क्षेत्र के राष्ट्रपति श्री क्लौदियो मारटिनी और अवसंरचना, परिवहन और सामाजिक राजनीति मंत्रियों के साथ बैठकें आयोजित हुईं।

सूचना और प्रसारण एवं संस्कृति मंत्री श्री जयपाल रेड्डी ने 13 से 16 मई, 2005 के दौरान रोम और वेनिस का दौरा किया। उन्होंने इटली के सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्री श्री रोको वुटिगलियोने और सांस्कृतिक विरासत राज्य मंत्री श्री अंटोनियो मार्ट्रसिलो के साथ बैठक की। भारत और इटली के बीच श्रव्य दृश्य सह-निर्माण के लिए एक करार पर इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया गया।

सीनेटर मारिया क्लौडिया इवानुच्ची की अध्यक्षता में अंतर-संसदीय संघ के इटली-भारत मित्रता समूह ने 22 से 30 नवम्बर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल उप-राष्ट्रपति श्री भैरें सिंह शेखावत और लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी से मिला।

इटली के अवसंरचना और परिवहन मंत्री श्री पेत्रो लुनार्डी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 19 से 21 सितम्बर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल की नागरिक उड्डयन मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, शहरी विकास मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ बैठकें हुई।

भारत के अवसंरचना क्षेत्र से एक 13 सदस्यीय शिष्टमंडल ने इंटरपोर्टो कैंपानो नोला (नेपल्स के पास) में आयोजित इटली-भारत लाजिस्टिक सप्ताह में भाग लेने के लिए 5 से 8 सितम्बर, 2005 के दौरान इटली का दौरा किया।

लाटविया

विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 5 से 7 अक्तूबर, 2005

आयरलैंड के प्रधानमंत्री श्री बर्टी अर्हेन 19 जनवरी, 2006 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ।

नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डॉ. जेन पीर बाल्केनेन्दे 20 जनवरी, 2006 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ।

के दौरान लाटविया का दौरा किया। लाटविया के विदेश मंत्री डॉ. आर्टिस पबरिक 21 से 25 मार्च, 2006 के दौरान भारत का दौरा करने वाले हैं। लाटविया के यू एन एस सी में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है तथा जी-4 संकल्प का सह-प्रायोजक है।

लिथुआनिया

विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 3 से 5 अक्तूबर, 2005 के दौरान लिथुआनिया का दौरा किया। उनके इस दौरा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग मजबूत हुआ। लिथुआनिया ने यू एन एस सी में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।

लग्जमबर्ग

लग्जमबर्ग के अर्थ व्यवस्था और विदेश व्यापार मंत्री श्री जियन्नोट क्रेके ने 28 मार्च से 1 अप्रैल, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया। तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह ने सितम्बर, 2005 में यू एन जी ए के साइडलाइन पर न्यूयार्क में अपने समकक्षी के साथ बैठक की थी।

लग्जमबर्ग ने गहन भारत-ई यू वार्ता के दौरान ई यू पक्ष का नेतृत्व किया जब 2005 के पूर्वार्द्ध में ई यू का यह अध्यक्ष रहा।

मालदोवा

उजवेकिस्तान से भारत प्रत्यायित मालदोवा के प्रथम राजदूत श्री इफिम चिलारी ने 26 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रपति को अपना परिचय-पत्र प्रस्तुत किया।

नार्वे

नार्वेजियाई संसद के विदेश कार्य समिति का एक शिष्टमंडल 23-26 जनवरी, 2005 को भारत का दौरा किया। नार्वे के व्यापार और उद्योग मंत्री श्री वोर्ग ब्रेंडे के नेतृत्व में 3-8 फरवरी, 2005 को एक व्यवसाय शिष्टमंडल भारत आया। उन्होंने टी ई आर आई द्वारा आयोजित 'दिल्ली स्थायी विकास शिखर सम्मेलन' में भी हिस्सा लिया।

विदेश मंत्री ने भारत-नार्वे संयुक्त आयोग के पहले सत्र की अध्यक्षता करने के लिए 16 और 17 जून, 2005 को नार्वे का दौरा किया। हाइड्रोकार्बन पर विद्यमान संयुक्त कार्य समूह को संयुक्त आयोग के अधीन लाया गया। विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सहयोगात्मक कार्य का कार्यक्रम तैयार करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति पर दो जे डब्ल्यू जी स्थापित किए गए।

भारतीय समुद्री जहाज तरंगिनी ने 3-6 अगस्त, 2005 को फ्रेड्रिकस्टाड (नार्वे) में टाल शिप रेस में हिस्सा लिया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर ने 29 अगस्त से 2 सितम्बर, 2005 के दौरान नार्वे का दौरा किया। उन्होंने गहरे समुद्र में अन्वेषण तथा जटिल भू-भौतिकी क्षेत्रों में अन्वेषण के क्षेत्र में नार्वे में विकसित नई प्रौद्योगिकी का भारत के लिए महत्व पर बल दिया। उन्होंने अधिक तेल वसूली और परिवर्धित तेल वसूली के क्षेत्र में नार्वे का समर्थन मांगा। यात्रा के दौरान पांच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए।

नार्वे के प्रधानमंत्री श्री जेंस स्काटटेनवर्ग ने 7-9 दिसम्बर, 2005 को भारत का दौरा किया। उनका यह दौरा 7 दिसम्बर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित टीकाकरण और प्रतिरोधन के लिए वैश्विक गठबंधन के साझेदारों की तीसरी बैठक के सिलसिले में था किंतु राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बैठकों के साथ इसे द्विपक्षीय कार्य दौरा में विस्तृत कर दिया गया। वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल से भी मिले। दोनों पक्ष वैक्सीन और उनके निर्माण पर अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की पूलिंग के लिए रणनीति तैयार करने हेतु कार्यबल स्थापित करने पर सहमत हुए। भारत ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय भूकंप चेतावनी अध्ययन संस्थान स्थापित करने के अपने इरादों से अवगत कराया तथा नार्वे की साझेदारी आमंत्रित की। नार्वे ने इस परियोजना में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

पोलैंड

भारत और पोलैंड के बीच काफी द्विपक्षीय सहयोग है। 15 से 17 सितम्बर, 2005 के दौरान वार्सा में इंडोलाजी पर मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

लॉ एंड जस्टिस पार्टी के लेच काजीनस्की चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति क्वासनीवस्की की जगह पर पोलैंड के राष्ट्रपति बने। इसी पार्टी के काजीमर्ग मारकीनकीविज नए प्रधान मंत्री चुने गए।

पुर्तगाल

25 और 26 जुलाई, 2005 को लिस्बन में पुर्तगाल के साथ विदेश मंत्रालय स्तरीय परामर्श आयोजित किया गया। सचिव (पश्चिम) ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। सचिव, संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 के लिए सांस्कृतिक

विनिमय कार्यक्रम के पाठ को अंतिम रूप देने के लिए 31 मार्च से 5 अप्रैल, 2005 के दौरान पुर्तगाल का दौरा किया। गोवा विधान सभा अध्यक्ष श्री फ्रांसिस्को सरडाहा ने 17 से 18 सितम्बर, 2005 को पुर्तगाल का दौरा किया। आई एन एस तरंगिनी ने 17 से 19 जून, 2005 के दौरान लिस्बन का सावना दौरा किया।

भारत में पुर्तगाली विरासत के परिरक्षण में उनके योगदान को देखते हुए 15 सितम्बर, 2005 को लिस्बन की सिटी काउंसिल द्वारा आयोजित एक समारोह में लिस्बन की एक गली का नाम कोचीन के विशप स्वर्गीय डॉ. जोसेफ कुरीतरा (1929-1999) के नाम पर रखा गया।

12 से 13 सितम्बर, 2005 को पोर्तो, पुर्तगाल में एस आर टी ई पी सी द्वारा एक भारतीय कपड़ा प्रदर्शनी आयोजित की गई। गोवा के कलाकार अंटोनियो जेवियर ट्रिंडेड (1870-1935) के पेंटिंग की प्रदर्शनी सितम्बर, 2005 में ओरियंट फाउंडेशन द्वारा नेशनल फाइन आर्ट्स सोसायटी, लिस्बन द्वारा आयोजित की गई। श्री विनय कुमार बहल के छायाचित्रों की एक प्रदर्शनी श्वेल्हा गोवा' (प्राचीन गोवा) के नाम से 1 जून, 2005 को इंस्टीच्यूटो फैमेओस की कला वीथी में पुर्तगाली समुदाय राज्य मंत्री श्री अंटोनियो ब्रागा द्वारा उद्घाटित की गई। भारतीय वास्तुशिल्प चार्ल्स कोरिया ने 13 अप्रैल, 2005 को वास्तुशिल्प संकाय, लिस्बन तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए मानद डाक्टोरेट की उपाधि ग्रहण की।

भारत-पुर्तगाल द्विपक्षीय व्यापार 2004 में 240 मिलियन अमरीकी डालर के करीब था (द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय निर्यात का हिस्सा 70% था)।

अबू सलेम अंसारी और मोनिका वेदी को पुर्तगाल ने नवम्बर, 2005 में भारत को प्रत्यर्पित किया।

रोमानिया

भारत के उप राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत ने 1 से 4 अक्तूबर, 2005 के दौरान रोमानिया का दौरा किया। रोमानिया की सरकार ने विशेषकर ऑटोमोबाइल, मशीनरी, कपड़ा, भेषज, ऊर्जा, पर्यटन, भवन निर्माण और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की।

उप राष्ट्रपति ने आई टी ई सी के तहत मौजूदा छात्रवृत्तियों के अलावा दो सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां प्रदान करने की घोषणा की। रोमानियाई नेतृत्व ने यू एन एस सी में भारत की उम्मीदवारी तथा जी-4 संकल्प के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। भारत का व्यापार गत 4 वर्षों में चार गुना हो गया है तथा इस वर्ष आधे विलियन के अंक को पार करने वाला है। विविध श्रेणी के क्षेत्रों में भारत का निवेश भी बढ़ रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर के नेतृत्व में 1 से 4 जुलाई, 2005 के दौरान एक भारतीय शिष्टमंडल रोमानिया गया। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग पर चार समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए।

अर्थ व्यवस्था और वाणिज्य मंत्री श्री इओन कोड्रुत सेरोन ने पेट्रोलियम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में व्यापार और निवेश तथा सहयोग के लिए विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए एक व्यावसायिक शिष्टमंडल के साथ 22 से 26 अक्तूबर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया।

सर्बिया और मोंटेनेग्रो (एस सी जी)

श्री बजराम कोसुमी 23 मार्च, 2005 को कोसोवो के नए प्रधान मंत्री के रूप में चुने गए। कोसोवो के 130000 नागरिकों ने कोसोवो के पूर्व प्रधानमंत्री रमुश हरदिनाज, जिन्होंने न्यायाधिकरण द्वारा युद्ध अपराधी ठहराए जाने के बाद मार्च, 2005 के पहले सप्ताह में त्यागपत्र देकर हेग न्यायाधिकरण के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया है, के अभियोजन-पूर्व रिहाई के लिए याचिका पर हस्ताक्षर किए।

मोंटेनेग्रो के उप प्रधान मंत्री श्री ब्रानीमीर गोजदेनोविक ने 24 से 28 अप्रैल, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया। उनके साथ मोंटेनेग्रो के पोतपरिवहन मंत्री तथा बार के मेयर भी थे। पोत मरम्मत पत्तन, बार तक पोत परिवहन लाइन खोल लेने और मोंटेनेग्रो की निजीकरण प्रक्रिया में भारतीय निवेश संबंधी आमंत्रण के इर्द गिर्द चर्चा घूमती रही। शिष्टमंडल ने मुंबई का भी दौरा किया तथा फिल्म उद्योग के साथ चर्चा का आयोजन किया गया।

विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 6 से 10 जुलाई, 2005 के दौरान सर्बिया और मोंटेनेग्रो का सरकारी दौरा किया तथा यू एन प्रणाली में सुधार तथा जी-4 संकल्प सहित समान सरोकार के मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने पोडगोरिका (मोंटेनेग्रो) का भी दौरा किया। सर्बिया और मैंटेनेग्रो के आर्थिक संबंध मंत्री डॉ. प्रेड्राग इवानोविक 7 से 11 फरवरी, 2006 तक भारत की यात्रा पर आऐ। इस यात्रा के दौरान व्यापार करार और दोहरा कराधान परिहार करार पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

ई यू परिवर्धन आयुक्त ने वेलग्रेड में 10 अक्तूबर को सर्बिया

और मोंटेनेग्रो तथा ई यू के बीच स्थिरता और संघ करार पर बातचीत शुरूकरने की घोषणा की जो देश की पूर्ण सदस्यता की दिशा में एक मौलिक कदम है।

स्लोवाक गणराज्य

भारत और स्लोवाक गणराज्य के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। 27 सितम्बर से 3 अक्तूबर, 2005 तक ब्रातिस्लावा में भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) और लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 'इंडिया इन्टरप्राइज एक्जीविशन' आयोजित किया गया। एक द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण करार पर बातचीत की गयी और इसी वर्ष पाठ पर अद्याक्षर किए गए। भा.सां.सं.प. द्वारा प्रयोजित एक कथक मंडली ने ब्रातिसलावा ग्रीष्म उत्सव में भाग लिया। लोक मामले संस्थान के अध्यक्ष डॉ. ग्रिगोरिज मेसेजनिकोव ने भा.सां.सं.प. के विशिष्ट व्यक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत का दौरा किया।

स्पेन

स्पेन ई यू के भीतर भारत के 6 प्रमुख व्यापार साझेदारों में से एक है। द्विपक्षीय करार निरंतर बढ़ रहा है। 2004 में यह 2 विलियन अमरीकी डालर को पार कर गया तथा 2005 में 3 विलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाने की संभावना है।

29 नवंबर, 2005 को नई दिल्ली में भारत-स्पेन संयुक्त आयोग का 8वां सत्र आयोजित किया गया जिसमें स्पेन का नेतृत्व पर्यटन और व्यापार राज्य मंत्री श्री पेड्रो मेलिजा ने किया जबकि वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री ई वी के एस इवान गोवन ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया।

वार्सीलोना के मेयर श्री जान क्लोस ने 22 से 24 अक्तूबर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया। वे दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले तथा दिल्ली के मेयर से मुलाकात की।

कासा एशिया और कासा डी ला इंडिया द्वारा आयोजित भारत-स्पेन ट्रिब्यून 15 और 16 दिसम्बर, 2005 को वार्सीलोना में आयोजित किया गया। इसे एच आर एच प्रिंसेसे इरेनी ऑफ ग्रीस ने सम्बोधित किया।

स्वीडन

'रायल टेक्नोलाजी मिशन' के संरक्षक के रूप में स्वीडन के राजा कार्ल XVI गुस्ताफ के नेतृत्व में 19 से 26 नवम्बर, 2005 के दौरान एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। दौरा बंगलौर और दिल्ली तथा सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार के क्षेत्रों तथा अन्य हाईटेक क्षेत्रों पर केंद्रित था। राजा और आर टी एम के सदस्य 24 नवम्बर, 2005 को राष्ट्रपति से मिले तथा सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, जैव रसायन अनुसंधान, परिवहन और सड़क नेटवर्क, स्वास्थ्य क्षेत्र में नानोटेक्नालाजी तथा ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर बातचीत के सत्र आयोजित किए गए। इस दौरे से उस महत्व का पता चला जो स्वीडन भारत के साथ आर्थिक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने पर देता है। दो अन्य बड़े शिष्टमंडल, पहला स्वीडिश वैंक ग्रुप एस ई बी के नेतृत्व में स्वीडिश कंपनियों के सी ई ओ का और दूसरा स्वीडन और अन्य नार्डिक देशों का व्यावसायिक शिष्टमंडल सितम्बर, 2005 में नई दिल्ली के दौरे पर आए।

विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 28 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 2005 के दौरान स्वीडन का दौरा किया। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा यू एन प्रणाली में सुधार पर अपने स्वीडिश समकक्ष के साथ चर्चा की।

संविधान पर स्वीडिश संसदीय समिति से एक 17 सदस्यीय शिष्टमंडल फरवरी, 2005 में भारत का अध्ययन दौरा किया। पुनः अगस्त/सितम्बर, 2005 में सांस्कृतिक मामलों पर स्वीडिश संसदीय समिति का 11-सदस्यीय बहु-दलीय शिष्टमंडल भारत आया।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन ने जून, 2005 में स्वीडन का दौरा किया। स्वीडन की संचार, क्षेत्रीय नीति और पर्यटन मंत्री सुश्री उलरिका मेसिंग ने 25 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने 9 और 10 दिसम्बर, 2005 को स्वीडन का दौरा किया तथा भारत तथा स्वीडन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग पर एक करार हस्ताक्षरित किया। 9 और 10 जनवरी, 2006 को प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य सचिव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लार्स डैनिलसन सरकारी दौरे पर भारत आए। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम के नारायणन से मिले और 9 जनवरी, 2006 को शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता की।

इस वर्ष का सम्मानित विश्व जल सप्ताह पुरस्कार किंग कार्ल XVI गुस्टाफ द्वारा विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के निदेशक सुश्री सुनीता नारायण को दिया गया।

स्विटजरलैंड

राष्ट्रपति श्री ए पी जे अब्दुल कलाम ने मई, 2005 में स्विटजरलैंड

का दौरा किया। उन्होंने जेनेवा में यूरोपीय न्यूक्लियर अनुसंधान संगठन और लुसाने एवं ज्यूरिख स्थित संघीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का दौरा किया तथा अणु भौतिकी, नानोटेक्नोलाजी, मस्तिष्क एवं दिमाग विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। वे ज्यूरिख में बोस-आइस्टीन प्रयोगशाला भी गए। राष्ट्रपति ने जैव प्रौद्योगिकी, नानोटेक्नोलाजी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अभिसरण और भारत एवं स्विटजरलैंड के बीच इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता में स्विटजरलैंड ने सामूहिक विनाश के हथियारों के विरुद्ध सुरक्षा एवं पर्वत युद्ध कौशल तथा सुरक्षा नीति जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की पेशकश की। राष्ट्रपति ने एवालांच फोरकास्टिंग में संयुक्त अनुसंधान की सलाह दी। राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय व्यापार में मात्रात्मक उछाल का आह्वान किया। भारत में 10वें सबसे बड़े विदेशी निवेशक के रूप में स्विटजरलैंड की भारत में उल्लेखनीय उपस्थिति है। राष्ट्रपति ने कृषि, आहार प्रसंस्करण और फिल्म निर्माण जैसे सहयोग के संभावित नए क्षेत्रों की ओर इशारा किया। स्विस पक्ष ने भारत में लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए निवेश की पेशकश की।

ई यू के 10 नए सदस्य देशों में लोगों के निर्बाध आवागमन पर संधि बढ़ाने के लिए स्विटजरलैंड में 25 सितम्बर को एक रेफरेंडम का आयोजन किया गया। 56% लोगों ने संधि के पक्ष में तथा 44% ने इसके विरुद्ध मतदान किया।

स्विटजरलैंड की रोटेशनल प्रेसीडेंसी प्रणाली के तहत 8 दिसम्बर, 2005 को यहां की संसद ने पेऊरल काउंसिलर और परिवहन मंत्री मोरिटज लियूनबर्गर को स्विस राष्ट्रपति के रूप में चुना। वर्तमान विदेश मंत्री और पेऊरल काउंसिलर मिचेलीन कैमो-रे उप राष्ट्रपति होंगे। दोनों के पास उनका वर्तमान विभाग बना रहेगा।

आर्थिक कार्य पेऊरल काउंसिलर श्री जोसफ डीस ने 19 से 23 जनवरी, 2006 के दौरान भारत का दौरा किया। नई दिल्ली में उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री एवं अधिकारियों के साथ गहन बातचीत की। उनके साथ आए उच्च स्तरीय व्यवसाय शिष्टमंडल ने 19 और 20 जनवरी, 2006 को कोलकाता में सी आई आई साझेदारी शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया।

नीदरलैंड

भारत और नीदरलैंड पर्याप्त द्विपक्षीय सहयोग के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है तथा यह 2 विलियन यूरो तक है। भारत में नीदरलैंड का कुल निवेश लगभग 2 विलियन अमरीकी डालर है।

नीदरलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा आर्थिक कार्य मंत्री श्री लौरेंस जन ब्रिंकहोर्स्ट ने 21 से 25 अक्तूबर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया। इस दौरे के दौरान नीदरलैंड उच्च शिक्षा संस्थान और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

नागरिक उड्डयन मंत्री श्री प्रफुल पटेल ने जून, 2005 में नीदरलैंड का दौरा किया। 21 नवम्बर, 2005 को हेग में कांसूलर के मुद्दे पर बैठक हुई।

डॉ. जन पीटर बालकेनेन्दे 17-20 जनवरी, 2006 तक भारत की यात्रा पर आये। यात्रा के दौरान बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों की गति को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया गया, पर्याप्त व्यापार और निवेश जिसकी विशेषता है।

तुर्की

भारत और तुर्की के बीच मैत्री एवं सहयोग के द्विपक्षीय संबंध हैं। लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल ने जून, 2005 में तुर्की का दौरा किया।

संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच वार्ता जारी है तथा सर्वोच्च स्तर पर सैन्य विनिमय के अंग के रूप में वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एस पी त्यागी ने मई, 2005 में तुर्की का दौरा किया। तुर्की के वायुसेना अध्यक्ष फरवरी, 2006 में भारत आने वाले हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने एक-दूसरे के हाइड्रोकार्बन सेक्टर, अफ्रीका और मध्य एशिया के तीसरे देशों में सहयोग तथा तुर्की के रास्ते कैस्पियन ब्रूक के परिवहन की संभावना में भागीदारी पर चर्चा करने के लिए जून, 2005 में इस्तांबूल (तुर्की) का दौरा किया।

इंस्ताबूल में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए तुर्की बैंककारी विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आवश्यक मंजूरी दी है।

यूनाइटेड किंगडम

ऐतिहासिक संबंधों, बढ़ते घनिष्ठ राजनीतिक परामर्शों, पर्याप्त आर्थिक सहायता और यू के में भारतीय मूल के काफी लोगों की मौजूदगी के मद्देनजर यू के के साथ भारत का संबंध

महत्वपूर्ण है। यूके भारत में सबसे बड़ा निवेशक है तथा 1991 के बाद और सितम्बर, 2005 तक पांचवा सबसे बड़ा। प्रतिवर्ष 5 विलियन पौंड का द्विपक्षीय व्यापार होता है। यूरोप में भारतीय निवेश का 60% यू के को जाता है, परियोजनाओं की संख्या की दृष्टि से भारत यू के में आठवां सबसे बड़ा निवेशक है।

प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सितम्बर, 2005 में भारत आए। दिल्ली में 6वें भारत-ई यू शिखर सम्मेलन के एक दिन बाद उदयपुर में सितम्बर में भारत-यूके द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा यू के के शिष्टमंडल में व्यापार और उद्योग मंत्री श्री एलन जानसन शामिल थे। प्रधान मंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया जिनकी सहायता विदेश मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने की।

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन सितम्बर, 2004 में प्रधान मंत्री की यू के यात्रा पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में था जब दो प्रधान मंत्रियों ने व्यापक सामरिक साझेदारी के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की योजना निर्धारित करने वाली श्भारत -यू केः एक नई और गतिशील साझेदारी की ओर' नामक संयुक्त घोषणा को स्वीकार किया था। संयुक्त घोषणा में विदेश मंत्रियों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन एवं बैठक की परिकल्पना थी तथा विदेश एवं रक्षा नीति, आतंकवाद से लड़ने, आर्थिक संबंध बढ़ाने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग घनीभूत करने पर बल के साथ भावी सहयोग के क्षेत्रों का रूपांकन था।

यू के ने शिखर सम्मेलन से एक सप्ताह पहले भारत के साथ नागरिक न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी सहयोग और वैज्ञानिक संपर्क संबंधी अपनी नीति की समीक्षा की।शिखर सम्मेलन में दोनों पक्ष नागरिक न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमत हुए।

भारत और यू के का आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने में सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर करार था। वे इस बात पर सहमत हुए कि धर्म, राजनीति, विचारधारा या चाहे जो कोई भी आधार हो पर आतंकवाद जायज नहीं हो सकता। प्रधान मंत्री ब्लेयर ने विस्तारित सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनर्पुष्टि की।

दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान में पर्याप्त वृद्धि के लिए वायु सेवाओं पर तथा हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग पर करार हस्ताक्षरित किए। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में कैंम्ब्रिज कालेज में एक चेयर को वित्तपोषित करेगा। श्री ब्लेयर ने छात्रवृत्ति प्रदान करने और अल्पकालीन विनिमय, ब्रिटेन जाने हेतु युवा भारतीयों को अनुसंधान एवार्ड तथा भारतीय संस्थाओं में युवा ब्रिटिश शोधकर्ताओं को समय बिताने का प्रावधान करने के लिए एक यू के-भारत शिक्षा पहल की घोषणा की।

फिल्मों के सह-निर्माण और बौद्धिक संपदा अधिकार पर करारों को भी अंतिम रूप दिया गया।

विदेश सचिव जैक स्ट्रा की यात्रा के दौरान जनवरी, 2004 में हस्ताक्षरित अवैध आव्रजकों की वापसी पर समझौता ज्ञापन को एक वर्ष के लिए फरवरी, 2005 में नवीकृत किया गया। संदिग्ध अवैध आव्रजकों की राष्ट्रीयता के सत्यापन हेतु विद्यमान क्रियाविधि को सरल बनाया गया ताकि प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके।

जीवनपर्यन्त अध्ययन, भावी और उच्च शिक्षा मंत्री बिल सम्मेल ने 31 जुलाई से 5 अगस्त, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया। यू के के रक्षा सचिव डॉ. जान रीड ने 5 एवं 6 अक्तूबर, 2005 को भारत का दौरा किया। आव्रजन, राष्ट्रीयता और नागरिकता मंत्री श्री टोनी मैरनुल्टी ने 7 से 9 नवम्बर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया।

पर्यावरण और वन मंत्री श्री ए राजा ने 10 से 12 अक्तूबर, 2005 के दौरान यू के का दौरा किया। वे वहां के पर्यावरण मंत्री इलियट मोर्ली से मिले। दोनों पक्षों ने उच्च स्तरीय स्थायी विकास वार्ता पर एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

मेरिलबोन के लॉर्डपोल के नेतृत्व में ब्रिटेन का एक संसदीय शिष्टमंडल और पांच संसद सदस्यों ने 8-से15 अक्तूबर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया। यह शिष्टमंडल राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की यू के शाखा से था। शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष, विदेश मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों तथा भारत-यू के संसदीय मित्रता समूह के सदस्यों के साथ बैठकें की। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भारत समूह के मित्रों का एक शिष्टमंडल 25 सितम्बर से 3 अक्तूबर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया।

लंदन में 17-18 नवम्बर, 2005 को भारत-यूके सामरिक वार्ता हुई जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने समकक्षी सरनिगेल निवाल्ड, विदेश नीति सलाहकार से मुलाकात की।

सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर सिफारिश करने के लिए 2000 में गठित गैर सरकारी निकाय - भारत-यूके गोल मेज की आठवीं बैठक श्री एम एच अंसारी और लार्डस्वराज

पोल की सह-अध्यक्षता में 6-7 फरवरी, 2005 को लीड्स में आयोजित हुई।

वैश्विक अर्थ व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और स्थायी विकास पर ग्लिनीगल्स में आयोजित जी 8+5 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री ने 6 से 9 जुलाई, 2005 के दौरान यूके का दौरा किया। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने संबंधी अपने संदर्शो को उजागर करने वाला एक कंट्री पेपर भारत ने प्रस्तुत किया और इसने जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी कार्य के नये सिद्धांत का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।

प्रधानमंत्री को आक्सफोर्ड विश्वविद्याालय द्वारा डाक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्रदान की गई।

यूरोपीय संघ (ई यू)

7 सितम्बर, 2005 को नई दिल्ली में छठे भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने एक व्यापक संयुक्त कार्य योजना को अपनाया जिसके तहत सामरिक साझेदारी द्वारा यथा परिकल्पित गहन सहयोग और विनियोजन को कार्यान्वित करने का प्रयास है। दोनों पक्षों ने इस अवसर पर एक राजनीतिक बयान भी जारी किया। 2004 में हेग में आयोजित 5वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में भारत और ई यू ने अपने संबंधों को सामरिक संबंध तक स्तरोन्नत किया।

यूरोपीय संघ जो एक मजबूत आर्थिक खिलाड़ी है, राजनीतिक अस्तित्व विकसित कर रहा है, अपनी भौगोलिक सीमा बढ़ा रहा है तथा समान विदेश और सुरक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

25 राष्ट्रों के एक ब्लाक, जिसका क्षेत्रफल और आबादी भारत के आधे से थोड़ी ज्यादा है, के रूप में ई यू भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र और एफ डी आई का सबसे बड़ा स्रोत और उच्च प्रौद्योगिकी का प्रमुख केद्र है। दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि हो रही है तथा व्यापार वर्ष 2004 में 33 बिलियन यूरो तक पहुँचा। जनवरी से अगस्त, 2005 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि से द्विपक्षीय व्यापार में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ई यू में भारतीय निवेश भी अब बढ़ रहा है।

ई यू के सदस्य राष्ट्रों में से यू के और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। जर्मनी इसकी सदस्यता का इच्छुक और जी-4 का सदस्य है। यू के, बैल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ईटली और नीदरलैंड भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश पार्टनर हैं।

छठा भारत-ई यू शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने एक शिष्टमंडल (2005 के उत्तरार्ध में यू के ने ई यू की रोटेटिंग प्रेसीडेंसी हासिल की) का नेतृत्व किया जिसमें श्री जोस मैनुअल बारोली, यूरोपीय आयोग अध्यक्ष, डॉ. जेवियर सोलाना, ई यू महासचिव एवं समान विदेश एवं सुरक्षा नीति प्रतिनिधि, डॉ. (सुश्री) बेनिटा फेरेरो वाल्डर, ई यू विदेश संबंध एवं यूरोपीय पड़ोस नीति आयुक्त और श्री पीटर मंडेलसन, व्यापार आयुक्त शामिल थे। व्यापार सचिव श्री एलन जांनसन भी सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया तथा उनकी सहायता विदेश मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने की।

छठे भारत-ई यू शिखर सम्मेलन में समर्थित संयुक्त कार्य योजना में वार्ता और परामर्श क्रियाविधि को मजबूत करने, राजनीतिक वार्ता एवं सहयोग गहन करने, लोगों एवं संस्कृति को साथ लाने, आर्थिक नीति वार्ता एवं सहयोग बढ़ाने तथा व्यापार एवं निवेश विकसित करने का प्रावधान है।

दोनों पक्ष विद्यमान क्रियाविधियों को मजबूत करके तथा सहयोग के लिए विचार किए जा रहे नए क्षेत्रों में इन्हें शुरू करके वार्ता को और गहन करेंगे। ये क्षेत्र हैंः बहुलतावाद एवं विविधता, क्षेत्रीय सहयोग (ई यू और सार्क), प्रजातंत्र एवं मानवाधिकार। कारगर बहुपक्षवाद, शांति बहाली और संघर्षोत्तर सहायता, निशस्त्राकरण एवं डब्ल्यू एम डी का अप्रसार तथा आतंकवाद एवं संगठित अपराध के विरूद्ध लड़ाई के क्षेत्रों में भी व्यापक सहयोग।

जहां तक लोगों एवं संस्कृति को एक साथ लाने का संबंध है, दोनों पक्षों के बीच प्रव्रजन एवं कांसूलर के मुद्दों, संसदीय, शिक्षा एवं शैक्षिक तथा सभ्य समाज विनिमयों को सुकर बनाने, सांस्कृतिक सहयोग और पारस्परिक दृश्यता बढ़ाने के लिए काम करने पर वार्ता होगी।

आर्थिक क्षेत्रों तथा पर्यावरण, स्वच्छ विकास एवं जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भेषज एवं जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, सीमा शुल्क, रोजगार एवं सामाजिक नीति, व्यवसाय सहयोग, विकास सहयोग सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और ई यू के बीच घनिष्ठ वार्ता होगी तथा सहयोग बढ़ेगा।

भारत और ईयू व्यापार एवं निवेश की बाधाएं दूर करने तथा द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहमति बढ़ान के लिए सार्थक कदम उठाने पर सहमत हो गए हैं। इन कदमों में उच्च स्तरीय

व्यापार समूह का गठन, विश्व व्यापार संगठन/दोहा विकास के एजेंडा से संबंधित मुद्दों पर वार्ता, व्यापार/सेनिटरी एवं फिटोसेनिटरी मुद्दे, व्यापार रक्षा उपकरण एवं सेवाएं शामिल हैं।

शिखर सम्मेलन में गैलिलियो परियोजना में भारत की भागीदारी पर एक संरचना करार शुरूकिया गया। इसी दिन राजनीतिक सम्मेलन के रूप में भारत-ई यू व्यापार शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ऊर्जा के भावी स्रोत के रूप में न्यूक्लियर फ्यूजन में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना में भारत की भागीदारी के लिए ई यू का सशक्त समर्थन दिसम्बर, 2005 में आई टी ई आर के पूर्व सदस्य के रूप में भारत के स्वीकार किए जाने का महत्वपूर्ण कारक था।

भारत-ई यू गोलजेज की 9वीं बैठक हैदाबाद में 18 से 20 सितम्बर, 2005 के दौरान हुई।

भारत-ई यू संयुक्त आयोग की 15वीं बैठक नई दिल्ली में 24 एवं 25 अक्तूबर, 2005 को हुई। श्री हर्वे जुवानजीन, उपमहानिदेशक, विदेशी मामले (एशिया एवं लैटिन अमरीका), यूरोपीय आयोग ने ई यू शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य सचिव ने किया। जे सी एम के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार एवं आर्थिक मामलों पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय व्यापार समूह की बैठक शीघ्र होगी। दोनों पक्ष चार नए कार्य समूहों (आहार प्रसंस्करण, भेषज एवं जैव प्रौद्योगिकी), एस पी एस (सेनिटरी, फिटो-सेनिटरी), टी बी टी (व्यापार में तकनीकी बाधाएं), कृषि मेरीन उत्पाद के विचाराधीन विषयों को अंतिमरूप देने तथा उनकी पहली बैठक 2006 की पहली तिमाही तक आयोजित करने पर सहमत हुए।

भारत-ई यू ऊर्जा पैनल की पहली बैठक ब्रुसेल्स में 29 जून, 2005 को हुई जिसमें भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश सचिव श्री श्याम सरन ने तथा ई यू पक्ष का नेतृत्व यूरोपीय आयोग के ऊर्जा एवं परिवहन महानिदेशक श्री लामौरेक्स ने किया। पैनल ने आई टी ई आर में भारत की भागीदारी सहित कोयला एवं स्वच्छ कोयला रूपांतरण प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता एवं नवीकरण ऊर्जा तथा फ्यूजन ऊर्जा पर तीन कार्य समूह गठित किए।

कांसूलर मुद्दों पर भारत-ई यू संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक 9 नवम्बर, 2005 को नई दिल्ली में हुई। आतंकवाद प्रतिवाद पर भारत-ई यू जे डब्ल्यू जी का आयोजन ब्रुसेल्स में 12 दिसम्बर, 2005 को हुआ।

कपड़ा पर भारत-ई यू जे डब्ल्यू जी की बैठक ब्रुसेल्स में 22 नवम्बर, 2005 को हुई।

सूचना समाज पर जे डब्ल्यू जी की चौथी बैठक ब्रुसेल्स में 7 अक्तूबर, 2005 को हुई।

भारत-ई सी एस एंड टी संचालन समिति की दूसरी बैठक 29 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में हुई। समिति ने 2005 -06 के लिए ई सी-भारत एस एंड टी कार्य योजना अंगीकृत किया जिसमें सूचना समाज प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य के लिए जेनोमिक्स एवं जैव प्रौद्योगिकी, नानो प्रौद्योगिकी एवं कार्यात्मक सामग्री, भूतल परिवहन अनुसंधान एवं विकास, ऊर्जा भौतिकी तथा एरोनाटिक्स के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना है।

संयुक्त कार्य योजना में की गई परिकल्पा के अनुसार पर्यावरण फोरम की बैठक 12 नवम्बर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। मुख्य विषय था : अपशिष्ट प्रबंधन, खासकर घातक अपशिष्ट और शहरी अपशिष्ट का प्रबंधन। इसके अलावा क्योटो प्रोतोकोल की स्वच्छ विकास क्रियाविधि के क्रियान्वयन पर एक भारत-ई यू कार्यशाला 11 नवम्बर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

ई यू-भारत आर्थिक क्रास सांस्कृतिक कार्यक्रम पर एक सेमिनार 13 से 14 दिसम्बर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

■■

अमरीका 8

संयुक्त राज्य अमरीका

भारत और अमरीका ने अपने संबंधों का विस्तार करने की ठोस वचनवद्धता का प्रदर्शन किया जिसके फलस्वरूप राजनैतिक और सरकारी स्तरों पर निरंतर संपर्क हुए और जिससे द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुआ। आपसी हित के वैश्विक, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर हमारे विचारों में निरंतर समानता आ रही है। बहु-फलकीय भारत अमरीकी क्रियाकलाप में शामिल थे - सामरिक और सुरक्षा मसले, रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, प्रसार का विरोध, व्यापार और निवेश,विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अतंरिक्ष, स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण।

मार्च, 2005 में अमरीकी विदेश मंत्री डा. कोंडोलीजा राइस की भारत यात्रा के पश्चात तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह ने अप्रैल, 2005 तक अमरीका का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति बुश से मुलाकात की जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत-अमरीका संबंध को ऊंचे स्तर पर पहुंचाने की वचनबद्धता व्यक्त की। अमरीकी राष्ट्रपति ने अंतराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा आपसी आर्थिक लाभ के लिए भारत के साथ मिलकर कार्य करने के अमरीकी प्रशासन के संकल्प का उल्लेख किया। हमारे विदेश मंत्री और अमरीकी विदेश मंत्री ने अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तौर-तरीकों का पता लगाया ताकि सामरिक भागीदारी में भारत-अमरीका अगला कदम पहल से संबंधित कार्य में तेजी लाया जा सके और ऊर्जा पर बातचीत आरंभ की जा सके।

विदेश सचिव श्री श्याम शरण ने भारत-अमरीका वैश्विक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए 16-19 मई, 2005 तक अमरीका का दौरा किया। विदेश सचिव ने एशियाई सुरक्षा वार्ता रूपरेखा के अंतर्गत राजनैतिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, निकोलस बर्न्स से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मामलों पर बातचीत की।

प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा

राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश के निमंत्रण पर प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 18-20 जुलाई, 2005 तक अमरीका का दौरा किया। संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने भारत-अमरीका संबंधों में परिवर्तन लाने और एक वैश्विक भागीदारी का निर्माण करने की अपनी वचनबद्धता की घोषणा की। बहुफलकीय सहयोगी भागीदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा गयी और अनेक पहलकदमियाँ की गयीं। इनमें आर्थिक और व्यापार संबंधों के क्षेत्र में सहयोग, भारत - अमरीका आर्थिक वार्ता की बहाली, दोनों पक्षों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक मंच की स्थापना, ऊर्जा एवं पर्यावरण, लोकतंत्र और विकास, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला, अप्रसार और सुरक्षा मामले, सामरिक भागीदारी में अगला कदम पहल की पूर्णता, उच्च प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, असैनिक नाभिकीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा, एच आई वी/एड्स के विरूद्ध युद्ध और आपदा राहत कार्रवाइयों को शामिल किया गया।

स्वच्छ और प्रभावी तरीके से विश्व में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए असैनिक नाभिकीय ऊर्जा के महत्व को स्वीकार करते हुए दोनों नेताओं ने भारत द्वारा अपने असैनिक ऊर्जा कार्यक्रम को विकसित करने की योजनाओं पर चर्चा की। राष्ट्रपति बुश ने व्यापक विनाश के हथियारों का प्रचार रोकने की भारत की सुदृढ़ वचनबद्धता की सराहना की और कहा कि उच्च नाभिकीय प्रौद्योगिकी संपन्न एक जिम्मेदार राज्य के रूप में भारत को वही लाभ और फायदे मिलने चाहिएं जो ऐसे राज्यों को सुलभ हैं। राष्ट्रपति बुश ने आश्वासन दिया कि वे कांग्रेस से सहमति प्राप्त करेंगे कि अमरीकी कानूनों और नीतियों में सामंजस्य लाया जाए और अमरीका अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ कार्य करके अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ इस प्रकार तालमेल बिठाये कि भारत के साथ पूर्ण असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग और व्यापार संभव हो सके। राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि अमरीका अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्युक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर पहल और जेनरेशन IV अंतरराष्ट्रीय मंच में शामिल होने के भारत के अनुरोध पर विचार करने के लिए अपने भागीदारों को प्रोत्साहित करेगा। दिसम्बर, 2005 में भारत को आई टी ई आर पहल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

हमारे प्रधान मंत्री ने सूचित किया कि भारत उन दायित्वों और कार्यों की जिम्मेदारी उठाने तथा उन लाभों और फायदों को प्राप्त करने के लिए तैयार है जो अमरीका जैसे उच्च नाभिकीय प्रौद्योगिकी संपन्न देशों को सुलभ हैं। इन दायित्वों में असैनिक और सैन्य नाभिकीय संयंत्रों की पहचान करके उन्हें अलग-अलग करना और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के समक्ष अपने असैनिक संयंत्रों के संबंध में घोषणा करना, अपने असैनिक नाभिकीय संयंत्रों को स्वैच्छिक रूप से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षापायों के अंतर्गत रखना और इन संयंत्रों के संबंध में एक अतिरिक्त आई ए ई ए प्रोतोकोल संपन्न करना तथा एम टी आर सी और एन एस जी दिशानिर्देशों के साथ तालमेल बैठाना और उनका पालन करना शामिल है।

प्रधान मंत्री ने 19 जुलाई, 2005 को अमरीकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय-अमरीकी समुदाय, अमरीकी मीडिया और नेशनल प्रेस क्लब के साथ भी क्रियाकलाप किया।

संयुक्त राष्ट्र के 60वें महाधिवेशन के अवसर पर 13 सितम्बर, 2005 को प्रधान मंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ हमारे प्रधान मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति ने 14 सितम्बर, 2005 को संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। भारत ने लोकतंत्र कोष में 10 मि. अमरीकी डालरों का योगदान दिया।

रक्षा

रक्षा मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने अमरीकी रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफील्ड के निमंत्रण पर 27-30 जून, 2005 तक अमरीका का दौरा किया।"अमरीका-भारत रक्षा संबंधों की नयी रूपरेखा" पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें अगले 10 वर्षों के लिए अमरीका-भारत रक्षा संबंधों की रूपरेखा बनायी गयी है और सहयोग के बेहतर स्तर की कल्पना की गयी है। अमरीका - भारत रक्षा नीति दल के अंतर्गत नया "रक्षा खरीद और उत्पादन समूह" बनाने का निर्णय लिया गया।

भारत और अमरीकी नौसेना के बीच प्रतिवर्ष किया जाने वाला नौसेना अभ्यास मालावार 2005 भारत के पश्चिमी तट में 25 सितम्बर से 4 अक्तूबर, 2005 तक किया गया। भारतीय और अमरीकी वायुसेना ने अपना संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कोप इन्डिया 05, नवम्बर, 2005 में पश्चिम बंगाल में किया।

भारत-अमरीका रक्षा नीति समूह (डी पी जी) की सातवीं बैठक 21-23 नवम्बर, 2005 तक वाशिंगटन डी सी में हुई। डी पी जी ने चार उप-समूहों : सैन्य सहयोग समूह, संयुक्त प्रौद्योगिकी समूह, वरिष्ठ सुरक्षा प्रौद्योगिकी समूह और वरिष्ठ प्रौद्योगिकी सुरक्षा समूह के रिपोर्टों की समीक्षा की। हाल में गठित रक्षा खरीद और उत्पादन समूह की पहली बैठक 21 नवम्बर, 2005 को वाशिंगटन डी सी में हुई।

आर्थिक

योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. मोन्टेक सिंह अहलूवालिया और अमरीकी ऊर्जा मंत्री सैमुअल डब्ल्यू बोडमैन के बीच 31 मई, 2005 को हुई बैठक के दौरान द्विपक्षीय ऊर्जा वार्ता का शुभारंभ किया गया। इस वार्ता तंत्र के तहत पांच कार्यकारी समूहों का गठन किया गया : (i) तेल एवं प्राकृतिक गैस (ii) कोयला (iii) अक्षय ऊर्जा और नयी प्रौद्योगिकियाँ (iv) विद्युत एवं ऊर्जा प्रभाविता तथा (v) असैनिक नाभिकीय ऊर्जा। कार्यकारी दलों के बीच निधार्रित क्षेत्रों में सहयोग की योजना बनाने के संबंध में अनेक चर्चाएं हुई। इस वार्ता तंत्र के प्रथम संचालन समिति की बैठक 22 दिसम्बर, 2005 को वाशिंगटन डी सी में विदेश सचिव और अमरीकी ऊर्जा अंडर सेक्रेटरी के बीच हुई।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा अमरीकी राष्ट्रपति के सलाहकार एलन हुब्बार्ड के बीच वाशिंगटन डी सी में हुई बैठक के दौरान 1 जून, 2005 को पुनर्गठित मंत्रिमंडल स्तरीय आर्थिक वार्ता तंत्र की पहली बैठक हुई। उन्होंने टी डी ए संरचना करार को शीघ्र शामिल करने, और निवेश संवर्द्धन तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उपायों पर बल दिया। 15 दिसम्बर, 2005 को मंत्रिमण्डल ने बोइंग कॉरपोरेशन ऑफ यू एस से एअर इन्डिया के लिए 68 विमान खरीदे जाने का अनुमोदन कर दिया। जुलाई, 2005 में धाबोल बिजली संयंत्र के मसले का समाधान हो गया और अब इस संयंत्र के जुलाई, 2006 से उत्पादन आरंभ करने की आशा है।

भारत और अमरीका ने अमरीकी परिवहन मंत्री नोरमन मिनेता की भारत यात्रा के दौरान 14 अप्रैल, 2005 को एक नये "मुक्त आकाश" हवाई परिवहन करार (ए टी ए) पर हस्ताक्षर किये। इस नये ए टी ए, जो 1956 के करार का स्थान लेगा, के उपरांत अनेक एअर लाइनों ने भारत और अमरीका के बीच सीधे उड़ानों की शुरूआत की है। भारत और अमरीका ने दो सहयोग ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं, एक परिवहन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर और दूसरा समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर। पहले करार से टौल-आधारित एक्समार्ग और राजमार्ग नेटवर्क परियेजनाओं का विकास करने और दूसरे से बंदरगाह

प्रबंधन, अंतर्देशीय जल परिवहन, समुद्री प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकीय विकास जैसे क्षेत्रों में अमरीकी अनुभव का उपयोग करना सुविधाजनक हो जाएगा।

अमरीकी वित्त मंत्री जॉन डब्ल्यू स्नो की भारत यात्रा के दौरान 9 नवम्बर, 2005 को नई दिल्ली में भारत-अमरीका वित्तीय और आर्थिक मंच की तीसरी बैठक हुई। अमरीकी व्यापार और विकास ऐजेसी (यू एस टी डी ए) और भारतीय वित्त मंत्रालय के बीच 9 नवम्बर, 2005 को सहयोग करार संपन्न किया गया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ और अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत रॉव पोर्टमैन ने 12 नवम्बर, 2005 को भारत - अमरीका व्यापार नीति मंच के पहले सत्र की सह-अध्यक्षता की। इस मंच का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाना है तथा इसकी कार्यसूची में टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं, कृषि, निवेश, सेवाओं, बौद्धिक सम्पदा और विश्व व्यापार संगठन की दोहा दौर की बैठकों पर चर्चा करना शामिल थी।

अमरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना रहा। जनवरी-अक्तूबर, 2005 के लिए अमरीका के साथ भारत का कुल व्यापार 22.21 बिलियन अमरीकी डालरों (पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान के 18.07 मि. अमरीकी डालरों से 23% अधिक) का रहा। इस अवधि के दौरान अमरीका को भारतीय निर्यात में 20% की वृद्धि हुई। हीरे, बहुमूल्य पत्थर, कपड़े अमरीका को होने वाले भारतीय निर्यात का 50% है जबकि इंजीनियरिंग सामान और मशीनरी, बहुमूल्य पत्थर और विमान तथा विमानन के घटक अमरीका द्वारा भारत में किये जाने वाले मुख्य निर्यात हैं।

कृषि के लिए अमरीकी अंडर सेक्रेटरी जे.बी. पेन्न की यात्रा के दौरान 12 नवम्बर, 2005 को अमरीका और भारत ने जुलाई, 2005 के दौरान प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान आरंभ किये गये अमरीका - भारत ज्ञान पहल को औपचारिक रूप देने के लिए भारत और अमरीका द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये। कृषि बोर्ड पर ज्ञान पहल की बैठक 15-16 दिसम्बर, 2005 तक वाशिंगटन में हुई।

प्रौद्योगिकी

जैसा कि एन एस एस पी पहल के अंतर्गत निहित है 30 अगस्त, 2005 को अमरीकी वाणिज्य विभाग ने नाभिकीय अप्रसार कारणों से अमरीका द्वारा कुछ मदों पर एकपक्षीय रूप से लगाये गये निर्यात नियंत्रण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और छह भारतीय इकाइयों को अमरीकी इकाई सूची से हटा दिया। इकाई सूची से हटायी गई छह भारतीय इकाइयों में शामिल थीं तारापुर, राजस्थान और कुदानकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन। अन्य तीन इकाइयाँ हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अधीनस्थ संस्थान।

भारत-अमरीका उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह (एच टी सी जी) की चौथी बैठक 30 नवम्बर - 1 दिसम्बर, 2005 तक नई दिल्ली में हुई। विदेश सचिव और अमरीकी वाणिज्य अंडर सेक्रेटरी डेविड मैककोरमिक ने बैठक की सह अध्यक्षता की। 30 नवम्बर, 2005 को एक सार्वजनिक-निजी मंच ने भारतीय और अमरीकी कंपनियों को नेनो-प्रौद्योगिकी, जैव - प्रौद्योगिकी और रक्षा व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपायों की अनुशंसा करने का अवसर प्रदान किया। एच टी सी जी ने निर्यात नीतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में हाल में हुई घटनाओं की समीक्षा भी की।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिबल और विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने 17 अक्तूबर, 2005 को वाशिंगटन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार संपन्न किया। इस करार में एक बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रोतोकोल भी शामिल किया गया जिससे बुनियादी विज्ञान, अंतरिक्ष, ऊर्जा, नेनो-प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सितम्बर, 2005 में आये कैटरीना तूफान के पश्चात भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत सहायता के लिए अमरीकी रेड क्रास को 5 मि. अमरीकी डालर दिये। इसके अतिरिक्त भारतीय वायु सेना के विमान द्वारा अमरीका को 25 टन राहत सामग्री दी गयी जिसमें कंबल, चादरें, तिरपाल और निजी साफ-सफाई के सामान शामिल थे।

भारत - अमरीका सांसद मंच ने 25-28 अक्तूबर तक वाशिंगटन का दौरा किया। सांसद श्री जे. बी. पंडा के नेतृत्व में शिष्टमण्डल ने अन्य के साथ - साथ विदेश मंत्री, अमरीकी रक्षा विमाग में अंडर सेक्रेटरी एरिक एडेलमैन, ऊर्जा विभाग के अंडर सेक्रेटरी जर्मन और इन्डिया हाउस कॉकस के वर्तमान और भूतपूर्व अध्यक्षों से मुलाकात की।

नाभिकीय

भारत और अमरीका ने 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए असैनिक नाभिकीय ऊर्जा पर एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया। विदेश विभाग में राजनैतिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी निक बर्न्स ने 21-22 अक्तूबर को कार्यकारी दल की पहली बैठक के लिए भारत का दौरा किया। तदुपरांत कार्यकारी दल की दूसरी

बैठक के लिए विदेश सचिव 21-22 दिसम्बर, 2005 को अमरीका में थे और उन्होंने अंडर सेक्रेटरी बर्न्स के साथ संयुक्त वक्तव्य की बचनबद्धताओं के अंतर्गत आने वाले प्रक्रियाओं की समीक्षा की।

अंतरिक्ष

भारत और अमरीका ने अंतरिक्ष सहयोग पर एक संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना की है। चंद्रायण मिशन के लिए एक तकनीकी सहायता करार को अंतिम रूप दिया गया है।

कनाडा

नाभिकीय

कनाडा और भारत के बीच क्रियाकलाप गहन हुए जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण करार, संपन्न किये गये। कनाडा द्वारा नाभकीय आपूर्ति समूह से संबंधित दोहरे उपयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षापायों के तहत भारतीय असैनिक नाभिकीय संयंत्रों के लिए नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित दोहरे उपयोग के मदों की आपूर्ति करने की उसकी इच्छा की घोषणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। तत्कालीन विदेशमंत्री श्री नटवर सिंह ने सितम्बर, 2005 में कनाडा का दौरा किया। द्विपक्षीय वार्ताओं के फलस्वरूप नाभिकीय सुरक्षा सहयोग पर करार संपन्न किया गया और अनेक असैनिक नाभिकीय मसलों पर वैज्ञानिक और तकनीकी वार्ता की गयी। यह घोषणा भी की गयी कि भारतीय प्रधान मंत्री वर्ष 2006 में कनाडा के दौरे पर जाएंगे।

सामरिक मामले

दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के बीच नीति नियोजन, आतंकवाद का मुकाबला और सामरिक मसलों पर नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई।

व्यापार और निवेश

अप्रैल, 2005 में कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री जिम पीटरसन के नेतृत्व में कनाडा के एक शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया। पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मई, 2005 में कनाडा का दौरा किया। जून, 2005 में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमण्डल ओटावा गया जिसके दौरान दोनों देशों के बीच उड़ानों की संख्या में पांच गुणा वृद्धि करने के संबंध में एक करार संपन्न किया गया। जनवरी, 2006 में क्यूबेक के प्रधान मंत्री जीन केरेस्ट के नेतृत्व में क्यूबेक के व्यवसायिक और शैक्षिक क्षेत्र में प्रतिनिधियों के एक शिष्टमण्डल ने कोलकाता में आयोजित भागीदारी शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

तेल एवं प्राकृतिक गैस

अगस्त, 2005 में तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग के लिए अलबर्टा अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया। कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री जिम पीटरसन के नेतृत्व में एक 115 संसदीय शिष्टमण्डल ने नई दिल्ली में आयोजित 11 वें प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन और प्रौद्योगिकी मंच में भाग लिया। इसमें कनाडा एक भागीदार देश था। श्री पीटरसन ने घोषणा की कि कनाडा ने दोनों देशों के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक संस्थानों के बीच अनुसंधान और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 6.75 कनाडियन डालरों की राशि निर्धारित की है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

नवम्बर, 2005 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री कपिल सिबल ने कनाडा का दौरा किया और भारत-कनाडा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार पर हस्ताक्षर किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव के नेतृत्व में सूक्ष्म प्रौद्योगिकी से संबद्ध एक शिष्टमण्डल कनाडा गया जिसका उद्देश्य भारत में एक संयुक्त सूक्ष्म-प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने की संभावना का पता लगाया था।

पर्यावरण

सितम्बर, 2005 में कनाडा के पर्यावरण मंत्री ने आपसी हित के बहुपक्षीय/वैश्विक पर्यावरणीय मसलों पर बातचीत करने के लिए भारत का दौरा किया। पर्यावरण और वन मंत्री श्री ए राजा ने नवम्बर/दिसम्बर, 2005 में मांट्रियल में आयोजित सी ओ पी - 11 की मंत्रिस्तरीय तैयारी बैठक में भाग लेने के लिए ओटावा का दौरा किया। नवम्बर/दिसम्बर, 2005 में पर्यावरण एवं वन मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमण्डल ने मांट्रियल में आयोजित वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन सी ओ पी - 11 में भाग लिया।

लातिन अमरीका और कैरीबिया

लातिन अमरीका क्षेत्र के साथ भारत के क्रियाकलाप और संवर्द्धित हुए। राजनैतिक वार्ता, सांस्कृतिक क्रियाकलाप और व्यवसाय, वाणिज्य तथा निवेश बढ़ाने के लिए विद्यमान तंत्रों को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया। मरसोकर, कैन (एंडीयन समुदाय), कैरिकॉम और मध्य अमरीकी देश समूह (सीका) जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ करार किए गये और उन पर कार्रवाई की गयी।

19 जुलाई, 2005 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कैपिटल हिल में अमरीकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए।

सी ई ओ फोरम के सदस्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ 18 जुलाई, 2005 को ह्वाइट हाउस में।

अर्जेन्टीना

अर्जेन्टीना के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे। विदेश राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने अप्रैल, 2005 में अर्जेन्टीना का दौरा किया और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के संबंध में अर्जेन्टीना के प्राधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने एशिया प्रशांत और ओसियानियाँ के लिए मित्र सांसदों के समूह के साथ और विदेश मामले समिति के सदस्यों के साथ मुलकात की। कृषि राज्य मंत्री ने जुलाई, 2005 में अर्जेन्टीना का दौरा किया और कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत की।

बोलीविया

वर्ष 2005 में बोलीविया में राजनैतिक उथल-पुथल रही। बोलीविया के साथ भारत का द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और सहयोगी रहा।

ब्राजील

ब्राजील के साथ भारत के संबंध और सुदृढ़ हुए। यात्राओं का आदान-प्रदान किया गया और जी - 4, जी 8+5 शिखर सम्मेलन और आइ बी एस ए (भारत - ब्राजील - दक्षिण अफ्रीका) जैसे द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर उच्च-स्तरीय क्रियाकलाप किये गये। भारत से हुई महत्वपूर्ण यात्राओं में शामिल थीं जुलाई में कृषि मंत्री श्री शरद पवार की यात्रा, रियो डी जेनारियो में आई वी एम ए मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्य मंत्री श्री कपिल सिबल की यात्रा और जून, 2005 में वैज्ञानिक परामर्शी समिति के अध्यक्ष की यात्रा। कृषि मंत्री की भारत यात्रा के दौरान आई सी ए आर और ब्राजील में इसके समकक्ष ई एम आर ए पी ए के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। साओ पाउलो के गवर्नर ने नवम्बर, 2005 में भारत का दौरा किया। विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और व्यावसायिकों के एक बड़े शिष्टमण्डल के साथ संयुक्त आयोग की बैठक और वाणिज्य सेमिनार के सिलसिलले में 2-4 फरवरी, 2006 तक ब्राजील गये।

ब्राजील को किया जाने वाला भारतीय निर्यात 984 मि. अमरीकी डालरों का और भारतीय आयात इस अवधि के दौरान 919 मि. अमरीकी डालरों का रहा। केमिक्सिल और फार्मेक्सिल के व्यापार शिष्टमण्डलों ने मई 2005 में साओ पाउलो का दौरा किया। ब्राजील की पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोब्रास ने मई में और खनन कंपनी सी वी आर डी ने जुलाई में भारत का दौरा किया। निजी क्षेत्र के बीच क्रियाकलाप बढ़ रहा है।

चिली

भारत और चिली के बीच द्विपक्षीय संबंधों में संतोषजनक प्रगति हुई है। चिली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन दोहराया है और अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।

संसदीय मामले और शहरी विकास मंत्री श्री गुलाम नवी आजाद के नेतृत्व में भारतीय सांसदों के एक नौ सदस्यीय शिष्टमण्डल ने जून, 2005 में चिली का दौरा किया। भारत-चिली अंतर संसदीय मैत्री समूह की स्थापना की गयी। विदेश राज्य मंत्री श्री राव इन्द्रजीत सिंह ने लोकतंत्रों के समुदाय पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 27 अप्रैल से 2 मई तक चिली का दौरा किया। विदेश राज्य मंत्री की यात्रा के दौरान एक अधिमानी व्यापार करार भी संपन्न किया गया।

घनिष्ठ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विकसित करने के अपने आपसी हित के अनुसरण में चिली के रक्षा मंत्री ने अप्रैल में भारत का दौरा किया। एन डी सी के 21 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने मई में चिली का दौरा किया,चीली वायु सेना प्रमुख ने अगस्त में भारत का दौरा किया आर डी आर डी ओ के चार सदस्यीय शिष्टमण्डल ने चिली का दौरा किया। रक्षा मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 27 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2005 तक चिली का दौरा किया। एच ए एल और चिली के ई एन ए ई आर के बीच एक करार संपन्न किया गया जिसके जरिए ई एन ए ई आर को एच ए एल के लिए पुर्जे बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया।

कोलंबिया

कोलंबिया के साथ द्विपक्षीय संबंध विविधतापूर्ण हुए। केमेक्सिल और राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र के एक 20 सदस्यी शिष्टमण्डल ने बोगोटा का दौरा किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्य मंत्री श्री कपिल सिबल ने जून, 2005 में कोलंबिया का दौरा किया और उन्होंने कोलंबिया के विदेश मंत्री के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता संपन्न किया।

क्यूबा

भारत-क्यूबा संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे। विदेश राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने सितम्बर, 2005 में क्यूबा का दौरा किया। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये गये। ओ एन जी सी विदेश लि. ने क्यूबाई ई ई जेड में दोहन के लिए तेल ब्लाक्स आबंटित करने के लिए

क्यूबाई प्राधिकारियों के साथ बातचीत की। भारतीय दवा कंपनियों ने अप्रैल, 2005 में हवाना में आयोजित स्वास्थ्य मेले में भाग लिया।

डोमिनिकन गणराज्य

सूचना प्रौद्योगिकी और निवेश संवर्द्धन मंत्री ने जून, 2005 और नवम्बर, 2005 में भारत का दौरा किया। उन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ क्रियाकलाप किया और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद के साथ मुलाकात की।

इक्वाडोर

इक्वाडोर में राजनैतिक उथल-पुथल रही। उप-राष्ट्रपति श्री अल्फ्रडो पलसियों को अप्रैल में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। भारत और इक्वाडोर के बीच प्रथम विदेश कार्यालय स्तरीय परामर्श जून, 2005 में क्विटो में हुआ जब सचिव (पश्चिम) एक शिष्टमण्डल के साथ इक्वाडोर गये। दोनों पक्ष बी आई पी पी ए, डी टी ए ए, सांस्कृतिक करार, शैक्षिक करार, ओ वी एल और पेट्रो इक्वाडोर के बीच समझौता ज्ञापन तथा राजनयिक अकादमियों के बीच करार को शीघ्र औपचारिक रूप देने पर सहमत हुए।

मैक्सिको

भारत और मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय संबंध विकसित और संवर्द्धित हुए। भारत-मैक्सिको संयुक्त आयोग की चौथी बैठक अक्तूबर, 2005 में नई दिल्ली में हुई। विदेश राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह और मैक्सिको की विदेश उप-मंत्री सुश्री लोर्डेस अरान्डा बेजाउरी ने अपने - अपने शिष्टमण्डलों का नेतृत्व किया। राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की अनिवार्यता से छूट देने पर करार, भारत के एफ एस आइ और एम आर आई मैक्सिको, के बीच शैक्षिक सहयोग करार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, एक शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करार करने पर सहमति हुई। लघु उद्योग क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर लघु उद्योग मंत्री की फरवरी, 2006 में होने वाली मैक्सिको की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने की आशा है।

प्रतियोगिता से संबद्ध मैक्सिको राज्य समिति के एक चार सदस्यीय शिष्टमण्डल अक्तूबर, 2005 में भारत आया और इसने वाणिज्य तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के साथ क्रियाकलाप किया। शिष्टमण्डल ने राज्य सभा के उप - सभापति, वित्त मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के साथ मुलाकात की।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान मैक्सिको को किया जाने वाला निर्यात एक विलियन अमरीकी डालर से अधिक का हो जाने की आशा है। द्विपक्षीय व्यापार दो बि. अमरीकी डालरों से अधिक का होने की आशा है जिससे मैक्सिको इस क्षेत्र में हमारे सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक हो जाएगा।

पराग्वे

पराग्वे के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंध हैं। पराग्वे के विदेश मंत्री डा. लेयला रेचिड डी कोवेल्स ने सहयोग संबर्द्धित करने के तरीकों का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया और उन्होंने नई दिल्ली में आवासी राजनयिक मिशन खोलने की घोषणा की।

पेरू

द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ और ठोस रहे। विदेश कार्यालय परामर्शों का तीसरा दौर जून, 2005 में जून में हुआ जब सचिव (पश्चिम) वहाँ एक शिष्टमण्डल के साथ गये थे। पेरू ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए समर्थन व्यक्त किया। पेरू ने भारत और सी ए एन (एन्डियन देशों के समूह) के बीच एक संयुक्त आयोग बनाने का प्रस्ताव किया। पेरू ने कृषि और रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में रूचि दिखायी है। पेरू के विदेश मंत्री के मार्च, 2006 में राजकीय यात्रा पर आने की आशा है।

वेनेजुएला

मार्च, 2005 में राष्ट्रपति उयूगो चावेज की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक निर्णायक घटना थी। हाइड्रोकार्बन्स से संबद्ध भारत-वेनेजुएला संयुक्त कार्यकारी दल की चौथी बैठक अप्रैल, 2005 में कराकस में हुई। तत्पश्चात राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान संपन्न समझौता ज्ञापन के अनुसरण में सैन क्रिस्टोबाल का तेल क्षेत्र ओ वी एल को सौंप दिया गया। राजस्थान में भारी तेल निकालने के लिए ऑयल इन्डिया लि. और पी डी वी एस ए के बीच संयुक्त उपक्रम के पहले चरण का शुभारंभ अक्तूबर, 2005 में हुआ।

संसदीय मामले और शहरी विकास मंत्री श्री गुलाम नवी आजाद के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने जून, 2005 में

वेनेजुएला का दौरा किया। स्वास्थ्य और दवाओं के क्षेत्र में सहयोग के फलस्वरूप वेनेजुएला को पर्याप्त मात्रा में दवाओं और आंखों के इलाज की सामग्रियाँ भेजी जा रही है। विदेश राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने पहले भारत-वेनेजुएला संयुक्त आयोग के लिए 31 अगस्त से 3 सितम्बर, 2005 तक वेनेजुएला का दौरा किया। राजनयिक और सरकारी पासपोर्टधारकों के लिए वीजा की छूट देने पर एक करार संपन्न किया गया।

वेनेजुएला के बुनियादी उद्योग और खनन मंत्रालय के निवेश संवर्द्धन उप-मंत्री ने नवम्बर,2005 में भारत का दौरा किया। डी टी ए ए वार्ता का पहला दौर भी नवम्बर, 2005 में भारत में आयोजित किया गया।

मध्य अमरीका

मध्य अमरीका के सात देशों - कोस्टारिका, बेलिज, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा के साथ भारत के संबंधों में ठोस विकास हुआ। आर्थिक वाणिज्यिक संबंधों में प्रगति हुई। इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में चित्र प्रदर्शनियाँ और फिल्म महोत्सवों का ओजन किया गया।

पनामा

पनामा के प्रथम उप - राष्ट्रपति और विदेश मंत्री श्री सैमुअल लेविस नवारो ने एक व्यवसायिक शिष्टमण्डल के साथ नवम्बर, 2005 में भारत का दौरा किया। इस शिष्टमण्डल ने वाणिज्य एवं उघोग मंत्री श्री कमलनाथ और विदेश राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह के साथ बातचीत की। वाणिज्यिक वीजा जारी किये जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पत्रों का आदान-प्रदान किया गया।

20 अक्तूबर, 2005 को पनामा में भारतीय नौवहन रजिस्ट्रार और पनामा समुद्री प्राधिकार के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। समुद्र परिवहन और बंदरगाह विकास पर एक समझौता ज्ञापन, एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और कृषि पर एक कार्य योजना पर भी सहमति हुई है। केमिक्सेसिल के 18 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने जून, 2005 में पनामा का दौरा किया/जुलाई, 2005 में पनामा में भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया।

ग्वाटेमाला

ग्वाटेमाला के विदेश संबंध मंत्री श्री जोर्ज ब्रिज अबुलाराक ने 1-7 मई, 2005 तक भारत का दौरा किया। भारत के विदेश मंत्रालय और ग्वाटेमाला के विदेश संबंधी मंत्रालय के बीच विदेश कार्यालय परामर्शों के लिए एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। दौरे पर आये मंत्री ने निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ क्रियाकलाप किया और वे बंगलौर के जैव-औद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों में गये। अक्तूबर, 2005 में आये स्टान तूफान के बाद भारत ने ग्वाटेमाला के लिए दवाएं और राहत सामग्रियाँ भेजी।

कैरिकोम

भारत ने कैरिकोम देशों के साथ पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंध बनाये रखा है। कैरिकोम क्षेत्र ने भी आर्थिक और तकनीकी सहयोग के भारत के प्रस्ताव और दी गयी ऋण श्रृंखलाओं का स्वागत किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, एच आई वी/एड्स की दवाओं सहित अन्य प्रकार के भेषजों, आई सी टी और कृषि क्षेत्रों की पहचान सहयोग के लिए मुख्य क्षेत्रों के रूप में की गयी।

गुयाना

भारत और गुयाना के बीच संबंध घनिष्ठ रहे। संसदीय मामले और शहरी विकास मंत्री श्री गुलाम नवी आजाद के नेतृत्व में भारतीय सांसदों के एक सद्भावना शिष्टमण्डल ने 30 मई से 2 जून, 2005 तक जार्जटाउन का दौरा किया। भारत सरकार की वित्तीय सहायता से 25 मि. अमरीकी डालरों की लागत से जार्जटाउन में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अप्रैल, 2005 में आरंभ हुआ। जुलाई, 2005 में द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण करार पर बातचीत की गयी। भारत द्वारा वित्त पोषित और 1.3 मि. अमरीकी डालरों की लागत से कैरिकोम सचिवालय के कंप्यूटरीकरण की परियोजना पूरी की गयी और इसे 6 अगस्त, 2005 को कैरीबियाई समुदाय (कैरिकोम) की 32 वीं वर्षगांठ के अवसर पर महासचिव को सौंपी गयी।

जून और नवम्बर, 2005 में जार्जटाडन में भारतीय पुस्तकों की एक प्रदर्शनी और भारतीय खाद्य समारोह का आयोजन किया गया।

जमैका

जमैका के साथ मारत के संबंधों में विकास होता रहा। भारत - जमैका विदेश कार्यालय परामर्श सितम्बर, 2005 में हुआ जब सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमण्डल किंग्सटन गया था। जमैका ने आई टी, भेषज और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भारत से सहयोग प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। वर्ष 2004-05 में जमैका को किये गये भारतीय निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 40% की वृद्धि हुई। अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जमैका ने भारत का समर्थन करना जारी रखा।

वेनजुएला के राष्ट्रपति श्री ह्यूगो चवेज फ्रियाज 5 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में डॉ. मनमोहन सिंह के साथ।

पैरागुए की विदेश मंत्री सुश्री लैला राशिद 22 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह के साथ।

दी बहामास

सितम्बर, 2005 में प्रथम विदेश कार्यालय परामर्शों के लिए सचिव (पश्चिम) के नेतृत्व में बहामास की भारतीय शिष्टमण्डल की यात्रा से बहामास के साथ हमारे संबंधों को गति मिली। नियमित विदेश कार्यालय परामर्शों के लिए एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। विदेश मंत्री श्री फ्रेडरिक मिशेल ने 22-29 जनवरी, 2006 से भारत का दौरा किया और आपसी हित के व्यापक मसलों पर द्विपक्षीय बातचीत की। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग करार भी संपन्न किया गया।

ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो

भारत तथा ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो के साथ द्विपक्षीय संबंध विकसित और विविधतापूर्ण हुए। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ करने को प्रमुखता दी गयी। भारत-कैरिकॉम आर्थिक मंच का आयोजन अगस्त, 2005 में किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। द्विपक्षीय व्यापार में प्रति वर्ष 30% की वृद्धि हो रही है जो इस वर्ष 50 मि. अमरीकी डालर से अधिक का हुआ। एस्सार समूह ने जमैका में एक इस्पात कंपनी स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंण्डल ने मई, 2005 में भारतीयों के आगमन की 160 वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले समारोहों में भाग लेने के लिए ट्रनिडाड एण्ड टोबेगो का दौरा किया।

ग्रेनाडा, डोमिनिका और मोंटसेराट राष्ट्रकुल

इस अवधि के दौरान ग्रेनाडा, डोमिनिका और मोंटसेराट राष्ट्रकुल के साथ हमारे संबंधों में विकास हुआ। ईवान तूफान से हुई तबाही के पश्चात भारत ने ग्रेनाडा को राहत सामग्रियाँ भेजीं और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में सहायता करने के लिए आई टी और कृषि विशेषज्ञों को भेजा। भारत ने डोमिनिका राष्ट्रकुल को अनिवार्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी क्योंकि वहाँ का केन्द्रीय मेडिकल डिपो आग लगने के कारण नष्ट हो गया था।

सूरीनाम

भारत-सूरीनाम द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे।

■■

संयुक्त राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन 9

वर्ष 2005 संयुक्त राष्ट्र की 60 वीं वर्षगांठ थी। वर्ष 2005-06 की मुख्य घटना रही सितम्बर, 2005 में न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 60 वें सत्र के आरंभ में विश्व शिखर सम्मेलन 2005 को आयोजन।

शिखर सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज में सर्वसम्मति से सदस्य देशों द्वारा लिये गये निर्णयों की झलक मिली। भारत ने बातचीत में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाई। इस दस्तावेज को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 60 वें सत्र के दौरान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय (सी सी आई टी) को अंतिम रूप देकर इसे पारित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसमें शांति निर्माण आयोग और मानवाधिकार परिषद जैसे नये निकायों की स्थापना किये जाने के लिए प्राधिकृत किया गया है और संयुक्त राष्ट्र की क्षमता का व्यापक रूप से समर्थन किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुधार से जुड़े व्यापक मसलों पर अन्य सदस्य देशों के साथ अपना सक्रिय क्रियाकलाप जारी रखा।

भारत ने निःशस्त्रीकरण, शांति रक्षा और शांति निर्माण, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय और कानूनी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र में अपनी निर्णायक भूमिका निभाना जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र में होने वाली चर्चा में भारत की भूमिका अक्सर महत्वपूर्ण विवादास्पद मसलों, विशेषकर जो विकासशील देशों के हितों के संवर्द्धन से संबंधित थे, पर सर्वसम्मति बनाने में सहायक रही।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 60 वे सत्र की उच्च-स्तरीय पूर्ण बैठक

संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च-स्तरीय पूर्ण बैठक (एच एल पी एम), जिसे विश्व शिखर सम्मेलन 2005 अथवा सहास्त्राब्दि समीक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, का आयोजन संयुक्त राष्ट्र की 60 वीं वर्षगांठ के दौरान ही 14-16 सितम्बर, 2005 तक आयोजित किया गया। प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने एच एल पी एम और यू एन जी ए के 60 वें सत्र के लिए भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। 15 सितम्बर, 2005 को एच एल पी एम में अपने संबोधन में प्रधान मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में लोकतंत्र का अभाव है और इसकी संरचना तथा नीति निर्णय प्रक्रिया में 1945 के विश्व की झलक मिलती है न कि 2005 के विश्व की। प्रधान मंत्री ने सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यता का विस्तार करके संयुक्त राष्ट्र में तत्काल और व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वास्तव में इसे एक प्रातिनिधिक निकाय बनाया जा सके। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को पारित किये जाने का स्मरण करते हुए प्रधान मंत्री ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु और प्रयास करने का आह्वान किया।

न्यूयार्क में प्रधान मंत्री ने चीन, पाकिस्तान, रूसी परिसंघ और अमरीका के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। उन्होंने भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका शिखर बैठक और गुट-निरपेक्ष आंदोलन (नाम) के अध्यक्ष के रूप में मलेशियाई प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित कार्यकारी रात्रि भोज में भाग लिया।

14 सितम्बर को प्रधान मंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अन्य नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष की स्थापना किये जाने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। भारत ने इस कोष में 10 मि. अमरीकी डालरों का योगदान किया।

तत्कालीन विदेश मंत्री श्री के नटवर सिंह यू एन जी ए सत्र के लिए प्रधान मंत्री के साथ गये थे। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान, चिली, क्यूबा, यूनान, जमैका, लक्जम्बर्ग, मैसिडोनियाँ, माल्टा, मालदीव, म्यामां, नेपाल, नार्वे, फिलीस्तीन, रोमानियाँ, सेनेगल, सूडान, तुर्की, उगांडा, अमरीका, वियतनाम और जाम्बिया के अपने समकक्षों के साथ बातचीत की। उन्होंने जी-4 विदेश मंत्रियों की एक बैठक की मेजबानी की और टीम-9 (सेनेगल, बुरकिना फासो, चाड, कोट डी आयवरी, इक्वाटोरियल गिनि, धाना, गिनि बिसाउ, माली) के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई जिसमें नाइजर को एक नये सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया। विदेशमंत्री ने भारत, रूस और चीन के

विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक; भारत - खाड़ी सहयोग (जी सी सी) राजनैतिक वार्ता; भारत एंडीयन समुदाय मंत्रिस्तरीय बैठक; एशिया सहयोग वार्ता (ए सी डी), नाम विदेश मंत्रियों की बैठक, राष्ट्रकुल मंत्रिस्तरीय कार्रवाई समूह (सी एम ए जी), जी - 15 विदेश मंत्रियों; समूह - 77 और सार्क क्षेत्र के विदेश मंत्रियों के साथ हुई बैठकों में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ फिलीस्तीन पर नाम मंत्रिस्तरीय समिति की बैठकों में भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए गैर-सरकारी शिष्टमण्डल

सत्रह सांसदों ने भारतीय शिष्टमण्डल के गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 60 वें सत्र में भाग लिया। सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मसलों पर भारत के दृष्टिकोण को रखा।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भारत यात्रा

संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यू एन एस जी) श्री कोफी अन्नान ने 25-28 अप्रैल, 2005 तक भारत का दौरा किया। यू एन एस जी ने विदेश मंत्री के साथ शिष्टमण्डल स्तर की व्यापक चर्चा की जिसमें संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार,आतंकवाद, शांति-रक्षा, सुनामी राहत और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों को शामिल किया गया। यू एन एस जी ने सुनामी के बाद अनेक देशों को भारत द्वारा तत्काल दी गयी सहायता की सराहना की। उन्होंने शांतिरक्षक सैनिकों की भूमिका की प्रशंसा की जिनके कार्यों को उन्होंने अनुकरणीय और प्रशंसनीय कहा।

सुरक्षा परिषद

सुरक्षा परिषद में इस वर्ष के दौरान भारत ने सार्वजनिक बहस में अफगानिस्तान, मध्य पूर्व आतंकवादी कृत्यों से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को उत्पन्न खतरे, मानवीय संकट और पश्च - संघर्ष शांति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर छह वक्तव्य दिये।

महासभा और सुरक्षा परिषद में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे

भारत ने यू एन जी ए के पूर्ण सत्र में निम्नलिखित से संबंधित कार्यसूची विषयों पर वक्तव्य दियेः संगठन के कार्यों पर महासचिव की रिपोर्ट; युवाओं के लिए विश्व कार्य योजना, अफ्रीका के विकास के लिए नई भागीदारी; महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और शिखर सममेलनों पर एकीकृत और समन्वित कार्रवाई और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई; वैश्विक सड़क सुरक्षा संकट; अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट; सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट और सुरक्षा परिषद में न्यायोचित प्रतिनिधित्व और सदस्यता वृद्धि का प्रश्न; संयुक्त राष्ट्र की मानवीय और आपदा राहत सहायता के बीच समन्वय को संवर्द्धित करना; अफगानिस्तान की स्थिति; महासागर और समुद्री कानून; और फिलीस्तीन का प्रश्न और मध्य पूर्व की स्थिति।

आतंकवाद

आतंकवाद से मुकाबले का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए प्रमुख मुद्दा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय के प्रारूप को प्रस्तुत किया। इसने "अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन" के उपायों पर गठित छठी समिति, में यू एन जी ए प्रस्ताव 51/210 द्वारा स्थापित तदर्थ समिति और "आतंकवादी कृत्यों से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को उत्पन्न खतरे" मद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद में होने वाले सावर्जनिक बहस में सक्रिय रूप से भाग लिया।

शांति - स्थापन आयोग का गठन

सितम्बर, 2005 में न्यूयार्क में आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज में परिलक्षित निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के साथ-साथ पारित यू एन जी ए प्रस्ताव के जरिए दिसम्बर, 2005 में शांति-स्थापन आयोग (पी बी सी) का गठन किया गया। पी बी सी की स्थापना एक अंतर-सरकारी परामर्शी निकाय के रूप में की गयी है जिसका कार्य पश्च-युद्ध शांति स्थापना -सापन और पुनर्निर्नाण के लिए समन्वित नीतियों का प्रस्ताव करना, पुनर्निर्माण और संस्थागत निर्माण प्रयासों पर ध्यान देना और विकास को बढ़ावा देना तथा सिफारिशें और सूचनाएं प्रदान कररा है।

शांतिरक्षा

भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा कार्रवाइयों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा कार्रवाइयों के लिए महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और अभी सैनिकों के योगदान के लिहाज से इसका तीसरे स्थान पर है। अभी भारतीय कार्मिक बुरूंडी, कोट डी आयवरी, साइप्रस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथोपिया और एरिट्रिया, जोर्जिया, कोसोवो, लेबनान, सियरालियोन और सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में कार्य कर रहे हैं। कोसोवो और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भारत के अनेक सिविल पुलिस कार्मिक लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर इस वर्ष भारत गोलान हाइट्स में संयुक्त राष्ट्र डिसइंगेजमेंट पर्यवेक्षक

बल में एक संभारतंत्रीय कंपनी और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल में एक चिकित्सा दल तैनात करने पर सहमत हुआ।

यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीच्यूशन ऑफ इन्डिया के तत्वावधान में सितम्बर, 2000 में भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में स्थापित संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा केन्द्र ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और अध्ययनों सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। भारत सरकार विकासशील देशों के कुछ मनोनीत व्यक्तियों का वित्त-पोषण करती है। अंतरराष्ट्रीय शांतिरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संघ की 11 वीं वार्षिक बैठक में, जो सी यू सन पी के में आयोजित हुई, अंतराष्ट्रीय शांतिरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संघ का सचिवालय सी यू एन पी में बनाने के निर्णय की घोषणा की गयी।

सुरक्षा परिषद सुधार

भारत ने सुरक्षा परिषद में न्यायोचित प्रतिनिधित्व और इसकी सदस्यता संख्या में वृद्धि करने से संबद्ध कार्यकारी दल और सुरक्षा परिषद से जुड़े अन्य मामलों पर सक्रिय रूप से भाग लिया। पुनर्गठित और विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की उम्मीदवारी को इस वर्ष और समर्थन मिला।

जी - 4 प्रक्रिया

जी - 4 देशों (बाजील, जर्मनी, जापान और भारत) का रूपरेखा प्रस्ताव यू एन जी ए के 59 वें पूर्ण सत्र में 11 जुलाई, 2005 को जी - 4 की ओर से बाजील द्वारा पेश किया गया। जी - 4 ने यू एन जी ए के 60 वें सत्र के दौरान इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अपने बीच और अन्य सदस्य राज्यों के साथ विचार - विमर्श जारी रखा है। 5 जनवरी, 2006 को भारत,जर्मनी और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के मुद्दे को पुनः उभारने के लिए 60 वें सत्र के दौरान जी - 4 प्रस्ताव को पुनः पटल पर रखा।

अफगानिस्तान

भारत ने अफगानिस्तान पर महासभा के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 29 नवम्बर, 2005 को यू एन जी ए के पूर्ण सत्र में इसने कार्यसूची मद 17 और 74(ड़) के अंतर्गत भी एक वक्तव्य दिया : "अफगानिस्तान की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर इसका प्रभाव" तथा "युद्ध ग्रस्त अफगानिस्तान में शांति,सामान्य स्थिति बहाल करने और पुनर्निमाण के लिए तत्काल अंतरराष्ट्रीय सहायता"।

इराक

मई, 2005 में भारत ने इराक के लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निमाण कोष सुविधा को 5 मि. अमरीकी डालरों की अतिरिक्त राशि प्रदान की (यू एन डी जी और विश्व बैंक इराक न्यास कोष प्रत्येक के लिए 2.5 मि. अमरीकी डालर) जिससे इस कोष के लिए भारत का कुल योगदान 10 मि. अमरीकी डालरों का हो गया। इसमें से 2.5 मि. अमरीकी डालरों की राशि संयुक्त राष्ट्र के इराक न्यास कोष के चुनावी कार्यों के लिए निर्धारित की गयी थी। भारत आई आर एफ एफ आई की दाता समिति का एक सदस्य है।

मध्य पूर्व

भारत ने यू एन जी ए के 60 वें पूर्ण सत्र में नवम्बर, 2005 को कार्यसूची मद सं 14 मध्य पूर्व की स्थिति और कार्यसूची मद सं 15 फिलीस्तीन का प्रश्न का और प्रासंगिक कार्यसूची मदों के अंतर्गत चौथी समिति में वक्तव्य दिया, फिलीस्तीन से संबद्ध गुट-निरपेक्ष आंदोलन की समिति के एक सदस्य के रूप में भारत ने फिलीस्तीन के मसले पर नाम बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष

महा सभा ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली से नये लोकतंत्रों को बढ़ावा देने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को समर्थन देने का आह्वान किया। इस पृष्ठभूमि में 4 जुलाई, 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष बनाने की घोषणा की।

भारत आरंभ से ही लोकतांत्रिक कोष बनाये जाने के प्रति वचनबद्ध रहा है। भारत इस पहल का समर्थन करने वाले पहले देशों में था। भारत ने इस कोष को 10 मि. अमरीकी डालरों का योगदान दिया है और यह इसके परामर्शी बोर्ड का सदस्य है।

आर्थिक मसले

सहस्त्राब्दि घोषणा पारित किये जाने के 5 वर्ष बाद उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (एम डी जी) और विकास के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर विशेष बल दिया गया। भारत ने एच एल पी बैठकों में हुई सहमति से आधार पर विशेष रूप से एम डी जी की उपलब्धियों के लिए संवर्द्धित सहायता और व्यापार तथा गंभीर ऋण राहत की आवश्यकता की दिशा में यू एन जी ए की द्वितीय समिति की बैठकों में सक्रिय कार्य किया, महासभा की वित्त-पोषण

के लिए उच्च-स्तरीय वार्ता 27 और 28 जून, 2005 को न्यूयार्क में आयोजित की गयी। इस बैठक में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने किया।

विदेश राज्य मंत्री ने 1-2 अगस्त, 2005 को जर्काता, इंडोनिशया में आयोजित एम डी जी पर एशिया-प्रशांत की बैठकों में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (इकोसॉस) का महत्वपूर्ण सत्र 29 जून से 27 जुलाई, 2005 तक आयोजित किया गया। इकोसॉस के कार्यों में मुख्यतः 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन की तैयारी प्रक्रिया में योगदान पर बल दिया गया।

आर्थिक मामले विभाग मे सचिव डा. मोहन राकेश ने ब्रेउन ऊड्स संस्थाओं, विश्व व्यापार संगठनों और व्यापार एवं विकास से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ 18 अप्रैल, 2005 को आयोजित इकोसॉस की स्प्रिंग उच्च-स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

पर्यावरण और सतत् विकास मसले

भारत ने सतत् विकास से संबद्ध आयोग, सतत् विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत उच्च-स्तरीय आयोग, जिसे कार्यसूची 21 और जोहान्नसबर्ग क्रियान्वयन योजनाके क्रियान्वयन की समीक्षा करने और इसे बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है, के कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान दिया। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा ने 11-22 अप्रैल, 2005 तक न्यूयार्क में आयोजित सी एस डी के 13 वें सत्र में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। इस प्रगति को तीव्र करने के लिए नीतिगत विकल्पों और व्यावहारिक उपायों पर बल दिया गया जैसा कि जल जमाव, स्वच्छता और मानवीय बस्तियों से संबद्ध जोहान्नसबर्ग क्रियान्वयन योजना में उल्लेख किया गया था।

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा ने 16-27 मई, 2005 तक न्यूयार्क में वनों सं संबद्ध संयुक्त राष्ट्र मंच के पाचवें सत्र में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया।

एच आई वी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च - स्तरीय बैठक - 2005

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा. अंबुमणि रामदोस ने जून, 2005 में एच आई वी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। इस बैठक में एच आई वी/एड्स पर वचनबद्धता घोषणा, जिसे जून, 2001 में एच आई वी/एड्स पर आयोजित यू एन जी ए सत्र में पारित की गयी थी, में वर्ष 2005 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की आंतरिक तकनीकी समीक्षा करने का अवसर मिला। भारत ने उच्च - स्तरीय बैठक में "रोकथाम" पर गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया।

मानीवय सहायता

भारत ने समूह-77 की ओर से "प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय सहायता, राहत और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग" से संबद्ध वार्षिक प्रस्ताव को प्रोयाजित करना जारी रखा। यू एन जी ए के 60 वें सत्र में पारित प्रस्ताव में संसाधनों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों के पुनर्निमाण प्रयासों के लिए समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का प्रादेश दिया गया जिस पर यू एन जी ए द्वारा 61 वें सत्र में विचार किया जाएगा। भारत ने "हिंद महासागर में आये सुनामी से हुई तबाही के पश्चात आपातकाल राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और रोकथाम को सुदृढ़ बनाने" से संबद्ध प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने में भी योगदान दिया।

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली/संयुक्त राष्ट्र कोष और कार्यक्रमों से संबंधित प्रचालानात्मक गतिविधियाँ

भारत ने संयुक्त राष्ट्र कोषों के कार्यों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाना जारी रखा।

सामाजिक, मानवाधिकार और मानवीय मसले

भारत ने एन जी ओ समिति में अत्यन्त सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने 1-12 अगस्त, 2005 तक आयोजित विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान संवर्द्धन और संरक्षण से संबद्ध व्यापक और समन्वित अंतरराष्ट्रीय अभिसमय से संबंधित तदर्थ समिति के छठे सत्र में भाग लिया।

जलवायु परिवर्तन

6-8 जुलाई, 2005 तक यू के के ग्लेनइगल्स में हुए शिखर सम्मेलन में जी- 8 देशों ने भारत सहित पांच गैर-सदस्य देशों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गयी। प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने विकासशील देशों को स्पष्ट प्रौद्योगिकियों को अन्तरण और इसके वित्तपोषण की तत्काल आवश्यकता के संबंध में भारत के दृष्टिकोण को रखा। ग्लेनइगलस में हुई चर्चा के बाद 1 नवम्बर, 2005 को लन्दन में जलवायु परिवर्तन पर गोलमज बैठक का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय

डॉ. मनमोहन सिंह 14 सितम्बर, 2005 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि के उद्घाटन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ।

लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी अप्रैल 2005 को मनीला में अंतर संसदीय संघ की 112वीं सभा को संबोधित करते हुए।

शिष्टमण्डल का नेतृत्व पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा ने किया।

अंतरराष्ट्रीय कानून और घटनाएं

60 वें सत्र के दौरान छठी समिति ने दो विधिक दस्तावेजों को स्वीकार कियाः इलेक्ट्रानिक संचार और अंतरराष्ट्रीय संविदाओं पर अभिसमय और संयुक्त राष्ट्र और संबंधित कार्मिकों की सुरक्षा से संबद्ध अभिसमय का वैकल्पिक प्रोतोकोल।

चुनाव

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र की अध्यक्ष को अक्तूबर, 2005 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए पुनः चुना गया।

भारत को 2006-2007 की अवधि के लिए श्रेणी "ख" के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के लिए पुनः चुना गया।

25 नवम्बर, 2005 को रोम में आयोजित एफ ए ओ सत्र के दौरान भारत को खाद्य एवं कृषि संगठन की कार्यकारी परिषद के लिए पुनः चुना गया।

भारत को 25 नवम्बर-2 दिसम्बर, 2005 तक डकर में आयोजित विश्व पर्यटन संगठन की महासभा के लिए विश्व पर्यटन संगठन की कार्यकारी परिषद के लिए पुनः चुन लिया गया।

श्रीमती सीमा बहुगुणा को नई दिल्ली स्थित अफ्रीकी - एशियाई विकास संगठन का सहायक महासचिव चुना गया।

संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट जेंसियाँ और अभिसमय/सम्मेलन

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू एफ पी)

भारत ने अफगानिस्तान में स्कूली विद्यार्थियों को भोजन मुहैया कराने के कार्यक्रम में डब्ल्यू एफ पी के साथ सहयोग करना जारी रखा है और इराक में ऐसे ही एक कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन दिया है। भारत डब्ल्यू एफ पी के 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का एक सदस्य है।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो)

युनिडो के औद्योगिक विकास बोर्ड का 30 वां सत्र 20-23 जून, 2005 तक वियना में आयोजित किया गया जिसमें सियरा लियोन के डा. कान्देह युम्केब्ला को महानिदेशक चुना गया जिसकी पुष्टि नवम्बर, 2005 में मुख्य सम्मेलन के 11 वें सत्र में की गयी। युनिडो के महानिदेशक श्री कार्लोस मार्गरीनोस ने 20-23 नवम्बर, 2005 को भारत का दौरा किया। भारत ने एशियाई समूह के समर्थन से औद्योगिक विकास बोर्ड में अपनी सदस्यता बनायी रखी।

स्वापक औषधों से संबद्ध आयोग (सी एन डी)

वियना में 7-8 दिसम्बर, 2005 तक भारतीय राजदूत की अध्यक्षता में वियना में आयोजित सी एन डी के 48 वें सत्र में वर्ष 2006-2007 के लिए यू एन ओ डी सी के संचित बजट का अनुमोदन कर दिया गया जिसमें पिछले 2004-2005 वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

यू एन टी ओ सी के पक्षकारों (सी ओ पी II) का दूसरा सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों का दूसरा सम्मेलन 10-21 अक्तूबर, 2005 तक वियना में आयोजित किया गया। सी ओ पी - II ने यू एन टी ओ सी के क्रियान्वयन में हुई प्रगति और राज्य पक्षकारों के समक्ष आयी कठिनाइयों पर चर्चा की। आग्नेयास्त्रों पर यू एन टी ओ सी का तीसरा प्रोतोकोल पहले सी ओ पी के समाप्त होने के पश्चात लागू हो गया।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

भारत ने 9 दिसम्बर, 2005 को भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किया।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (यू एन एफ सी सी सी)

पर्यावरण और वन मंत्री श्री ए राजा ने यू एन एफ सी सी सी के पक्षकारों के 11 वें सम्मेलन में, जिसका आयोजन क्योतो प्रोतोकोल के प्रथम बैठक/सम्मेलन के साथ-साथ 28 नवम्बर, 9 दिसम्बर 2005 तक मांट्रियाल में किया गया था, भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। बैठक में विकसित देशों की भावी वचनबद्धता की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अंतर्गत वे अपने ग्रीन - हाउस गैस के विसरण स्तर पर में इस प्रकार कमी लायेंगे कि वर्ष 2012 में समाप्त होने वाली प्रथम वचनबद्धता और अगली वचनबद्धता के बीच कोई अंतर न रहे।

निःशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले

भेदभाव रहित और वैश्विक नाभिकीय निःशस्त्रीकरण तथा सामूहिक विनाश के सभी हथियारों का विश्व स्तर पर उन्मूलन करने की भारत की वचनबद्धता की झलक इसके नीतिगत वक्तव्यों और राजनयिक पहलकदमियों में मिली।

क्षेत्रीय स्तर पर विश्वास और सुरक्षा निर्माण प्रक्रिया तथा

आसियान क्षेत्रीय मंच तथा एशिया में आपसी क्रियाकलाप और विश्वासोत्पादक उपायों से संबद्ध सम्मेलन में भारत की भागीदारी को और गति मिली।

निःशस्त्रीकरण मामले पर भारत के दृष्टिकोण का प्रसार करने के उद्देश्य से निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में सक्रिय प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और गैर-सरकार संगठनों के साथ नियमित संपर्क बनाये रखे गये।

भारत उन संवेदनशील सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर नियंत्रण लगाता रहा है जिनका सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी डिलिवरी प्रणाली में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जा सकता है। सामूहिक विनाश के हथियारों (गैर-कानूनी गतिविधियों की रोकथाम) से संबद्ध अधिनियम से वैश्विक शांति और सुरक्षा लक्ष्यों में योगदान करने की भारत की वचनबद्धता परिलक्षित हुई।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यू एन जी ए)

विश्व शिखर सम्मेलन - 2005 में अपने संबोधन में प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने नाभिकीय प्रसार से विश्व को बचाने और नाभिकीय निःशस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नये सिरे से प्रयास करने का आह्वान किया। इस बात पर बल देते हुए कि संस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन आतंकवाद की त्रासदी से निपटने के लिए एक शक्तिशाली हथियार होगा; उन्होंने कहा "हम आतंकवाद के आगे तनिक भी नहीं झुकेंगे। हम इस बात को सिरे से अस्वीकार करते हैं कि आतंकवाद को औचित्यपूर्ण ठहराने का कोई आधार हो सकता है"। भारत के विदेश मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि समयबद्ध तरीके से बहुपक्षीय वार्ता पर आधारित सार्वभौमिक और प्रामाणिक नाभिकीय निःशस्त्रीकरण का प्रयास जारी रहना चाहिए।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 60वें सत्र की पहली समिति, जो निःशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मसलों की देख-देख करती है, में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखी। अराजक तत्वों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों को प्राप्त करने और इनका दुरूपयोग करने की संभावना से उत्पन्न गंभीर वैश्विक खतरों के संबंध में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता को स्वीकार करते हुए आतंकवादियों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों को प्राप्त करने से रोकने के उपायों पर भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया जैसा कि पिछले तीन सत्रों के दौरान हुआ था।

भारत ने वैश्विक नाभिकीय निःशस्त्रीकरण पर अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण, जिससे उत्तरोत्तर शस्त्रीकरण का स्तर घटेगा और सभी के लिए सुरक्षा की गारंटी मिल सकेगी, को दोहराया। भारत ने पहली बार 1982 में पेश किये गये अपने प्रस्ताव "नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर रोक से संबद्ध अभिसमय" को पुनः पेश किया जिसमें निःशस्त्रीकरण सम्मेलन से एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के संबंध में बातचीत करने का आह्वान किया गया है जो नाभिकीय हथियारों की प्रमुखता को कम करने की दिशा में पहले कदम के रूप में किसी भी हाल में नाभिकीय हथियारों के प्रयोग और इसके प्रयोग की धमकी पर रोक लगा पायेगा।

1998 में भारत द्वारा पहली बार प्रस्तुत प्रस्ताव "नाभिकीय खतरों में कमी" को भी पुनः पटल पर रखा गया जिसमें नाभिकीय सिद्धांतों की समीक्षा करने और नाभिकीय हथियारों के अनचाहे और अचानक उपयोग के जोखिम को कम करने हेतु तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है।

भारत के प्रस्ताव "अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका" में हथियारों की होड़ के गुणात्मक पहलु और वास्तव में बहुपक्षीय और भेदभाव रहित प्रत्युत्तर की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत का मानना है कि जिम्मेदार राज्यों को प्रौद्योगिकी से वंचित रखने से अप्रसार के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पायेगी बल्कि इसे एक दण्डात्मक कार्रवाई ही मानी जाएगी।

सयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग

संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग एकमात्र वैश्विक मंच है जिसे निःशस्त्रीकरण और हथियारों पर नियंत्रण लगाने के संबंधित मसलों पर विचार करने और महासभा को अपनी अनुशंसाएं देने का प्रादेश प्रदान किया गया है। यू एन डी सी का मौलिक सत्र आहूत नहीं किया गया। जैसा कि वर्ष 2004 में हुआ था, लगातार दूसरे वर्ष आयोग सर्वसम्मति के अभाव में अपनी कार्यसूची पारित नहीं कर पाया। हालांकि गुट-निरपेक्ष समूह द्वारा अनेक प्रस्ताव किये गये परन्तु यूरोपीय संघ और अमरीका के विचारों में समानता नहीं आ पायी।

निःशस्त्रीकरण मामलों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का परामर्शी बोर्ड

यह बोर्ड, जिसमें न्यायोचित भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर महासचिव द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल हैं, निःशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर अपनी अनुशंसाएं महासचिव को देता है। संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण संस्थान के न्यासी बोर्ड के रूप में भी यह कार्य करता है। भारत ने बोर्ड के जेनेवा सत्र में भाग लिया।

निःशस्त्रीकरण सम्मेलन

निःशस्त्रीकरण सम्मेलन (सी डी) "बहुपक्षीय निःशस्त्रीकरण के संबंध में बातचीत करने वाला एकमात्र निकाय" है जिसमें 65 ऐसे राज्य शामिल हैं जो सैन्य आधार पर महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2005 के सत्र में इसकी बैठकें 24 जनवरी-1 मार्च, 30 मई-15 जुलाई और 8 अगस्त-23 सितम्बर 2005 तक जेनेवा में हुई। औपचारिक पूर्ण बैठकों के अतिरिक्त इस सम्मेलन ने निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की वर्तमान कार्यसूची और नये मसलों पर अनौपचारिक एवं औपचारिक बैठकें की। निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत ने विभिन्न प्रस्तावों पर हुए विचार-विमर्शों में सक्रिय रूप से भाग लिया। विचार-विमर्श के दौरान भारत ने निःशस्त्रीकरण सममेलन के लिए एक ऐसी कार्ययोजना बनाने में मदद करने के लिए लचीला और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जिसमें इसके सभी सदस्य राज्यों के हित और प्राथमिकताएं परिलक्षित हुईं।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई ए ई ए)

भारत ने नाभिकीय सुरक्षा से संबद्ध अभिसमय का अनुसमर्थन किया और इसने आई ए ई ए महानिदेशक के पास अनुसमर्थन दस्तावेजों को जमा करवा दिया। भारत ने नाभिकीय सामग्रियों के भौतिक संरक्षण से संबद्ध अभिसमय के संशोधन पर आयोजित सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने आई ए ई ए कानूनों के अंतर्गत सुरक्षोपाय और प्रमाण से संबद्ध परामर्शी समिति के शासक मण्डल में समान विचार वाले देशों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया।

आई ए ई ए के जी सी का 49 वां सत्र 26-30 सितम्बर, 2005 तक आयोजित किया गया। भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डा. अनिल ककोदकर ने किया।

आई ए ई ए में भारत ने आई ए ई ए की संवर्द्धक भूमिका, विशेषकर नाभिकीय ऊर्जा और संबद्ध प्रौद्योगिकियों के विकास से जुड़ी गतिविधियों और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के अनुप्रयोग से जुड़ी गतिविधियों पर बल दिया और इनका समर्थन किया।

प्रबंधन विभाग के उप-महानिदेशक श्री डेविड वालर और नाभिकीय ऊर्जा विभाग के उप-महानिदेशक श्री यूरी सोकोलोव ने भारत का आधिकारिक दौरा किया। उन्होंने ए ई सी के अध्यक्ष, बी ए आर सी के निदेशक और अन्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ मुलाकात की और परमाणु ऊर्जा विभाग के संयंत्रों का दौरा किया।

रासायनिक हथियार अभिसमय (सी डब्ल्यु सी)

इस वर्ष के दौरान भारत ने दी हेग में रासायनिक हथियारों पर रोक (ओ पी सी डब्ल्यु) लगाने के लिए संगठन में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। भारत रासायनिक हथियार अभिसमय का एक राज्य पक्षकार है। इस अभिसमय द्वारा निधार्रित समय-सीमा के अनुसरण में रासायनिक हथियारों और इसके उत्पादन संयंत्रों को नष्ट करने में भारत का रेकार्ड सर्वविदित है।

राज्य पक्षकारों के दसवें सम्मेलन, जो 7-11 नवम्बर, 2005 तक आयोजित किया गया, में ओ पी सी डब्ल्यू में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने एक वक्तव्य में (i) आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास पर अनुच्छेद XI के क्रियान्वयन की आवश्यकता और (ii) 8 वें सम्मेलन में पारित राष्ट्रीय क्रियान्वयन उपायों पर अनुच्छेद VII कार्य योजना की समीक्षा करने पर बल दिया। इस बात पर बल दिया गया कि राज्य पक्षकारों ने इस अभिसमय के क्रियान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। परन्तु ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने अभी तक कार्य योजना के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है।

जैविक हथियार अभिसमय (बी डब्ल्यू सी)

जैविक (जीवाणु) और जीव विष अभिसमय के राज्य पक्षकारों के चौथे समीक्षा सम्मेलन का सत्र नवम्बर, 2002 में पुन/आरंभ हुआ जिसमें वर्ष 2003,2004 और 2005 में राज्य पक्षकारों का एक सप्ताह का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2006 के अंत तक छठे समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

बी डब्ल्यू सी के राज्य पक्षकारों की तीसरी वार्षिक बैठक 5-9 दिसम्बर, 2005 तक जनेवा में हुई जिसमें साझी समझबूझ और वैज्ञानिकों के लिए विषय - वस्तु, प्रख्यापन और आचरण संहिता बनाने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई पर चर्चा की गयी और इसे बढ़ावा दिया गया। राज्य पक्षकारों की बैठक की तैयारी के लिए 13-24 जून, 2005 तक जेनेवा में विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की गयी।

भारतीय शिष्टमण्डल ने विशेषज्ञों की बैठक और राज्य पक्षकारों की बैठक में हुए विचार-विमर्शों में सक्रिय भागीदारी की। आचरण संहिता के संबंध में भारत के राष्ट्रीय अनुभव को बांटने के उद्देश्य से भारतीय शिष्टमण्डल ने विशेषज्ञों की बैठक में "वैज्ञानिकों के लिए आचरण संहिता पर भारतीय पहल" के संबंध में अपनी प्रस्तुती दी। भारतीय शिष्टमण्डल ने एक कार्यकारी दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जिसमें भारत द्वारा

स्थापित विधिक और नियामक रूपरेखा का उल्लेख किया गया था। राज्य पक्षकारों की बैठक में एक अन्य प्रस्तुती और कार्यकारी दस्तावेज से वैज्ञानिकों के लिए आचरण संहिता पर भारतीय दृष्टिकोण का और खुलासा हुआ।

कतिपय पारंपरिक हथियारों के संबंद्ध अभिसमय (सी सी डब्ल्यु)

भारत उस अभिसमय का एक उच्च पक्षकार है जो उन कतिपय पारंपरिक हथियारों के प्रयोग पर रोक और प्रतिबंध लगाने के लिए प्रादेशित है जिनका उपयोग काफी खतरनाक और अंधाधुध प्रभाव वाला हो सकता हे। भारत ने इसके सभी प्रोतोकोलों का अनुसमर्थन किया है। जिसमें भूमिगत विस्फोटकों, धोखे से किये गये हमलों और अन्य तरीकों पर रोक और प्रतिबंध लगाने से संबद्ध संशोधित प्रोतोकोल II और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों से संबद्ध प्रोतोकोल V शामिल हैं। भारत ने इस अभिसमय के अनुच्छेद 1 में किये गये संशोधन का भी अनुसमर्थन किया है।

वर्ष 2001 में आयोजित सी सी डब्ल्यु से संबद्ध अभिसमय के राज्य पक्षकारों के द्वितीय समीक्षा सम्मेलन में (क) युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के मुद्दे का समाधान करने के तौर-तरीकों और (ख) मानव-रोधी भू-सुरंगों को छोड़कर अन्य प्रकार के विस्फोटक सुरंगों पर चर्चा करने के लिए सरकारी विशेषज्ञों का एक बहु-प्रयोजन समूह गठित करने का निर्णय लिया गया। भारत ने वर्ष 2002 और 2003 में सरकारी विशेषज्ञों के समूह के प्रथम छह सत्रों की अध्यक्षता की। वर्ष 2004 और 2005 में सरकारी विशेषज्ञों के समूह की छह और बैठकें आयोजित की गयी। भारत ने वर्ष 2005 में युद्ध के विष्फोटक अवशेषों से संबद्ध कार्यकारी समूह की बैठकों में समन्वयक के रूप में नाम समूह की ओर से अध्यक्षता की।

सी डब्ल्यू सी के राज्य पक्षकारों की एक बैठक 21-25 नवम्बर, 2005 तक जेनेवा में हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी विशेषज्ञों का समूह 2006 में भी अपना कार्य जारी रखेगा। इसमें यह निर्णय भी लिया गया कि सरकारी विशेषज्ञों का समूह 6-17 नवम्बर, 2006 तक जेनेवा में आयोजित होने वाली तीसरी समीक्षा बैठक की भी तैयारी करेगा।

खतरनाक सुरंगों, धोखे से लगाये गये विस्फोटकों और अन्य तरीकों के उपयोग पर रोक अथवा प्रतिबंध लगाने से संबद्ध सी सी डब्ल्यु के संशोधित प्रोतोकोल II के राज्य पक्षकारों की वार्षिक बैठक भी 23 नवम्बर, 2005 को जेनेवा में आयोजित की गयी। भारत ने संशोधित प्रोतोकोल के क्रियान्वयन के लिए अपने द्वारा की गयी कार्रवाइयों और विस्फोटक सुरंगों से मुक्त विश्व की कल्पना के प्रति अपनी बचनवद्धता के बारे में बैठक को बताया।

भारत एक ऐसी चरणबद्ध प्रक्रिया, जिस में बारूदी सुरंगों के अंधाधुंध अंतरण और उपयोग से उत्पन्न भयानक मानवीय त्रासदी को कम करते हुए वैध प्रतिरक्षा जरूरतों को भी पूरा किया जाए, के जरिए मानव-रोधी सुरंगों पर भेदभाव रहित, सार्वभौमिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगाने के लिए वचनबद्ध है। भारत ने दिसम्बर, 2004 में नैरोबी में आयोजित अभिसमय के प्रथम समीक्षा सम्मेलन में एक पर्यवेक्षक की हैसियत से भाग लिया। भारत ने पर्यवेक्षक के रूप में ओटावा अभिसमय के राज्य पक्षकारों की वार्षिक बैठक में भाग लिया जो 28 नवम्बर - 2 दिसम्बर, 2005 तक जगरेब में आयोजित की गयी थी। हालांकि भारत बारूदी सुरंगों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न मानवीय चिंताओं को स्वीकार करता है परन्तु यह ओटावा आभिसमय का एक पक्षकार नहीं है क्योंकि इस अभिसमय में देशों के उन सुरक्षा हितों पर ध्यान नहीं दिया गया है जिसके कारण वैध सुरक्षा मानदण्डों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य तथा सुपरिभाषित मानकों के अनुसरण में सुरक्षा उद्देश्यों से बारूदी सुरंगों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है।

लघु और हल्के (एस ए एल डब्ल्यु)

भारत लघु हथियारों के प्रसार और उनके अनुचित कारोबार की समस्या के प्रति अत्यंत सजग है और लघु अस्त्र एवं हल्के हथियारों के अवैध कारोबार के संबंध में जुलाई, 2001 में संपन्न संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाए गए प्रोग्राम ऑफ एक्शन (पी ओ ए) के कार्यान्वयन सहित इनके प्रभावी समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय खोज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए हमेशा से ही वचनबद्ध है।

लघु और हल्के हथियारों के सभी पहलुओं पर रोक लगाने, इनका मुकाबला करने और इनके गैर-कानूनी व्यापार का उन्मूलन करने से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में लघु और हल्के हथियारों के संबध में बातचीत करने और इनकापता लगाने के लिए दस्तावेज तैयार करने हेतु महासचिव द्वारा गठित बहुद्देश्यीय कार्यदल सर्वसम्मति से राजनैतिक तौर पर एक बाध्यकारी दस्तावेज तैयार करने पर सहमत हुआ। इस दस्तावेज को महासभा द्वारा 60 वे सत्र में पारित किया गया। भारत ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया और इसने बातचीत की प्रक्रिया में रचनात्मक भूमिका निभाई।

लघु एवं हल्के हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र कार्ययोजना के

क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए राज्यों की दूसरी द्विवर्षीय बैठक जुलाई, 2005 में न्यूयार्क में हुई। लघु एवं हल्के हथियारों की गैर-कानूनी दलाली और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सहायता के क्षेत्रों में और प्रगति करने का आह्वान करते हुए इस बैठक में जुलाई, 2001 में लघु एवं हल्के हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई योजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।

बाह्य अंतरिक्ष मामले

बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण सहयोग से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र समिति का 48 वां सत्र वियना में 8-17 जून, 2005 तक आयोजित किया गया। भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष ने किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों और कर्यक्रमों को दर्शाने के लिए इसरो ने "इन्डिया इन स्पेस" नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया। यू एन सी ओ पी यू ओ एस के 48वें सत्र के साथ आयोजित इस प्रदर्शनी को पर्याप्त संख्या में लोगों ने देखा।

बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र समिति की विधिक उप-समिति का 44 वां सत्र 4-15 अप्रैल, 2005 तक वियना में आयोजित किया गया। भारतीय शिष्टमण्डल ने उप-समिति के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन

नाम विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक 20 सितम्बर,2005 को यू एन जी ए के 60 वें सत्र के दौरान ही आयोजित की गयी। भारत ने "महासभा की उच्च-स्तरीय पूर्ण बैठक के परिणामों के क्रियान्वयन की अनुवर्ती कार्रवाई" पर बैठकों में होने वाली बहस में सक्रिय रूप से भाग लिया।

भारत ने फिलीस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 19 सितम्बर, 2005 को फिलीस्तीन से संबद्ध नाम समिति की वार्षिक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। फिलीस्तीन पर नाम के मंत्रिस्तरीय शिष्टमण्डल के एक सदस्य के रूप में भारत ने क्वार्टेट के सदस्यों और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के साथ मंत्रिस्तरीय शिष्टमण्डल की बैठकों में भाग लिया।

नाम विदेश मंत्रियों की एक विशेष बैठक 13 जून, 2005 को दोहा में आयोजित दूसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित की गयी। दक्षिण शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमण्डल के नेता विदेश राज्य मंत्री ने इस बैठक में भाग लिया।

राष्ट्रमण्डल

भारत ने 25-27 नवम्बर, 2005 तक माल्टा के वेलेट्टा में आयोजित राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। शासनाध्यक्षों की बैठक के दौरान घोषित डिजिटल डिवाइड पर राष्ट्रकुल कार्ययोजना के लिए भारत का 1 मि. यूरो का योगदान और भारत द्वारा वित्त-पोषित और क्रियान्वित पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क को प्रमुख पहलकदमियॉ मानी गयीं। भारत 53 सदस्यीय राष्ट्रमण्डल का सबसे बड़ा सदस्य और पांचवां सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है।

भारत ने 25-27 नवम्बर, 2005 तक वेलेट्टा में आयोजित राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक और 23-24 नवम्बर तक शासनाध्यक्षों की बैठक के पूर्व विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने इस बैठक में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। वेलेट्टा बैठक की विषय-वस्तु थी "विकास के लिए राष्ट्रमण्डल की नेटवर्किंग"। भारत ने बेलेट्टा बैठक के साथ ही राष्ट्रमण्डल मंत्रिस्तरीय कार्यवाई समूह के सदस्य के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा किया।

परिवर्तित स्वरूप के अंतर्गत यह राष्ट्रमण्डल की पहली बैठक थी जिसमें बैठक के पूर्व विदेश मंत्री की बेहतर भूमिका रही। विदेश मंत्रियों की बैठक दो दिनों तक चली (23 और 24 नवम्बर)। बैठक की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए सी एम ए जी की बैठक 24 नवम्बर को भी हुई। बैठक के दौरान हुई मुख्य बदस में आतंकवाद, छोटे राज्यों, राष्ट्रमण्डल विकास की नेटवर्किंग और बहुपक्षीय व्यपार को शामिल किया गया।

चोगम विज्ञप्ति के अतिरिक्त वेलेट्टा बैठक में बहुपक्षीय व्यापार, लघु राज्यों के गोजो समाधान, जिसके अंतर्गत छोटे राज्यों की चितांओं का समाधान करने के विशेष प्रयास किये गये हैं, से संबद्ध राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्ष का वेलेहा वक्तव्य और विकास के लिए राष्ट्रमण्डल नेटवर्किंग पर माल्टा घोषणा वक्तव्य जारी किया गया।

सितम्बर, 2005 में फिजी द्वीप में आयोजित राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की बैठक में पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष श्री एच.ए. हालिमा को वर्ष 2005-08 के लिए सी पी ए की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष चुना गया। लोक सभा अध्यक्ष को सी पी ए का उपाअध्यक्ष चुना गया। भारत वर्ष 2007 में 53 वें वार्षिक सी पी ए सम्मेलन की मेजबानी करेगा। लार्ड स्वराज पॉल के नेतृत्व में राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की यू के

शाखा के एक शिष्टमण्डल ने अक्तूबर, 2005 में भारत का दौरा किया।

विदेश मंत्री ने 16 सितम्बर, को राष्ट्रमण्डल विदेश मंत्रियों की बैठक में ओर 17 सितम्बर को न्यूयार्क में राष्ट्रमण्डल मंत्रिस्तरीय कार्रवाई योजना की बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने 19 और 20 सितम्बर, 2005 को बरबाडोस में राष्ट्रमण्डल वित्त मंत्रियों के सममेलन में भाग लिया। कानून और न्याय मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज ने 17-20 अक्तूबर, 2005 तक अकरा, घाना में राष्ट्रमण्डल कानून मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

राष्ट्रमण्डल सचिवालय द्वारा भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज के सहयोग से नई दिल्ली में 25 और 26 अगस्त, 2005 को विकास और लोकतंत्र पर राष्ट्रमण्डल एशियाई सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में प्रधान मंत्री ने बीज व्याख्यान दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर सी लोहाटी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, जस्टिस डा. ए एस आनन्द और भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एम जग्न्नाथ राव ने 11-15 सितम्बर, 2005 तक लंदन में राष्ट्रमण्डल विधि पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोहों में भाग लिया।

राष्ट्रमण्डल महासचिव जनरल डॉन मैककिनोन ने विकास और लोकतंत्र पर आयोजित राष्ट्रमण्डल एशियाई सेमिनार में भाग लेने के लिए 24-26 अगस्त, 2005 तक भारत का दौरा किया।

आसियान क्षेत्रिय मंच

आसियान क्षेत्रिय मंच की 12 वीं मंत्रिस्तरीय बैठक वियनसियेन, लाओस में 29 जुलाई, 2005 को हुई। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने किया। उस बैठक में विश्वासोत्पादक उपायों से संबद्ध वर्तमान अंतर-सत्र समूह के स्थान पर विश्वासोत्पादक उपयों और निरोधात्मक राजनय से संबद्ध अंतर - सत्र समूह स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आसियान क्षेात्रीय मंच की 12 वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में भारत ने 26-28 अक्तूबर, 2005 तक कोच्ची में सहयोगी समुद्री सुरक्षा में सहयोग पर आसियान क्षेत्रिय मंच कार्यशाला का आयोजन किया।

भारत ने आसियान क्षेत्रीय मंच के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न बैठकों, यथा 22 - 23 फरवरी, 2005 तक यूरोपीय संघ की सह अध्यक्षता और जर्मनी तथा कंबोडिया की भागीदारी के साथ बर्लिन, जर्मनी में सी बी एम पर ए आर एफ आई एस जी; जर्मनी के बर्लिन में ही 21फरवरी, 2005 को रक्षा अधिकारियों की वार्ता; चीन के सान्या में 7 ओर 8 मार्च तक "अपारंपरिक सुरक्षा मसलों पर सहयोग बढ़ाने" से संबद्ध कार्यशाला; 2-4 मार्च, 2005 तक सिंगापुर में समुद्री सुरक्षा में क्षेत्रीय सहयोग पर सेमिनार; 6-8 अप्रैल, 2005 तक बैंकाक, थाइलैड में आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के मुकाबले से संबद्ध आसियान क्षेत्रीय मंच की अंतर-सत्रीय बैठक; 3-5 अक्तूबर, 2005 तक फिलीपींस के काबु शहर में सायबर आतंकवाद पर आसियान क्षेत्रीय मंच के सेमिनार; 17 और 18 नवम्बर, 2005 को सिंगापुर और कनाडा द्वारा सिंगापुर में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच निर्यात लाइसेंसिंग विशेषज्ञों की बैठकों में भाग लेकर आसियान क्षेत्रीय मंच के क्रियाकलापों में भाग लिया।

एशिया में क्रियाकलाप और विश्वासोत्पादक उपायों पर सम्मेलन (सीका)

भारत सीका का संस्थापक सदस्य है। जून, 2000 में अल्माटी में आयोजित सीका शिखर सम्मेलन ने तीन दस्तावेज तैयार करने का निर्णय लिया था, (i) सीका प्रक्रिया नियमावली (ii) सीका सी बी एम सूची (iii) सीका सचिवालय की संविधि। अक्तूबर, 2004 में हुई सीका मंत्रिस्तरीय बैठक में दो दस्तावेजों को स्वीकार किया गया। सीका सचिवालय की संविधी के संबंध में बातचीत चल रही है।

अन्तरराष्ट्रीय कानून और विकास

छठी समिति की रिपोर्ट

यह वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की छठी समिति के लिए फलदायक सत्र रहा। समिति ने दो कानूनी दस्तावेज अपनाए नामतः इलेक्ट्रानिक संचारों पर अभिसमय, और संयुक्त राष्ट्र और सहायक कार्मिक की सुरक्षा पर अन्तरराष्ट्रीय संविदा एवं वैकल्पिक प्रोतोकोल के लिए अभिसमय। इस सत्र के दौरान अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद पर वृहद अभिसमय को अपनाने को दी गई महत्ता के दृष्टिगत सत्र के दौरान प्रयास किए गए ताकि अन्तर राष्ट्रीय आतंकवाद पर वृहद आसमय के प्रारूप के शेष बकाया मुद्दे के समाधान इससे अधिक महत्वपूर्ण सर्वसम्मति पर पहुंचने के दृष्टिगत आतंकवाद और अन्तरराष्ट्रीय मानवीय कानून पर वृहद अभिसमय के अन्तर्गत कानूनी व्यवस्था के आलेखन, स्व.निर्धारण की भाषा प्रारूपण द्वारा समाधानकिया जा सके। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए समिति ने वृहद अभिसमय के प्रारूप को सम्पन्न करने के लिए तदर्थ समिति की बैठक दिनांक 27 फरवरी से 3 मार्च, 2006 तक बुलाने का निर्णय लिया। यह स्पष्ट करने के लिए

कि तदर्थ समिति ने इस बैठक के दौरान अभिसमय को अन्तिम रूप देने का हरेक प्रयास किया है, पिछले वर्ष के विपरीत इस वर्ष छठी समिति का इस एजेंडा मद पर संकल्प इकसठवें सत्र के दौरान किसी तदर्थ समिति की बैठक को प्राधिकृत नहीं करता। यह स्परणीय है कि छठी समिति ने गत वर्ष के संकल्प में इसी तरह से प्रावधान अपनाए थे जिसने मार्च,-अप्रैल, 2005 में हुई तदर्थ समिति की बैठक के दौरान परमाणु आतंकवाद पर अभिसमय के प्रारूप को अन्तिम रूप देना और अपनाना सुकर बनाया

समग्र भेंट

इस वर्ष की समग्र मद : "समुद्र और समुद्री कानून" पर हुए विचार-विमर्श में मुख्यतः विश्व के सामुद्रिक पर्यावरण और वहनीय मछली पकड़ने के संव्यवहारों के संरक्षण पर जोर दिया गया। इस सत्र के दौरान महासभा ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों की समुद्री जीव विविधता मामलों के अध्ययन के लिए अपने 59/24 संकल्प के पैराग्राफ 73 के अनुपालनार्थ स्थापित तदर्थ खुले यिचसले अनौपचारिक कार्य दल में भाग लेने का निर्णय लिया। इसने अगले तीन वर्षों के लिए समुद्र और सामुद्रिक कानून पर खुले सिरवाले संयुक्त राष्ट्र के साथ अनौपचारिक परामर्श प्रक्रिया जारी रखने का भी निर्णय लिया।

महासभा ने नियमित प्रक्रिया की स्थापना एक तैयारी चरण के रूप में "निर्धारणों का निर्धारण" करने का निर्णय लिया जिसे दो वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है। इस सम्बन्ध में महासभा ने संचालन दल द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की निशाबन्दी सहित समान भौगोलिक आधार पर एक तदर्थ संचालन दल स्थापित किया गया।

वहनीय मछली पालन पर सभा ने समीक्षा बैठक की तैयारी के लिए महासचिव से मछली भण्डार करार के लिए मार्च, 2006 में पक्ष राष्ट्रों का अनौपचारिक विचार-विमर्श के 5 वें दौर की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया। यह भी निर्णय लिया गया था वे राष्ट्र, जो करार के पक्ष नहीं हैं, इस बात को छोड़कर कि उन्हें वोट का अधिकार नहीं होगा, करार के पक्ष राष्ट्रों के अनौपचारिक विचार-विमर्श के 5 वें दौर में पूरी तरह से भी भाग ले सकते हैं।

अन्तरराष्ट्रीय समुद्र संगठन (आई एम ओ)

दिनांक 10-14 अक्तूबर, 2005 को लन्दन में अन्तरराष्ट्रीय समुद्र संगठन का राजनयिक सम्मेलन हुआ जिसमें समुद्री नौवहन सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों के दमन के लिए अभिसमय, 1988 के अंतिम पाठ को अपनाया गया। यह पहल 2000 में संयुक्त राज्य अमेरीका पर 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद अन्तरराष्ट्रीय समुद्र संगठन द्वारा की गई। संशोधित गैर कानूनी गतिविधियों के दमन के लिए अभिसमय और इसका प्रोतोकोल में विभिन्न मुद्दों दिएगए हैं जो आतंकवाद से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन निशस्त्रीकरण और अप्रसार के मुद्दों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए है। इसके अलावा यह संयुक्त राज्य अमेरीका और इसके भागीदारों द्वारा आरम्भ की गई "सुरक्षा प्रसार पहल" गतिविधियों को कानूनी जामा देने का भी प्रयास है। भारत ने इन संशोधनों का विरोध किया था और अपनी शिकायतों को कानूनी समिति के समक्ष तथा अन्तरराष्ट्रीय समुद्र संगठन राजनयिक सम्मेलन के दौरान भी दर्ज कराया।

समुद्र और समुद्री कानून

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 60वें सत्र में दो संकल्प 60/30 और 60/31 क्रमशः "समुद्र और समुद्री कानून" और "वहनीय मत्स्य पालन जिसमें संकट ग्रस्त मत्स्य भण्डारों और अधिक स्थान परिवर्तन मत्स्य भण्डार तथा सम्बद्ध लिखतों के संरक्षण और प्रबंधन से सम्बन्धित 10 दिसम्बर, 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए करार, 1995 के माध्यम सहित वहनीय मत्स्य पालन" की एजेंडा मदों को अपनाया गया। महासभा ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982 के संयुक्त चरित्र की पुनः पुष्टि करते हुए राष्ट्रीय विधान की इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अभिसमय के साथ सुमेलीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। सभा ने आदाता एजेंसियों और राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों की वित्तीय सहायता और अभिसमय के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अपनी क्षमता बनाने के लिए उनको तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर आयोग को अपनी प्रस्तुतियों भी तैयारी के लिए आह्वन किया है। यह राष्ट्रों को समुद्री डकैटी, समुद्र में सशस्त्र डकैटी, जहाजरानी और अन्य समुद्री हितों के खिलाफ तस्करी और आतंकवादी कार्यों का मुकाबला करने में सहयोग को प्रोत्साहित किया। सभा ने राष्ट्रों को भूमि आधारित स्रोतों से समुद्री प्रदूषण को नियन्त्रित करने कम करने और कमी लाने और गहरे समुद्र की जानकारी और ज्ञान में सुधार विशेष तौर पर गहरे समुद्री जैव विविधता और पर्यावरण प्रणालियों की सीमा और दुबर्लता में सुधार के लिए भी कहा। सभा ने सामाजिक - आर्थिक पहलू ("वैश्विक प्रक्रिया") सहित समुद्री पर्यावरण की स्थिति वैश्विक रिपोर्टिंग

और निर्धारण के लिए नियमित प्रक्रिया कार्य के सम्बन्ध में संगठनात्मक व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था में "निर्धारणें के निर्धारण" के निष्पादन को देखने के लिए एक तदर्थ संचालन दल शामिल होगा, दो संयुक्त एजेंसियां प्रक्रिया और विशेषज्ञ दल का सह-नेतृत्व करेंगी। व्यवस्था के क्रियाकलाप स्वैच्छिक अंशदानों और भागीदार संगठनों और निकायों के लिए उपलब्ध अन्य संसाधनों के माध्यम से वित्त पोषण होगा।

मत्स्य पालन से सम्बन्धित मामलों पर महासभा ने सभी राष्ट्रों से मत्स्य भण्डार करार के अनुसार संकट ग्रस्त मत्स्य भण्डारों के संरक्षण, प्रबन्धन और दोहन के लिए और करार के प्रावधानों के अपने राष्ट्रीय कानूनों के साथ सुमेलीकरण के लिए सावधानी और पर्यावरण-प्रणाली पहुंच को लागू करने का आह्वन किया। इसने राष्ट्रों को उच्च समुद्रों अथवा अन्य राष्टों के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्र में गैर-कानूनी मछली पकड़ने में शामिल अपने पोतों को अनुमति न देने और गैर-कानूनी, रिर्पोट न की गई और अनियमित मछली पकड़ने का मुकाबला कहने का कहा।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर विशेष समिति

"संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर और संगठनों की भूमिका को सुदृढ करने पर विशेष समिति" अन्तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अनुरक्षण, न्यास परिषद; अन्य समितियों/निकायों जो अन्तर-राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य में भी लगे है, विशेष तौर पर प्रतिबन्धों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित तीसरे देशों की सहायता के सम्बन्ध में तालमेल से सम्बन्धित बहुत से प्रस्तावों परविचार कर रही है। महासभा ने अपने 60 वें सत्र में विशेष समिति की अपने कार्य की इसके 2005 सत्र की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद संकल्प 60/23 को अपनाया है। महासभा ने विशेषसमिति से प्रतिबन्धों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित तीसरे राष्ट्रों की सहायता से सम्बन्धित चार्टर प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रतिफल को प्राथमिकता देने का स्टैन्ड यह रहा है कि सुरक्षा परिषद प्रतिबन्ध लगाने वाले निर्णयों भाग के रूप में प्रभावित तीसरे देशों के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग

कानून और संधि प्रभाग ने इलेक्ट्रानिक वाणिज्य, परिवहन और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्यदल की बैठकों में भाग लिया। इस वर्ष जुलाई में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 38 वें वार्षिक सत्र के दौरान आयोग ने अन्तरराष्ट्रीय संविदाओं में इलेक्ट्रानिक संचारों के उपयोग पर अभिसमय को अपनाया गया। उक्त अभिसमय में पक्ष स्वायत्तता और इलेक्ट्रानिक संचारों की कानूनी मान्यता सहित इलेक्ट्रानिक वाणिज्य पर प्रारूप कानून के बहुत से आवश्यक सिद्धान्त शामिल हैं। तथापि कुछ सिद्धान्तों को काफी संशोधित किया गया है ताकि अभिसमय में अपेक्षित व्यापक सुनिश्चितता की आवश्यकता को पूरा करने, विशेषतौर पर संविदा के समय और स्थान के प्रावधानों के लिए काफी संशोधित किया गया है। अभिसमय में प्रस्ताव आमंत्रित करने स्वचालित सूचना प्रणालियों का उपयोग और इलेक्ट्रानिक संचारों गुटियों सहित नये सिद्धान्तों को भी शामिल किया गया है जिसमें नई कानूनी चिन्ताएं झलकती है जो 1996 के प्रथम प्रारूप कानून के जारी होने के बाद उभरी हैं।

समुद्री परिवहन कानून

प्रभाग ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्य दल III (परिवहन कानून) के पन्द्रहवें और सौलहवें सत्र जो क्रमशः 18-28 अप्रैल, 2005 न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमरीका और दिनांक 20 नवम्बर-9 दिसम्बर, 2005 को वियना, आस्ट्रिया में हुए थे, भाग लिया। उक्त कार्य दल तकनीकी विकास के कारण इस क्षेत्र में उभरे व्यावहारिक परिवर्तनों से निपटने के लिए समुद्री और अन्य माध्यमों द्वारा माल के अन्तरराष्ट्रीय परिवहन से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने की दृष्टि से एक नये अभिसमय के लिए वार्तालाप कर रहा है। पन्द्रहवें सत्र में संविदा की स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और पंच फैसले से सम्बन्धित प्रावधानों पर विचार विमर्श किया गया था। हालांकि सोलहवें सत्र में कार्यदल ने अधिकार क्षेत्र और पंच फैसले से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श जारी रखा, इसके अलावा इसने जहाज मालिक की जवावदेही, माल की सुपुर्दगी और वाहक की जिम्मेदारी की अवधि से सम्बन्धित प्रावधानों पर भी विचार विमर्श गया।

अन्तरराष्ट्रीय जलमाप चित्रण संगठन

विधिक एवं संधि प्रभाग ने अन्तरराष्ट्रीय जल माप चित्रण संगठन पर अभिसमय के पुनर्निर्माण में भाग लिया। इसके अन्त में अन्तरराष्ट्रीय जल माप चित्रण संगठन को स्थापित करते हुए 1956 अभिसमय को पुनःजीवित करने और विस्तार करने के साथ साथ इसके सामान्य और वित्तीय विनियम के लिए एक रणनीति योजना कार्यदल की स्थापना की गई है। इस वर्ष इस प्रभाग ने रणनीति योजना कार्यदल की छठी और सातवीं बैठकों में भाग लिया जो क्रमशः सिडनी और मैक्सिको में हुई थी।

एशिया अफ्रीका कानूनी परामर्शदात्री संगठन

वर्ष 2005 के एशिया अफ्रीका कानूनी परामर्शदात्री संगठन का वार्षिक सम्मेलन दिनांक 27 जून से 1 जुलाई, 2005 तक नैरोबी (केन्या) में हुआ था। सम्मेलन के दौरान संगठन ने अन्तरराष्ट्रीय कानून के बहुत से चालू मुद्दों पर विचार-विमर्श कियाः अपने छप्पनवें सत्र में अन्तरराष्ट्रीय कानून आयोग के कार्य से सम्बन्धित मामलों पर रिपोर्ट; अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद; महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के खिलाफ सहयोग की स्थापना करना; अन्तरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, हाल ही घटनाएं; अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग और अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के कार्य पर रिपोर्ट; पर्यावरण और वहनीय विकास; और लोक ज्ञान की अभिव्यक्ति और इसका अन्तरराष्ट्रीय संरक्षण।

बी आई एमएस टी ई सी

बी आई एम एस टी ई सी के सदस्य राष्ट्रों के नेता 2004 में हुई शिखर बैठक में आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त प्रयासों को सुदृढ करने और इस सम्बन्ध में अपने प्रयासों में तालमेल के लिए बी आई एम एस टी ई सी सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आतंकवाद और अपराध पर संयुक्त कार्य दल स्थापित करने पर सहमति हुई। भारत ने दिसम्बर, 2004 में नई दिल्ली में हुई आतंकवाद और राष्ट्रपार अपराध का मुकाबला करने पर प्रथम संयुक्त कार्यदल बैठक आयोजन किया। नई दिल्ली संयुक्त कार्य दल - आतंकवाद और राष्ट्रपार अपराध मुकाबला बैठक में आसूचना के आदान-प्रदान; आतंकवाद के वित्तपोषण; वैधानिक और कानून के प्रवर्तन के मामले और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी प्रदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए चार उपदलों की स्थापना का निर्णय लिया गया और उक्त लक्ष्य चार नेतृत्व अविपालों - श्रीलंका, थाइलैण्ड, भारत और म्यांमार को क्रमशः सौंपने का भी निर्णय लिया गया। वैधानिक और कानून प्रवर्तन के मुद्दों पर उप-दल की प्रथम बैठक दिनांक 5-7 दिसम्बर, 2005 को नई दिल्ली में हुई। सभी बी आई एम एस टी ई सी के सदस्य राष्ट्रों ने बैठक में भाग लिया। उक्त उप-दल ने सदस्य देशों के सम्बन्ध में मौजूद आतंकवाद और राष्ट्रपार अपराध का मुकाबला करने के लिए कानूनी ढाँचे पर व्यापक - रूप से विचार-विमर्श किया। सदस्य राष्ट्रों ने वैधानिक और प्रशासनिक विभिन्न उपायों पर भी जोर दिया जो उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद पर अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय और संगत सुरक्षा परिषद के संकल्पों के कार्यान्वयन के लिए अपनाए हैं। प्रतिनिधिमंडलों ने संसाधनों की सीमित उपलब्धतता, आतंकवाद का मुकाबला करने के अभिसमयों के कार्यान्वयन में शामिल तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव और अन्य पेचीदगियां तथा अन्तर-सरकारी तालमेल में अन्तर्गस्त अन्य समस्याओं का भी उल्लेख किया। इसके अलावा प्रतिनिधियों ने प्रत्यपर्ण और पारस्परिक कानूनी सहायता को सुसाध्य बनाने के लिए उचित तंत्र के विकास में उनको समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीय कानूनों, द्विपक्षीय संधियों और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के समेकन की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतिनिधिमंडलों ने बी आई एम एस टी ई सी के सदस्य राष्ट्रों के बीच अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीले पदार्थ के अवैध व्यापार का मुकाबला करने के करार के प्रारूप जो भारत द्वारा प्रस्तावित किया था, पर भी विचार किया गया। उप-दल ने ऐसे किसी करार की महत्ता को पहचाना और इस पर और आगे कार्य करने निर्णय लिया।

प्रत्यर्पण और अपराधिक कानून के मुद्दों पर न्यायिक सहायता

फ्रांस और ओमान के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर बातचीत की गई और उन्हें अन्तिम रूप दिया गया जो इनके प्रवर्तन की अपेक्षाओं को पूरा करने पर प्रवर्तित हो गई हैं। ईरान के साथ भी प्रत्यर्पण संधि के लिए वार्तालाप जिसको अन्तिम रूप देने के लिए आगे वार्तालाप अपेक्षित होगा। तथापि बेलारूस, ओमान और नेपाल के साथ वार्तालाप विभिन्न चरणों में है।

आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता के विषय में ईरान, मॉरीशस और सिंगापुन के साथ करारों पर वार्तालाप करके अन्तिम रूप दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरीका, सिंगापुर और फ्रांस के साथ करारों के सम्बन्ध में प्रविष्टि के प्रवर्तन के लिए आवश्यक अपेक्षाओं का पूरा किया। परिणामतः वे प्रवृत हो गई हैं। नेपाल, मैक्सिको और हाँगकाँग के साथ वार्तालाप जारी है।

निजी अन्तरराष्ट्रीय कानून

भारत के विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों के वैधानिकीकरण की आवश्यकता को समाप्त करने के हेग अभिसमय, 1961 और अन्तर-देश अंगीकार के सम्बन्ध में बाल संरक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय, 1993 का पक्ष बनने के बाद प्रभाग आवश्यक जाँच-पड़ताल पूरा करके अब सिविल अथवा वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और अतिरिक्त न्यायिक दस्तावेजों की विदेशी सेवा पर हेग अभिसमय, 1965 और सिविल अथवा वाणिज्यिक मामलों में विदेशी साक्ष्य लेने पर हेग अभिसमय, 1970 को भारत की अधिस्वीकृति की प्रक्रिया अब जारी है। इससे भारतीय न्यायालयों और पक्षों को दूसरे देश जो इन अभिसमयों के लिए राष्ट्र पक्ष हैं से बड़ी संख्या

में दस्तावेजों की सेवा और साक्ष्य लेने के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग लेने में काफी मदद मिलेगी।

अन्तरराष्ट्रीय कानून के विकास में एक एण्ड टी प्रभाग की भागीदारी

मंत्रालय ने दिनांक 29-31 जुलाई, 2005 को संधि कानून पर नेपाल की शाही सरकार के कानून मंत्रालय के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए काठमाण्डू में कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में लगभग चालीस अधिकारियों ने भाग लिया।

भारत ने जनवरी और अगस्त, 2005 में न्यूयार्क में हुए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और गरिमा के संरक्षण और संवर्धन और व्यापक और समग्र अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय पर तदर्थ समिति के सत्रों में भी भाग लिया। प्रस्तावित अभिसमय में विकलांग व्यक्तियों के सभी मानव अधिकारों के पूर्ण और समान भोग की अपेक्षा की गई है और इसके लिए यह राष्ट्रों पर अपने राष्ट्रीय विधानों में विकलांगता के आधार पर समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार प्रदान करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जवाबदेही देने की अपेक्षा करता है।

प्रारूप पर कार्यदल कानूनी-रूप से सितम्बर, 2005 में जेनेवा के दबाब युक्त अप्रकटीकरणों से सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए मानदंडात्मक लिखत से बंधा है। इस बैठक के दौरान कार्य-दल ने प्रारूप अभिसमय को अपनाया जो दबावयुक्त अप्रकटीकरण से व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। उक्त अभिसमय दबाब-युक्त अप्रकटीकरण को परिभाषित करता है और दबाब युक्त अप्रकटीकरण के अध्यधीन न होने वाले व्यक्तियों के नये अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। इसमें दण्डमुक्ति के भी प्रावधान हैं और स्वतंत्र निगरानी तंत्र की व्यवस्था है। प्रारूप अभिसमय को मानवाधिकार आयोग और उसके बाद अनुमोदन के लिए महासभा को भेजा जायेगा।

इस प्रभाग ने सिन्धु जल संधि के तकनीकी मुद्दों और संगत प्रावधानों के उपयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए बगलिहार और किशनगंगा परियोजनाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप में भाग लिया।

बहुत सी मंत्रिमण्डलीय टिप्पणियों की कानूनी दृष्टि से जाँच पड़ताल की गई और उन्हें मंजूर किया गया जिसमें शामिल थे स्थाई कार्बनिक प्रदूषणों पर स्टॉकहोम अभिसमय को स्वीकृति; राष्ट्रीय जंगली जीव नियत्रंण ब्यूरो का गठन; अगोचर सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण अभिसमय पर यूनेस्को अभिसमय, स्पष्ट विकास तंत्र; बाघ परियोजना के कार्यान्वयन के जबावदेह राष्ट्रीय बाध संरक्षण प्राधिकरण के गठन के लिए जंगली जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को संशोधित करने के लिए अध्यादेश का प्रख्यापन; राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव; वीपो प्रतिलिप्याधिकार संधि और वीपो निष्पादन और फोनोग्राम संधि का पक्ष बनने और रोम अभिसमय को भी संशोधित करने के लिए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 में संशोधन; यूक्रेन और कजाख्स्तान के साथ प्रत्यपर्ण संधियां।

विभिन्न अन्य अन्तरराष्ट्रीय कानून के मुद्दों और मामलों, विशेषतौर पर राजनयिक सम्बन्धों पर वियना अभिसमय, 1961; वाणिज्यिक सम्बन्धों पर वियना अभिसमय, 1963; पारपत्र अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अन्तर्गत पारपत्र से सम्बन्धित मामले; भारतीय दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 86 जिसमें भारतीय न्यायालयों में विदेशी सरकार पर बाद चलाने से पहले केन्द्रीय सरकार सहमति जरूरी है, के उपयोग से सम्बन्धित थे, की जांच-पड़ताल की गई।

भारत ने वर्ष के दौरान दूसरे देशों के साथ बहुत से बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संधियों/करारों पर हस्ताक्षर किये/को संशोधित किया। इनमें शामिल हैंः सार्क पंच फैसले परिषद की स्थापना के लिए करार, सीमा शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता, सार्क करार और दोहरे कराधान के परिहार और कर के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर सार्क सीमित बहुपक्षीय करार; एशिया और प्रशान्त के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा अंगीकृत एशियन राजमार्ग नेटवर्क पर अन्तरसरकारी करार; वैश्विक विकास नेटवर्क; भ्रष्टाचार के खिलाफ अभिसमय; सशस्त्र संघर्ष में बच्चों को शामिल करने पर बाल अधिकारों पर अभिसमय का वैकल्पिक प्रोतोकोल; बच्चों की बिक्री, बाल वैश्यावृत्ति और बाल अश्लील साहित्य पर बाल अधिकारों के अभिसमय का वैकल्पिक प्रोतोकोल। एक वृहद सूची **परिशिष्ट-IX** में रखी गई है। वर्ष, 2004 के दौरान जारी किए गए पूर्ण शक्ति लिखतों की सूची **परिशिष्ट-X** में दी गई है और संशोधन लिखतों की सूची **परिशिष्ट-XI** में दी गई है।

■■

10 बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

विश्व अर्थव्यवस्था के साथ गहन एकीकरण करने का अपना प्रयास जारी रखते हुए भारत की आर्थिक कूटनीति विशेषकर अपने पूर्व के देशों के साथ भारत की स्वाभाविक ताकतों को बढ़ाने पर केन्द्रित रही। भारत ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में और बहुपक्षीय, क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय समूहों में विकासशील देशों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने में सक्रिय भूमिका निभाई।

सार्क

तेरहवां सार्क शिखर सम्मेलन 12 एवं 13 नवम्बर, 2005 को ढ़ाका में हुआ।

भारत ने काफी बहस की है कि यदि दक्षिण एशिया को क्षेत्रीय सहयोग एवं वैश्विकरण की वृहतर प्रक्रिया का एक गतिमान घटक बनना है, जैसा कि विश्व में हो रहा है, तो इसकी एक आवश्वयक पूर्वापेक्षा के रूप में सदस्य देशों के बीच सबसे पहले आर्थिक एकीकरण लाना होगा। प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने सार्क के एक नए दृष्टिकोण को सामने रखा, जहां प्रदेश के बीच लोगों, सामानों और सेवाओं तथा विचारों के मुक्त आवागमन के रास्ते में राजनीतिक विभाजनें आड़े नहीं आएंगी। इस परिप्रेक्ष्य में, प्रधानमंत्री ने आपसी आधार पर प्रदेश के समस्त देशों को पारगमन सुविधाएं तथा वास्तविक खुला आकाश प्रबंध के माध्यम से बेहतर हवाई सम्पर्क प्रदान करने का प्रस्ताव किया।

सार्क के आठवें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल करने पर सार्क के राज्य एवं सरकार प्रमुखों द्वारा सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था। अफगानिस्तान के प्रवेश के साथ ही सार्क को और अधिक पूर्ण क्षेत्रीय पहचान हासिल हो जाएगी।

सम्मेलन में आपसी हित के क्षेत्रों में सार्क के साथ सहयोग करने हेतु अन्य क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सत्ताओं की बारंबार अभिरूचि को नोट किया गया। भारत ने पर्यवेक्षकों के रूप में सार्क के साथ सहबद्ध करने हेतु चीन के साथ-साथ जापान द्वारा दर्शाई गई अभिरूचि का स्वागत किया है।

सार्क आपदा प्रबंधन एवं तैयारी केन्द्र की अगवानी करने के भारत के प्रस्ताव का सम्मेलन द्वारा अभिनंदन और इसे स्वीकार किया गया है। यह एक स्पष्ट मान्यता थी कि आपदा तैयारी, आकस्मिक राहत और पुनर्वास के लिए समर्पित एक स्थायी क्षेत्रीय प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता है। इस संबंध में भारत का रिकॉर्ड और प्रदर्शित क्षमताएं सर्वविदित हैं। इस केन्द्र को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ गहन रूप से संबद्ध किया जाएगा।

एक उत्कृष्ट केन्द्र में समस्त दक्षिण एशिया के विद्वानों, वैज्ञानिकों और छात्रों को एकजुट करने वाले दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रस्ताव का स्वागत किया गया था।

सम्मेलन में भारत द्वारा किए गए अन्य प्रस्तावों को भी सकारात्मक ढंग से नोट किया गया, जैसे कि एक क्षेत्रीय अनाज भंडार, कपड़ा एवं हस्तशिल्प संबंधी सार्क संग्रहालय, एक क्षेत्रीय टेलि-मेडिसीन नेटवर्क की स्थापना करना तथा 14वें सार्क सम्मेलन में दौड़ाने के लिए एक सार्क कार रैली का आयोजन करना।

सम्मेलन का एक मुख्य विषय आतंक-विरोधी सहयोग था। सम्मेलन की घोषणा में आतंकवाद की घोर भर्त्सना शामिल थी और इस महाविपत्ति को समाप्त करने के लिए पुनर्बलित प्रतिबद्धता थी। पहली बार, इस संग्रहित चुनौती से निपटने में दोहरे मानदण्डों को रोकने के लिए एक स्पष्ट सहमति भी देखी गई थी।

सम्मेलन में तीन महत्वपूर्ण व्यापार सुविधाकरण करारों पर हस्ताक्षर भी हुआ था। इसमें निम्न शामिल हैं:-

- सीमाशुल्क मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता संबंधी करार
- सार्क मध्यस्थता परिषद की स्थापना संबंधी करार
- कर मामलों में दोहरे कराधान को रोकने तथा आपसी प्रशासनिक सहायता संबंधी सीमित करार

वर्ष 2005 के दौरान साफ्टा (साऊथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया) से संबंधित लम्बित मामलों को सुलझा लिया गया है। जैसे ही सदस्य देशों द्वारा सार्क सचिवालय में अनुसमर्थन दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है, 1 जनवरी, 2006 से पूर्वव्यापी प्रभावी के साथ साफ्टा लागू हो जाएगा।

तेरहवां सार्क शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना थी, जो सार्क के अस्तित्व में आने के बाद इसके तीसरे दशक में प्रवेश

करने पर आयोजित हुई। भारत क्षेत्रीय परियोजनाओं में सहयोग का एक सबल हिमायती रहा, जिसमें विशेषकर अवसंरचना जैसे क्षेत्र, गरीबी उन्मूलन तथा प्राकृतिक आपदा जैसी सीमापार की चुनौतियों से निपटना, एचआईवी/एड्स तथा एवियन फ्लू जैसी महामारियों से निपटना और अपने समस्त रूपों एवं प्रदर्शनों में आतंकवाद को समाप्त करना शामिल था।

सार्क सम्मेलन में 2007 की प्रथम तिमाही में अगले सम्मेलन की मेजवानी करने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

आसियान-भारत संबंध

प्रधानमंत्री ने 14 दिसम्बर, 2005 को कुआलालम्पुर में हुए चौथे भारत-आसियान सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत-आसियान अन्तर्संम्पर्क को 2002 में सम्मेलन स्तरीय साझेदारी तक उठाया गया था।

सम्मेलन में, आसियान एकीकरण हेतु पहल के लिए समर्थन के माध्यम से कम्बोडिया, लाओस, म्यामांर और वियतनाम (सीएलएमवी) को भारत द्वारा दी गई सहायता की आसियान नेताओं ने सराहना की। लाओं पीडीआर में एक उद्यमवृत्ति विकास केन्द्र की स्थापना की गई है और यह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसी तरह के केन्द्र कम्बोडिया, म्यामांर और वियतनाम में बनाए जा रहे हैं और ये 2006 के दौरान कार्य कर सकेंगे। आसियान देशों के बीच विकास की दूरी को कम करने के लिए लक्षित परियोजनाओं हेतु आसियान विकास कोष में 1 मिलियन अमरीकी डालर के अंशदान की भारत ने घोषणा की।

भारत और आसियान ने व्यापार एवं निवेश सम्पर्कों को बढ़ाने के लिए निकट सम्पर्क में काम करने पर सहमति जताई। यह सहमति हुई कि भारत-आसियान एफटीए पर वार्ताओं को जून 2006 तक पूरा कर लिया जाएगा।

यह सहमति हुई कि एक भारत आसियान प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा तथा एक सूचना प्रौद्योगिकी शासकीय एवं उद्योग मंच की स्थापना की जाएगी।

भारत ने आसियान देशों में एक शिक्षा मेला आयोजित करने का प्रस्ताव किया जिससे भावी छात्रों को भारतीय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के साथ एकजुट किया जा सके। आसियान पक्ष की ओर से इसका स्वागत किया गया, जहां उनके राजनयिकों हेतु एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के भारतीय प्रस्ताव के लिए सराहना करने के साथ-साथ टेलि-मेडिसीन और टेलि-एजुकेशन प्रयोगों हेतु इन चार देशों के साथ भारत को सेटेलाईट आधारित नेटवर्क से जोड़ने की व्यवस्था करने और इसकी देखभाल करने की भारत की घोषणा का भी स्वागत किया गया। इस सम्मेलन के दौरान बनी सहमति के क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए भारत-आसियान सहयोग कोष हेतु 5 मिलियन अमरीकी डालर अतिरिक्त प्रावधान की प्रधानमंत्री ने घोषणा की।

आसियान स्पेश टेक्नोलॉजी मिशन ने 13-15 सितम्बर, 2005 को भारत अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, बंगलौर का दौरा किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी 5वें भारत-आसियान कार्यदल की बैठक 21 एवं 22 नवम्बर, 2005 को मानेसर, गुड़गांव में हुई। इससे पहले हैदराबाद में बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर एक कार्यशाला हुई थी।

स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स संबंधी भारत-आसियान कार्य दल की बैठक 13 एवं 14 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में हुई। इसके बाद 27 जुलाई, 2005 को म्यामांर में कृषि संबंधी परामर्श हुआ। परिवहन एवं अवसंरचना संबंधी कार्यदल की दूसरी बैठक 20 एवं 21 अक्तूबर, 2005 को नई दिल्ली में हुई।

वर्ष के दौरान भारत और आसियान के बीच एक मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय पत्रकारों के पांच दलों ने विभिन्न आसियान देशों का भ्रमण किया।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग द्वारा 16-20 जनवरी, 2006 को आसियान देशों के लिए एक आईटी ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन किया गया था। इस केन्द्र ने कम्प्यूटर नेटवर्किंग में सीएलएमवी देशों हेतु एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया।

पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन

प्रथम पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 14 दिसम्बर, 2005 को कुआलालम्पुर में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ने आसियान देशों, आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य तथा न्यूजीलैण्ड के नेताओं के साथ एक सम्मेलन में भाग लिया। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना थी। इसने पहली बार उन देशों के नेताओं को एकजुट कर दिया, जो बढ़ते अन्तर-संबंधों और बढ़ती अन्तर-निर्भरता के लिए परिभाषित हैं तथा इसने क्षेत्र को विश्व अर्थव्यवस्था हेतु विकास का एक ईंजन बना दिया है।

पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रों के एक मैत्रीपूर्ण और समृद्ध समुदाय के निर्माण के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समुदाय का वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों के लिए एक संधिहीन एकीकृत बाजार होना चाहिए, जिससे सामान्य चुनौतियों से निपटने में इसके अपार संसाधन का साझा प्रयोग किया जा सके। प्रधानमंत्री ने एक सन्तुलित और संस्थागत अवसंरचना की

स्थापना का प्रस्ताव किया जो क्षेत्रीय सहयोग एवं कार्रवाई के लिए आधार तैयार करेगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एक पैन-एशियन फ्री ट्रेड एरिया ऐसे समुदाय के लिए शुरूआती ब्लॉक हो सकता है।

पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में कुआलालम्पुर घोषणा को अपनाया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रदेश में समुदाय निर्माण के लक्ष्य को परिलक्षित किया गया है। यह घोषणा सहभागी देशों हेतु विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थायित्व, ऊर्जा संरक्षण एवं प्रदेश में आर्थिक एकीकरण को गहन करने के लिए कटिबद्ध है। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन वार्षिक तौर पर आयोजित होगा और एक आसियान सदस्य देश द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी।

77 का दल

विदेश मंत्री ने 22 सितम्बर, 2005 को न्यूयार्क में हुई 77 के दल (जी-77) की विदेश मंत्रियों की 29वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

श्री ई0 अहमद, विदेश राज्य मंत्री ने 12-16 जून, 2005 को दोहा, कतर में हुए द्वितीय दक्षिण शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने दोहा घोषणा में योगदान किया और दोहा कार्रवाई योजना को सम्मेलन में अपनाया गया, तथा सम्मेलन में शुरू की गई विकास एवं मानवीय सहायता संबंधी दक्षिण कोष में 2 मिलियन अमरीकी डालर देने का वादा किया।

मेकाँग-गंगा सहयोग

मेकाँग-गंगा सहयोग छः देशों-भारत एवं पांच आसियान देशों, यथा, कम्बोडिया, लाओ पीडीआर, म्यामांर, थाईलैण्ड तथा वियतनाम-द्वारा नवम्बर, 2000 में वियनताने में शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति एवं परिवहन और संचार में सहयोग को बढ़ाना है। मेकाँग-गंगा सहयोग के अन्तर्गत दिल्ली-हनोई रेल सम्पर्क के एक अंग के रूप में, राईट्स लिमिटेड द्वारा किए गए जिरीबाम (मणिपुर)-मण्डले (म्यामांर) रेल मार्ग के व्यवहार्यता अध्ययन को पूरा कर लिया गया है तथा इसकी रिपोर्ट विचाराधीन है।

दिल्ली-हनोई रेल/सड़क सम्पर्कों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 28 जून, 2005 को बैंकॉक में परिवहन एवं संचार संबंधी मेकाँग-गंगा सहयोग कार्य दल की बैठक हुई। राईट्स लिमिटेड ने जिरीबाम-मण्डले रेल मार्ग संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन पर मेकाँग-गंगा सहयोग देशों को विवरण प्रस्तुत किया।

संस्कृति में सहयोग के हिस्से के रूप में, मेकाँग-गंगा सहयोग देशों के परम्परागत वस्त्रों का एक संग्रहालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा सीम रिप, कम्बोडिया में पूर्ण होने की स्थिति में है।

भारत ने प्रत्येक मेकोंग-गंगा सहयोग देशों के लिए 10 सांस्कृतिक अध्येतावृत्तियां प्रस्तावित की हैं।

ग्लेनिगल्स शिखर सम्मेलन (जी-8 शिखर सम्मेलन)

इस वर्ष के लिए जी-8 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन की अध्यक्षता में 6-8 जुलाई, 2005 को ग्लेनिगल्स होटल, स्कॉटलैण्ड में हुआ था। ब्राजील, चीन, भारत, मेक्सिको तथा दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन के प्रमुखों को 7 जुलाई, 2005 को विश्व अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन एवं दीर्घकालीन विकास पर चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। अल्जीरिया, इथियोपिया, घाना, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका एवं तंजानिया के नेताओं के साथ-साथ अफ्रीकी संघीय आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व बैंक के प्रमुखों ने 8 जुलाई 2005 को अफ्रीका एवं विकास संबंधी चर्चा में भाग लिया।

जी-8 के साथ इस बैठक से पहले 7 जुलाई, 2005 को ब्राजील, चीन, भारत, मेक्सिको एवं दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक के अन्त में एक घोषण जारी की गई थी, जिसमें वैश्विक आर्थिक असंतुलनों, विकास हेतु वित्तपोषण, व्यापार वार्त्ताओं का चालू दोहा दौर, जलवायु परिवर्तन और दीर्घकालीन विकास से संबंधित मामले शामिल थे।

जी-15

पंद्रह के दल (जी-15) के एक संस्थापक सदस्य के रूप में, जी-15 देशों के बीच आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न जी-15 परियोजनाओं एवं गतिविधियों में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई। भारत कई जी-15 परियोजनाओं जैसे कि सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों, औषधीय एवं सुगन्धित पौधों हेतु जीन बैंकों की स्थापना तथा सेनेगल में उद्यमवृत्ति एवं तकनीकी विकास केन्द्र का समन्वय कर रहा है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (भारत) द्वारा 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत से स्थापित किया गया नाइजीरिया मशीन टूल्स पूरा कर लिया गया है और इसे जल्द ही नाइजीरिया सरकार को सौंप दिया जाएगा।

एशियाई राजमार्ग नेटवर्क

एशियाई राजमार्ग नेटवर्क संबंधी कार्यदल की सर्वप्रथम बैठक 14 एवं 15 दिसम्बर, 2005 को बैंकॉक में अनस्केप सचिवालय

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 14 दिसम्बर, 2005 को कुआलालम्पुर में पहले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ।

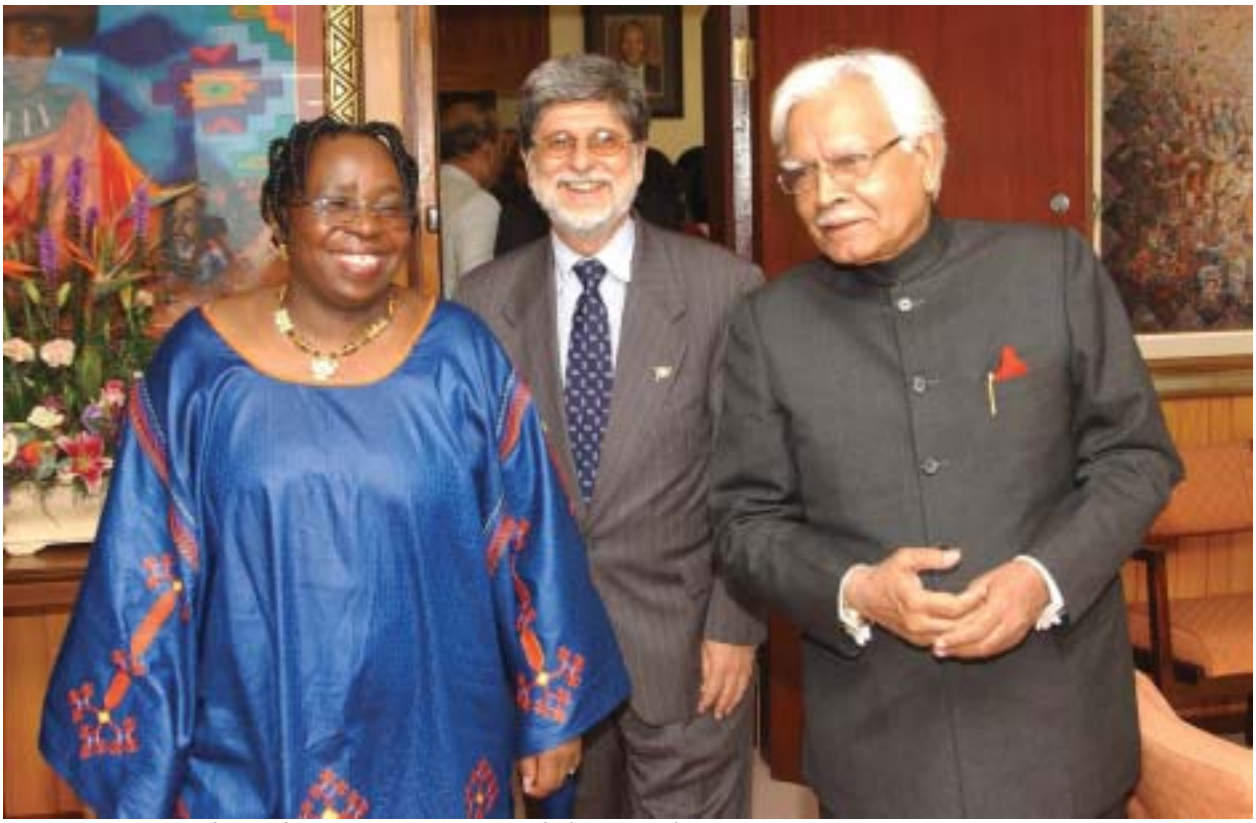

आई बी एस ए कोरम विदेश मंत्री 10 मार्च, 2005 को केप टाउन में साउथ अफ्रिका की सुश्री नीकीसजाना दियामिनी- जूमा, ब्राजील के श्री सेल्सो एमोरिम और भारत के श्री के. नटवर सिंह।

में हुई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एशियाई राजमार्ग नेटवर्क के कार्यान्वयान की स्थिति की समीक्षा करना, कार्यदल हेतु विचारार्थ विषयों को अपनाना तथा एशियाई राजमार्ग नेटवर्क के विकास से संबंधित मामलों पर नीतियों की चर्चा करना और जानकारी का आदान-प्रदान करना था। इस समय 32 देशों में से 28 ने इस पर हस्ताक्षर किया है और 14 देशों ने करार का अनुसमर्थन किया है।

बहुपक्षीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी की पहल (बिमस्टेक)

2004 में बैंकॉक में प्रथम बिमस्टेक सम्मेलन और फुकेत में वरिष्ठ आधिकारिक एवं मंत्रिस्तरीय बैठकों से उभरने वाली पहलों के गहन एवं सफलतम अनुवर्त्तन से बिमस्टेक के सदस्य देशों के बीच भागीदारी की अच्छी प्रवृत्ति का पता चला है। नौवीं वरिष्ठ आधिकारिक बैठक 31 मई-1जून, 2005 को ढ़ाका में हुई थी।

आठवीं बिमस्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक और दसवीं वरिष्ठ आधिकारिक बैठक 17-19 दिसम्बर, 2005 को ढ़ाका में हुई थी।

बिमस्टेक एफटीए संबंधी रूपरेखा करार के परिप्रेक्ष्य में कार्यबल और व्यापार वार्त्ता समिति (टीएनसी) की विभिन्न बैठकों में अच्छी प्रगति हुई है। हालांकि, वस्तुओं संबंधी एफटीए के बारे में काफी अधिक प्रगति हासिल हुई है, वार्त्ताओं को अन्तिम रूप देने के समय-सीमा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मामलों को शीघ्र सुलझाया जाना बांकी है। बिमस्टेक एफटीए हेतु उद्गम नियमावली पर वार्त्ताएं चल रही हैं। समस्त लम्बित मामलों को निपटा लिए जाने की आशा है जिससे कि वस्तुओं संबंधी एफटीए को शीघ्र अंतिम रूप दिया जा सके और इस पर हस्ताक्षर शीघ्र हो सके, क्योंकि बिमस्टेक रूपरेखा करार में बताई गई समय-सीमा का सख्ती से पालन करते हुए वार्त्ताओं का निष्कर्ष हासिल करने के पक्ष में है। दस्वीं टीएनसी की बैठक 21-27 दिसम्बर, 2005 को काठमाण्डू में हुई थी। टीएनसी की ग्यारहवीं बैठक 6-11 फरवरी, 2006 को बैंकॉक में होना निर्धारित है।

बिमस्टेक सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग के साथ-साथ व्यापार एवं निवेश सम्पर्कों की समीक्षा करने, आकलन करने तथा आगे बढ़ाने के लिए बिमस्टेक व्यापार मंच, आर्थिक मंच एवं व्यापार और निवेश क्षेत्र की बैठकें क्रमशः 29 अगस्त, 30 अगस्त तथा 1 एवं 2 सितम्बर, 2005 को नई दिल्ली में हुई।

मौसम एवं जलवायु संबंधी एक कार्यशाला 23-25 जुलाई, 2005 को भारत में हुई थी। बिमस्टेक मौसम एवं जलवायु केन्द्र अगस्त, 2004 से अपने वास्तविक चरण में है। वास्तविक चरण में केन्द्र की स्थापना हेतु प्रशासनिक, वित्तीय एवं कार्यात्मक पहलुओं की चर्चा करने के लिए अधिशासी निकाय का संघटन करने हेतु बिमस्टेक सदस्य देशों की एक बैठक 17 एवं 18 जनवरी, 2006 को हुई थी।

भारत ने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटेक) योजना के अन्तर्गत बिमस्टेक सदस्य देशों हेतु 300 छात्रवृत्ति स्लॉटों का आबंटन किया है। इन छात्रवृत्ति के अतिरिक्त, परम्परागत मेडिसीन, यथा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं सिद्ध, के क्षेत्रों में अन्तर-स्नातक/स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तरों पर भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में 30 छात्रवृत्तियाँ आबंटित की गई हैं और बिमस्टेक सदस्य देशों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक के अनुवर्त्तन में और बहुरूपात्मक परिवहन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ निरन्तरता में, 16-26 अगस्त, 2005 को वड़ोदरा के रेलवे स्टाफ कॉलेज में एशियाई परिवहन विकास संस्थान (एआईटीडी) द्वारा दूसरे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था जो रेलवे संबंधी संसाधन जुटान और वित्तीय प्रबंधन पर केन्द्रित था। "ट्रांस-एशियन रेलवे नेटवर्क इन मेम्बर कन्ट्रिज " संबंधी तृतीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 20-31 मार्च, 2006 तक होना निर्धारित है। बिमस्टेक सदस्य देशों के रेलवे के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की दूसरी बैठक 8 एवं 9 दिसम्बर, 2005 को म्यामांर में हुई थी। बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को मेकाँग-गंगा सहयोग के देशों तक फैलाने का प्रस्ताव है।

भारत ने अक्तूबर, 2005 में ऊर्जा मंत्रियों की प्रथम बैठक की मेजबानी की, जिसके पहले नवीकरण ऊर्जा विकास परियोजना संबंधी विशेषज्ञ दल की बैठक हुई। इस सम्मेलन में सदस्य देशों की संबंधित अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक विकास के संवर्द्धन में ऊर्जा दक्ष उपायों की क्षमता को स्वीकार किया गया। बैठक में अपनाई गई कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन में भारत ने 25-27 जनवरी, 2006 को "कन्सेप्ट पेपर ऑन बिमस्टेक इनर्जी सेंटर" पर चर्चा करने के लिए एक कार्यशाला तथा 6 फरवरी, 2006 को "हार्मोनाईजेशन ऑफ ग्रिड स्टेंडर्डस" पर दूसरी कार्यशाला का आयोजन किया।

रक्षा एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री बी0के0 हांडिक के नेतृत्व में 4 युवा सांसदों के एक दल ने तीन बिमस्टेक देशों, यथा- बंगलादेश, थाईलैण्ड एवं भूटान का 10-16 जुलाई, 2005 तक भ्रमण किया।

बिमस्टेक सदस्य देशों हेतु "रिलिवेन्स ऑफ एनसिलराईजेशन इन दी कन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाईजेशन एण्ड इमर्जिंग ट्रेड रिलेशन्स " पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार भारतीय लघु उद्योग

परिषद द्वारा 28 एवं 29 नवम्बर, 2005 को आयोजित किया गया था।

भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (ईबसा)

तीनों विदेश मंत्रियों ने ईबसा त्रिपक्षीय आयोग हेतु 10 एवं 11 मार्च, 2005 को केपटाऊन में बैठक की और मिलेनियम समीक्षा सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सुधारों, दक्षिण सहयोग, अफ्रीकी विकास हेतु नई साझेदारी, नई एशिया अफ्रीका सामरिक साझेदारी, विश्व व्यापार संगठन, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, मध्य पूर्व में स्थिति तथा भूख एवं गरीबी उन्मूलन हेतु ईबसा सुविधा से संबंधित मामलों पर चर्चा की। बैठक में ईबसा सदस्य देशों के बीच कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले 7-9 मार्च, 2005 तक ईबसा फोकल प्वाईंट्स की तीसरी बैठक हुई थी।

इस वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में ईबसा कार्य दल की बैठकें/कार्यशालाएं और संगोष्ठियां हुईं, जिसमें केपटाऊन में 4-5 मार्च 2005 को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यदल की बैठक, रियो डी जेनेरो में 3-4 अगस्त, 2005 को "आर्थिक विकास एवं सामाजिक एकता" संबंधी एक ईबसा सेमिनार और नई दिल्ली में 3-7 अक्तूबर, 2005 को ई-गवर्नेन्स संबंधी एक कार्यशाला शामिल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अन्तर्गत क्रमशः भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील द्वारा एचआईवी/एड्स, बायोटेक्नोलॉजी, नेनोटेक्नोलॉजी, ओसीनोग्राफी पर भी कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। कृषि संबंधी ईबसा विशेषज्ञ दल की एक बैठक 18 एवं 19 जनवरी, 2006 को नई दिल्ली में हुई थी। व्यापार एवं निवेश संबंधी ईबसा कार्यदल की तीसरी बैठक 27 एवं 28 जनवरी, 2006 को भारत में हुई थी।

ईबसा फोकल प्लाईंट्स की चौथी बैठक का आयोजन 3 एवं 4 अगस्त, 2005 को रियो डी जेनेरो में किया गया था। इस बैठक में ईबसा वार्त्ता मंच के तहत लोगों-से-लोगों के सम्पर्क के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सांसदों एवं पत्रकारों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ वायु सेवाओं संबंधी त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को तैयार करने, ईबसा एफटीए की संभाव्यता को तलाशने के लिए व्यापार संबंधी कार्यदल की मंशा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में संतोषजनक अन्तर्संबंध तथा ईबसा वेबसाईट के विकास में प्रगति को नोट किया गया।

ईबसा फोकल प्वाईंट्स की पांचवी बैठक 24-25 नवम्बर, 2005 को दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था कि शुरूआती ईबसा सम्मेलन 2006 में किया जाएगा, जो तीनों नेताओं की सुविधा पर निर्भर होगा, जिसके पहले ब्राजील में मार्च, 2006 के उत्तरार्द्ध में ईबसा त्रिपक्षीय आयोग की तीसरी बैठक होगी। अग्रणी देश की एक प्रणाली को अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत भारत को शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश तथा कृषि का दायित्व सौंपा गया है। पर्यटन, कृषि, व्यापार एवं निवेश, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, ईबसा वेबसाईट, ईबसा विदेश मंत्रियों तथा सांस्कृतिक पर्व-त्योहारों के क्षेत्रों में विभिन्न बैठकों/अनुवर्त्ती कार्रवाईयों पर सहमति बनी है।

तीसरी त्रिपक्षीय आयोग की बैठक और इससे पहले फोकल प्वाईंट्स की बैठक का आयोजन 28-30 मार्च, 2006 को किया जाना निर्धारित है।

इण्डियन ओसियन रिम एशोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (आइओआर-एआरसी)

आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन, उष्णकटिबंधी चक्रवातों से संबंधित मामलों संबंधी एक कार्यशाला नई दिल्ली में मार्च, 2005 में आयोजित हुई थी।

आइओआर-एआरसी के मंत्रियों की छठी परिषद का आयोजन 16-22 फरवरी, 2006 को तेहरान में हुआ था। इससे पहले वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की आठवीं बैठक, व्यापार एवं निवेश संबंधी कार्यदल, इंडियन ओसियन रिम एकेडमिक ग्रुप की बैठकों का आयोजन किया गया।

एशिया प्रशान्त व्यापार करार (आप्टा)

बैंकॉक करार की नामावली को बदलकर "एशिया प्रशान्त व्यापार करार" कर दिया गया है। एशिया प्रशान्त व्यापार करार की शासकीय परिषद की प्रथम बैठक, जिसके पहले बैंकॉक करार (अब एशिया प्रशान्त व्यापार करार) की स्थायी समिति का 24वां सत्र चला था, 1 एवं 2 नवम्बर, 2005 को बीजिंग में हुई थी। बैठक में एक शासकीय घोषणा को अपनाया गया था।

एशियाई सहयोग वार्त्ता (एसीडी)

एशियाई सहयोग वार्त्ता की चौथी शासकीय बैठक 5 एवं 6 अप्रैल, 2005 को इस्लामाबाद में हुई थी। सऊदी अरब को एशियाई सहयोग वार्त्ता के एक नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। कतर 2006 में पांचवीं बैठक की मेजबानी करेगा।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

विश्व व्यापार संगठन के शासकीय सम्मेलन का छठा सत्र 13-18 दिसम्बर, 2005 तक हांगकांग में चला था। इस बैठक में विश्व व्यापार संगठन के एक नए सदस्य के रूप में सऊदी अरब को शामिल किया गया था।

■■

11 तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग और विकास सहभागिता

सह विकासशील राष्ट्रों के साथ भारत के तालमेल का एक महत्वपूर्ण घटक तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग है। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आइटेक) तथा अफ्रीका योजना के विशिष्ट राष्ट्रमंडल सहायता (स्केप) को तकनीकी सहयोग (टी सी) प्रभाग और विकास सहभागिता (डी पी) प्रभाग कार्यान्वित करता है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया तथा पैसिफिक और कैरेबियाई क्षेत्रों के द्वीपों के 156 विकासशील देशों के साथ भारत अपनी विकासात्मक विशेषज्ञता और अनुभवों का आदान-प्रदान करता है।

विदेश मंत्रालय का आइटेक और विकास सहभागिता कार्यक्रम, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के दायरे के अन्दर सद्भावना का निर्माण करने तथा पारस्परिक लाभकारी संबंध बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है। 1964 में शुरू होने के बाद से आइटेक कार्यक्रम ने भारत के लिए महादेशों से विकास सहभागियों को एकजुट किया है।

टी सी प्रभाग को आइटेक के तहत 49 करोड़ रू.,स्केप के तहत 6.5 करोड़ रू. आवंटित किये गये हैं जबकि डी पी प्रभाग को आपदा राहत के लिए सहायता के रूप में 5.1 करोड़ रूपये और विकास सहभागिता के अन्तर्गत 8 करोड़ रू. आवंटित किये गये हैं।

आइटेक कार्यक्रम के छह घटक हैं, अर्थात्:

(i) भारत में आइटेक सहभागी देशों के नामितों का प्रशिक्षण (सिविल तथा सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों दोनों में);

(ii) भारतीय विशेषज्ञों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति;

(iii) भारतीय उपकरण भेंटस्वरूप देना;

(iv) वरिष्ठ अधिकारियों का भारत में अध्ययन दौरा;

(v) प्रौजेक्ट तथा प्रौजेक्ट से संबंधित सहायता जैसे कि उपकरणों की आपूर्ति, परामर्शदात्री सेवाएं और सुसाध्यता अध्ययन;

(vi) आपदा राहत के लिए सहायता (ए डी आर)।

सिविल प्रशिक्षण

भारत सरकार सिविलियनों का प्रशिक्षण संबंधी व्यय जिसमें कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, शिक्षण शुल्क, जीविका भत्ता, आवास, अध्ययन दौरे, चिकित्सा सहायता और पुस्तक भत्ता शामिल है, वहन करती है। सिविल प्रशिक्षणार्थियों के लिए जिन संस्थानों में, छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां सभी सहभागियों के लिए एकल बिस्तर वाला आवास प्रदान करने के लिए होटल सुविधा की अधिकतम वित्तीय सीमा को बढ़ा दिया गया है। 240 पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए 45 भारतीय संस्थानों का पैनल बनाया गया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और लेखा, लेखा-परीक्षा, बैंकिंग, शिक्षा आयोजना एवं प्रशासन, अंग्रेजी भाषा, उद्यमशीलता, खाद्य प्रौद्योगिकी, जनशक्ति संसाधन योजना, श्रम प्रशासन, प्रबंधन, संसदीय प्रणाली का अध्ययन, ग्रामीण विकास, लघु उद्योग, वस्त्र प्रौद्योगिकी, मोबाइल प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा कई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगें।

कुल मिलाकर आइटेक/स्केप कार्यक्रम द्विपक्षीय रूप से कार्यान्वित किए गए हैं। हालांकि, कभी-कभी कार्यक्रमों के लाभग्राही के रूप में क्षेत्रीय समूहों को भी शामिल किया गया है। आसियान, जी - 15 तथा बिमस्टेक देशों को प्रशिक्षण स्लाट मुहैया कराए गए हैं और अफ्रीकी संघ, ए ए आर डी ओ, पैन अफ्रीकी संसद तथा कारीकोम सचिवालय के लिए प्रशिक्षण स्लाट्स विनिर्दिष्ट किए गए हैं। आइटेक/स्केप के तहत अनुमोदित नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा, इन क्षेत्रीय समूहों के नामितों के लिए विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

आइटेक कार्यक्रम के तहत, टेरी (द इनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट) के सहयोग से 22-25, अगस्त, 2005 को "की वलनरेबिलिटीज इन स्माल आइलैंड डिवलपिंग स्टेट्स (सीड्स), स्कोप फॉर टेक्नालॉजी को-आपरेशन विथ इंडिया" पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। 22 लघु द्वीप विकासशील देशों के 25 सहभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान,आइटेक सहभागी देशों के 3600 नामितों को टी सी प्रभाग प्रशिक्षण देने का आशा रखता हैं, विदेश मंत्रालय के आइटेक/स्केप कार्यक्रम के तहत विदेशी नामितों के लिए सिविल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर रहे संस्थानों की सूची **परिशिष्ट-XIV** पर दी गई है। अप्रैल, 2005 - जनवरी, 2006 की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट तथा प्रयुक्त स्लाट से संबंधित देश-वार स्थिति **परिशिष्ट-XV** पर दी गई है।

वित्त वर्ष 2005-06 के लिए व्यय का विवरण **परिशिष्ट-XIII** पर संलग्न है।

रक्षा प्रशिक्षण: भारत, राष्ट्रीय डिफेन्स कॉलेज, नई दिल्ली और डिफेन्स सर्विसेस स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, तमिलनाडु जैसी सुप्रतिष्ठित भारतीय रक्षा संस्थानों में चुनिन्दा देशों के नामित प्रशिक्षणार्थियों को रक्षा सेवा के सभी तीनों अंगों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण में सुरक्षा और सामरिक अध्ययन, रक्षा प्रबंध, आर्टिलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरीन और हाइड्रोग्राफी, संभारीय, उग्रवाद का मुकाबला एवं जंगल युद्धरचना तथा प्रबंधन और गुणवत्तायुक्त आश्वासन सेवाएं शामिल हैं।

46 वां नेशनल डिफेन्स कॉलेज पाठ्यक्रम जनवरी, 2006 में शुरू हुआ जिसमें भिन्न-भिन्न देशों के 21 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मई, 2005 में शुरू हुए 61 वें डी एस एस सी पाठ्यक्रम में 29 विदेशी रक्षा अधिकारी भाग ले रहे हैं। इन दो पाठ्यक्रमों के अलावा,वर्ष 2005-06 के दौरान, विदेशी सैन्य प्रशिक्षुओं के लिए अन्य 301 पाठ्यक्रम (146 सैन्य, 85 नौसैना तथा 70 वायु सेना पाठ्यक्रम) चिन्हित किए गए हैं। ये पाठ्यक्रम आइटेक-I तथा आइटेक-II कार्यक्रमों, स्व-वित्तपोषित स्कीम के तहत तथा पारस्परिक आधार पर आवंटित किए जाते हैं। आइटेक-I के तहत शामिल पाठ्यक्रम पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है जिसमें शिक्षण शुल्क, जीविका भत्ता, आवास, चिकित्सा भत्ता, अध्ययन दौरे तथा वापसी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा शामिल है; आइटेक-II कार्यक्रम के तहत वापसी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा लागत प्रापक सरकार द्वारा वहन की जाती है और अन्य सभी व्यय भारत सरकार वहन करती है। वर्ष 2005-06 के लिए 12 करोड़ रू. की राशि रक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई हैं। वर्ष 2005-06 के लिए आवंटित स्लाट का विवरण **परिशिष्ट-XVI** पर देखा जा सकता हैं।

विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति

वर्ष के दौरान 40 विशेषज्ञ प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न देशों में भेजे गए हैं। इन विशेषज्ञों द्वारा प्रतिनियुक्ति वाले क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, डेयरी फार्मिंग, शहर आयोजना, रक्षा, मत्स्य पालन, कृषि, विधि कार्य तथा दूरसंचार शामिल हैं। विदेशों में सौंपे गए दायित्व को पूरा कर रहे विशेषज्ञों का विवरण **परिशिष्ट-XVII** पर देखा जा सकता है।

विकास सहभागिता एवं परियोजना सहयोग

सह विकासशील देशों के विकास परियोजनाओं के लिए भारतीय देन में और अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से जनवरी, 2005 में एक नया प्रभाग-'विकास सहभागिता' प्रभाग बनाया गया है। इसके साथ-साथ इस प्रभाग को प्रोजेक्ट डिलीवरी तथा संबंधित सहायता कार्य में आन्तरिक विशेषज्ञता भी विकसित करना है ताकि कई क्षेत्रीय प्रभागों द्वारा अलग-अलग चलायी जा रही मौजूदा सभी एक समान परियोजनाओं को मिलाकर परियोजनाओं संबंधी सभी सहयोगात्मक कार्य के लिए यह मंत्रालय में धीर-धीरे एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सके।

नए प्रभाग के पास अभी निम्नलिखित परियोजनाएं हैं - माले में आतिथ्य एवं पर्यटन अध्ययन के लिए भारत-मालदीव मैत्री संकाय, जिम्बाबवे में लघु तथा मध्यम उद्यमों का विकास, मंगोलिया में सौर विद्युतीकरण एवं प्रदर्शन परियोजना, हनोई में सूचना एवं प्रौद्योगिकी में उच्चतर संसाधन केन्द्र, कंबोडिया के सीयम रीप स्थित ता प्रोह्म मंदिर परिसर का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार, लाओस में एक सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा एक विशेषज्ञतायुक्त अस्पताल, यमन के एक औद्योगिक संपदा साना और उलन बटार में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का स्तरोन्नयन, और जांबिया में महात्मा गाँधी माध्यमिक स्कूल का स्तरोन्नयन।

आपदा राहत के लिए सहायता

विश्व के विभिन्न भागों में आए प्राकृतिक विपत्तियों में आपदा राहत सहायता प्रदान करने में भारत ने तत्परतापूर्वक जवाबी कार्रवाई की है। वर्ष के दौरान उत्तरी कोरिया, तुवालू, जमैका, डोमिनिकन गणराज्य, फिलीपीन्स, किर्गीस्तान, सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन्स, बोस्निया और हर्जीगोविना, ग्वाटेमाला, हैती और ताजिकिस्तान को सहायता प्रदान की गई। भारतीय आपदा राहत सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, राहत आपूर्तियां और चावल शामिल है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में अक्तूबर में आए बड़े भूकंप के कारण भारत द्वारा पाकिस्तान को दी गई मानवीय सहायता के अतिरिक्त थी।

■■

12 निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन

निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन प्रभाग अपने वार्षिक प्रकाशन "इंडिया इमर्जिंग ग्लोबल प्लेयर ऑन दी वर्ल्ड इकॉनोमिक स्टेज" में भारत की आर्थिक प्रगति, क्षेत्रवार विकास, सामाजिक एवं विधिक परिप्रेक्ष्य तथा संभावित व्यापार और निवेश के अवसरों की पूरी जानकारी देता है। यह अंग्रेजी के अतिरिक्त जापानी, चीनी, रूसी, जर्मन, फ्रैंच, इटालियन, स्पेनिश तथा अरबी भाषा में भी उपलब्ध है।

आई टी पी प्रभाग अपने विस्तृत निवेश तथा व्यापार ब्रीफ के जरिए बाजार की रणनीति पर सलाह देने और निर्यात के अवसरों और व्यापार की प्रवृतियों पर अपने निर्यातकों और नीति-निर्माताओं को वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना जारी रखे हुए है। यह ब्रीफ विदेश स्थित हमारे सभी मिशनों के लिए भी एक उपयोगी दस्तावेज होता है और यह उनके संवर्धनात्मक कार्यकलापों में मदद करता है।

इस प्रभाग की वेबसाइट <www.indiainbusiness.nic.in> जो कि भारतीय कूटनीति के आर्थिक और वाणिज्यिक पहलुओं के प्रति विशेष रूप से समर्पित है, को निरन्तर नई विशिष्टताओं और हाईपरलिंकों के साथ अद्यतन किया जाता है। यह वेबसाइट सूचना का एक उपयोगी और विश्वसनीय स्रोत बन गया है।

इस प्रभाग ने मंत्रालय के एक्स पी प्रभाग के सहयोग से अपने बाह्य प्रचार-प्रसार में विशेष अनुपूरकों, विवरणिकाओं, सी डी रोम और फिल्मों, जैसे दूरगामी पहलों के माध्यम से भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है।

इस प्रभाग ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और अर्थव्यवस्था में सुधार और उदारीकरण तथा निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा भारत में विदेशी कंपनियों के द्वारा संपर्क/शाखा कार्यालयों को खोलने से संबंधित प्रस्तावों की प्रक्रिया तत्परता से निपटाने से संबंधित अन्य नीतिसंबंधी बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस प्रभाग ने ऊर्जा मामलों के संबंध में हुई सरकारी और गैर-सरकारी बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने मिशनों के नेटवर्क के जरिए भारतीय कंपनियों के कार्य को सुकर बनाया।

प्रभाग ने भारतीय निर्यात तथा निवेश के पहलों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, सी आई आई, फिक्की, नासकोम, एसौचेम, वाणिज्य विभाग और डी आई पी पी जैसे व्यापार और उद्योग निकायों के साथ तालमेल किया। इन संगठनों और संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं, जर्नलो एवं अन्य संगत सूचनाओं को विदेश स्थित भारतीय मिशनों को नियमित रूप से परिचालित किया गया ताकि उन्हें आई टी, जैव-प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे ज्ञान आधारित उद्योगों में हुई प्रगति से अद्यतन रखा जा सके।

भारत तथा विश्व के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विमान-सेवा को बढ़ाने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में आई टी पी प्रभाग, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बैल्जियम, कतर, सिंगापुर तथा न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय नागर विमानन संबंधी वार्त्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।

भारत में एफ डी आई प्रवाह को बढ़ावा देने के अपने अभियान के एक भाग के रूप में सउदी अरब चैम्बर ऑफ कामर्स एडं इंडस्ट्री तथा आबु - धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडलों की नवम्बर, 2005 में किये गए दौरे के साथ यह प्रभाग सक्रिय रूप से जुड़ा रहा।

यह प्रभाग, भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक हितों के लिए रियायती शर्तों पर लाइन्स ऑफ क्रेडिट के उपयोग की नीति के अनुसरण में लगा रहा। अप्रैल - नवम्बर, 2005 की अवधि के दौरान 450 मिलियन अमरीकी डालर की एल ओ सी की राशि संवितरण हेतु अनुमोदित की गई। इस एल ओ सी से भारतीय कंपनियों को अफ्रीका, एशिया तथा लाटीन अमेरिका के कई देशों में सेवाओं तथा सामानों की आपूर्ति के लिए आदेश तथा प्रौजेक्ट के कांट्रैक्टस हासिल करने में मदद मिली है।

आई टी पी प्रभाग ने हैदराबाद में 1 और 2 दिसम्बर, 2005 को आयोजित प्रथम भारत- अफ्रीकी-एशियाई तथा जी सी सी फार्मा एवं स्वास्थ्य सम्मेलन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। यह सम्मेलन - भारत की फार्मास्यूटिकल, जैव-प्रौद्यागिकी, हर्बल एवं अन्य स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने तथा इन क्षेत्रों में स्थित देशों में प्रोद्योगिकी अन्तरण, उत्पादन इकाइयों और संयुक्त उपक्रमों को लगाने के लिए भारत को एक विश्वसनीय सहभागी के रूप में प्रदर्शित करने में सफल रहा।

जर्मनी के हनोवर में 24-28 अप्रैल, 2006 को आयोजित होने वाली हनोवर औद्योगिक मेले में भारत की भागीदारी से संबंधित तैयारी में आई टी पी प्रभाग सक्रिय रूप से लगा हुआ है। भारत इस प्रतिष्ठित आयोजन में एक सहभागी देश है। ■■

नीति नियोजन और अनुसंधान 13

नीतिगत नियोजन और अनुसंधान प्रभाग नीतिगत अनुसंधान और भारतीय विदेश नीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित विषय-वस्तुओं के विश्लेषण में विशेषज्ञता रखने वाली संस्थाओं: प्राबुद्ध व्यक्तियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्व के विशिष्ट क्षेत्रों पर अनुसंधान केन्द्रित करने वाले विश्वविद्यालयों के क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों और मंत्रालय की विदेश नीति के नियोजन, निर्माण और कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए बहुमूल्य जानकारी हासिल करने और आपसी संबंध बनाने एवं उन्हें सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ मंत्रालय की पारस्परिक चर्चा के लिए एक अंतरापृष्ठ के रूप में कार्य करता है।

प्रभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में अवस्थित शैक्षणिक संस्थाओं/प्रबुद्ध व्यक्तियों को सम्मेलन, सेमिनार आयोजित करने, अनुसंधान दस्तावेज तैयार करने, भारत के विदेश से संबंधों और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ट्रैक-II कार्यक्रमों के लिए विद्वान एवं सहायता का आदान प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान, प्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के प्रमुख मुद्दों पर 29 सेमिनारों एवं अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित किया। संस्थाओं/सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित सेमिनार/सम्मेलन/बैठक/अध्ययन परियोजनाओं, जिनका आंशिक वित्तपोषण, नीतिगत नियोजन और अनुसंधान प्रभाग द्वारा किया गया था, की सूची **परिशिष्ट-XII** में दी गई है।

नीतिगत नियोजन प्रभाग उन प्रमुख विकासों, जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध को बढ़ाता है, को उजागर करते हुए मंत्रिमंडल के लिए एक मासिक सार रिपोर्ट भी तैयार करता है। प्रभाग का अनुसंधान अनुभाग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को संकलित, संपादित एवं प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के आपसी संबंधों के सार-संग्रह के रूप में कार्य करती है। इस रिपोर्ट में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर सरकार के विचारों को दर्शाया जाता है।

अनुसंधान अनुभाग भारत की विदेशी सीमाओं के सभी पहलुओं की जांच और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले मानचित्र शीटों की संवीक्षा के संबंध में सर्वे ऑफ इण्डिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से भी परस्पर चर्चा करता है। विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित गलत मानचित्रों की संवीक्षा करना और उन्हें सही कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेवारी भी अनुसंधान अनुभाग की है। विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के जरिए संबंधित सरकारों या प्रकाशकों के साथ गलत चित्रण का मामला उठाया गया था ताकि उनका आवश्यक सुधारात्मक हल ढूंढा जा सके। यह प्रभाग देश में लाए गए विदेशी प्रकाशनों में भारत की विदेशी सीमाओं के चित्रण की संवीक्षा के लिए भी जिम्मेवार है और यह इस मामले से संबंधित मंत्रालयों को अपनी सलाह देता है। विभिन्न सरकारी और अर्द्ध-सरकारी एजेंसियों को उनके सरकारी कार्यों में इस्तेमाल के लिए मानचित्रों की आपूर्ति में सर्वे ऑफ इंडिया और रक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग करता है। अनुसंधान अनुभाग विद्वानों के मंत्रालय के रिकार्ड पाने के आवेदनों पर भी विचार करता है।

■■

14 प्रोतोकोल

बड़ी संख्या में बाहर के देशों से होने वाले और बाहर के देशों में होने वाले उच्च-स्तरीय दौरों, सम्मेलनों, प्रत्यायक समारोहों, सरकारी विचारणाओं और अन्य बहुआयामी कार्यों का संचालन प्रोतोकाल प्रभाग ने किया। विदेशी हस्तियों की बड़ी संख्या में दौरों को संचालित करने की प्रोतोकोल प्रभाग की क्षमता ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत के संवर्धित संबंध में योगदान किया है। प्रोतोकोल मानदण्डों और मानकों को निरन्तर सरल एवं कारगर बनाना मुख्य लक्ष्य रहा है। अधिकृत विदेशी दूतावासों, राजनयिकों एवं कौंसल अधिकारियों के लिए वैट वापसी तंत्र को कार्यान्वित किया गया था।

2005-06 हेतु यात्राएँ

राज्य/सरकार प्रमुख/उप राष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर के अधिकारियों द्वारा राजकीय दौरे

क्रम सं.	उच्चाधिकारी	तारीख
1.	माननीय डॉ. रिकार्डो लागोस, चिली के राष्ट्रपति	18-22 जनवरी
2.	महाराजा जिग्मे शिंगे वांगचुक, भूटान के राजा	24-29 जनवरी
3.	माननीय श्री कार्लो अजैगलियो सियाम्पी, इटली के राष्ट्रपति	12-16 फरवरी
4.	माननीय डॉ. हिन्ज फिशर, आस्ट्रिया के राष्ट्रपति	16-22 फरवरी
5.	माननीय श्री हुगो चावेज त्रियास, वेनेजुएला के राष्ट्रपति	4-7 मार्च
6.	माननीय श्री इस्लाम ए करीमोव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति	4-6 अप्रैल
7.	माननीय श्री वेन जियाबाओ, चीन के राज्य परिषद के प्रमुख	9-12 अप्रैल
8.	माननीय अमीर, कतर, शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी	13-15 अप्रैल
9.	माननीय श्री ली सीन लोंग, सिंगापुर के प्रधानमंत्री	28-30 जून
10.	माननीय श्री जेम्स एलिक्स माइकल, सेशल्स के राष्ट्रपति	31 जुलाई-2 अगस्त
11.	माननीय लीसेनिया करसे, फिजी द्वीप के प्रधानमंत्री	8-15 अक्तूबर
12.	माननीय डॉ. नवीनचन्द्र रामगुलाम, मॉरीशस के प्रधानमंत्री	23-30 अक्तूबर
13.	माननीय वक्लव क्लौस, चेक गणराज्य के राष्ट्रपति	6-12 नवम्बर
14.	माननीय श्री सुसीलो बमबंग युधोयोनो, ईण्डोनेशिया के राष्ट्रपति	21-24 नवम्बर
15.	माननीय श्री महिन्दा राजापाक्से, श्रीलंका	27-30 दिसम्बर के राष्ट्रपति
16.	माननीय अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बादशाह तथा दो पवित्र मस्जिदा के संरक्षक	24-27 जनवरी, 2006

राज्य/सरकार प्रमुख/उप राष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर के अधिकारियों द्वारा सरकारी/कर्मचारी दौरे

1.	माननीय श्री पॉल मार्टीन, कनाडा के प्रधानमंत्री	17-18 जनवरी
2.	माननीय श्री हामीद करजई, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति	23-25 फरवरी
3.	माननीया युवराज्ञी महा चक्री सिरिंधॉर्न, थाईलैण्ड	27 फरवरी-10 मार्च

4.	माननीय युवराज फिलिप, बेल्जियम	11-19 मार्च
5.	माननीय श्री मौमून अब्दुल गयूम, मालदीव के राष्ट्रपति	27 मार्च-1 अप्रैल
6.	माननीय जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति	16-18 अप्रैल
7.	माननीय श्री जुनिचिरो कोईजुमी, जापान के प्रधानमंत्री	28-30 अप्रैल
8.	माननीय श्री महमूद अब्बास, फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के राष्ट्रपति	19-20 मई
9.	माननीया श्रीमती चन्द्रिका भण्डारनायके कुमारतुंगा, श्री लंका के राष्ट्रपति	2-4 जून
10.	माननीय डॉ. थाक्सीन सिनवतरा, थाईलैण्ड के प्रधानमंत्री	3-4 जून
11.	माननीय जिग्मे सिंगे वांगचुक, भूटान के राजा	1-4 अगस्त
12.	अधिकारी माननीय री जोस मैनुअल बारोसो, यूरोपीय आयोग के राष्ट्रपति (छठे भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन के लिए)	6-8 सितम्बर
13.	अधिकारी माननीय टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री	6-8 सितम्बर
14.	माननीय श्री ली कुआन येव, सिंगापुर के मंत्री - परामर्शदाता का राजकीय दौरा	18-23 नवम्बर
15.	माननीय युवराज्ञी महाचक्री सिरंधॉर्न, थाईलैण्ड की युवराज्ञी का राजकीय दौरा	18-23 नवम्बर
16.	महाराजा कार्ल ज्र्ज्र्रु गुस्ताफ, स्वीडन का कार्यकारी दौरा	20-26 नवम्बर
17.	नार्वे के प्रधानमंत्री का कार्यकारी दौरा	7-8 दिसम्बर

विदेश मंत्री तथा समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा सरकारी दौरे

1.	माननीय श्री सिदी मोरो सन्नेह, गाम्बिया के विदेश मंत्री	11-13 जनवरी
2.	माननीय श्री लाउरी चन, सोलोमन द्वीप के विदेश मंत्री	17-18 जनवरी
3.	माननीय श्री शेख टिडियन गडियो, सेनेगल के विदेश मंत्री	21-24 जनवरी
4.	माननीय श्री फ्रेडरिक मिचेल, बहामास के विदेश मंत्री	26 जनवरी-1 फरवरी
5.	माननीय श्री रमजानी बाया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के विदेश मंत्री	1-4 फरवरी
6.	माननीय श्री जैक स्ट्राव, ब्रिटेन के विदेश मंत्री	16-18 फरवरी
7.	माननीय श्री कमल खराजी, इरान के विदेश मंत्री	20-22 फरवरी
8.	माननीय श्री लक्ष्मण कादिरगमर, श्रीलंका के विदेश मंत्री	24-26 फरवरी
9.	माननीय डॉ. एन हसन विरजुदा,ईण्डोनेशिया के विदेश मंत्री	28 फरवरी-2 मार्च
10.	माननीय श्री फिल गॉफ, न्यूजीलैण्ड के विदेश मंत्री	4-6 मार्च
11.	माननीय श्री रमेश नाथ पाण्डे, नेपाल के विदेश मंत्री	7-9 मार्च
12.	माननीय श्री माइकल फ्रेण्डो, माल्टा गणराज्य के विदेश मंत्री	7-12 मार्च
13.	माननीया सुश्री कोंडोलीजा राईस, अमरीका की विदेश मंत्री	15-16 मार्च
14.	माननीया सुश्री लीला रचीद, पारागुआ की विदेश मंत्री	17-23 मार्च
15.	माननीय राजदूत ओलु अडेनिजी, नाईजीरिया के विदेश मंत्री	21-23 मार्च
16.	माननीय जनरल मार्शल रन्जेवा, मेडागास्कर के विदेश मंत्री	21-25 मार्च
17.	माननीय श्री नुयेन डी नेन, वियतनाम के विदेश मंत्री	31 मार्च-4 अप्रैल
18.	माननीय श्री कोफी अन्नान, महासचिव, संयुक्त राष्ट्र	25-28 अप्रैल
19.	माननीय श्री जोर्ज ब्रिज अबुलरक, ग्वाटेमाला के विदेश मंत्री	1-7 मई

20.	माननीय श्री मुस्तफा उस्मान इस्माइल, सूडान के विदेश मंत्री	6-8 जून
21.	माननीय श्री अलेक्जेंडर डाउनर, आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री	6-9 जून
22.	माननीय श्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री	3-6 जुलाई
23.	माननीय श्री बान की - मून, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री	31 जुलाई-2 अगस्त
24.	माननीय डॉ. अहमद शहीद, मालदीव के विदेश मंत्री	11-14 अगस्त
25.	माननीय श्री डोनाल्ड सी मैकिनून, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल	23-25 अगस्त
26.	माननीय श्री अनुरा भण्डारनायक, श्रीलंका के विदेश मंत्री	25-26 अगस्त
27.	माननीय श्री मदन मुरलीधर डुल्लू, मॉरीशस गणराज्य के विदेश मंत्री	28 अगस्त-4 सितम्बर
28.	माननीय श्री सैमुअल लेविस नवारो, पनामा के प्रथम उप राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री	18-24 नवम्बर
29.	माननीय श्री मंगल समरवीरा, श्री लंका के विदेश मंत्री	30 नवम्बर-1 दिसम्बर

राज्य/सरकार प्रमुख/उपराष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर के अधिकारियों के निजी पारगमन दौरे

1.	माननीय श्री जुल्स रत्तनकुमार अजोधिया, सूरीनाम के उप राष्ट्रपति (प्रवासी भारत दिवस 2005 के मुख्य अतिथि)	4-12 जनवरी
2.	माननीय श्री अनिरूद्ध जगन्नाथ, मॉरीशस के राष्ट्रपति	10-22 जनवरी
3.	माननीय श्री ओलफर रगनर ग्रीमसन, आइसलैण्ड के राष्ट्रपति और श्रीमती डोरिट मुसैफ	3-9 फरवरी
4.	तुर्की के प्रधानमंत्री (दिल्ली)	6 फरवरी
5.	माननीय असी संगय चोदेन वांगचुक, भूटान की रानी	6-21 फरवरी
6.	माननीय श्री जीन पियरे बेम्बा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उप राष्ट्रपति	2-5 मार्च
7.	माननीय श्री जोसफ गबिला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति का पारगमन दौरा (मुम्बई)	13 मार्च
8.	माननीय श्री जोसफ कबिला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति का पारगमन दौरा (मुम्बई)	23 मार्च
9.	माननीय प्रमुख ओलीसीगन ओबसाँजो, नाइजीरिया के राष्ट्रपति का पारगमन दौरा (मुम्बई)	13-14 अप्रैल एवं 23-24 अप्रैल
10.	माननीय श्री रखमनोव, ताजिकिस्तान के राष्टपति का पारगमन दौरा (चैन्नै)	21 अप्रैल एवं 24 अप्रैल
11.	पेरू के राष्ट्रपति का पारगमन दौरा	1 जून (कोलकाता) 7 जून (मुम्बई)
12.	माननीय श्री फेस्टस गांटीबान्चे मोगे, बोत्सवाना गणराज्य के राष्ट्रपति का निजी दौरा	21-26 मई (दिल्ली एवं मुम्बई)
13.	श्रीमती मुसेवेनी, युगाण्डा की प्रथम महिला निजी दौरा	11-15 जून (पुणे एवं मुम्बई)
14.	माननीय श्री अंद्रानिक मरकेरियन, अर्मेनिया गणराज्य के प्रधानमंत्री का पारगमन दौरा	13 जून

15.	माननीया युवराज्ञी लल सलमा, मोरक्को की प्रथम महिला का निजी दौरा (मुम्बई)	28-30 जून
16.	माननीय अलहजी यहया ए जे जे जमीह, गाम्बिया के राष्ट्रपति का पारगमन दौरा (मुम्बई)	1 जुलाई
17.	माननीय श्री महिन्दा राजापाक्से, श्री लंका के प्रधानमुत्री का निजी दौरा (मुम्बई एवं इन्दौर)	12-15 जुलाई
18.	गाम्बिया के राष्ट्रपति का पारगमन दौरा	8 अक्तूबर (कोलकाता) 12 अक्तूबर(चेन्नै)
19.	श्रीमती मौरिन के मनवासा, जाम्बिया की प्रथम महिला	8-15 अक्तूबर
20.	मोरक्को के महाराजा (मुम्बई)	2-6 दिसम्बर
21.	ईण्डोनेशिया के उप-राष्ट्रपति का पारगमन दौरा	17-22 जनवरी, 2006
22.	माननीय शेख मोजाह बिन नसीर अल मिसनेद, कतर की प्रथम महिला	6-13 फरवरी, 2006
23.	भूटान की सबसे बड़ी रानी	5-15 फरवरी, 2006

विदेश मंत्री तथा समकक्ष स्तर के अधिकारियों का निजी/पारगमन दौरा

1.	माननीय श्री जेन पिटरसन, नार्वे के विदेश मंत्री	जनवरी
2.	माननीय श्री लौरी चेन, सोलोमन द्वीप के विदेश मंत्री	17-20 जनवरी
3.	माननीय री सादिक एस सोफेव, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री	7-8 फरवरी
4.	माननीय श्री सिदी मोरो सन्नेह, गाम्बिया के विदेश मंत्री	4-10 मार्च
5.	माननीय श्री बिल क्लिंटन, सुनामी राहत कार्य हेतु यू एन एस जी के विशेष दूत	25-27 मई

भारत के राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के विदेश दौरे

1.	प्रधानमंत्री का मॉरीशस दौरा	30 मार्च-2 अप्रैल
2.	प्रधानमंत्री का बांडुंग/जकार्त्ता दौरा (अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन हेतु)	22-25 अप्रैल
3.	प्रधानमंत्री का रूसी परिसंघ का दौरा	8-10 मई
4.	राष्ट्रपति का रूसी परिसंघ, स्वीट्जरलैण्ड, आइलैण्ड और उक्रैन का दौरा	22 मई-4 जून
5.	प्रधानमंत्री का ब्रिटेन दौरा	6-9 जुलाई
6.	प्रधानमंत्री का अमरीकी दौरा	16-22 जुलाई
7.	प्रधानमंत्री का अफगानिस्तान दौरा	28-29 अगस्त
8.	प्रधानमंत्री का पेरिस एवं न्यूयार्क दौरा (यू एन जी ए हेतु)	11-17 सितम्बर
9.	उप राष्ट्रपति का रोमानिया, बेलारूस एवं अर्मेनिया दौरा	1-8 अक्टूबर
10.	प्रधानमंत्री का ढ़ाका दौरा (सार्क सम्मेलन हेतु)	11-13 नवम्बर
11.	प्रधानमंत्री का मास्को दौरा	4-7 दिसम्बर
12.	प्रधान मंत्री का मलेशिया दौरा 13 वें आसियान सम्मेलन में	12-13 दिसम्बर
13.	उप राष्ट्रपति का दुबई दौरा यू ए इ के प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि में	5-6 जनवरी, 2006
14.	भारत के राष्ट्रपति कासिंगापुर, फिलिपीन्स, दक्षिण कोरिया	31 जनवरी - 9 फरवरी, 2006

1-3-2005 से 19-1-2006 की अवधि के दौरान अपने प्रत्यय-पत्रों को प्रस्तुत करने वाले विदेशी राजदूतों / उच्चायुक्तों की सूची

नाम	प्रत्यय-पत्रों का प्रस्तुतीकरण
माननीय श्री अलबर्टो जे. पिंजन एम, पनामा के राजदूत	26-4-05
माननीय री ओलेग लेपतेंको, बेलारूस गणराज्य के राजदूत	26-4-05
माननीय डॉ असोत काचारियन, गर्मेनिया गणराज्य के राजदूत	26-4-05
माननीय ले. जन. कयुम्बा न्यामवासा, रूआण्डा गणराज्य के राजदूत	26-4-05
माननीय श्री एफीम चिलारी, मोलदोवा गणराजय के राजदूत	26-4-05
माननीय श्री अरतुरो दुआर्त ओर्तिज, ग्वाटेमाला के राजदूत	26-4-05
माननीय श्री चांग बंथेंग, कम्बोडिया शाही दूतावास के राजदूत	8-8-05
माननीय श्री लियाकत अली चौधरी, बांगलादेश जनवारी गणराज्य के उच्चायुक्त	8-8-05
माननीय डा. शब्बीर हुसैन परिभाई, लिसोथो राज्य के उच्चायुक्त	8-8-05
माननीय श्री युसूफ उमर दौले, जिबूती गणराज्य के राज्दूत	8-8-05
माननीय श्री लर्बी मुकारिक, मोरक्को राज्य के राजदूत	8-8-05
माननीय श्री शिलोहो फ्रांसीस मोलोई, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के उच्चायुक्त	8-8-05
माननीय श्री विलियम इहलर्स, उरूग्वे के राजदूत	8-8-05
माननीय श्री क्रियान्था रोमेश जयसिंघे, श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के उच्चायुक्त	8-12-05
माननीय श्री जॉन इकॉनामिड्स, ग्रीक, हेलेनिक गणराज्य के राजदूत	8-12-05
माननीय श्री एन्ड्रिस जेनोनोस, साईप्रस गणराज्य के उच्चायुक्त	8-12-05
माननीय श्री मोहम्मद अली दाहर - सूर, जॉर्डन के हेसेमाईट किंग के राजदूत	8-12-05
माननीय श्री असको नुमिनेन, फिनलैण्ड गणराज्य के राजदूत	8-12-05

माननीय श्री जयराम रोनाल्ड गजराज, गुयाना सहकारी गणराज्य के उच्चायुक्त	8-12-05
माननीय श्री मोहम्मद बिन युसुफ सलवानी, ओमान सल्तनत के राजदूत	8-12-05
माननीय श्री मार्टिन एन. कपिवाशा, नामिबिया गणराज्य के उच्चायुक्त	8-12-05
अब्दुलरहमान अल-इमादी, कतर देश के राजदूत	8-12-05
माननीय श्री फ्रांसिस एस. के. बयाह, केन्या गणराज्य के उच्चायुक्त	8-12-05
माननीय श्री ली बोनखम, लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के राजदूत	8-12-05

सौंपे गए कार्य को पूरा करने पर 1.3.2005 से 20.1.2006 की अवधि के दौरान भारत से जाने वाले विदेशी राजदूतों/उच्चायुक्तों की सूची

नाम	जाने की तारीख
माननीय श्री हेमायेतुद्दीन बांगलादेश जनवादी गणराज्य के उच्चायुक्त	14.3.2005
माननीय श्री चेयांग येंग नुयान कम्बोडिया के राजदूत	22.3.2005
माननीय श्री नबील टी. तलहौनी जॉर्डन के हेशेमाईट किंग्डम के राजदूत	30.4.2005
माननीय मेजर जनरल चार्ल्स डी एन पी नमोलोह नामिबिया गणराज्य के राजदूत	20.5.2005
माननीय श्री एच. मुतुमा कथुरिमा केन्यागणराज्य के उच्चायुक्त	11.6.2005
माननीय श्री एन्ड्रेस जी. स्कार्पेरिस साईप्रस से उच्चायुक्त	14.8.2005
माननीय श्री युसफ हसन अल-साई करत प्रदेश के राजदूत	16.8.2005
माननीय श्री मंगला मूनसिंघे श्रीलंका लोकतांत्रिक गणराज्य के उच्चायुक्त	25.8.2005
माननीय श्री इफ्ताथियोस लोजास यूनान के राजदूत	3.9.2005
माननीय श्री चार्ल्स एम. पी. वलिम्बवा युगाण्डा गणराज्य के उच्चायुक्त	4.9.2005
माननीय डॉ.मोहम्मद साद अली यमन गणराज्य के रादूत	13.9.2005
माननीय श्री ग्लेन लिंदोहम फिनलैण्ड के राजदूत	28.9.2005

माननीय श्री खलीफा बिन अली हर्थी ओमान सल्तनत के राजदूत	28.9.2005
माननीय प्रोफेसर माइक ओकुयी धाना गणराज्य के उच्चायुक्त	22.10.2005
माननीय श्री खम्पसोंग डौंगिथी लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के राजदूत	28.10.2005
माननीया श्रीमती अना मारिया करेइरा अंगोला गणराज्य	9.11.2005
माननीय श्रा जेलिको जंजेतोविद बोस्निया एवं हर्जेगोविना के राजदूत	12.11.2005
माननीय मसूद खलीली अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के राजदूत	27.11.2005
माननीय हीमो रिच्टर जर्मनी संघीय गणराज्य के राजदूत	2.12.2005
माननीय श्री हसन गौस तुर्की गणराज्य के राजदूत	20.01.2006

1 मार्च, 2005 के बाद स्थापित किए गए दूतावास

1. जिबूती गणराज्य का दूतावास-	23-6-2005
2. पारागुआ का दूतावास-	अक्तूबर, 2005
3. आईलैण्ड गणराज्य का दूतावास-	22-1-06

■■

पासपोर्ट, वीजा और कोंसली सेवा 15

केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के माध्यम से और विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों के पासपोर्ट, वीजा और कोंसल विंग के माध्यम से विदेश मंत्रालय का सी पी वी प्रभाग भारतीय नागरिकों तथा अप्रवासी भारतीयों को पासपोर्ट तथा कोंसली सेवा और विदेशी नागरिको को कोंसली तथा वीजा सेवा प्रदान करता है।

इस समय भारत में 30 पासपोर्ट कार्यालय हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हैं और मशीनों से मुद्रित तथा मशीन - रीडेबल पासपोर्ट जारी करते हैं। पासपोर्ट जारी करने के लिए अनुमति आदेश इलेक्ट्रानिक पद्धति से दिया जाता है। पासपोर्ट से संबंधित समस्त नैमित्तिक कार्य कम्प्यूटरीकृत है जैसे कि नकदी सृजन, सूचकांक की जांच, पासपोर्ट, पते अंकित करना एवं प्रेषण करना तथा रिकार्ड इलेक्ट्रानिक पद्धति से रखा जाता है। पासपोर्ट आवेदन-पत्रों को भी स्कैन किया जा रहा है और इनको संचित इलैक्ट्रानिक पद्धति से किया जाता है।

जन शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली को सुदृढ़ करने के एक भाग के रूप में आवेदकों की सहायता करने तथा साथ ही शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए सभी पासपोर्ट कार्यालयों को सुविधा काउण्टर तथा सहायता डेस्क स्थापित करने के निदेश दिये गए हैं। संयुक्त सचिव (सी पी वी) के गहन पर्यवेक्षण में कोंसल, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग में भी एक जन शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली कार्यरत है। सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोगो को सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी तथा सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

पासपोर्ट सेवाएं

डाक घरों और जिला कार्यालयों के जरिए विकेन्द्रीकरण

विकेन्द्रीकरण योजना के एक भाग के रूप में जिला स्तरों पर जिला पासपोर्ट कक्ष खोले गए हैं जहां जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पासपोर्ट के आवेदन-पत्र प्राप्त करते हैं और जांच करने के एवं पुलिस से सत्यापन कराने के बाद पासपोर्ट जारी करने के लिए इन्हें संबंधित पासपोर्ट कार्यालय को भेजते हैं। इस समय भारत के 28 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में लगभग 462 जिला पासपोर्ट कक्ष हैं। जिला पासपोर्ट कक्षों के खुल जाने के फलस्वरूप पासपोर्ट कार्यालयों में भीड़ - भाड़ काफी हद तक कम हो गई है। पुलिस से सत्यापन कराने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के अलावा जिला पासपोर्ट कक्ष आवेदकों को राहत भी प्रदान करते हैं, जिन्हें पासपोर्ट कार्यालयों तक पहुंचने के लिए लम्बी यात्रा नहीं करनी पड़ती हैं। पासपोर्ट के आवेदन-पत्र स्पीड पोस्ट केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए भी प्राप्त किए जाते हैं। इस समय लगभग 218 ऐसे स्पीड पोस्ट केन्द्र हैं जो पासपोर्ट के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार करते हैं। अतिरिक्त स्पीड-पोस्ट केन्द्रों को भविष्य में खोलने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

क्रियान्वयनाधीन परिवर्तन

बिना बारी के पासपोर्ट जारी करने की 'तत्काल' योजना के फलस्वरूप, प्रणाली तात्कालिक आधार पर पासपोर्ट जारी करने की मांग के संबंध में त्वरित प्रतिक्रिया करने में सफल हुई है। वर्ष 2005 के दौरान 'तत्काल' योजना के तहत कुल 244516 पासपोर्ट जारी किए गए जिसके परिणामस्वरूप 39.85 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। 22 पासपोर्ट कार्यालयों में दूरभाष-पूछताछ प्रणाली उपलब्ध है तथा पासपोर्ट कार्यालय बंगलौर में टच स्क्रीन पूछताछ किऑस्क प्रायोगिक आधार पर आरम्भ किया गया।

पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली की समीक्षा

पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली की समीक्षा संबंधी अन्तर्मंत्रालय समिति ने, जिसकी स्थापना मंत्रिमण्डल सचिवालय में की गई थी, पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को सरल बनाने के लिए कई सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को काफी संख्या में क्रियान्वित किया जा चुका है तथा संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके शेष सिफारिशों पर कार्यान्वयन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट अब शीघ्रतापूर्वक जारी किये जा रहे हैं। तत्काल के लिए नए आवेदकों को पहले लगने वाले 35 दिनों की समयावधि को कम कर अब 20 दिन कर दिया गया है। पासपोर्ट पुनः जारी किये जाने के मामलों में अवधि को 1-10 दिनों से घटा कर 1-5 दिन कर दिया गया है। अतिरिक्त पुस्तिका, गुम पासपोर्ट, क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के सभी मामलों और स्वरूप, नाम, जन्मतिथि, जन्म-स्थान और हस्ताक्षरों में परिवर्तन होने के मामले में पूर्ण

10 वर्षों की वैधता वाला पासपोर्ट अब जारी किया जा रहा है।

आधारभूत संरचना

सरकार ने बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर और भुवनेश्वर में पासपोर्ट कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया है। इस समय आठ स्थानों पर अर्थात, मुम्बई, चण्डीगढ़ कोचीन, कोझीकोड, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटना और पणजी में पासपोर्ट कार्यालयों के भवन विदेश मंत्रालय के स्वामित्व में हैं। छह पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यालय परिसर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं तथा 16 पासपोर्ट कार्यालय किराए के भवनों में हैं। चार पासपोर्ट कार्यालयों अर्थात तिरूचिरापल्ली, गुवाहाटी, जालंधर और मुम्बई के लिए भूमि खरीदने की कार्रवाई भी चल रही है। जनवरी, 2005 में उग्रवादियों द्वारा आग लगाए जाने की घटना के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, श्रीनगर पूर्णतः जल कर राख हो गया। इसने मई 2005 में एक किराए के भवन में पुनः कार्य करना शुरू कर दिया है।

कम्प्यूटीकरण

इस समय सभी 30 पासपोर्ट कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालयों में ई - मेल की सुविधा उपलब्ध है। सभी पासपोर्ट कार्यालयों के लिए वेब पृष्ठ भी सृजित किए गए हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालयों को परस्पर जोड़कर एक व्यापक कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क और संयोजकता की परिकल्पना की गई है।

कार्यभार

जनवरी से दिसम्बर, 2005 तक की अवधि के दौरान कुल 3570730 पासपोर्ट जारी किए गए तथा 464122 विविध सेवाएं प्रदान की गई। प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदन-पत्रों / जारी किए गए पासपोर्टों/प्रदान की गई विविध सेवाओं की संख्या और राजस्व एवं व्यय संबंधी आंकड़ों का पासपोर्ट कार्यालयवार ब्यौरा **परिशिष्ट-IV** में दिया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में फरवरी और मार्च, 2005 के दौरान लंबित पड़े कार्यों को समाप्त करने का अभियान शुरू किया गया ताकि लंबित पड़ी लगभग 43000 फाइलों को समाप्त किया जा सके। इसी प्रकार का एक अभियान इस वर्ष जयपुर और गाजियाबाद में भी शुरू किया गया। वित्त मंत्रालय की कर्मचारी अध्ययन इकाई (एस आई यू) ने पासपोर्ट कार्यालयों का मानक अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2005 के पहले सप्ताह में दे दी। पासपोर्ट कार्यालयों में विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। इससे पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था में बढ़ते कार्यभार को समंजित करने में मदद मिलेगी।

पासपोर्ट फाइलों की स्कैनिंग

पुराने आवेदन-पत्रों को संचित करने के लिए स्थान की कमी और संदर्भ के लिए अथवा न्यायालय संबंधी मामलों के लिए उन्हें शीघ्र पुनः निकालने की कठिनाइयां काफी लम्बे समय से चली आ रही समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए पुराने आवेदन-पत्रों को स्कैन करने और सूचना को सी डी में संचित करने का निर्णय लिया गया। गैर-योजना व्यय से सम्बद्ध समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया। पुराने पासपोर्ट आवेदन पत्रों को स्कैन करने का काम सभी पासपोर्ट कार्यालयों में पूरा हो गया है।

पासपोर्ट अधिकारियों का सम्मेलन

1 सितंबर, 2005 को कोलकाता में पासपोर्ट अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए 15-30 सितम्बर, 2005 के दौरान सभी पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित कार्यो को समाप्त करने का निदेश दिया। तदनुसार लंबित पड़े कार्यों को समाप्त करने के प्रयास किये गये। विदेश राज्य मंत्री ने सी पी वी प्रभाग में आन्तरिक निगरानी को सुदृढ़ बनाए जाने की भी इच्छा व्यक्त की। केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में निगरानी प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए आवश्यक उपाय किये गए हैं।

कोंसली सेवाएं

विदेश स्थित सभी मिशन/केन्द्र विदेशों में भारतीय नागरिकों तथा अप्रवासी भारतीयों को कोंसली सेवाएं प्रदान करते हैं। विदेशों में भारतीयों की मृत्यु के मामलों में शवों/अस्थियों को शीघ्र प्रेषित करने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने, स्थानीय एवं भारतीय प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क करने और मृतक के संबंधियों को स्थिति से अवगत कराए रखने में हमारे मिशनों और केन्द्रों द्वारा तत्परतापूर्वक सहायता प्रदान की गई। वित्त मंत्रालय की कर्मचारी अध्ययन इकाई (एस आई यू) ने 27 वर्ष पुराने कोंसुली कार्यों के लिए मानकों की दुबई, ढाका, लंदन, क्वालालमपुर और कुवैत में समीक्षा की और अक्तूबर, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस प्रकार तैयार किये गए संशोधित मानकों के आधार पर सभी मिशनों और केन्द्रों से उनकी स्टाफ संबंधी आवश्यकताओं को भेजने का अनुरोध किया गया है। भारत और स्थानीय केन्द्रों दोनों में स्टाफ की संख्या में वृद्धि करने के लिए एक समेकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को दिसंबर, 2005 में भेजा गया है।

विदेशों में गिरफ्तार भारतीयों की संख्या तथा विदेशों में भारतीय मृतकों की संख्या के मामले में आकड़ें अपूर्ण और प्रतीक्षित हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान भारतीय मिशनों के माध्यम से मृतक के आश्रितों को नगद भुगतान करने के लिए

निम्नलिखित देशों को दी गई मुआवजे की राशि निम्नानुसार हैं:

कुवैत	4,62,72,046 रूपये
लेबनान	12,500 अमरीकी डालर
मलेशिया	20,495.54 अमरीकी डालर
ओमान	4,42,93,995 रूपये
सऊदी अरब	1,85,63,287 रूपये
संयुक्त अरब अमीरात	1,47,65,504 रूपये

वीजा सेवाएं

विगत वर्षों में भारतीय मिशनों और केन्द्रों द्वारा वीजा प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अधिकांश मिशन और केन्द्र या तो उसी दिन काउण्टर पर अथवा अधिक से अधिक 48 घंटे के अन्दर वीजा प्रदान कर देते है।

खाड़ी, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमरीका में मिशनों और केन्द्रों की वीजा एवं पासपोर्ट शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण की एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रथम चरण में, उन मिशनों और केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा जिनमें प्रदान की गई सेवाओं की मात्रा अधिक है। वर्ष के दौरान दुबई, इस्लामाबाद तथा न्यूयार्क में कांसुली कार्यों का कम्प्यूटीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। कई अन्य मिशनों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

सी पी वी प्रभाग के मुख्यालय स्थित कार्यालय में वर्ष 2005 के लिए निम्नलिखित सरकारी तथा राजनयिक पासपोर्ट जारी किये गए:

1. जारी किए गए राजनयिक पासपोर्ट की संख्या 1552
2. जारी किए गए सरकारी पासपोर्ट की संख्या 17,000
3. नवीकरण किये गए राजनयिक पासपोर्ट की संख्या 2455
4. नवीकरण किये गए सरकारी पासपोर्ट की संख्या 4586

प्रदत्त अन्य विविध सेवाओं के अलावा, वर्ष के दौरान वेनेजुएला तथा कोरिया (दक्षिण कोरिया) गणराज्य के साथ अल्पकालिक राजनयिक तथा सरकारी पासपोर्टों को वीजा की आवश्यकता से मुक्त करने के लिए दो करारों पर हस्ताक्षर किये गए।

कोंसली सत्यापन

वर्ष 2005 के दौरान कोंसल,पासपोर्ट और वीजा प्रभाग में 531944 दस्तावेजों को कोंसली सत्यापन प्रदान किया गया जिसमें से 195255 वाणिज्यिक दस्तावेज थें। यह सेवा बिना कोई प्रभार लिए उसी दिन प्रदान की जाती है तथा यह सेवा अविलम्ब एवं कुशलतापूर्वक प्रदान की जाती है।

कोंसली करार - प्रत्यर्पण और पारस्परिक विधिक सहायता कार्यक्रम

संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिए एक विधिक एवं सांस्थानिक ढांचा प्रदान करने के लिए तथा वित्तीय एवं अन्य अपरोधों के बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विस्तारों के प्रति कार्रवाई करने के लिए अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय करारों के संबंध में वार्ताएं की जा रही हैं ताकि इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास को वैधानिक आधार प्रदान किया जा सके। इन कोंसली करारों में ये शामिल हैं प्रत्यर्पण संधियां, आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता तथा सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता।

उपराष्ट्रपति द्वारा अक्तूबर, 2005 में बेलारूस की यात्रा के दौरान आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता के करार पर हस्ताक्षर किये गए तथा अक्तूबर, 2005 में मारीशस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दो करार - आपराधिक मामलों में प्रत्यर्पण संधि और पारस्परिक विधिक सहायता - पर हस्ताक्षर किये गए। बहरीन, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधियां प्रवृत्त हुई हैं।

वर्ष के दौरान भारतीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता तथा प्रत्यपर्ण संधियों पर बातचीत करने के लिए ईरान का दौरा किया। प्रत्यर्पण संधि पर बातचीत करने के लिए बेलारूस के एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की।

प्रत्यर्पण मामले और विधिक सहायता

यह मंत्रालय आपराधिक एवं सिविल/वाणिज्यिक अपराधों दोनों के लिए विदेशी सरकारों के साथ प्रत्यर्पण और विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए सक्रियतापूर्वक प्रयासरत रहा। प्रत्यर्पण के ये अनुरोध विभिन्न देशों के साथ हुई प्रत्यर्पण संधियों/प्रत्यर्पण व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत के दायित्वों के आधार पर किए जाते हैं। वर्ष 2005 के दौरान, विभिन्न जांच एजेंसियों से प्राप्त प्रत्यर्पण के 9 अनुरोध बाहरी देशों को भेजे गए हैं। इसी अवधि के दौरान, बाहरी देशों से भारत ने प्रत्यर्पण के 10 अनुरोधों को प्राप्त किया। वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा 3 व्यक्तियों का प्रत्यर्पण किया गया और बाहरी देशों से भारत में 7 व्यक्ति प्रत्यर्पित किये गए। वर्ष 2005 में, भारत ने विदेशों के सरकारों से विधिक सहायता हेतु 78 अनुरोध प्राप्त किये और आपराधिक मामलों में विधिक सहायता के 27 भारतीय अनुरोध विदेशों के सरकारों को भेजा। मंत्रालय ने 1500 गिरफ्तारी वारंट/सम्मन/नोटिस एवं अन्य न्यायिक प्रक्रियाएं विदेशों में रह रहे व्यक्तियों को तामील/निष्पादित करने के लिए न्यायिक प्राधिकारियों/राज्य सरकारों से प्राप्त की।

■■

16 प्रशासन और स्थापना

श्री के. नटवर सिंह द्वारा अपने पदत्याग के बाद प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 21 नवंबर, 2005 को विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अपने हाथों में ले लिया। विदश मंत्रालय में प्रधानमंत्री के कार्य में दो राज्य मंत्रियों, श्री ई. अहमद और श्री आनन्द शमा द्वारा सहायता की जाती है श्री आनंद शर्मा ने 30 जनवरी, 2006 को विदेश राज्यमंत्री का पदभार संभाला। राव इंदरजीत सिंह जिन्होंने 30 जनवरी, 2006 तक राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया,ने गृह राज्य मंत्री बन जाने के बाद अपना पदभार त्याग दिया था।

भारत की विदेश नीतिपरक उद्देश्यों का प्रभावी अनुसरण विदेश में भारत की राजनयिक उपस्थिति की वृद्धि को अनिवार्य बनाता है। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि मंत्रालय के मुख्यालयों में सभी स्तरों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती हो। प्रशासनिक विभाग की मुख्य चुनौती उपलब्ध संसाधनों को अनुकूलतम बनाने की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहां सहायता स्टाफों की संख्या कम थी वहां अपेक्षित संख्या में नियुक्ति कर दी गई है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, विस्तृत अध्ययन के बाद, परस्परव्यापी कार्यों और कुल उपलब्ध संसाधनों में संभावित सहक्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए कार्मिकों की नियुक्ति के कार्य को युक्तिसंगत पूरा किया गया था। विशेष पहल के रूप में, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से, रिक्त पदों की जगह नियमित स्टाफ की लंबित भर्ती के लिए कुछ साचिविक सहायता कार्य की आउटसोर्सिंग की गई थी।

योग्य कर्मियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए और कर्मियों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के लिए , सभी प्रोन्नति पैनल समय पर प्रदर्शित किए गए थे। मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए सरकार के विशेष भर्ती अभियान को जोरदार ढंग से निष्पादित किया। यद्यपि ऐसे रिक्त पदों की संख्या काफी कम थी, फिर भी मंत्रालय ने उन्हें भरने का प्रयत्न किया। मंत्रालय में विक्लांग व्यक्तियों के पदों के आरक्षण संबंधी संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया।

नियमित पारस्परिक चर्चा के साथ स्टाफ पक्ष वाले संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र को और अधिक सक्रिय बनाया गया। समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक स्टाफ शिकायत अधिकारी को विशेष रूप से पदनामित किया गया।

इसके अधिदेश के अनुसार, वाशिंगटन, ब्राजीलिया, साओ पोलो, काइरो, इस्तामबुल, वेलिंगटन, बीजिंग, शंघाई, सिओस, कैनवेरा और सिडनी में मिशनों/पदों की जांच निरीक्षण महा निदेशालय द्वारा की गई थी।

परिशिष्ट-I की सारणी में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, मंत्रालय में स्टाफ की संख्या, समूह 'डी' को छोड़कर 3549 है जो कि भारत में नियुक्त है और 164 स्टाफ विदेशों के मिशनों/पदों पर हैं। इसमें भारतीय विदेश सेवा (आई एफ एस), भारतीय विदेश सेवा बी (आइ एफ एस बी), दुभाषिए और विधिक एवं संधि (एल एंड टी) संवर्ग शामिल हैं। करांची में भारत का प्रधान कोंसलावास फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

सीधीभर्ती (डी आर), विभागीय प्रोन्नति (डीपी) और आरक्षित पदों के लिए परीक्षा सहित सीमित विभागीय परीक्षाओं (एल डी ई) के माध्यम से 1 अप्रैल से 30 नवंबर, 2005 तक मंत्रालय में विभिन्न समूहों में की गई भर्ती परिशिष्ट - ख्ख् की सारणी में दी गई है।

परिशिष्ट-III की सारणी मंत्रालय के अधिकारियों की भाषा में प्रवीणता के ब्यौरे को दर्शाती है।

मंत्रालय ने अपने प्रयास जारी रखे थे जिनका उद्देश्य नियमों एवं विनियमों के सरलीकरण के जरिए एवं नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर कार्यक्षमता को अधिक से अधिक करना था। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मैकेनिज्म के प्रयोग से अधिकारियों को वेतन के वितरण की प्रक्रिया को स्वचालित किया गया था। वैयक्तिक सूचना प्रणाली और नाम आधारित/पदनाम आधारित ई-मेल आई डी- का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया गया था।

लैंगिक मुद्दा

मंत्रालय अपने कर्मियों के बीच बेहतर लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है। चुनौतिपूर्ण पदों और कार्यों को अपने हाथों में लेने के लिए महिला अधिकारियों को भी समाय अवसर प्रदान किए जाते हैं और वर्तमान में 22 महिला अधिकारी राजदूतों/उच्चायुक्तों/थायी प्रतिनिधियों/प्रधान कौंसलों के रूप में विदेशों में नियुक्त हैं। इस समय 7 अपर सचिव स्तर, 29 संयुक्त सचिव स्तर और 11 निदेशक स्वर के पद के अलावा 6 सचिव स्तर के पद पर महिला अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र और इससे संबंधित संगठनों अर्थात यूनेस्को जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख पदों पर भी महिला अधिकारी नियुक्त हैं।

विदेश मंत्रालय में विभिन्न संवर्गों में महिला अधिकारियों के वर्तमान पद **परिशिष्ट-XVIII** में दर्शाए गए हैं।

कार्यस्थल पर महिला अधिकारियों की प्रताड़ना की शिकायतों का निवारण करने और राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं/निकायों के साथ सहयोग और संपर्क करने के लिए मंत्रालय में महिलाओं का एक प्रकोष्ठ है। संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी इसका प्रमुख है।

कल्याण

कल्याण प्रभाग विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के आम कल्याण की और मंत्रालय में कैंटीन सेवाओं के प्रबंधन की देखरेख करता है। वर्ष 2005-06 के दौरान, मंत्रालय के सात कर्मचारियों की सक्रिय सेवा के दौरान ही मृत्यु हो गई है। कल्याण विभाग ने सर्मचारी लाभ कोष से पात्र आश्रितों को इलाज, अंत्येष्टि और अनुग्रह भुगतान के लिए आवश्यक सहायता दी। इस विभाग की सिफारिश पर, विदेशी मामले दंपती संघ (ई ए एस ए) ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों में से प्रत्येक को 20,000 रू.का चेक भेंट किया।

मंत्रालय के विदेशों में कार्यरत अधिकारियों के बच्चों के लिए भारत में विश्वविद्यालय की शिक्षा को आसान बनाने की योजना के अंतर्गत कल्याण विभाग ने एम बी बी एस के लिए 5 छात्रों, इंजिनियरिंग के लिए 17 छात्रों और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 3 छात्रों की भर्ती की औपचारिकताएं पूरी की थीं। केंद्रीय विद्यालयों की 60 सीटें विदेश मंत्रालय के अधिकारियों/स्टाफ के बच्चों के लिए थीं। वर्ष के दौरान, इस विभाग द्वारा किए गए अन्य कल्याण कार्य थे - सांप्रदायिक सद्भावना, रेड क्रॉस, सशस्त्र बल और विदेश मंत्रालय की स्टाफ लाभ कोष के लिए झंडा दिवसों के लिए निधियों के एकत्रीकरण की व्यवस्था करना। विदेश मंत्रालय में दो आश्रितों को अनुकंपा आधार पर एल डी सी के नियमित पदों पर और एक आश्रित को दैनिक मजदूरी आधार पर नियुक्त किया गया था। विदेश मंत्रालय के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को तरजीह देने की नीतिगत हल शुरू की गई है। विदेश से लौटने वाले परिवारों के लिए एक सुरक्षित परिवहन सेवा शुरू की गई है। तनाव - नियंत्रण के क्षेत्र में मुख्यालयों में आर्ट ऑफ लिविंग का पाठ्यक्रम करवाया गया था और विदेशों में काम करने वाले विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए मिशनों में तनाव नियंत्रण पर प्रश्नोत्तर किए गए हैं। यह विभाग मंत्रालय के कर्मचारियों में टीम-भावना को बढ़ाने में सक्रिय रहा है।

स्थापना

स्थापना प्रभाग के कार्यों में विदेश में भत्तों का निर्धारण, फर्नीचर और उपस्करों की खरीद एवं रखरखाव; भारत और विदेश दोनों जगह संपत्ति को पट्टे पर देना और उसका रखरखाव; विदेशों में सरकारी कारों की खरीद एवं रखरखाव; ऑवजेक्ट डी आर्ट सामग्रियों की आपूर्ति आदि शामिल हैं।

विदेशों में भत्ते के निर्धारण के संबंध में, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के संयुक्त दल द्वारा 16-25 अक्तूबर, 2005 को सूचकांक आधारित योजना की 8वीं वार्षिक समीक्षा की गई थी। दल ने न्यूयॉर्क, टोरंटो और ब्रूसेल्स का दौरा किया, जहां बाजार सर्वेक्षण कराने के साथ - साथ न्यूयार्क में अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा आयोग (आई सी एस सी) और ब्रूसेल्स में यूरोपियन आयोग (ई सी) में भत्तों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन चर्चा भी हुई थी। दल ने इंडेक्सेशन व्यवस्था और आई सी एस सी और ई सी द्वारा इंडेक्सेशन व्यवस्था को और प्रभावी तथा बदलते हुए वैश्विक माहौल के अनुरूप बनाने के लिए की गई व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जांच की। महत्वपूर्ण सुझावों में से एक सुझाव वर्तमान दैनिक उपभोग प्रतिमान के अनुरूप इसे अपनाने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की समीक्षा करने की जांच करना था। इस प्रयोजनार्थ अपर सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता वाली एक विशेष समिति पहले ही गठित कर ली गई है। भारत के बढ़ते हुए वैश्विक प्रोफाईल और बदलते हुए जीवन को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने सादृश्यमूलक अनुदान की व्यवस्था को यौक्तिक बनाने का एक व्यापक प्रस्ताव भी तैयार किया है। इसके अनुमोदित हो जाने के बाद, नई व्यवस्था में योजना की आंशिक इंडेक्सेशन पर आधरित स्व-सुधार की आंतरिक व्यवस्था होने के अलावा, यह और अधिक युक्तिमूलक और न्यायसंगत

हो जाएगी। वी आई पी और वी वी आई पी के दौरों सहित, विशेष समारोहों की देख - रेख करने वाले मिशनों/पोस्टों के हमारे प्रमुखों के लिए विशेष अनुदानों की व्यवस्था को और भी सरल बनाया गया है दूसरी महत्वपूर्ण पहल अफगानिस्तान और इराक में हमारे मिशनों/पदों में कार्य कर रहे भारत के अधिकारियों को कष्ट भत्ता देने का सरकार का निर्णय है ताकि अत्यंत कष्ट के प्रभाव को कम किया जा सके।

साऊथ ब्लॉक और अकबर भवन में एम इ ए भवनों के बेहतर रखरखाव के विशेष प्रयास किए गए थे। आम सुविधाओं को बेहतर बनाने के अलावा,मंत्रालय विभिन्न प्रभागों/अनुभागों में मॉड्यूलर सिटिंग व्यवस्था लागू करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह का उपयोग किया जा सके। साऊथ ब्लॉक और अकबर भवन में मौजूदा अग्निशमन ढांचे को बेहतर बनाने एवं उन्नयन करने के भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

के. जी. मार्ग पर विदेशी मामले होस्टलों को एक नया रूप दिया गया है। पूरे भवन का रंग-रोगन किया गया और रिसेप्शन क्षेत्र में बेहतर फ्लोरिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग की गई। गोल मार्केट के नए होस्टल में पुराने लिफ्टों को बदलने की प्रक्रिया भी चल रही है। सुरक्षा, संचार और जल आपूर्ति की समस्याओं का कारगर ढ़ंग से समाधान करते हुए, द्वारका में एम ई ए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की दखली को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशों से लौटने वाले अधिकारियों की शुरूआती रहने संबंधी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए पांच इकाइयों को ट्रांजिट हाऊस में बदलने का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण हो चुका है।

अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन प्रभाग के लिए डलहौजी रोड पर सी-I हटमेंट्स के नवीकरण का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। साऊथ ब्लॉक के गेट नं. 4 और 8 पर प्रवेश के तरीके को बेहतर बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्टेट-ऑफ - द - आर्ट प्रौद्योगिकी के साथ विशेष मानचित्र - सह - अवस्थिति कक्ष बनाने के प्रस्ताव पर मंत्रालय कार्य कर रहा है। विदेशों में हमारे मिशनों/पोस्टों के लिए कलात्मक वस्तुओं के चयन हेतु बनाई गई समिति उपर्युक्त कलात्मक वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रसिद्ध आर्ट गैलरी/इम्पोरियमों का अनेक दौरा करने के अलावा दिसंबर, 2005 के दौरान चार बार बैठक भी कर चुकी है। समिति कलात्मक क्षेत्र के क्षेत्रीय उत्पादकों/आपूतिकर्ताओं के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए बंगलौर, हैदराबाद और चैन्नै का भी दौरा करती है। अधिकांश मिशनों/पोस्टों की जरूरतें पूरी कर ली गई थीं। सार्क उप - क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थल जिन्ना हाउस,मुंबई के नवीकरण की परियोजना से संबंधित प्रारंभिक कार्य कुल मिलाकर पूरा हो चुका था। परियोजना संबंधी कार्य शीघ्र ही शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

मंत्रालय ने विदेशों में मिशनों/पोस्टों के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को अद्यतन बनाने के प्रस्ताव की पहल की है ताकि उन्हें मौजूदा स्थिति के अनुरूप किया जा सके। प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, विशेष रूप से संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए, कुर्सी क्षेत्र मानदंडों; मिशनों/पोस्टों के प्रमुखों के आवासों पर फर्नीचर और उपस्कर के प्रावधान; विदेशों में मिशन/पोस्ट के प्रमुखों के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय टी वी चैनलों के प्रावधान; सरकारी कारों की खरीद की प्रक्रिया को आसान करने के संबंध में अलग से अनेक वैयक्तिक प्रस्ताव भी चलाए गए हैं।

परियोजना प्रभाग

परियोजना प्रभाग की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय के इस्तेमाल के लिए भारत में और विदेश में पहले से बनी बनाई संपत्तियों की खरीद और संपत्तियों के निर्माण की है। विदेशों में स्थित मुख्यालयों में सरकारी संपत्तियों की मरम्मत/नवीकरण से संबंधित प्रस्तावों को निपटाने की जवाबदेही भी परियोजना प्रभाग की है। वर्तमान में, सरकार के पास 77 चांसरी भवन, 83 एच ओ एम/एच ओ पी आवास और विदेशों में 610 अधिकारी/स्टाफ आवास भवन हैं। वर्तमान में 37 निर्माण परियोजनाएं निष्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, जिनमें जेनेवा, सिंगापुर और करांची में तीन प्रमुख नवीकरण/फिर से बनाने की परियोजनाएं शामिल हैं। फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, एशियन अफ्रीकन लीगल कंस्लटेटिव ऑर्गेनाइजेशन्स (एस एल सी ओ) कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, कोलकाता में आई सी सी आर क्षेत्रीय कार्यालय में और पी आर ओ भवनों के लिए जयपुर, बंगलोर और लखनऊ में निर्माण कार्य प्रगति पर है। विदेशों में निर्माण/पुनः निर्माण परियोजनाओं के लिए, जेनेवा में राष्ट्रपति आवास और करांची में तीन सरकारी संपत्तियों के पुनः निर्माण का कार्य पहले ही सौंप दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में, विदेश मंत्रालय के मुख्यालय के रूप में नई दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू भवन के निर्माण के लिए और काठमांडू में भारतीय दूतावास के लिए और कार्यालय और स्टाफ के आवासों के निर्माण के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन ले लिया गया है।

योजनेतर व्यय समिति ने मुंबई में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

और आवासों के निर्माण के लिए तथा काबुल में भारतीय दूतावास परिसर के निर्माण के लिए भूमि की खरीद की अनुमति दे दी है।

अबूजा में चांसरी के निर्माण के लिए, सिंगापुर में पुनः निर्माण परियोजना के लिए, वीजिंग में भारतीय दूतावास परिसर के लिए, काठमांडू में भारतीय दूतावास परिसर के लिए और वार्सा में भारतीय दूतावास परिसर के लिए स्थानीय निकाय से अनुमति मांगी जा रही है। इस्लामाबाद में आवासीय परिसर, ब्रासीलिया में दूतावास परिसर, लंदन में अपार्टमेंट तथा ताशकंद में दूतावास परिसर जैसी निर्माण प्रक्रियों की तैयारी अंतिम चरण में है। सक्षम प्राधिकारियों से वित्तीय मंजूरी मांगी जा रही है। टोक्यो में सरकारी संपत्तियों के पुनःनिर्माण के लिए और ढाका में चांसरी एवं मकानों के निर्माण के लिए मंत्रालय की डिजाइन चयन समिति के अनुमोदन से संबंधित परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। मंत्रालय बहरीन में भारतीय दूतावास परिसर, पोर्ट लुईस में चांसरी परिसर, परामारिबो में भारतीय संस्कृति केंद्र और बैंकॉक में दूतावास और भारतीय संस्कृति केंद्र के निर्माण के लिए डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए चुने गए परामर्शदाताओं से वैचारिक डिजाइन आमंत्रित कर रहा है। वैचारिक डिजाइन प्राप्त होने के बाद, मंत्रालय की डिजाइन चयन समिति द्वारा इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए परामर्शदाताओं का चयन किया जाएगा। निर्माण के पूर्व क्रियाकलापों की प्रगति के आधार पर यह संभावना है कि अगले वित्तीय वर्ष में अनेक परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इन निर्माण परियोजनाओं में प्रमुख परियोजनाएं हैं - जवाहरलाल नेहरू भवन, चाणक्यपुरी आवासीय क्वार्टर्स, काठमांडू/मस्कट/ब्रासीलिया/अबूजा/वार्सा/बीजिंग/इस्लामाबाद/काबुल/ताशकंद और बैंकॉक में भारतीय दूतावास परिसर का निर्माण। इसके अलावा, सिंगापुर में पुनर्निर्माण परियोजना और लंदन मं एपार्टमेंटों का निर्माण कार्य भी अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण स्तर तक पहुंच सकता है। 'आल्को' निर्माण परियोजना भी समाप्ति की अंतिम अवस्था में है। अगले वित्तीय वर्ष में विदेश सेवा संस्थान परिसर का निर्माण आंशिक रूप से पूर्ण करने के लिए अलग से प्रयास किया जा रहा है।

मंत्रालय ने अपनी किराया देयता को कम करने की दृष्टि से भारत में और विदेशों में संपत्तियों के निर्माण एवं प्राप्ति के लिए दो - सूत्री दृष्टिकोण को अपनाया है। विदेशों में कुछ स्थलों पर दिए जाने वाले अत्यधिक किराए को ध्यान में रखते हुए और कतिपय स्थानों में संपत्तियों की खरीद के लिए अनुकूल परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अगले कुछ वर्षों में संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्राथमिक स्थानों की एक सूची बनाई गई है। चालू वित्तय वर्ष में, उलानबटार में राजदूतावास-सह-चांसरी की खरीद की गई है और पेरिस में अतिरिक्त चांसरी भवन और जॉर्जटाऊन में चांसरी निर्माण के लिए प्लॉट खरीदने के लिए वित्तीय अनुमोदन ले लिया गया है। तेहरान, कराकास और ब्यूनॉस आयर्स में दूतावास के लिए संपत्तियों की खरीद के अधिग्रहण प्रस्तावों पर गहन चर्चा चल रही है। मंत्रालय नैरोबी और अदिस अबाबा में भूमि खरीदने के प्रस्तावों की जांच भी कर रहा है।

बजट अनुमान 2005-06 में पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 66.41 करोड़ रू. के आवंटन का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है और अनुपूरक अनुदान मांगों की दूसरी किस्त में 42 करोड रू. का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। विभिन्न निर्माण परियोजनाओं और अधिग्रहण प्रस्तावों में प्रगति के वास्तविक मूल्याकंन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2006-07 में पूंजीगत परिव्यय के बजटीय आबंटन में पर्याप्त बढ़ोतरी की मांग की गई है।

ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी

इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग, न्यूयार्क स्थित प्रधान कौंसलावास और दुबई स्थित प्रधान कौंसलावास और दुबई स्थित प्रधान कौंसलावास के पासपोर्ट एवं वीजा विंगों का कम्प्यूटरीकरण इस वर्ष पूरा कर लिया गया था। रियाद, मस्कट और आबूधावी में दूतावासों का निर्माण कार्य कार्यान्वयन की अंतिम अवस्था में है। काफी अधिक संख्या में पासपोर्ट और वीजा सेवा प्रदान करने वाले 20 अन्य भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है। इस वर्ष के दौरान, 100 भारतीय दूतावासों और कौंसलावासों के वीजा अनुभागों को सॉफ्टवेयर सुविधा प्रदान की गई थी।

■■

17 समन्वय

समन्वय प्रभाग की तीन शाखाएं हैं अर्थात संसद अनुभाग, समन्वय अनुभाग और छात्र कक्ष।

संसद अनुभाग

समन्वय प्रभाग विदेश मंत्रालय का संसद से संबंधित सभी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु है; इन कार्यों में प्रश्न-उत्तर, आश्वासन, विदेशी संबंधों पर बहस और संसद के दोनों सदनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। समन्वय प्रभाग विदेश मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठकों का आयोजन भी करता है और विदेश मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य तथा जिन मामलों पर विदेश मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है उनसे संबंधित अन्य संसदीय समितियों के कार्य का समन्वय और देखभाल करता है।

समन्वय अनुभाग

समन्वय अनुभाग राज्यपालों, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा उपाध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों के मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, न्यायपालिका के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों आदि द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए राजनीतिक दृष्टि से अनापत्ति प्रदान करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करता है। विदेश मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद सामान्यतः राजनीतिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करता है। इन पहलुओं में ये शामिल हैं; इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश; यात्रा के लिए राजनीतिक और कार्यात्मक औचित्य; आयोजनकर्ताओं की पृष्ठभूमि और पूर्ववृत्त; तथा हमारे संबंधित मिशन/केन्द्र से प्राप्त सिफारिश। किसी सरकारी अधिकारी को विदेश जाने की अनुमति प्रदान करने से पहले इस मंत्रालय की सिफारिश अनिवार्य है।

वर्ष के दौरान समन्वय अनुभाग ने विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में विभिन्न भारतीय खिलाड़ियों और खेल-कूद टीमों की भागीदारी के लिए और भारत में विदेशी खेल-कूद टीमों के लिए बड़ी संख्या में अनुमोदन प्रदान करने पर भी कार्रवाई की है।

वर्ष के दौरान आतंकवाद विरोधी दिवस (21 मई), सद्भावना दिवस (20 अगस्त) और कौमी एकता सप्ताह/दिवस (18-25 नवम्बर) पूर्ण गरिमा के साथ मनाए गए। मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों दोनों में शपथ दिलाई गई।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करने, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत एमेच्योर डब्ल्यू./टी लाइसेंस प्रदान करने, विदेशों में स्थित भारत विदेश सांस्कृतिक मित्रता और सांस्कृतिक सोसाइटियों के लिए सहायता अनुदान के वास्ते अनापत्ति देने के अनुरोधों पर भी वर्ष के दौरान तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई। इसी प्रकार गैर-अनुसूचित उड़ानों और विदेशी नौसेना पोतों एवं जलयानों द्वारा यात्राओं के लिए कूटनीतिक मंजूरी देने के लिए कार्रवाई की गई।

छात्र कक्ष

छात्र कक्ष, जो समन्वय प्रभाग का एक भाग है , मेडिकल एवं इंजीनियरी संस्थानों में एमबीबीएस/बीडीएस, इंजीनियरी डिग्री, बी. फार्मेसी और इंजीनियरी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में आरक्षित स्थानों पर विदेशी स्व-वित्त पोषित छात्रों के चयन, नामांकन और प्रवेश के संबंध में कार्रवाई करता है।

यह कक्ष विभिन्न मेडिकल संस्थानों और अनुसंधान पाठ्यक्रमों में ऐच्छिक प्रशिक्षण सहित इंजीनियरी, भेषज प्रबंधन और अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले विदेशी छात्रों के संबंध में राजनीतिक दृष्टि से स्वीकृति देने के संबंध में भी कार्रवाई करता है।

यह कक्ष विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्व-वित्त पोषित छात्रों की राजनीतिक स्वीकृति और प्रवेश से संबंधित मामलों के बारे में विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों और संस्थानों के साथ सम्पर्क स्थापित करता है।

एमबीबीएस/बीडीएस एवं इंजानीयरी/फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शैक्षिक वर्ष 2005-06 में क्रमशः 164 एवं 78

आवेदन प्राप्त हुए थे जिन पर कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए 1150 विदेशी छात्रों को राजनीतिक दृष्टि से अनापत्ति प्रदान की गई।

■■

18 सूचना का अधिकार प्रभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन देश में प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्राधिकरणों के नियंत्रण के तहत उपलब्ध सूचना को हासिल करने के लिए सूचना के अधिकार की एक व्यवहारिक सामाजिक व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण को अपने रिकॉर्डों को विधिवत् इस ढ़ंग से और इस स्वरूप में तालिकाबद्ध एवं सूचीबद्ध रखना चाहिए कि यह इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना के अधिकार की सुविधा प्रदान करे। साथ ही, कम्प्यूटरीकृत किए जाने हेतु उपयुक्त समस्त दस्तावेज यथोचित समय में और संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप कम्प्यूटरीकृत किए गए हों और विभिन्न प्रणालियों पर समग्र देश से एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़े गए हों जिससे कि इन रिकार्डों तक पहुँच की सुविधा प्रदान की जा सके। विदेश मंत्रालय में इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए, अक्तूबर, 2005 से सूचना का अधिकार (आर टी आइ) प्रभाग नामक एक नए प्रभाग का सृजन किया गया है। आर टी आई प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारि होते हैं जो केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी भी होते हैं।

इस अधिनियम के आदेशपत्र के अनुसार, "विदेश मंत्रालय से संबंधित मूल जानकारी" शीर्षक के अन्तर्गत जानकारी की एक व्यापक सूची ऑनलाईन कर दी गई है। इस सूची में मंत्रालय के समस्त पहलुओं, इसकी संरचना, आबंटित दायित्व, कार्यों, निर्णय लेने वाली प्रक्रिया, संवर्ग संचालन और लाभार्थियों की सूची सहित सहायता कार्यक्रमों की जानकारी शामिल है। नागरिकों की जानकारी हेतु उपलब्ध सुविधाओं के विवरण में जन सूचना अधिकारियों (आर टी आई एक्ट 2005 के अनुच्छेद 4(1)ख(XVI) के अनुसार) के साथ-साथ मुख्य अपील प्राधिकारी (आर टी आइ एक्ट 2005 की धारा 19(1)के अन्तर्गत) के नाम और पते, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इण्डियन कॉऊंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स तथा केन्द्रीय पासपोर्ट कार्यालयों की सूचना मंत्रालय की वेबसाईट www.mea.gov.in, www.mealib.nic.in, पर रख दी गई हैं।

विदेश प्रचार

19

विदेश प्रचार प्रभाग, विदेशों के साथ घनिष्ठ पारस्परिक संबधों के जरिए और साथ ही साथ विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों को अद्यतन सूचना एवं आंकडों का प्रचार-प्रसार करने के माध्यम से भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को निरंतर उन्नत बनाता रहा।

वर्ष के दौरान प्रभाग ने विदेश नीति के मीडिया संबंधी उन विभिन्न पहलुओं पर भी सक्रिय रूप से भाग लिया जिन्हें मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता दी गई थी। इनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का मामला तथा संयुक्त राष्ट्र सुधारों, पड़ोसी देशों तथा विश्व के प्रमुख देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के मामले शामिल हैं। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की अफगानिस्तान, बंगलादेश (सार्क शिखर सम्मेलन), फ्रांस, इंडोनेशिया, (एशियन-अफ्रीकन सम्मेलन), मलेशिया (पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और चतुर्थ भारत-आसियान शिखर सम्मेलन), रूस, यू.के. (जी-8 शिखर सम्मेलन) और अमरीका (द्विपक्षीय एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा) की यात्रा के समाचार तंत्र संबंधी पक्षों पर ध्यान दिया। महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, चीन के प्रीमियर वेन जियाबाओ, जापान के प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोईजुमी, यू.के. के प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षा सऊदी अरब के राजा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और विश्व के अन्य नेताओं की भारत यात्राओं के मीडिया संबंधी कार्यों की देखरेख भी प्रभाग द्वारा ही की गई।

विदेश प्रचार प्रभाग ने भारत की हित-चिंता के मुख्य सार्वभौम मसलों जैसे कि आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, निरस्त्रीकरण, लोकतंत्र, विकास, और आर्थिक एवं पर्यावरण संबंधी मसलों पर भारत के दृष्टिकोण को उजागर करने के कार्य को अनवरत रूप से निभाया। दक्षिण-दक्षिण सहयोग, अफगानिस्तान और अफ्रिकी देशों को सहायता में भारत के योगदान को विवरण देने और प्रकाशनों के जरिए दोनों ही परिप्रेक्ष्य में भली भांति प्रक्षेपित किया।

आधिकारिक प्रवक्ता का कार्यालयः आधिकारिक प्रवक्ता के कार्यालय ने संपूर्ण वर्ष के दौरान विदेशी और भारतीय मीडिया के साथ दैनंदिन आधार पर गहन संपर्क कायम रखा। विदेश नीति से संबंधित मुख्य घटनाओं, आने-जाने वाली उच्चस्तरीय यात्राओं और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों सहित दैंनदिन गतिविधियों पर नियमित रूप से मीडिया को विवरण दिया। प्रेस विज्ञप्तियां और वक्तव्य तथा ब्रीफिंग के बिंदु ई-मेल द्वारा नियमित रूप से लगभग 200 पत्रकारों को परिचालित किए जाते रहे तथा साथ ही साथ मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए। मीडिया के साथ संयोजकता को कारगर बनाने के लिए प्रवक्ता के कार्यालय ने इलेक्ट्रानिक पद्धतियों पर अपने विश्वास को निरंतर बढ़ावा दिया। आधिकारिक प्रवक्ता ने मीडिया की व्यापक गतिविधि का संवर्धन करने के लिए दिल्ली के बाहर भी बैठकों का आयोजन किया जिसके परिणामस्वरूप मुंबई आस्थानी विदेशी प्रेस प्रवक्ता कार्यालय के साथ नियमित संपर्क बना रहा।

आधिकारिक प्रवक्ता के कार्यालय ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारपत्रों और टेलीविजन संगठनों के साथ प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के साक्षात्कारों का भी आयोजन किया। विदेश सचिव द्वारा अनेक पृष्ठभूमि ब्रीफिंग्स भारत एवं विदेशी मीडिया के साथ आयोजित की गई।

वेबसाइटः सूचना का प्रसारण करने वाले, मंत्रालय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण - वेबसाइट http://meanindia.nic.in - को प्रभाग द्वारा निरंतर अद्यतन बनाया जाता रहा। प्रधान मंत्री अन्य मंत्रियों एवं विदेश सचिव द्वारा विदेश नीति पर भाषण/वक्तव्य, प्रेसविज्ञप्तियां, आधिकारिक प्रवक्ता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई ब्रीफिंग का लिप्यंतरण, साक्षात्कार, ओप-एड, संसद प्रश्न - उत्तर विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों पर टिप्पणियां और अन्य संबद्ध दस्तावेजों को मीडिया तथा विदेश नीति के मसलों में रूचि रखने वालों के लाभ हेतु सरकारी वेबसाइट पर रीयल-टाइम आधार पर अपलिंक किया गया। मंत्रालय की मासिक पत्रिका "इंडिया पर्सपेक्टिव" और अन्य सभी प्रकाशनों और श्रव्य-दृश्य सामग्री का प्रभाग द्वारा प्रकाशन तथा अधिग्रहण किया गया और उसे वेबसाइट पर भी डाला गया। प्रधान मंत्री की यात्राओं और महत्वपूर्ण गतिविधियों को वेबसाइट पर पृथक उपखंडों में डाला गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, भारत-अमरीका उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग दल, मंत्रालय के लेखे, हज संबंधी मामले, और कैलाश मानसरोवर यात्रा सहित नए विशेष विषयों पर अलग-अलग वेब पृष्ठ तैयार किए गए। हाल ही में अद्यतन की गई सामग्री को सरलता से पुनः प्राप्त करने हेतु "व्हाट्स न्यू" शीर्षक से एक नए संपर्क का सृजन किया गया। प्रभाग द्वारा निकाले जाने वाले इलेक्ट्रानिक न्यूजवायर के रूप में विदेश नीति की महत्वपूर्ण घटनाओं का साप्ताहिक समेकन संपूर्ण विश्व में भारत की ओर देखने वाले लोगों को सामग्री मुहैया कराता रहा। प्रभाग ने सार्वभौम लोकतंत्र पहल के लिए वेबसाइट www.gdi.nic.in भी तैयार की।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों के वेबसाइटों के हायपरलिंक्स ने विभिन्न मंत्रालयों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सरलता से भारत संबधी सूचना उपलब्ध कराई।

मीडिया को सुविधा प्रदान करना

भारत की यात्रा पर आए राज्य प्रमुखों/सरकार प्रमुखों के साथ आने वाले विदेश मीडिया शिष्ट मंडलों को यंत्रोपकरणों और सम्पर्क के संबंध में सहायता एवं समर्थन जुटाने का काम करने के साथ-साथ विदेश प्रचार प्रभाग ने विदेश यात्राओं पर जाते समय राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और उप राष्ट्रपति के साथ जाने वाले भारतीय मीडिया शिष्टमंडलों को भी इस प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की। वर्ष के दौरान प्रभाग ने अफगानिस्तान, आस्ट्रिया, बेल्जियम, भूटान, कनाडा, चिली, चीन, चेक गणराज्य, फिजी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, जापान, मालदीव, मारीशस, नार्वे, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, थाईलैंड, नीदरलैंड, यू. के उजबेकिस्तान और वेनेजुएला से आने वाले राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की यात्राओं के संबध में भारत की यात्रा पर आए मीडिया प्रतिनिधिमंडलों और भारतीय मीडिया को सहायता प्रदान की जिसके लिए उसने मीडिया एडवाइजरी जारी की, प्रेस सम्मेलनों का आयोजन किया समारोह स्थल तक उनकी पहुँच को सुकर बनाया और उन्हें परिवहन तथा आवास संबंधी सुविधाएं प्रदान की। विदेश मंत्री / मंत्रियों के स्तर की यात्राओं के दौरान भी इसी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान उनके साथ जाने वाले भारतीय मीडिया के प्रतिनिधिमंडलों को समस्त संभारतंत्रीय व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई जिनमें पत्रकारों द्वारा कवरेज को फाइल करने के लिए सुविधाओं से पूर्णतः सज्जित मीडिया केंद्रों का गठन तथा संचालन, मीडिया ब्रीफिंग तथा अन्य व्यवस्थाओं का आयोजन करना शामिल था ताकि कवरेज समय पर उपलब्ध हो सके। इनमें राष्ट्रपति की आइसलैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका, स्विटजरलेंड, तंजानिया, और उक्रेन, उपराष्ट्रपति की अर्मेनिया, बेलारूस और रोमानिया तथा प्रधानमंत्री की अफगानिस्तान, बंग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, मारीशस, रूस, यू. के. और अमरीका की यात्राएं शामिल हैं। विदेश मंत्री की अफगानिस्तान, बंगलादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, ईरान, कजाखस्तान, लाओस, मारीशस, म्यांमार, पाकिस्तान, रूस और श्रीलंका की यात्राओं के दौरान भी इसी प्रकार की सहायताएं उपलब्ध कराई गई। विशेष कार्यों के लिए विदेश जाने वाले भारतीय पत्रकारों को भी आवश्यक सहायता प्रदान की गई।

अप्रैल, 2005 में श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा के उद्घाटन के लिए श्रीनगर और कमान पोस्ट (नियंत्रण रेखा पर) 60 से भी अधिक मीडिया कार्मिकों की यात्रा को प्रभाग ने सुविधा प्रदान की। इस प्रभाग ने आसियान सचिवालय के साथ समन्वय करके, भारत-आसियान मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 10-10 भारतीय पत्रकारों के पांच बैचों को आसियान देशों में भेजा।

300 से भी अधिक भारत आस्थानी प्रतिष्ठित मीडिया संगठनों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई ताकि वे विभिन्न हितकारी मसलों पर उपलब्ध कराई गई प्रासंगिक सूचना के जरिए अपना कार्य सुचारू रूप से चला सकें इसके अतिरिक्त प्रत्यय पत्रों, वीजा तथा आवास अनुमति के मामलों में भी उन्हें सुविधा प्रदान की गई। 340 विदेशी पत्रकारों को वीजा विस्तार और/अथवा प्रत्यायन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।

परिचयात्मक यात्राएं: विदेशी मीडिया में भारत के विशुद्ध और समसामयिक चित्रण प्रस्तुत करने के लिए विदेशी पत्रकारों की परिचयात्मक भारत यात्राएं भी इस प्रभाग का मुख्य कार्य हैं क्योंकि इससे पत्रकारों को भारत की विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, उद्योग तथा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर गतिविधियों की अनोखी एवं फर्स्टहैंड सूचना उपलब्ध हो जाती है। प्रभाग ने विदेश स्थित हमारे मिशनों के सहयोग और सिफारिश पर भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठित केंद्रों की ऐसी यात्राओं का आयोजन जारी रखा। यात्रा पर आए पत्रकारों की मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों, विद्धानों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का भी आयोजन किया गया। फरवरी, 2005 से जनवरी, 2006 तक ऐसी यात्राओं पर 60 पत्रकारों की मेजबानी की गई। इनमें आस्ट्रिया, मिस्त्र, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, लात्विया, मलेशिया, मारीशस, मंगोलिया, फिलीपींस, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया,

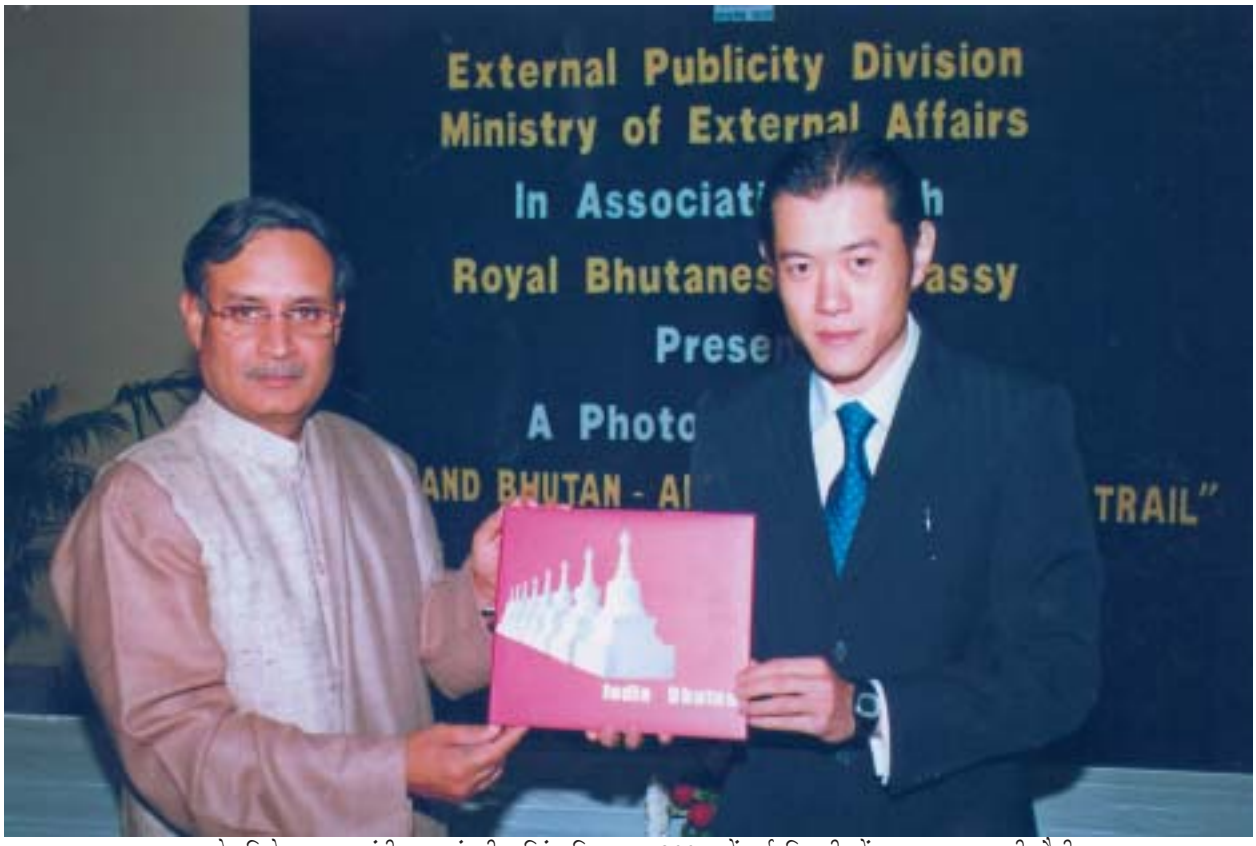

भारत के विदेश राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह दिसम्बर, 2005 में नई दिल्ली में भारत-भूटान की मैत्री पर फोटो प्रदर्शनी के उद्घाटन में भूटान के युवराज महामान्य जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक।

विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा 3 फरवरी, 2006 को ब्रासीलिया में ब्राजील के विदेश मंत्री श्री सैल्जो अमोरिम के साथ।

तुर्की और अमरीका के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक शामिल थे।

आठ पाकिस्तानी पत्रकारों के समूह को सात दिन की यात्रा पर आमंत्रित किया गया।

श्रव्य-दृश्य प्रचारः विदेशों में भारत की सकारात्मक छवि को दर्शाने वाले वृत्त चित्रों को प्रभाग तैयार कराता है/प्राप्त करता है और विदेशी चैनलों पर प्रसारण के लिए भेजता है। फिल्ममहोत्सवों और विदेशों में भारतीय फिल्म सप्ताहों में भागीदारी के लिए फीचर फिल्मों की अधिप्राप्ति और आपूर्ति तथा सांस्कृतिक प्रचार और प्रदर्शनियों का आयोजन करना प्रभाग द्वारा किए जा रहे अन्य श्रव्य-दृश्य प्रचार कार्य हैं।

भारत इंडोनेशिया के सांस्कृतिक संबंधों पर एक गीतात्मक फिल्म "अनेक रस" जम्मू और कश्मीर पर (24 कैपसूल्स) लघु फिल्मों की एक श्रृंखला "इंटीग्रल इंडिया", जम्मू और कश्मीर की भारतीय पहचान पर एक लाजवाब फिल्म "पेशेंट स्टोन," भारत में पर्यावरण पर "ग्रीन सिग्नल्स", "रीविजिटिंग इंडिया बाइ रेल"; भारत चीन संबंधों पर "डाउन द एजेस"; "विनिंग ए फ्यूचर"; संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना में भारत की भूमिका पर "पीसकीपर्स," भारत नेपाल आर्थिक सहयोग पर "एन्ड्योरिंग फ्रैंडशिप", अप्रैल, 2005 से जनवरी, 2006 तक पूर्ण की गई। मंत्रालय द्वारा अधिप्राप्त तैयार किए गए कुछ वृत्त चित्र विदेशी टी वी चैनलों पर अलजीयर्स, बिश्केक, काहिरा, कालम्बो, दुबई, जार्ज टाउन, हो चिमिन्ह सिटी,काबुल, लागोस, सेंट पीटर्सबर्ग, विंडहॉक और जजीबार में दिखाई गई।

अप्रैल-जनवरी, 2006 के दौरान विदेशी प्रोडक्शन हाउसों और अंतर्राष्ट्रीय टी वी चैनलों से विभिन्न विषयों पर भारत में वृत्तचित्रों की शूटिंग के लिए 300 से भी अधिक प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई और उनका अनुमोदन किया गया।

प्रभाग ने फिल्म महोत्सवों/फिल्म सप्ताहों का आयोजन करने के लिए जिन भारतीय मिशनों को भरपूर सहायता प्रदान की उनमें आबिदजान (आइवरी कोस्ट), अकरा (घाना), अंकारा (तुर्की), बाकू (अजरबैजान), बोगोटा (कोलम्बिया), ब्रसेल्स (बेल्जियम), बुडापेस्ट (हंगरी), हरारे (जिम्बाब्वे), काठमांडु (नेपाल), लीमा (पेरू), मैड्रिड (स्पेन) मनीला (फिलीपींस), नैरोबी (केन्या), पेरिस (फ्रांस), पोर्ट लुई (मारीशस), प्राग (चेक गणराज्य), रबात (मोरक्को), रोम (इटली), वार्सा (पोलैंड), और यांगोन (म्यांमा) शामिल हैं।

नई दिल्ली में 15-24 जुलाई, 2005 तक आयोजित 7 वें ओसियन्स सिनेफैन फिल्म समारोह को प्रभाग ने सहायता प्रदान की। 1-11 दिसंबर, 2005 तक कराची में आयोजित कारा फिल्म महोत्सव में भारतीय फीचर फिल्में भेजने में भी प्रभाग ने सहायता की।

मिशनों को पुस्तकालय तथा भेंट स्वरूप दिए जाने के लिए बीटाकैम कैसेट्स, सीडी रोम,ऑडियो वीडियो सीडी, और कैसेटों के रूप में दृश्य-श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई गई श्रव्य-दृश्य टी.वी., वी सी आर, डिश एंटीना की मंजूरी के लिए मिशनों द्वारा मंत्रालय को किए अनुरोधों पर प्रभाग द्वारा कार्रवाई की गई।

प्रभाग ने कई फोटो प्रदर्शनियां एकत्र की और उन्हें मिशनों को भेजा गया। इनमें से "लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महात्मा गांधी" को बीजिंग, ढाका, हवाना, टोक्यो, वेनकूवर और वाशिंगटन स्थित मिशनों भेजा गया; भारत में बौद्ध स्थलों और विरासत पर "द पाथ आफ कम्पैशन" को बीजिंग, क्वालालंपुर और वियनतियाने स्थित मिशनों को भेजा गया; पुराने गोवा के चर्चों के बारे में "वेल्हा गोवा" को ढाका, हवाना, लिस्बन स्थित मिशनों को तथा "जम्मू और कश्मीर" को ढाका, हवाना और जद्दाह स्थित मिशनों को भेजा गया।

"इंडिया-भूटान एलोंग द फ्रेडंशिप ट्रेल" शीर्षक से एक फोटो प्रदर्शनी दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन विदेश राज्य मंत्री और भूटान के युवराज ने किया। इस अवसर पर इसी विषय पर एक काफी टेबल पुस्तक काविमोचन किया गया ति उसके बाद भारत-भूटान संबंधों पर - "ए ब्रिज सो नियर" फिल्म दिखाई गई।

इंडिया पर्सपेक्टिव्सः भारतीय मिशनों और केंद्रों के जरिए वितरण हेतु मंत्रालय की मासिक पत्रिका इंडिया पर्सपेक्टिव दस भिन्न-भिन्न भाषाओं में निरंतर प्रकाशित हो रही है। इस पत्रिका का उद्देश्य एक ओर जहां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बढ़ावा देने का है वहीं दूसरी और सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को भी पूर्णतः प्रसारित करती है। इंडिया पर्सपेक्टिव्स के वर्तमान एवं पुराने अंक इलेक्ट्रॉनिक रूप में पाठकों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की गई। रीबिल्डिंग अफगानिस्तान : इंडिया एट वर्क (सी डी के साथ); इंडिया मूड्स एंड मेमोरीज; इंडिया कोशेंट इंडिया एंड अफ्रीका - पार्टनर्स इन पीस एंड प्रोगेस इंडिया - पार्टनर फॉर डिवेलपमेंट इन साउथ बांडुंग (बांडुंग सम्मेलन की 50 वी जयंती पर) रिपोर्ट ऑफ इंडिया - चायना जॉयंट स्टडी ग्रुप

ऑन कंप्रेहेंसिव ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशनइंडिया - ए डायनेमिक डेमोक्रेसी (रीप्रिंट एंड जर्मन वर्शन) ए फारेन पॉलिसी फॉर इंडिया (रीप्रिंट) कैलाश मानसरोवर यात्रा 2005।

इन प्रकाशनों को विदेश स्थित भारतीय मिशनों का तथा भारत स्थित विदेशी मिशनों को भेजा गया और अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं के समय में उपयोग में लाया गया। इसके अलावा विदेश स्थित भारतीय मिशनों को उनके पुस्तकालयों के उपयोग और उपहार के लिए पुस्तकें, भारतीय प्रकाशन तथा अन्य प्रचार सामग्री भेजी गई।

■■

20 विदेश सेवा संस्थान

भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों और विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा विदेश सेवा संस्थान ने विदेशी राजनयिको के लिए अपनी कूटनीति एवं विदेश नीति कार्यक्रम जारी रखे। वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा विदेशी राजनयिकों के लिए दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम (पी सी एफ डी), विदेशी राजनयिकों के लिए एशिया के बारे में एक उन्नत पाठ्यक्रम (ए सी ए एफ डी), विदेशी राजनयिकों के लिए प्रथम कूटनीति एवं विदेश नीति कार्यक्रम (डी एफ पी पी एफ डी) तथा वियतनामी एवं सूडानी राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय की विदेश सेवा मूल कार्यक्रम के सदस्यों के लिए भारतीय विदेश नीति पर एक वार्त्ता आयोजित की गई। वर्ष के दौरान नार्वे, सऊदी अरब, मेक्सिको एवं इंडोनेशिया के विदेश सेवा संस्थानों के साथ सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश सेवा संस्थान अन्य देशों में अपने समकक्ष संस्थानों के साथ सांस्थानिक संबंध भी बनाए रखे।

भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण: संस्थान के मुख्य कार्यकलापों में एक भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षुओं को विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों के साथ - साथ भारतवर्ष दोनों में अपने पेशेवर कैरियर के दौरान ऐसे सभी कार्यों के लिए तैयार करना है जो उनके लिए आवश्यक है। तदनुसार 2004 बैच के प्रशिक्षुओं को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विदेश नीति, रक्षा तथा सुरक्षा, आर्थिक कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रीय कानून, संसदीय कार्य, सांस्कृतिक कूटनीति, प्रोटोकॉल तथा कौंसली विषयों के माड्यूल्स शामिल हैं। इस कार्यक्रम में प्रशासन और लेखा, वार्ता कौशल, प्रतिनिधित्व - कौशल और मीडिया के साथ संबंध बनाना भी शामिल है। प्रशिक्षण माड्यूल्स-व्याख्यानों, सजीव सेमिनारों के साथ-साथ विभिन्न प्रमुख संस्थानों के साथ संबद्ध कर कार्यान्वित किये गए। सहभागियों को विषयवस्तु की गहरी समझ प्रदान करने, भारत के पड़ोसियों के बारे में उनकी जानकारी को संवर्धित करने और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यों से उन्हें परिचित कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भूटान और अफगानिस्तान के दो अध्ययन दौरे भी शामिल किये गये हैं। 2004 के भा. वि. से. के प्रशिक्षु अधिकारियों ने जनवरी, 2006 में अपना प्रशिक्षण पूरा किया और उन्हें विदेशों में पदस्थापित किये जाने से पूर्व विभिन्न प्रभागों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मंत्रालय में वापस भेजा गया।

राष्ट्रीय लालबहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रतिष्ठापन पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात 2005 बैच के भा. वि. से. के प्रशिक्षुओं ने विदेश सेवा संस्थान में 5 दिसम्बर, 2005 से एक - वर्षीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया।

अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ संबंधों का प्रोन्नयन: राष्ट्रीय लालबहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, राष्ट्रीय सीमा-शुल्क, उत्पाद एवं स्वापक अकादमी, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान एवं पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान ब्यूरो जैसी अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ विदेश सेवा संस्थान ने नियमित संपर्क बनाए रखा है। भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य सेवाओं के बीच संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से, जिसे विदेश मंत्रालय द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, विदेश सेवा संस्थान अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ प्रयासरत है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्थान ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए भारतीय विदेश नीति पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पत्रकारों के लिए "कूटनीति एवं भारतीय विदेश नीति" पर एक पाठ्यक्रम संचालित की। इसी प्रकार का पाठ्यक्रम 2006 में आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है। इसी रूपरेखा पर वरिष्ठ भा. पु. से. के अधिकारियों के लिए "भारतीय विदेश नीति की मुख्य विचारधारा" पर 5-10 दिसम्बर, 2005 तक एक एक-सप्ताह का गहन कार्यक्रम आयोजत किया गया। यह पाठ्यक्रम पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अनुरोध पर संचालित किया गया। ब्यूरो ने संस्थान को इसी प्रकार का पाठ्यक्रम 2006-07 में आयोजित करने के लिए संपर्क किया है।

मंत्रालय के कर्मचारियों/अधिकारियों का प्रशिक्षणः विदेश सेवा संस्थान ने नियमित रूप से विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए "मूल व्यावसायिक पाठ्यक्रम" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। यह प्रशिक्षण स्टाफ सदस्यों को कम्प्यूटर में दक्षता बढ़ाने तथा उन्हें प्रशासन, लेखा, कौंसली कार्य, प्रारूपण, कार्यालय प्रक्रिया तथा संचार के स्वरूप के विभिन्न पहलुओं से अद्यतन बनाने से संबंधित है। मंत्रालय की सूचना एवं ई-गवर्नेन्स प्रभाग की सहायता से विदेश सेवा संस्थान ने मंत्रालय के स्टाफ -कर्मियों को विशेष रूप से डिजाइन किये गए साफ्टवेयर पैकेजों पर प्रशिक्षण देना शुरू किया है जिसे लेखा एवं कांसुली कार्यों में उपयोग में लाया जा सकता है। मूल व्यावसायिक पाठ्यक्रम का यह प्रशिक्षण एक अभिन्न अंग बन गया है। अप्रैल, 2005 से मार्च, 2006 तक विदेश सेवा संस्थान ने छह मूल व्यावसायिक पाठ्यक्रम आयोजित किया।

"प्रतिनिधित्व कौशल एवं शिष्टाचार" पर विदेश सेवा संस्थान को मिशन प्रमुखों/केन्द्र प्रमुखों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का भी दायित्व सौंपा गया। ऐसी पहली कार्यशाला 17-19 जून, 2005 को आयोजित की गई।

विशेष आयोजनः भूतपूर्व विदेश सचिव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सहालकार श्री जे. एन. दीक्षित की मृत्यु की प्रथम पुण्यतिथि का समारोहपूर्वक आयोजन के लिए तथा "जे. एन. दीक्षित संग्रह" के उद्घाटन के लिए संस्थान के पुस्तकालय में 3 जनवरी, 2006 को एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। श्री दीक्षित ने अपनी वसीयत में अपनी व्यक्तिगत पुस्तकों के संग्रह को संस्थान के पुस्तकालय में भेंट की है।

विदेशी राजनयिकों के लिए कार्यक्रमः विदेशी राजनयिकों के लिए 38 और वां, 39 वां और 40 वां व्यावसायिक पाठ्यक्रम (पी सी एफ डी) क्रमशः 22 अगस्त-30 सितम्बर, 2005 और 9 नवम्बर-16 दिसम्बर, 2005 तक आयोजित किया गया। 40 वां पी सी एफ डी 1 फरवरी, 2006 से प्रारम्भ हुआ है। 22 देशों के 27 राजनयिकों ने 38 वें पी सी एफ डी में, 20 देशों के 24 राजनयिकों ने 39 वें, पी सी एफ डी में तथा 26 देशों के 28 राजनयिकों और अरब लीग राज्यों के दो प्रतिनिधियों ने 40 वें पी सी एफ डी में भाग लिया।

18-29 अप्रैल, 2005 को विदेशी राजनयिकों के लिए एशिया पर आयोजित चौथे उच्च पाठ्यक्रम (ए सी ए एफ डी) में 19 देशों के 20 राजनयिकों ने भाग लिया। विदेशी राजनयिकों के लिए प्रथम कूटनीति एवं विदेश नीति कार्यक्रम (डी एफ पी पी एफ डी) 17-27 अक्तूबर, 2005 तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 11 राजनयिकों ने भाग लिया। ये दोनों कार्यक्रम सेवा - कालीन/वरीय स्तर के राजनयिकों के लिए तैयार किये गए थे। वियतनाम के दस राजनयिकों तथा सूडान के बीस राजनयिकों के लिए क्रमशः 13-30 जून, 2005 तथा 26 सितम्बर - 4 नवम्बर, 2005 तक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किये गए। सिंगापुर से भारत अध्ययन दौरे पर आए वहां के विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा मूल कार्यक्रम के सदस्यों के लिए 23 सितम्बर, 2005 को भारतीय विदेश नीति पर एक वार्ता आयोजित की गई।

क्वालांलम्पुर में 13 दिसम्बर, 2005 को आयोजित चतुर्थ भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह द्वारा घोषणा किये गए प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव आसियान देशों के राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम विदेश सेवा संस्थान के माध्यम से संचालित किया जाना था। यह विशेष पाठ्यक्रम आसियान सचिवालय के समन्वय से आयोजित की जाने की प्रक्रिया में है।

वर्ष के दौरान सांस्थानिक संपर्कों के रूप में विदेश सेवा संस्थान तथा नार्वे, सऊदी अरब, मेक्सिको और इंडोनेशिया के समकक्ष संस्थानों के बीच सहयोग का ढांचा प्रदान करने वाली करार/समझौता - ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। बोत्सवाना के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव मि. अर्नेस्ट एस. म्पोफु, मेक्सिको के विदेश मंत्रालय के अवर सचिव, मा. डि लुर्डेस अरांडा बिजौरी, और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामरिक अध्ययन केन्द्र के प्रमुख मि. अमानुल्लाह रूश्ताकी के साथ मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर, सूचनाओं के आदान-प्रदान पर तथा विशेषज्ञों/अधिकारिं के आदान-प्रदान पर विचार-विमर्श किया गया।

■■

21 राजभाषा नीति का अनुपालन तथा विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार

विदेश मंत्रालय विदेशों में अपने मिशन/केन्द्रों के साथ-साथ अपने कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा हिन्दी के उन्न्यन और प्रचार-प्रसार के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही यह मंत्रालय विदेशों में भी हिन्दी के उन्नयन और प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

द्विपक्षीय संधियां, करार, समझौता ज्ञापन, प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण, लोक लेखा समिति के पैराग्राफ, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जाने वाले संसदीय प्रश्न द्विभाषी रूप में जारी किये जा रहे हैं। हिन्दी, विदेश सेवा संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है। नव-प्रशिक्षुओं को उनके विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सरकार की राजभाषा नीति तथा उसके कार्यान्वयन (नियम एवं विनियम) पर गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति समय-समय पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण करती है।

विदेशों में हिन्दी का उन्नयन तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विदेशों के विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में रखे गए 12 पीठों के लिए विजिटींग हिन्दी प्राध्यापक प्रतिनियुक्त करती है। कई देशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की गई है जो हिन्दी के उन्नयन तथा प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करते हैं। भारत के सक्रिय सहयोग से मारीशस में एक विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना की जा रही है। इसके शासी निकाय तथा कार्यकारी बोर्ड का गठन हो चुका है और मारीशस द्वारा महासचिव एवं भारत द्वारा उप महासचिव मनोनीत किये जाने के बाद इसकी पहली बैठक आयोजित की जाएगी।

विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र विदेशी राष्ट्रिकों को हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिसके लिए स्थानीय हिन्दी शिक्षण कक्षाएं आयोजित की जाती है। विदेश स्थित मिशनों/केन्द्र को वित्तीय सहायता प्रदान कर तथा पाठ्यपुस्तकों, शब्दकोषों, श्रव्य-दृश्य कैसेट,कम्प्यूटर साफ्टवेयर, सीडी - रोम, हिन्दी पत्रिकाएं एवं बालसुलभ साहित्य इत्यादि दानस्वरूप भेंट कर विदेशों में हिन्दी के उन्नयन एवं शिक्षण कार्य में लगी स्थानीय संगठनों को सहायता दी जाती है। विशिष्ट हिन्दी शिक्षण किट भी मिशन/केन्द्र को उपलब्ध कराए गए हैं जिसकी काफी मांग है। केंद्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए हिन्दी सीखने में तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में हिन्दी सीखने के लिए शिक्षावृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए मिशन/केन्द्र विदेशी राष्ट्रिकों को प्रोत्साहित करती है।

विदेशों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय दिवसों पर अधिकांश मिशन/केन्द्र द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधित राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण को हिन्दी में पढ़ा जाता है। भारतीय समुदाय के स्थानीय सदस्यों की भागीदारी से हिन्दी में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। हिन्दी दिवस समारोह के आयोजन के साथ-साथ मिशनों/केन्द्रों द्वारा साहित्यिक कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिताएं तथा कवि सम्मेलन भी आयोजित किये जाते हैं। कुछ भारतीय मिशन हिन्दी में पत्रिकाएं भी निकालते हैं। समय-समय पर विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिए विदेशों में हिन्दी सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। 4 और 5 फरवरी, 2006 को एशिया पैसिफिक देशों का क्षेत्रीय हिन्दी सम्मेलन सिडनी में आयोजित किया गया जिसमें क्षेत्र की भाषाओं को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की गई। स्थानीय भाषा से हिन्दी में तथा हिन्दी से वहां की स्थानीय भाषा में अनुवाद करने के लिए 32 देशों में हिन्दी दुभाषिया का पैनल बनाया गया है।

संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को एक भाषा के रूप में लागू कराने के लिए विदेश राज्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति द्वारा एक समर्थन दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और इस संबंध में रचनात्मक बैठकें आयोजित की गई है।

■■

सांस्कृतिक संबंध

22

भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और पारस्परिक समझ को स्थापित और सुदृढ़ करने तथा उन्हें पुनरूज्जीवित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की औपचारिक रूप से 1950 में स्थापना की गई थी।

परिषद के मुख्य क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं :

भारत सरकार और अन्य अभिकरणों की ओर से विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रशासन तथा अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का कल्याण;

भारतीय नृत्य और संगीत सीखने के लिए विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना;

प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान;

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और परिसंवादों का आयोजन एवं उनमें भाग लेना;

विदेशों में प्रमुख सांस्कृतिक समारोहों में भाग लेना;

विदेशों में "भारत उत्सव" का आयोजन;

मंचीय कलाकारों का आदान-प्रदान;

विदेशों में मंचीय कलाकारों द्वारा प्रदर्शनों का आयोजन;

विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम, जिसके तहत प्रसिद्ध व्यक्तियों को भारत आने का निमंत्रण दिया जाता है और अनेक मुद्दों पर व्याख्यान देने के लिए विशेषज्ञों को विदेश भेजा जाता है;

विदेशों में भारतीय अध्ययन पीठों की स्थापना और प्रचालन;

विदेशी संस्थानों को पुस्तकों, श्रव्य दृश्य सामग्री, कलाकृतियों और वाद्य यंत्रों को उपहार स्वरूप देना;

अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिये जाने वाले जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के लिए सचिवालय उपलब्ध कराना;

वार्षिक मौलाना आज़ाद स्मृति व्याख्यान और मौलाना आज़ाद निबंध-प्रतियोगिता का आयोजन;

भारत और विदेशों में वितरण हेतु पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन;

विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों को बनाए रखना;

एक समृद्ध पुस्तकालय और मौलाना अबुल कलाम आजाद की पांडुलिपियों का रख-रखाव;

दुर्लभ पांडुलिपियों का अंकीयकरण;

परिषद ने 11 नवम्बर, 2005 को अपने संस्थापक अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद की 115 वीं वर्षगांठ मनायी। भा.सा.सं.प. के 9 क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई और तिरूवनंतपुरम के कार्यरत हैं।

विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र और पीठ

विदेशों में भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए परिषद विदेशों में 18 भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों और 19 भारतीय अध्ययन पीठों का संचालन करती है।

18 सांस्कृतिक केन्द्र काहिरा (मिस्र), बर्लिन (जर्मनी), पोर्ट लुई (मारीशस), पारामारिबो (सूरीनाम), जार्जटाउन (गुआना), जकार्ता (इंडोनेशिया), मास्को (रूसी परिसंघ), लंदन (यू के) अल्माती (कजाकिस्तान), ताशकन्द (उजबेकिस्तान), डरबन और जहानसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिडाड एण्ड टोबौगो), कोलंबो (श्रीलंका), दुशान्वे (ताजिकिस्तान), कुआलालम्पुर (मलेशिया), सूवा (फिजी) और टोक्यो (जापान) में और दो उप केन्द्र बाली (इंडोनेशिया) और लौटोका (फिजी) में हैं। परिषद ढ़ाका (बंगलादेश) में संगीत और नृत्य अकादमी का वित्तपोषण भी करती है। परिषद ने काबुल, काठमान्डू, वाशिंगटन और मध्य-पूर्व में नये केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

विदेशों में भारतीय अध्ययन पीठों के संचालन का उद्देश्य हिंदी, संस्कृत, तमिल, आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता का शिक्षण है। ये पीठ निम्नलिखित देशों में है मास्को

(रूस), बुडापेस्ट (हंगरी), मास्को (रूस) सिओल (दक्षिण कोरिया), वारसा (पोलैंड), पोर्ट ऑफ स्पेन (ट्रिनिडाड एण्ड टोबैगो), अंकारा (तुर्की), सोफिया (बुल्गारिया), बुखारेस्ट (रोमानियाँ), बीजिंग (चीन), मैड्रिड (स्पेन), बैंकाक (थाइलैंड), पेरिस (फ्रांस), ओश (किर्गिस्तान), ताशकन्द (उजबेकिस्तान), ब्रसल्स (बेल्जियम) और मोका (मारीशस)। परिषद ने सेमेस्टर आधार पर हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी में और मंगोलिया तथा पोलैंड में रोटेटिंग पीठों की स्थापना की। सिरेइसे पो,पेरिस और लेइडेन, नीदरलैंड में लघु - आवधिक प्रोफेसरशिप के संबंध में भी कार्रवाई की गयी।

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र वार्ता, व्याख्यान, दृश्य कलाओं की प्रदर्शनियों, निबंध प्रतियोगिताओं, नृत्य एवं संगीत कार्यक्रमों, नाटकों, फिल्म प्रदर्शनों,समाचार बुलेटिनों का प्रकाशन, सेमिनारों इत्यादि का आयोजन करते हैं। वे भारतीय संगीत, नृत्य, तबला और योग सिखाने के लिए नियमित कक्षांए भी चलाते हैं। वे केन्द्र आगंतुकों के लिए पुस्तकालयों, वाचनालयों और श्रव्य-दृश्य श्रव्य-दृश्य पुस्तकालय भी संचालित करते हैं। इन केन्द्रों ने अपने प्रत्यायन के देश में छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों, मत - निर्माताओं और संस्कृति से जुड़े व्यक्तियों सहित उस देश के विभिन्न वर्ग के नागरिकों के साथ अपना नटवर्क बनाया है। इस कार्य का उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक धरोहर की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करना है।

छात्रवृतियाँ

भा. सां. सं. प. की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृति योजना का क्रियान्वयन। परिषद स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रमों के लिए तथा साथ ही इंजीनियरिंग, फार्मेसी, व्यापार प्रशासन, प्रबंधन और लेखाविधि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृति योजनाओं का संचालन करती है। इस वर्ष भा. सा. सं. पं की विभिन्न योजनाओं और विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय की और से एजेंसी कार्यों के अंतर्गत 60 देशों के छात्रों को 1264 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गयीं। भा सा. सं. प. की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत कुल 732 छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा ली जबकि विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के लिए किये गये एजेंसी कार्यों के तहत 34 छात्रों ने अध्ययन किया।

भा. सां. सं. प. ने अफगानी छात्रों के लिए 500 नई छात्रवृत्तियों का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी ली है।

छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रशासन और क्रियान्वयन के अतिरिक्त परिषद स्व-वित्त पोषित योजनाओं और भा. सां. सं. प. की छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत भारत में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों के सामान्य हित-कल्याण पर भी निगरानी रखती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिषद ने मई - जून, 2005 में विदेशी छात्रों के लिए शिमला-कुल्लु -मनाली में ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन किया। परिषद ने निम्नलिखित स्थानों पर पांच शीतकालीन शिविर भी आयोजित कियेः चेन्नई, पांडिचेरी/तंजोर/मदुरई/कोडाइकनाल; कन्याकुमारी; बीकानेर/जयसलमेर/जोधपुर/उदयपुर/चित्तौरगढ़/अजमेर/; ग्वालियर/ओरछा/खजुराहो/बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान/जबलपुर/ शिवपुरी/ग्वालियर/मम्बई/पुणे/औरंगाबाद/अजन्ता/एलोरा; और मुम्बई/गोवा। विदेशी छात्रों द्वारा इन शिविरों का स्वागत हुआ और उन्होंने इनमें बड़ी संख्या में भाग लिया। वृत्तिभोगियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परिषद ने विदेशी छात्रों के लिए ए टी एम कार्ड की सुविधा भी मुहैया करायी है।

परिषद ने 20 दिसम्बर, 2005 को हंसध्वनि थिएटर, प्रगति मैदान में 13 वें अंतरराष्ट्रीय छात्र महोत्सव का भी आयोजन किया।

प्रदर्शनियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद ने आठ अर्ध प्रतिमाओं का निर्माण करके उन्हें स्थायी रूप से स्थापित किये जाने के लिए विदेश भेजी। इनमें महात्मा गाँधी की चार, रवीन्द्रनाथ टैगोर की तीन और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक आवक्ष प्रतिमा शामिल थी। इन्हें वर्ष 2005-06 के दौरान अल्माती (कजाकिस्तान), ब्रसल्स (बेल्जियम), निकोसिया (साइप्रस), बेलग्रेड (सर्बिया मोंटनेगरो), बर्लिन (जर्मनी), बुडापेस्ट (हंगरी), टोरंटो (कनाडा) और लंदन (यू के) में स्थापित किया जाएगा।

इस वर्ष के दौरान परिषद ने विदेशों में तीन प्रदर्शनियाँ आयोजित की जिनके शीर्षक थे "सेलेब्रिटिंग वूमन - अमृता शेरगिल रीविजिटेड" - रूस और ताजिकिस्तान के लिए; 'दी एक्जिवीशन ऑफ कंटेम्प्ररी ग्राफिक प्रिंट्स' - अर्जेन्टीना, ब्राजील और सीरिया के लिए तथा; वूमन बाय वूमन - डरबन, केप टाउन, जोहान्नसबर्ग और प्रीटोरिया, दक्षिण अफ्रीका के लिए।

भा. सां. सं. प. ने विदेश में दो अन्य प्रदर्शनियों का प्रायोजन भी किया। पहला श्री जतिन दास की हाथ से बनाये गये पंखों पर कुआलालम्पुर (मलेशिया) और मनीला (फिलीपींस) के लिए तथा दूसरा श्रीमती अमीना आहुजा की कैलिग्राफिक चित्रकारी पर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद (पाकिस्तान)

के लिए। परिषद ने विदेशों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए कुछ कलाकारों को यात्रा अनुदान/हवाई किराया भी दिया।

परिषद ने मोजाम्बिक (सिल्वेरियो सल्वाडोर सितोए) और बंगलादेश (प्रो. मो. किबरिया) के विदेशी कलाकारों की प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया।

सृजनात्मक वार्ता

परिषद ने नई दिल्ली में 4 और 5 सितम्बर, 2005 को "भारत-थाईलैंड ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संपर्क" पर थाईलैंड के शाही दूतावास के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन किया।

पहले भारत विद्या सम्मेलन का सफल आयोजन 15-17 सितम्बर, 2005 तक वारसा विश्वविद्यालय, वारसा में भारतीय दूतावास के सहयोग से किया गया। सम्मेलन में इस क्षेत्र के 22 भारत विद्या से जुड़े विद्वानों ने भाग लिया।

परिषद ने नीमराना पहल के अंतर्गत 3-4 दिसम्बर, 2005 तक 14 सदस्यीय पाकिस्तानी शिष्टमण्डल की मेजबानी की।

परिषद ने 6-14 दिसम्बर, 2005 तक दक्षिण अफ्रीका के आर्कविशप डेसमंड टुटु की यात्रा की मेजबानी की।

विदेश जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमण्डल

वर्ष 2005-06 के दौरान परिषद ने विश्व के सभी क्षेत्रों के 3 देशों के लिए 72 सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों को प्रायोजित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा स्थानीय कलाकारों के साथ कार्यशाला एवं व्याख्यान के आयोजन पर विशेष बल दिया गया। विदेशों में कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संख्या में युवा कलाकारों और देश के विभिन्न भागों से लोक मंडलियों को विदेशों में कार्यक्रम के लिए प्रायोजित किया गया।

इनमें से कुछ सांस्कृतिक मंडलियों ने बड़े कार्यक्रमों/महोत्सवों में भाग लिया - यथा, उत्तरी कोरिया में अप्रैल स्प्रिंग उत्सव, संयुक्त अरब अमीरात में हेरिटेज इन्डिया फेस्टिवल, जापान में अकी वर्ल्ड एक्सपो, अमरीका में ह्यूस्टन उत्सव, जिम्बाबवे में हरारे अंतरराष्ट्रीय उत्सव और ट्रिनिडाड एण्ड टोबैगो में भारतीयों के आगमन की 160 वीं वर्षगांठ। निम्नलिखित के दौरान संगीत और नृत्य के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया - भारत के राष्ट्रपति की आइसलैंड की यात्रा, जांजीबार अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय व्यापार प्रदर्शनी पोलैंड, मिलान उत्सव नीदरलैंड, अंतरराष्ट्रीय रोमा संगीत एवं नृत्य उत्सव बुल्गारिया, भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50 वीं वर्षगांठ, रूस-भारत संयुक्त संगीत युगलबंदी, पारंपरिक कला उत्सव डरबन, दक्षिण अफ्रीका, बभारिया (जर्मनी) में भारत सप्ताह, स्पेन में कासा एशिया उत्सव, थाईलैड में अंतरराष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत उत्सव, भूटान में इमतरात स्थापना दिवस समारोह, चीन में सांतवां एशियाई कला महोत्सव, जोर्डन में विश्व सांस्कृतिक मंच - 2005, जर्मनी में डी आई जी पीठ यात्रा और आस्ट्रिया में एलेगरो विवो इन्टरनेशनल कम्मेर संगीत उत्सव इत्यादि।

जरूरतमंद कलाकारों को यात्रा अनुदान दिये गये जैसे कि 9 सदस्यीय समारतानम मंडली (विकलांग) को अमरीका जाने के लिए, और श्री गायत्री शंकरन (दृष्टिहीन महिला कलाकार) को यू के एवं कनाडा जाने के लिए और श्री फयाज वसीफुद्दीन डागर को अमरीका जाने के लिए यात्रा अनुदान दिये गये।

भारत आने वाले सांस्कृतिक शिष्टमण्डल

भा.सां.सं.प. भारत के विभिन्न नगरों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए विदेशी मंचीय कलाकारों की यात्राओं का आयोजन करती है। इन मंडलियों की मेजबानी द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत और साथ ही विदेश स्थित भारतीय मिशनों की अनुशंसाओं तथा भारत स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों और सांस्कृतिक केन्द्रों के अनुरोध पर की जाती है। भारतीय कला स्वरूप की अपनी दो श्रृंखलाओं "होरायजंस" और "रेट्रोस्पेक्टिब्स" के अंतर्गत परिषद ने नई दिल्ली और अन्य शहरों में उदीयमान और उत्कृष्ट कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित किये।

अप्रैल - दिसंबर, 2005 के दौरान परिषद ने वियतनाम, सूडान, रूस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से सात विदेशी सांस्कृतिक मंडलियों के दौरों की मेजबानी की।

परिषद ने 24-28 अक्टूबर, 2005 तक "बिल्डिंग ब्रिजेज" नामक पांच दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव और 7-8 नवम्बर, 2005 तक "दी स्पिरिट ऑफ बनारस" नामक तीन दिसवीय उत्सव का आयोजन कमानी सभागार, नई दिल्ली में किया। विदेशी मंडलियों ने जयपुर, चंडीगढ़ बंगलौर ग्वालियर सहित अन्य शहरों में भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किये।

अपनी "रेट्रोस्पेक्टिब्स" श्रृंखला के अंतर्गत परिषद ने उभरते कलाकारों के कार्यक्रम भी आयोजित किये। 5-7 सितम्बर, 2005 तक तीसरे ठुमरी उत्सव, 6-8 अगस्त, 2005 तक चौथे मल्हार उत्सव और 22-24 जून, 2005 तक श्रीनगर में सूफी उत्सव का आयोजन किया।

भारत आने वाले और विदेश जाने वाले व्यक्ति

भा.सां.सं.प. ने विशिष्ठ अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत विद्वानों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को सुकर बनाना जारी रखा। विदेशी दौरों के लिए प्रायोजित विशिष्ट व्यक्तियों में शामिल थे - श्री गोपी कृष्णन, कोत्तूर, कलाकार, चेन्नई 15-30 मई, 2005 तक "विदेशी कवियों पर सेमिनार" में भाग लेने के लिए जर्मनी और आस्ट्रिया का दौरा; डा. गिरीश नाथ झा, सहायक प्राध्यापक, जे एन यू, 1-3 जून,2005 तक "एशिया लेक्स सम्मेलन" में भाग लेने के लिए सिंगापुर का दौरा; प्रो. सत्यव्रत शास्त्री, संस्कृत विद्वान नई दिल्ली, 4 और 5 जून, 2005 तक "दूसरे अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमरीका की यात्रा; 22-27 जून, 2005 तक" अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 विद्वानों की थाइलैंड की यात्रा; डा. रूप किशोर शास्त्री, प्रमुख, वेद विभाग, गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार और डा. पी के श्रीवास्तव, 12-19 जुलाई, 2005 तक "वेदों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनिशिया की यात्रा; डा. अमिताभ चक्रवर्ती, वरिष्ठ व्याख्यता, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर त्रिपुरा पश्चिम, 13-16 जुलाई, 2005 तक" अलंकार शास्त्र के इतिहास से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय सोसायटी के 15 वें द्विवार्षिक सम्मेलन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अमरीका का दौरा; डा. गीति सेन, इन्डिया इन्टरनेशनल सेंटर पब्लिकेशन में मुख्य सम्पादक और सांस्कृतिक इतिहासकार एवं आलोचक, दिल्ली, 4-25 सितम्बर, 2005 तक "राष्ट्र का इतिहास," राष्ट्रीय संस्कृति की बदलती कार्यसूची पर व्याख्यान देने के लिए यू के, हंगरी, आयरलैंड और स्पेन की यात्रा; डा. सी राजेन्द्रन, संस्कृत प्राध्यापक, कालीकट विश्वविद्यालय, केरल, 22 सितम्बर - 2 अक्तूबर, 2005 तक "काव्य साहित्य में प्रकृति और प्रेम" और शाब्दिक प्राधिकार पाठ भाग और ज्ञान के आरंभिक वर्गीकरण पर क्राकोव में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिए पोलैंड का दौरा किया; प्रोफेसर गिरिजेश पंत, अध्यक्ष पश्चिमी एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान,जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 28-30 सितम्बर, 2005 तक अरब सांस्कृतिक अकादमी द्वारा आयोजित सेमिनार "विश्व शांति स्थापना में सांस्कृतिक क्रियाकलाप की भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन " में भाग लेने के लिए; श्री पचोम पोयिल राजीवन, जन-संपर्क अधिकारी, कालीकट विश्वविद्यालय 6-8 अक्तूबर, 2005 तक वारसा काव्य उत्सव में भाग लने के लिए पोलैंड का दौरा; सुश्री लतिका पडगांवकर, फिल्म आलोचक, नई दिल्ली, 14-22 अक्तूबर, 2005 तक मनीला में आयोजित 7 वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने के लिए फिलीपींस का दौरा।

इस वर्ष भा.सां.सं.प. ने जिन विशिष्ठ व्यक्तियों का भारत में स्वागत किया वे हैं : प्रो. गुराम चिकोवानी, भारतीय भाषा और संस्कृति केन्द्र, रिबलिसी, जार्जिया के मानक अध्यक्ष और संस्थापक, 18-24 अप्रैल, 2005; श्री नजीब बलाल, केन्या के माननीय राष्ट्रीय धरोहर राज्य मंत्री, की 3-8 जून, 2005 तक की सद्भावना यात्रा के लिए; डा. ओवेन बेन सिचोन, समाज नृविज्ञान विभाग, केप टाउन विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नेल्सन मंडेला पीठ संभालने के लिए, 19 अगस्त-5 दिसम्बर, 2005, तक; श्री तंजीम अहमद, सांसद, बंगलादेश, 2-7 अक्तूबर, 2005 तक जाम्बिया की प्रथम महिला श्रीमती माउरीन म्वानावासा और छह सहयोगी 8-15 अक्तूबर, 2005 तक; पीकींग विश्वविद्यालय चीन के हिंदी विभाग के छात्र और तान युनशाल पुरस्कार प्राप्त श्री सुन जिआनफेंग, 4-18 दिसम्बर, 2005 तक और ब्रसल्स ललित कला केन्द्र के महाप्रबंधक और बोजर महोत्सव के महानिदेशक श्री पॉल दुजार्दिन की यात्रा।

प्रकाशन

परिषद पांच विभिन्न भाषाओं में छह पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है नामत; "इन्डियन होरायजंस" और "अफ्रीका क्वार्टरली" (अंग्रेजी); "गंगनाञ्चल" (हिंदी); "पेपेलेस डी ला इन्डिया" (स्पेनिश); "रिकोन्ट्रे एवेल एल इन्डे" (फ्रेंच); और "तकाफत्-उल-हिंद" (अरबी)। "इन्डियन होरायजंस", 'गंगनाञ्चल' और "अफ्रीका क्वार्टरली" को नये स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस वर्ष के दौरान परिषद ने "ऐट होम इन दी वर्ल्ड" का प्रकाशन किया। तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह ने 6 सितम्बर, 2005 को होटल ताज महल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में इस पुस्तक का विमोचन किया। परिषद ने "बायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू" (अरबी), "इन्डिया विंस फ्रीडम" (फ्रेंच), और मनु मित्तल द्वारा सम्पादित "इन दी सोल्स ट्वायलाइट" जैसी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया।

परिषद ने 'ऋषि' नाम हिंदी भाषा शिक्षण साफ्टवेयर का भी विकास किया।

प्रस्तुतियॉ

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों के जरिए अफगानिस्तान, आर्मेनियाँ, आष्ट्रेलिया, भूटान, बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, फिजी, फिनलैंड, जर्मनी, गुयाना,

हंगरी, ईरान, कोरिया, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मारीशस, नाईजीरिया, नामीबिया, नेपाल, पोलैंड, पनामा, रूस, सूरीनाम, सेनेगल, श्रीलंका, ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो, ताजिकिस्तान, तंजानियाँ, तुर्की, लीबिया, यू.के., अमरीका, उक्रेन और बेनेजुएला सहित 36 देशों में पुस्तक कलाकृतियाँ, श्रव्य-दृश्य सामग्री, वाद्य यंत्र आदि भेजीं जो अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, स्थानीय उच्चाधिकारियों, पुस्तकालयों और संस्थानों को उपहार स्वरूप दी जाती हैं।

पुस्तकालय

इस वर्ष के दौरान परिषद ने भा.सां.सं.प. के पुस्तकालय में मौलाना आजाद के संग्रह (गोशा-ए-आजाद) में उपलब्ध पांडुलिपियों और दस्तावेजों के अंकीयकरण पर कार्य किया और 100 पुस्तकों का अंकीयकरण किया गया। वर्ष 2005 के दौरान पांच विद्वानों को पुस्तकालय फेलोशिप प्रदान किये गये। इस अवधि के दौरान 2700 आगंतुक पुस्तकालय में आये।

लेखे

सामान्य गतिविधियों के प्रचालन के लिए भा.सां. सं.प. का वर्ष 2005-06 का संशोधित बजट अनुमान 5760.00 लाख रू. का है और वर्ष 2005-06 के लिए प्रस्तावित संशोधित अनुमान 6470.00 लाख रू. है। इस वर्ष अनुमानित प्राप्तियाँ 50.00 लाख रू. की हैं।

वेबसाइट

परिषद की वेबसाइट www.iccrindia.org का उद्घाटन 11 नवम्बर, 2005 को किया गया।

■■

23 इंडिया काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स

भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से इंडिया काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की स्थापना 1943 में की गई थी। देश में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए यह एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित केन्द्र है। संसद के अधिनियम, 2001 का अधिनियम सं. 29 तथा (संशोधन अधिनियम) 2004 का सं. 5 के द्वारा आई सी डब्ल्यू ए को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। आई सी डब्ल्यू ए ने अपने अधिदेश के अनुसरण में, क्रियाकलापों का एक ओजस्वी कार्यक्रम आरम्भ किया है। इसका लक्ष्य, अपनी संगोष्ठियों, प्रकाशनों, व्याख्यानों और विशेषीकृत पुस्तकालय के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली की जटिलताओं की मूल समझ की जानकारी प्रदान करना है।

सप्रू हाऊस बिल्डिंग

अनेक सिविल मरम्मत कार्य आरम्भ किये गए और उन्हें जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। सप्रू हाऊस को, राष्ट्रीय महत्व के किसी संस्थान को इसमें स्थापित करने के लिए यथोचित दर्जा दिया जा रहा है।

सहायता अनुदान

आईसीडब्ल्यूए के लिए वर्ष 2005-06 के लिए 1.80 करोड़ रूपए के सहायता अनुदान का अनुमान लगाया गया और उसे अनुमोदित किया गया।

संस्थागत संबध

आई सी डब्ल्यू ए तथा चीन लोक गणराज्य की चीनी पिपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बीच सहयोग के समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में 11 अप्रैल, 2005 को हस्ताक्षर किये गए।

प्रकाशन

परिषद अपने आवधिक प्रकाशनों, इण्डिया - क्वार्टरली और फॉरेन अफेयर्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

एशिया पेसिफिक में सुरक्षा और सहयोग परिषद भारत का सचिवालय और अफ्रीका केन्द्र

एशिया पेसिफिस में सुरक्षा और सहयोग परिषद, भारत के सचिवालय को सप्रु हाऊस में पुनर्स्थापित किया गया है। परिषद ने कई पैनल चर्चाएं आयोजित की और "जैवीय आतंकवाद एवं जैविक संरक्षा" पर एक पुस्तक का लोकार्पण किया। साथ ही इसने "एशिया पैसिफिस में सुरक्षा के गैर-पारंपरिक खतरों" पर पैनल चर्चा आयोजित की। "समाप्त करने से पूर्व क्या आतंकवाद के मूल कारणों का समाधान करना आवश्यक है" विषय पर राजदूत ए. एन. राम की अध्यक्षता में सप्रू हाउस में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इन चर्चाओं और संगोष्ठियों में प्रतिष्ठित पत्रकारों और शिक्षाविदों ने भाग लिया।

पुस्तकालय

मरम्मत, नवीकरण, स्थान - विस्तार के बाद सप्रू हाऊस के पुस्तकालय को वातानुकूलित किया गया और इसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के लिए एक संदर्भ पुस्तकालय के रूप में उपयोग किए जाने के लिए बेहतर बनाया गया। इस अवधि के दौरान 226 शीर्षकों पर पुस्तकों और धारावाहिकों को शामिल करके इसके मौजूदा अमूल्यवान संग्रह का परिवर्धन किया गया। पुस्तकालय को भारत और विदेशों से 381 शीर्षकों पर अनुसंधान पत्रिकाएं और महत्वपूर्ण दैनिक प्रकाशन प्राप्त हुए। इनमें से 202 शीर्षकों पर विख्यात पत्रिकाओं को अनुसंधानरत विद्यार्थियों के लिए समसामयिक ज्ञान सेवा के एक भाग के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व राजनीति संबंधी महत्वपूर्ण लेखों की लगभग 4000 प्रविष्टियां भारत और विदेश दोनों की अनुसंधान पत्रिकाओं से तैयार की गई। प्रयोक्ताओं के लिए संदर्भ संबंधी सहायता के एक भाग के रूप में आईसीडब्ल्यूए की अक्तूबर, 2004 से जून, 2005 की फॉरेन अफेयर्स रिपोर्ट के खण्ड 3 और 4 में प्रकाशनार्थ समसामयिक घटनाओं संबंधी विषयों की चयन सूचियां तैयार की गई।

यूएनडीपी की पूर्ण न्यासी योजना के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ, न्यूयार्क से लगभग 5512 नए दस्तावेज प्राप्त किए गए और इसके संग्रह में शामिल किए गए। इसी तरह, यूरोपीय संघ और भारत सरकार के लगभग 1436 प्रकाशन पुस्तकालय द्वारा प्राप्त किए गए और उन्हें प्रयोक्ताओं को उपलब्ध करा

गया। इसके अलावा, 8 बड़े राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और 4 क्षेत्रीय समाचार पत्रों से 31000 प्रेस क्लिपिंग चुनी गई जिसने संग्रह की संख्या को लगभग 2.9 मिलियन तक पहुंचा दिया। तत्काल संदर्भ के लिए एशियन एज, इकॉनोमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल हेराल्ड, ट्रिब्यून एवं नेशन (करांची) भी रखे गए हैं।

7900 से भी अधिक आगन्तुकों ने अपने अनुसंधान कार्य और संदर्भ के लिए पुस्तकालय का उपयोग किया। इस अवधि के दौरान 202 अनुसंधानरत विद्यार्थियों,विषय विशेषज्ञों, पत्रकारों को पुस्तकालय के सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अनुसंधानरत विद्यार्थियों ने अपने अनुसंधान कार्य के लिए पुस्तकालय सामग्री का उपयोग किया। महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बरहामपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, कर्नाटक विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, लखनऊ विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय सम्मलित थे।

अफ्रीकी राष्ट्रों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए पुस्कालय में विशेष रूप से बनाए गए अफ्रीका केन्द्र में महत्वपूर्ण पठन सामग्री को शामिल किया गया।

पुस्तकालय का स्वचलन कार्य प्रगति पर है। इस प्रयोजनार्थ एक पृथक मल्टीमीडिया सेक्सन भी सृजित किया गया है।

सेमिनार/गोष्ठी/सम्मेलन

आईसीडब्ल्यूए ने वर्ष 2005-06 के दौरान अनेक सेमिनार, गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किए। श्रीलंका के विरोधी दल के नेता श्री रानिल विक्रमसिंघे, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री आई. के. गुजराल तथा मेक्सिकों के विदेशी संबंधों के उपमंत्री सुश्री लुर्डेस अराण्डा बिजौरी द्वारा विशेष व्याख्यान दिये गए। सम्पूर्ण सूची **परिशिष्ट-XIX** पर दी गई है।

■■

24 विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस)

आर आई एस नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध एवं विकास सहयोग का विशेषज्ञ है। आरआईएस विदेश मंत्रालय का स्वायत्त निकाय है। इसका अधिदेश समय-समय पर संदर्भित क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय सहयोग व्यवस्था सहित बहुपक्षीय आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर भारत सरकार की सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करना है। आईआरएस की कल्पना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के थिंक टैंक के बीच कारगर नीति वार्तालाप को पोषित करने वाले मंच के रूप में की गई है।

सरकार को उपलब्ध कराई गई अनुसंधान और नीतिगत सूचना सामग्रियांः

आरआईएस ने नीति निर्माण तथा वर्ष में आयोजित प्रमुख शिखर बैठकों एवं अन्य वार्ताओं के लिए तैयारी में मदद के लिए अनुसंधान अध्ययन किए। इनमें से कुछ निवेश निम्नवत हैंः-

- **पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान-भारत शिखर सम्मेलनः**

  आरआईएस भारत-आसियान साझेदारी को अनुसमर्थित करता रहा है तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की तैयारियों में सरकार की मदद करता रहा है। 19 अप्रैल, 2005 को भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पर एक नोट विदेश मंत्रालय को भेजा गया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और एशियाई आर्थिक समुदाय पर एक अन्य नोटः चर्चा के लिए नोट 5 मई 2005 को विदेश मंत्रालय को भेजा गया तथा 9 मई 2005 को आयोजित अंतर-मंत्रालयीय बैठक में इस पर चर्चा हुई जिसकी अध्यक्षता सचिव (पूर्व) ने की।"एशियाई आर्थिक समुदाय की ओर " पर एक संकल्पना कागजात तैयार किया गया और भारत-आसियान वरिष्ठ अधिकारी बैठक के लिए 17 मई, 2005 को विदेश मंत्रालय को भेजा गया। आरआईएस ने भारत की पूर्वी नीति और पूर्वोत्तर भारत पर (8 जून, 2005 को) और विश्व और एशिया में क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाः भारत के लिए विकास (11 जून 2005 को) पर नोट तैयार करके प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद को प्रदान किया। तदनंतर "पूर्वी एशिया के साथ भारत का आर्थिक एकीकरणः एशिया के लिए जीत " और "ईएएस रीजन में विद्यमान एफटीए/आरटीए" पर नोट 25 नवम्बर, 2005 को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए निवेश के रूप में विदेश मंत्रालय को भेजे गए। आरआईएस ने एशियाई आर्थिक समुदाय की ओरः पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा" पर एक पुस्तिका भी तैयार किया जिसे दिसम्बर, 2005 में क्वालालंपुर में पहले ईएएस में आग लेने वाले शिष्टमंडलों को भारत द्वारा परिचालित किया गया। आरआईएस ने इस अवसर पर एक अन्य खंड भारत-आसियान आर्थिक संबंधः भूमंडलीकरण की चुनौतियों को पूरा करनाः भी जारी किया।

- **सार्क सम्मेलन और साफ्टा वार्ता**

  आरआईएस सार्क प्रक्रिया के लिए नियमित रूप से सूचनाएं प्रदान करता रहा है।"साफ्टा को मूर्त रूप देनाः कुछ मुद्दे" और साफ्टा और इससे परेः दक्षिण एशिया के विकास के लिए क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की क्षमता का दोहन " पर नोट 27 जनवरी, 2005 को विदेश मंत्रालय को भेजे गए।"दक्षिण एशियाई आर्थिक संघः भारत -श्रीलंका साझेदारी की भूमिका " पर एक नोट तैयार करके 29 अगस्त, 2005 को विदेश मंत्रालय को भेजा गया। "साफ्टा और इससे परेः सार्क आर्थिक सहयोग के लिए एजेंडा " पर नोट 28 जनवरी, 2005 को पीएमओ को भेजा गया। इसके अलावा "दक्षिण भारत में आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग " और "साफ्टा तथा इससे परेः सार्क के लिए एजेंडा " पर नोट सार्क शिखर सम्मेलन की तैयारी हेतु सूचना सामग्री के रूप में पीएमओ को 3 नवम्बर, 2005 को उपलब्ध कराया गया।

- **भारत-जापान संयुक्त अध्ययन समूहः**

  भारत-जापान संयुक्त अध्ययन समूह के लिए निवेश के रूप में विस्तृत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के निर्माणकारी

ब्लाक के रूप में भारत-जापान आर्थिक सहयोग पर एक नोट 13 जुलाई, 2005 को आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया। "भारत-जापान आर्थिक सहयोग का संदर्भ " पर प्रारूप अध्याय 1 तथा अध्याय 4 (निवेश) की टीकायुक्त आनलाइन भारत-जापान संयुक्त अध्ययन समूह के लिए निवेश के रूप प्रदान किया गया तथा इन्हें 29 सितम्बर, 2005 को विदेश मंत्रालय को भेजा गया। तदनंतर अध्याय 2: माल व्यापार और अध्याय 6: सहयोग के अन्य क्षेत्र तथा अध्यायः 8 सीईसीए/ईपीए का प्रारूप तैयार करने के लिए भी आरआईएस से अनुरोध किया गया।

- **भारत-कोरिया संयुक्त अध्ययन समूहः**

  आरआईएस का भारत-कोरिया जेएसजी में प्रतिनिधित्व रहा है तथा इसकी बैठकों में इसने हिस्सा लिया है। जेएसजी रिपोर्ट का व्यापार एवं सेवा नामक अध्याय आरआईएस ने तैयार किया है।

- **हांगकांग मंत्री स्तरीय सम्मेलनः**

  आरआईएस ने डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय सम्मेलनों अर्थात दोहा दौर का विकास प्रभावः अभिलाभ और वास्तविक लागत का घटना, दोहा को वस्तुतः विकास दौर बनाना, और व्यापार सुविधाः पैगमेटिजम और काशन के बीच संतुलन लाने की आवश्यकता के एजेंडा पर 3 नीति सांक्षक्तियों का सेट आरआईएस ने तैयार करके जारी किया।

- **विदेश व्यापार नीतिः**

  "रोजगारोन्मुख निर्यात नीति की ओर" पर अध्ययन की प्रारंभिक रिपोर्ट 8 अप्रैल, 2005 को घोषित विदेश व्यापार नीति की तैयारी में निवेश के रूप में तैयार की गई। तदनंतर जून, 2005 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

- **भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका त्रिपक्षीय आयोगः**

  आरआईएस आईबीएसए वार्ता में मदद करता रहा है। भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका आर्थिक सहयोगः व्यापक आर्थिक साझेदारी पर एक नोट 25 जुलाई, 2005 को विदेश मंत्रालय को भेजा गया। इसके पश्चात भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका आर्थिक सहयोगः भावी कदम पर एक अन्य नोट 17 सितम्बर, 2005 को भेजा गया। आरआईएस ने 27-28 जनवरी, 2006 को नई दिल्ली में आयोजित व्यापार और निवेश संबंधी कार्यदल की बैठक के लिए मुख्य निवेश भी उपलब्ध कराये तथा भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में हिस्सा लिया।

इस अवधि के दौरान आरआईएस में चल रहे मुख्य शोध अध्ययन इस प्रकार हैं:

डब्ल्यूटीओ और विकासशील देशः हांगकांग मंत्री स्तरीय सम्मेलन की ओर, भारत-कोरिया गंणतत्र आर्थिक सहयोग, डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में व्यापार सुविधा, रोजगार उन्मुख निर्यात नीति की ओर, अंतर्राष्ट्रीय आहार सुरक्षा विनियमन और विकासशील देशों से प्रसंस्कृत आहार निर्यात, राष्ट्रीय जैव सुरक्षा दिशानिर्देश तथा जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकोल, भारत मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार, व्यापार वरीयताओं की वैश्विक प्रणाली तीसरा चक्र, विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट 2006, डब्ल्यूटीओ विकास चक्र वार्ता में गैर कृषि उत्पादों के लिये व्यापार पहुंच, आसियान-भारत एफटीए के तहत उत्पत्ति नियम, विभिन्न करारों को लागू करने में सावधानी पूर्ण सिद्धान्त/दृष्टिकोण का निर्वचन, और भारत-पाकिस्तान व्यापार और आर्थिक संबंधः भविष्य और चुनौतियां आदि।

नीतिवार्ता, सम्मेलन और संगोष्ठी

2005-06 के दौरान विकासशील देशों में बौद्धिक वार्ता को बढ़ावा देने संबंधी अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए आरआईएस ने अनेक नीति वार्ताओं, सम्मेलन और संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवधि में आयोजित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम नीचे दिये गये हैं:-

- **एशियाई आर्थिक समुदाय पर चौथा उच्च स्तरीय सम्मेलन, नई दिल्ली, 18-19 नवम्बर, 2005:**

  आरआईएस ने दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान, सिंगापुर के साथ मिलकर 18-19 नवम्बर, 2005 को नई दिल्ली में एशियाई आर्थिक एकताः एशियाई आर्थिक समुदाय की ओर पर चौथे उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन को सासाकावा शांति प्रविष्ठान, जापान और यूएनडीपी क्षेत्रीय केन्द्र, कोलोम्बो का समर्थन प्राप्त था। दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान, सिंगापुर के निदेशक राजदूत के0 केवशपाणी तथा सासाकावा शांति प्रतिष्ठान, टोकियो के अध्यक्ष प्रोफेसर अकिनोरीसेंकी ने उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया। सम्मेलन में एशियाई शताब्दीः भारतीय आर्थिक एकता की प्रसांगिकता, क्षेत्रीय व्यापार और निवेश उदारीकरणः

रूझान और शक्यताऐं, एशिया में वित्तीय और मौद्रिक सहयोग, एशियाई उर्जा सुरक्षा के लिये क्षेत्रीय सहयोग का भविष्य, और भारतीय अस्मिता और सामरिक मुद्दे जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के एजेन्डे पर एक गोल मेज चर्चा का भी आयोजन किया गया।

- **एशियाई आर्थिक समुदाय, आरआईएस सम्मेलन, ताईवान, चीन, 15-16 सितम्बर, 2005:**

  आरआईएस और शांक्सी वित्त और अर्थ विश्वविद्यालय, चीन ने "नए एशिया का निर्माणः एशियाई आर्थिक समुदाय" पर तीसरे-उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 15-16 सितम्बर, 2005 को तायायान, चीन में किया। सम्मेलन में एशियाई आर्थिक समुदाय की प्रासंगिकता, चीन और भारतः एशियाई विकास और समृद्धि के सह संचालक, एशियाई क्षेत्रीय एकता के ब्लाक बनाना, एशिया में मौद्रिक और आर्थिक एकताः एशियाई मुद्रा यूनिट, एशियाई आर्थिक एकता रणनीतिक महत्व जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। सम्मेलन को अनेक प्रख्यात नेताओं और विशेषज्ञों ने संबोधित किया।

- मंत्री स्तरीय डब्ल्यूटीओ हांगकांगः दक्षिण एशिया की चुनौतियां के लिए एजेंडा पर क्षेत्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली, 11-12 अगस्त, 2005:

  आरआईएस ने मंत्री स्तरीय डब्ल्यूटीओ हांगकांगः दक्षिण एशिया की चुनौतियां के लिए एजेंडा पर क्षेत्रीय सम्मेलन संयुक्त रूप से वैश्विक जैव विविधता मंच, आईयूसीएन, एशिया और भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैंबर परिसंघ के साथ मिलकर नई दिल्ली में 11-12 अगस्त, 2005 को आयोजित किया। सम्मेलन की शुरूआत डब्ल्यूटीओ व्यापार और विकास पर पैनल चर्चा के साथ हुई। दूसरे सत्र इस प्रकार थेः डब्ल्यूटीओ और कृषि, गैर कृषि बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दे, डब्ल्यूटीओ और पर्यावरणः बेहतर संबंध का सुनिश्चय, एसपीएस उपाय और विकासशील देशों की बाजार पहुंचः कार्यान्वयन मुद्दे, क्षेत्रीय फोकसः पर्यावरण, जैव विविधता और डब्ल्यूटीओ, तथा डब्ल्यूटीओ, साप्टा और पर्यावरणः क्षेत्रीय सरोकार। "जायजा लेनाः हांगकांग की ओर" पर एक पूर्ण सत्र भी था। अनेक प्रख्यात नेताओं और विशेषज्ञों ने इसे संबोधित किया।

- **अंतर्राष्ट्रीय आहार सुरक्षा विनियम तथा प्रसंस्करित आहार निर्यातः भारत और थाइलैंड का तुलनात्मक अध्ययन पर कार्यशाला, नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2005:**

  आरआईएस ने 13 अगस्त, 2005 को नई दिल्ली में आस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, मेलवोर्न विश्वविद्यालय तथा थामसट विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा वित्तपोषित "अंतर्राष्ट्रीय आहार सुरक्षा और विनियम तथा प्रसंस्कारित आहार निर्यातः भारत और थाईलैंड का तुलनात्मक अध्ययन " पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

- **दक्षिण-दक्षिण आर्थिक सहयोगः मेकोंग-गंगा संबंध की गवेषणा पर राष्ट्रीय परामर्श, नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2005:**

  आरआईएस और सीयूटीएस के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक और पर्यावरण केंद्र ने नई दिल्ली में 1 सितम्बर, 2005 को दक्षिण-दक्षिण आर्थिक सहयोग मेकाँग-गंगा संबंध की गवेषणा पर राष्ट्रीय परामर्श का आयेजन किया। सम्मेलन में मेकांग-गंगा संबंध की गवेषणा -व्यापार, निवेश एवं वित्त; मेकांग-गंगा संबंध की गवेषणा- अवसंरचना एवं ऊर्जा; मेकांग-गंगा संबंध की गवेष्णा- सहयोग के अन्य क्षेत्र; और कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एचआरडी, एसएमई, स्वास्थ्य और भेषज, पर्यटन आदि जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। अनेक प्रख्यात नेताओं एवं विशेषज्ञों ने इसे संबोधित किया।

- **जैव सुरक्षा कार्टागेना प्रोटोकोल पर राष्ट्रीय परामर्शः एमओपी के सम्मुख मुद्दे, नई दिल्ली, 24 मई, 2005**

  पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ मिलकर आरआईएस ने नई दिल्ली में 24 मई, 2005 को जैव सुरक्षाः एमओपी-2 के सम्मुख मुद्दे पर कार्टागेना प्रोटकोल पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। सम्मेलन में चेतावनीपूर्ण सिद्धांत और अनुपालन तंत्रः नीति स्पेस की गवेषणा; जिम्मेदारी और निवारणः अंतर्राष्ट्रीय रूझानों और घरेलू नीति विकल्प; सामाजिक आर्थिक सरोकारों का समावेशन; चुनौतियां और नीति विकल्प; और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता तथा घरेलू अधिनियमों एवं दिशा-निर्देशों में सामंजस्य जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। अनेक प्रख्यात नेताओं एवं विशेषज्ञों ने इसे संबोधित किया।

- **डब्ल्यू टीओ के दोहा दौर, हांगकांग 12 दिसम्बर, 2005 में विकास**

  डब्ल्यूटीओ ने हांगकांग मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बगल

में आरआईएस ने हांगकांग के एनजीओ सेंटर में 12 दिसम्बर, 2005 को दोहा चक्र में विज्ञान पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इसे अनेक प्रख्यात नेताओं एवं विशेषज्ञों ने संबोधित किया।

- **भारत, चीन और आशियान देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उभरते एशियाई आर्थिक समुदाय में उनकी भूमिका पर सेमिनार, नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2006**

  आरआईएस ने 25 जनवरी, 2006 को भारत,चीन और आशियान देशों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता और उभरते एशियाई आर्थिक समुदाय में उनकी भूमिका पर एक सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान, सिंगापुर के निदेशक और राजदूत श्री के केशववाणी, और डा0 तैन बी गोअव आईएसईएएस के अतिथि वरि0 अनसंधान अध्यक्षता तथा अध्यक्ष आशियान अर्थव्यवस्था अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, नौंयांग प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, सिंगापुर ने कुछ नीतिगत सबक लेने के लिए 35 भारतीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, 31 चीनी प्रातों तथा 10 आशियान अर्थव्यवस्थाओं के वास्ते प्रतिस्पर्धातमक संकेतकों का व्यापक आंकलन की जांच करने वाले अनुभव जन्य अध्ययन प्रस्तुत किए। प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की सापेक्षिक प्रतिस्पर्धात्मकता के इस विश्लेषणात्मक एवं आनुभाव आकलन ने हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता, विज्ञान और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु नीतिगत सुधारों का स्वरूप एवं दिशा पर समृद्ध विचार-विमर्श की पृष्ठभूमि प्रदान की।

- **एशियाई शताब्दीः उत्तरपूर्व एशिया, आशियान और भारत की गतिकी पर प्रख्यात व्यक्ति व्याख्यान, नई दिल्ली 27 जनवरी, 2006**

  आरआईएस ने प्रो0 चुंग डुक-कू, संसद सदस्य (राष्ट्रीय एसेंबली) और पूर्व मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 27 जनरी, 2006 को प्रख्यात व्यक्ति व्याख्यान का आयोजन किया।

आऊटरिच, वैश्विक उपस्थिति और नेटवर्किंग

आरआईएस ने अपने कार्य से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भागीदारी के माध्यम से अपनी अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता और आऊटरिच बढ़ाने का कार्य जारी रखा। आरआईएस ने 12 से 16 सितम्बर, 2005 के दौरान आयोजित डब्ल्यूटीओ के हांगकांग मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया और इसके समकक्ष तीन सेमिनारों, पैनल विचार-विमर्श का आयोजन किया। इस सम्मेलन के एजेंडे पर आरआईएस नीति संक्षिप्तियां प्रस्तुत की गई जिन पर चर्चा हुई।

साझेदार संस्थाओं के साथ सेमिनारों के संयुक्त आयोजन के माध्यम से संस्थानिक नेटवर्किंग को मजबूत बनाया गया। चीन और भारत में एशियाई आर्थिक समुदाय पर उच्च स्तरीय सम्मेलन का संयुक्त रूप से आयोजन करके दक्षिण-पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान, सिंगापुर और शौनशी वित्त और आर्थिक विश्वविद्यालय, चीन के साथ संबंध मजबूत किए गए। आईएसईएएस, सिंगापुर के साथ मिलकर दो संयुक्त प्रकाशन भी निकाले गए।

नया एशिया फोरम एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकता को बढ़ावा देने संबंधी कार्यकलापों के प्रमुख केन्द्र के रूप में कार्य करना जारी रखा। इस नेटवर्क की अपनी वेबसाईट www.newasiaforum.org है और एक तिमाही पत्रिका न्यू एशिया मानीटर है।

आरआईएस भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूएनईएससीएपी के एशिया व्यापार अनुसंधान नेटवर्क के लिए संस्थानिक सलाहकार बोर्ड का सदस्य बना रहा और हाल की बैठकों में हिस्सा लेता रहा। कोलंबो स्थित आईयूसीएन-एशिया क्षेत्र ने डब्ल्यूटीओ पर क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन में आरआईएस की मदद की। राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन ने भी आरआईएस में एक अध्ययन संस्थित किया है।

पहले की तरह, आरआईएस ने नेशनल फोकल प्वाइंट रूप में वैश्विक वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर शोधकर्ताओं के सार्क नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखा और इसके कार्य कार्यक्रम में हिस्सा लेता है। आरआईएस सार्क नेटवर्क की तरफ से आईपीएस, श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप में साऊथ एशिया इकोनामिक जर्नल निकालता है।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

- **अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर आईएफएस प्रोबेशनर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थन की ओर से आरआईएस ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों के विभिनन पहलुओं पर 16 से 22 जुलाई, 2005 के दौरान आईएफएस प्रोबेशनर्स के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- **भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ अधकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला**

  वित्त मंत्रालय की ओर से आरआईएस ने भारतीय

आर्थिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 29 अगस्त से 2 सितम्बर, 2005 तक आरआईएस में विश्व और एशियाः भारत के सामने चुनौतियां और विकल्प पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया।

- **अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे और विकास नीति पर कार्यक्रम**

आरआईएस की बढ़ती लोकप्रियता तथा सकारात्मक फीडबैंक के प्रत्युत्तर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे और विज्ञान नीति का कार्यक्रम अब 2005-06 से 4 सप्ताह के कंपेक्ट फार्मेट में अन्य विकासशील देशों के और अधिक अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के लिए प्रदान किया जाएगा। 20 फरवरी से 4 सप्ताह के लिए कार्यक्रम शुरू होगा। विदेश मंत्रालय के आईटीईसी कार्यक्रम के साथ मिलकर यह संचालित किया जाता है।

- **डब्ल्यूटीओ रेजीम के विकास पर व्याख्यान कार्यक्रम**

विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय की ओर से आरआईएस ने 24 नवम्बर, 2005 को आरआईएस में 24 विदेशी राजनयिकों के लिए डब्ल्यूटीओ रेजीम का विकास पर व्याख्यान के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।

आरआईएस प्रकाशन

2005-06 के दौरान आरआईएस ने चार पुस्तकें प्रकाशित की, आठ नीति संक्षिप्तियों और 17 चर्चा कागजात जारी किए। आरआईएस डायरी के चार अंकों के अलावा साउथ एशिया इकोलाजी जर्नल के दो अंक तथा बायोटेक्नोलाजी एंड डवलेपमेंट रिव्यू के चार अंक तथा न्यू एशिया मानीटर के चार अंक निकाले गए (अनुबंध-I) । आरआईएस के प्रकाशन इसकी वेबसाइट www.ris.org.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

बजट

2005-2006 के दौरान विदेश मंत्रालय से आरआईएस को 137 लाख रूपए की बजटीय सहायता मिली।

■■

पुस्तकालय

26

मंत्रालय के पुस्तकालय में लगभग एक लाख पुस्तकें, बेहतर स्रोत सामग्री और मानचित्रों का विशाल संग्रहण, माइक्रोफिल्में एवं सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं। यह शोध की सहायता के लिए आधुनिक उपकरणों से भी सुसज्जित है। पुस्तकालय लगभग 500 पत्रिकाओं, जर्नलों और अखबारों की खरीदारी और रखरखाव करता है। यहाँ एक आन्तरिक कम्प्यूटर प्रणाली है जिसमें एक सर्वर और 12 पी सी हैं। इस प्रणाली में हिन्दी में भी डाटा की एन्ट्री और सुधार कार्य किया जाता है। पुस्तकालय में विदेशी मामलों एवं वर्तमान मामलों पर सी डी - रोम डाटाबेस है। पुस्तकालय के पी सी में सी डी - राइटर और लेजर राइटर भी लगे हैं। यहाँ एक रंगीन स्कैनर (ओ सी आर क्षमता के साथ - साथ संग्रहण एवं सुधार प्रतिबिम्बों की सुविधा सहित), एक माइक्रोफिल्म/फिश रीडर प्रिंटर, प्लेन पेपर फोटोकॉपियर और डेस्क टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के साथ-साथ एक एच पी ऑफिस-जेट प्रो लेजर भी है।

पुस्तकालय के समस्त पहलुओं को शामिल करते हुए एक एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पैकेज लिबसीस का प्रयोग कर समस्त प्रलेखन/संदर्भिका सेवाओं के साथ-साथ अन्य पुस्तकालय कार्यों एवं सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। लिबसीस में मार्क के साथ-साथ नॉन-मार्क के स्वरूप का प्रयोग किया जाता है। लिबसीस बूलीयन आपरेटरों के प्रयोग से शब्द-आधारित फ्री टक्स्ट सर्चिंग की सहायता करता है। लिबसीस डाटाबेस को अद्यतन करने से पहले डाटा निवेश का ऑनलाईन सत्यापन करता है। विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय के समस्त पी सी में इन्ट्रानेट के माध्यम से समस्त पुस्तकों, मानचित्रों, दस्तावेजों एवं पत्रिकाओं से चुने गए लेखों जिन्हें 1986 से पुस्तकालय में प्राप्त किया गया, प्रकाशनों से प्राप्त लेखों जिन्हें 1986 से पुस्तकालय में प्राप्त किया गया, (और सक्रिय रूप से चल रहे 1986 से पहले के प्रकाशनों), की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध है। पुस्तकालय के सूचना डाटाबेसों तक http://mealib.nic.in नामक विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय के बेवसाईट पर इन्टरनेट के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

पुस्तकालय में प्राप्त समस्त नए दस्तावेजों-पुस्तकों, मानचित्रों, माईक्रोफिल्मों, पत्रिकाओं से चुने गए लेखों- को विदेशी मामले संबंधी डाटाबेस में नियमित रूप से संग्रहित किया जा रहा है। इस डाटाबेस और सी डी - रोम डाटाबेसों के प्रयोग से, पुस्तकालय वर्तमान जागरूकता सेवा और संदर्भिका एवं निर्देशिका सेवाएँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय से निम्नलिखित नियमित तौर पर जारी किए जाते हैं:

- विदेशी मामले प्रलेखन बुलेटिन - अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों एवं संबंधित विषयों पर चुने गए लेखों की एक सूची।
- वर्तमान संस्करणें - विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय में लाए गए पुस्तकों/प्रकाशनों की एक टीकापूर्ण सूची।

हाल में, पुस्तकालय ने यथार्थ पुस्तकालय की स्थापना के लिए भी कार्य शुरू कर दिया हैं।

विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय द्वारा अंशदान किए गए जर्नलों के महत्वपूर्ण लेखों का सार प्रदान करने हेतु एक आर्टिकल एलर्ट सर्विस विदेश सेवा के अधिकारियों एवं प्रभाग के प्रमुखों के लिए ई - मेल के माध्यम से नेट पर उपलब्ध है।

सी डी - रोम प्रकाशन : विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय ने एन आई सी के साथ मिलकर विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों (1948 से लेकर 1998-1999 तक) और विदेशी मामले रिकॉर्ड (1955 से लेकर 1999 (अगस्त)तक) का एक पूर्ण विषयक सीडी-रोम रूपान्तर तैयार किया है। सी डी पर उपलब्ध जानकारी को किसी बताए गए शब्द या शब्दों की सन्धि पर खोज सहित खोजों के सम्मिश्रण द्वारा सुधारा जा सकता है। इस सी डी - रोम रूपान्तर को 1 जनवरी, 2000 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया था। इस सी डी को पटियाला हाऊस, नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय से लिया जा सकता है।

पुस्तकालय का प्रयोग करने वाले लोग और शोधकर्त्तागण पुस्तकालय में आ सकते हैं तथा सी डी-रोम डाटाबेसों एवं विदेशी मामले सूचना सुधार प्रणाली (फेयर्स) सहित विभिन्न डाटाबेसों की जानकारी ले सकते हैं। पुस्तकालय के समस्त पाठकों के लिए फोटोकॉपी करने तथा कम्प्यूटर से प्रिंट - आऊट लेने की भी सुविधा है।

पुस्तकालय सुधारों के लिए सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से एक विश्वस्तरीय आधुनिक यथार्थ/डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना और विस्तार करना है।

विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय 1981-1990 की अवधि और उसके बाद की अवधियों के लिए भारत की द्विपक्षीय संधियों एवं करारों के ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए एक परियोजना का समन्वय भी कर रहा है।

■■

परिशिष्ट

परिशिष्ट ।

वर्ष 2005-06 के दौरान मुख्यालयों और विदेश में मिशनों/पदों में संवर्ग की संख्या (इनमें वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए पद और आस्थगित/वाह्य-संवर्ग के पर भी शामिल हैं)

क्र.सं.	संवर्ग/पद	मुख्यालय में पद	मिशनों में पद	कुल
1	ग्रेड I	4	22	26
2	ग्रेड II	5	29	34
3	ग्रेड III	46	129	175
4	ग्रेड IV	29	114	143
5	क.प्रशा.ग्रेड/वरिष्ठ स्केल	44	140	184
6.	(i) जूनियर स्केल	1	29	30
	(ii) प्रोबोशनर रिजर्व	35	-	35
	(iii) लीव रिजर्व	15	-	15
	(iv) डेपूटेशन रिजर्व	19	-	19
	(v) ट्रेनिंग रिजर्व	7	-	7
	उप योग	**205**	**463**	**668**
आई एफ एस (बी)				
7	(i) ग्रेड I	82	122	204
	(ii) डेपूटेशन रिजर्व	6	-	6
8	(i) ग्रेड II/III	146	229	375
	(ii) लीव रिजर्व	30	-	30
	(iii) डेपूटेशन रिजर्व	16	-	16
	(iv) ट्रेनिंग रिजर्व	25	-	25
9	(i) ग्रेड IV	195	428	623
	(ii) लीव रिजर्व	60	-	60
	(iii) डेपूटेशन रिजव	55	-	55
10	(i) ग्रेड V/VI	317	96	413
	(ii) लीव रिवर्ज	60	-	60
	(iii) डेपूटेशन रिवर्ज	14	-	14
11	(i) साइफर कैडर के ग्रेड II (साइफर असिस्टेन्ट)	44	148	192
	(ii) लीव रिजर्व	24	-	24
12	(i) स्टेनोग्राफर कैडर	182	485	667
	(ii) लीव रिजर्व	47	-	47
	(iii) ट्रेनिंग रिजर्व (हिंदी)	10	-	10
	(iv) डेपूटेशन रिजर्व	12	-	12
13	इन्टरप्रेटर कैडर	6	27	33
14	एल एण्ड टी कैडर	14	1	15
	उप योग	**1345**	**1536**	**2881**
	कुल योग	**1550**	**1999**	**3549**

परिशिष्ट II

अप्रैल से नवम्बर, 2005 तक विदेश मंत्रालय में विभिन्न समूहों में की गई भर्ती और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी की आरक्षित पदों पर भर्ती

समूह	पदों की कुल संख्या	आरक्षित पदों की संख्या			अनारक्षित
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	
समूह "क"	44	5	2	5	32
समूह "ख"	66	11	4	1	50
समूह "ग"	16	4	1	शून्य	11
समूह "घ"	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाह्य संवर्ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

परिशिष्ट III

30 नवम्बर, 2005 को अधिकारियों (भा. वि. से के कनिष्ठ वेतनमान का ग्रेड I भाषा-वार ब्यौरा)

भाषा	अधिकारियों की संख्या	भाषा	अधिकारियों की संख्या
अरबी	90	पर्सियन	21
बर्मी	1	पुर्तगाली	19
भाषा इंडोनेशिया	12	रूसी	80
चीनी	57	स्वीडिश	1
डच	1	स्पेनी	60
फ्रेंच	72	सर्वो - क्रोएशियाई	3
जर्मन	32	सिंहली	2
गोरखाली	1	थाई	2
हेब्रयु	3	तिब्बती	2
हंगेरियन(मगयार)	1	तुर्की	6
इतालवी	5	युक्रेनियन	1
जापानी	25	वियतनामी	1
कजाक	1	मंदारिन	1
किशवाहिली	7	कोरियाई	1
नेपाली	3	मलय भाषा	1

परिशिष्ट IV

1 जनवरी, 2005 से 31 दिसंबर, 2005 तक प्राप्त आवेदनों और तत्काल स्कीम सहित जारी पासपोर्ट, प्राप्त विविध आवेदन एवं प्रदत्त सेवाओं की संख्या के साथ-साथ पासपोर्ट कार्यालयों का राजस्व (तत्काल स्कीम के तहत प्राप्त राजस्व सहित) और व्यय के आकड़ों को दर्शानेवाला विवरण।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/ पासपोर्ट कार्यालय का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या	प्राप्त विविध आवेदनों की संख्या	दी गई विविध सेवाएं	तत्काल योजना के अन्तर्गत जारी पासपोर्ट	तत्काल योजना के अन्तर्गत राजस्व	कुल राजस्व	कुल व्यय
अहमदाबाद	219068	208198	22122	22026	4834	7150000	227097172	26257360
बंगलौर	190481	186602	37798	37434	13991	22552500	220581803	25086191
बरेली	51903	48129	3945	3926	1884	2902000	55357755	8799369
भोपाल	60667	58287	6436	6392	3664	5207900	65875934	5753705
भुवनेश्वर	28861	27176	2348	2003	1459	1952500	31632745	3519332
चंडीगढ़	223949	212086	32222	32375	7786	12108000	259629583	20938927
चेन्नई	237561	212143	33162	24543	27924	41969000	287415422	25940780
कोचीन	185852	178824	40798	41634	17273	24394900	216698136	25307025
दिल्ली	207497	233118	33884	33375	22910	57748900	256794786	35762440
गाज़ियाबाद	55157	51885	7850	7716	3197	4751400	59641277	5840199
गुवाहाटी	22983	21287	2027	730	3168	4674500	29388700	3889750
हैदराबाद	307678	270703	36121	35744	29573	56079150	368094288	30621758
जयपुर	117138	134747	11286	8097	7214	10757500	130823151	18221812
जालंधर	174175	164219	22057	21644	743	1290600	201622243	21045181
जम्मू	12371	11928	933	859	297	419500	14041132	1570588
कोलकाता	137081	122917	15423	14999	4791	6908500	145927312	13992870
कोझीकोड	237367	244799	28444	28158	28005	40590500	290979994	25495585
लखनऊ	171833	152671	12300	11939	2383	2977000	182997811	27909206
मुम्बई	239863	223436	33045	32996	9012	17063000	256044615	49234447
नागपुर	31735	28517	2525	2280	3235	4147500	35850158	2527834
पणजी	24381	23914	7582	7516	2021	2856500	30789962	3879998
पटना	75850	77770	4972	4777	541	758000	73212425	8950558
पुणे	76036	68044	11124	10735	6028	8182000	84895980	7007497
राँची	22127	22815	1837	1706	1351	1925500	22151100	2274562
श्रीनगर	8921	5512	1029	925	278	378900	9710315	11711242
सुरत*	71398	75449	6667	6438	2746	3393200	74419900	
ठाणे**	98041	87635	9469	9256	5170	7598100	105001425	
त्रिची	225403	220429	22194	21063	14525	21298500	300256226	22163691
त्रिवेंद्रम	122135	131833	25449	24361	16172	22963000	158505030	14645798
विशाखापटनम	71936	65657	8743	8475	2341	3460100	80850661	6522593
कुल योग	**3709448**	**3570730**	**483792**	**464122**	**244516**	**398458650**	**4276287041**	**454870298**

* एल ओ सी आर पी ओ अहमदाबाद के साथ संयुक्त रहने के कारण आर पी ओ अहमदाबाद का व्यय इसमें शामिल है ।

** एल ओ सी, आर पी ओ मुम्बई के साथ संयुक्त रहने के कारण आर पी ओ मुम्बई का व्यय इसमें सम्मिलित है ।

परिशिष्ट V

वर्ष 2005-06 में विदेश मंत्रालय का वित्त

वर्ष 2005- 2006 के बजट अनुमान में विदेश मंत्रालय के लिए बजट आबंटन 3928.00 करोड रू0 है जो वर्ष 2004-05 की तुलना में 7.89 प्रतिशत यानि 287.31 करोड़ रू0 की वृद्वि दर्शाता है । वर्ष 2005-06 के लिए संशोधित अनुमान में बजट अनुमान वर्ष 2005-06 की तुलना में 6.47 प्रतिशत यानि 254.00 करोड़ रू0 की वृद्वि की गयी है ।

विदेश मंत्रालय का व्यय और बजट (2001-2002 से 2005-2006)

वर्ष	वास्तविक व्यय (करोड़ रूपए में)	अंतर प्रतिशत में
2001-2002	2624.55	शून्य
2002-2003	3253.79	23.98
2003-2004	3344.53	2.79
2004-2005	3756.15	12.31
2005-2006 (बजट अनुमान)	3928.00	4.58
2005-2006 (संशोधित अनुमान)	4182.00	6.47

परिशिष्ट VI

2005-06 के बजट में क्षेत्र-वार आबंटन

क्षेत्र	आबंटन (करोड़ रू.)
विदेश मंत्रालय सचिवालय	128.22
राजदूतावास एवं मिशन	893.00
पासपोर्ट एवं उत्प्रवास	158.74
विशेष राजनयिक व्यय	781.01
तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	1594.72
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अंशदान	122.62
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को अनुदान	60.50
विदेशी सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	278.40
अन्य	164.79

परिशिष्ट VII

भारत के सहायता कार्यक्रम के प्रमुख गंतव्य

चालू वित्त वर्ष 2005-06 में भारत के सहायता एवं ऋण कार्यक्रमों के मुख्य लाभार्थी निम्नलिखित हैं -

देशों को ऋण एवं सहायता	करोड़ रूपए में
भूटान	1113.11
बंगलादेश	52.00
नेपाल	66.01
श्रीलंका	25.00
मालदीव्स	13.20
म्यांमार	22.00
अफ्रीकी देश	60.98
अन्य (विकासशील देशों सहित)	503.83

3.1 भारत की कुल बजटीय सहायता का 60 प्रतिशत हिस्सा भूटान को सहायता के रूप में दिया जाता है । भारतीय सहायता कार्यक्रम के अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ता देशों में शामिल हैं- अफ्रीकी देश 3 प्रतिशत , नेपाल 4 प्रतिशत, बंगलादेश 3 प्रतिशत, श्रीलंका,माल्दीव और म्यामांर प्रत्येक 1 प्रतिशत और अफगानिस्तान सहित अन्य देश 27 प्रतिशत।

3.2 भारत सरकार ने बंगलादेश और भूटान की सरकारों को ऋण उनकी विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिए हैं । वर्ष 2005-06 के दौरान बंगलादेश की सरकार और भूटान को दिए गए ऋण की राशि क्रमशः1.00 करोड़ रूपए और 278.00 करोड़ रूपए हैं ।

4. विदेश मंत्रालय का बजट तत्वतः एक योजनेतर बजट है । फिर भी, वर्ष 1996-97 से मंत्रिमंडल के अनुमोदन से एक योजना बजट शीर्ष स्थापित किया गया है । इस शीर्ष के अंतर्गत भारत सरकार के"भूटान को सहायता कार्यक्रम" के अंतर्गत भूटान सरकार के अनुरोध पर परियोजना सहायता के एक हिस्से के रूप में भूटान में शुरू की गई विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों की पूर्ति की जाती है । भूटान में इस समय पूरी की जा रही ताला पनबिजली परियोजना एक प्रतिष्ठापूर्ण और महत्वपूर्ण परियोजना है । योजना लेखा शीर्ष के अंतर्गत वित्त पोषित की जा रही अन्य दो परियोजनाएँ भी भूटान में ही हैं अर्थात पुनातशांगचु और डुगसुम सीमेंट संयत्र ।

5. चालू वित्त वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में अनुमानित व्यय 128.22 करोड़ रूपए का है जो कि मंत्रालय के कुल अनुमानित राजस्व व्यय का लगभग 3 प्रतिशत बैठता है । विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों एवं पोस्टों पर कुल अनुमानित व्यय 893.00 करोड़ रूपए तक का होने की आशा है जो कि मंत्रालय के कुल राजस्व व्यय का लगभग 24 प्रतिशत है ।

6. पासपोर्ट एवं वीजा शुल्कों तथा अन्य प्राप्तियों से विदेश मंत्रालय का राजस्व 1275.25 करोड़ रू0 का होने की संभावना है । यह अनुमान है कि पासपोर्ट शुल्क का हिस्सा इसमें से लगभग 580.00 रू0 का,वीजा फीस का हिस्सा 670.00 करोड़ रूपए का और अन्य प्राप्तियाँ 25.25 करोड़ रूपए की रहेंगी ।

परिशिष्ट VIII

विदेश मंत्रालय के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

परिनिर्वाचित राजदूत कार्यालय के सृजन पर परिहार्य व्ययः मंत्रालय कार्य के आबंटन के बिना ही न्यूयार्क में परिनिर्वाचित राजदूत के पद का सृजन कर दिया। तदुपरांत 15.95 करोड़ रू0 के व्यय के बाद इस कार्यालय को अक्टूबर,2004 में बंद कर दिया गया ।

(2005 की रिपोर्ट सं0-2)

अनियमित व्ययः भारत सरकार के आदेशों में किसी केन्द्रीय मंत्री के आवास पर मात्र 2.50 लाख रू की लागत पर फर्नीचर विद्युत उपकरण लगाये जा सकते है परन्तु वर्ष 2000-2003 के दौरान विदेश सचिव के आवास पर फर्नीचर,फर्निशिंग और एअर कंडीशनरों पर 40.92 लाख रू0 का अनियमित व्यय किया गया।

(2005 की रिपोर्ट सं0-2)

सरकारी धन की हानिः कोंसली मैनुअल में दी गयी प्रक्रिया का पालन करने में असफलता, अप्रभावी मानिटरिंग प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण के अभाव के कारण भारतीय उच्चायोग, लंदन में 11.58 लाख रू0 के सरकारी धन की हानि हुई ।

(2005 की रिपोर्ट सं0-2)

परिशिष्ट IX

भारत द्वारा अन्य देशों के साथ संपन्न अथवा नवीकृत संधियों/अभिसमय/समझौते

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
बहुपक्षीय				
1.	सी 108 समुद्री किराया कों की पहचान दस्तावेजों का अभिसमय		17.01.2005 (संशोधन)	16.01.2006
2.	परमाणु सुरक्षा अभिसयम	20.09.1994	31.03.2005 (संशोधन)	29.06.2005
3.	सीमा-शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय		01.04.2005 (स्वीकृति)	29.06.2005
4.	पी आई सी पर रोट्टेरडम अभिसमय		24.05.2005 (स्वीकृति)	22.08.2005
5.	कतिपय परम्परागत हथियार जो अत्यधिक खतरनाक समझे जाये अथवा अंधाधुंध प्रभाव पड़ता हो के उपयोग के निषेध अथवा प्रतिबन्ध पर अभिसमय, 1980 के अनुच्छेद I में संशोधन		18.05.2005 (स्वीकृति)	
6.	युद्ध के विस्फोट अवशेषों पर प्रोतोकोल (प्रोतोकोल V)		18.05.2005 (स्वीकृति)	
7.	आतंकवाद के दमन पर दक्षेस क्षेत्रीय अभिसमय के लिए अतिरिक्त प्रोतोकोल	06.01.2004	26.07.2005 (संधोशन)	
8.	सशस्त्र संघर्ष में बच्चों को शामिल करने पर बाल अधिकार पर अभिसमय का वैकल्पिक प्रोटोकोल	15.11.2004	30.11.2005 (संशोधन)	
9.	बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति, और बाल आश्लील साहित्य पर बाल अधिकारों पर अभिसमय का वैकल्पिक प्रोतोकोल	15.11.2004	16.08.2005 (संशोधन)	15.09.2005
10.	अगोचर साँस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अभिसमय	03.11.2005	12.08.2005 (संशोधन)	
11.	एशिया आपदा तैयारी केन्द्र का चार्टर	07.07.2005	04.10.2005 (संशोधन)	
12.	भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय	09.12.2005		
13.	सार्क पंच-निर्णय परिषद की स्थापना के लिए करार	13.11.2005		

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
14.	दोहरे कराधान के परिहार और कर के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर सार्क सीमित बहुपक्षीय करार	13.11.2005		01.01.2006
15.	सीमा-शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर सार्क करार	13.11.2005		
16.	एशिया राजमार्ग नेटवर्क पर अन्तरसरकारी करार	27.04.2004		
17.	वैश्विक विकास नेटवर्क की स्थापना का करार	28.10.2005		
18.	समुद्री कानून के लिए अन्तरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के विशेषधिकार और उन्मुक्तियों पर करार		14.11.2005 (स्वीकृति)	
19.	अन्तरराष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों पर प्रोतोकोल		14.11.2005 (स्वीकृति)	
20.	खतरनाक कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय	14.05.2002	09.01.2006	
ख. द्विपक्षीय				
	आस्ट्रेलिया			
1.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग से सम्बन्धित भारत गणराज्य की सरकार और आस्ट्रेलिया की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	21.10.2005		21.10.2005
	आस्ट्रिया			
2.	स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधार भूत ढाँचे में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और आस्ट्रिया सरकार के बीच करार	17.02.2005		01.05.2005
3.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ और चिकित्सा विश्वविद्यालय, इन्सब्रुक के बीच सहयोग का विकास पर समझौता ज्ञापन	17.02.2005		17.02.2005
	बहामास			
4.	भारत गणराज्य की सरकार के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रमंडल के लोक सेवा गणराज्य, बहामास के बीच परामर्श पर समझौता ज्ञापन	08.09.2005		08.09.2005
	बहरीन			
5.	भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन किंगडम की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि	13.01.2004	08.04.2005	

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
6.	सम्मनों, न्यायिक दस्तावेजों, आयोगों, निर्णयों और पंचनिर्णयों के निष्पादन की सेवा के लिए दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में अधिकार क्षेत्र और न्यायिक सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन किंगडम की सरकार के बीच करार	13.01.2004	16.07.2005	16.07.2005
7.	आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन किंगडम की सरकार के बीच करार	13.01.2004		23.02.2005
	बांग्लादेश			
8.	बाढ़ राहत सहायता कोषों के उपयोग के सम्बन्ध में भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	11.02.2005		11.02.2005
9.	वर्ष 2005-2008 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवरी गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान - प्रदान कार्यक्रम	06.08.2005		
	भूटान			
10.	कृषि और संवदघ सेक्टरों के क्षेत्र में सहयोग पर कृषि मंत्रालय, भारत की गणराज्य सरकार तथा कृषि मंत्रालय, भूटान की गणराज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	25.01.2005		25.01.2005
11.	भूटान में पुनत्सांगचू (चरण - II) और भांगडेचू पन-विद्युत परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के बारे में भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	25.01.2005		25.01.2005
12.	भारत और भूटान सीमावर्ती शहरों के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	25.01.2005		25.01.2005
	बोत्सवाना			
13.	"विमान वहित अफ्रीका" अभ्यास संबंध पर बोत्सवाना सरकार तथा भारत की गणराज्य सरकार के बीच तकनीकी समझौता	14.05.2005		14.05.2005
	बुल्गारिया			
14.	भारत गणराज्य तथा बुल्गारिया गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि	03.10.2003	13.05.2005	
15.	भारत गणराज्य सरकार तथा बुल्गारिया की गणराज्य सरकार के बीच विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (2005-2008) में सहयोग कार्यक्रम	05.12.2005		

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
	कम्बोडिया			
16.	अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की रोकथाम, संगठित अपराध तथा अवैध नशीले पदार्थों के गैर-कानूनी व्यावार पर भारत की गणराज्य सरकार और किंगडम आफ कंबोडिया भी शाही सरकार के बीच करार	16.12.2005		
	कनाडा			
17.	स्वच्छ विकास तंत्र बी परियोजनाओं सहित जलवायु परिवर्तन पर भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	08.12.2005		08.12.2005
	चिली			
18.	भारत गणराज्य तथा चिली गणराज्य के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ढांचा करार	20.01.2005		
19.	भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय तथा चिली गणराज्य के कृषि मंत्रालय के बीच पादप और पादप सामग्री तथा पशु उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित सफाई और पादप सफाई मामलों पर समझौता ज्ञापन	20.01.2005		20.01.2005
20.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा में सहयोग के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इंस्टीट्यूटो डी इन्वेस्टिगेशन्स एग्रोपिक्यूरिअस सेंटियागो चिली के बीच समझौता ज्ञापन	20.01.2005		20.01.2005
21.	**चीन** भारत - चीन सीमा सवाल का समाधान करने के लिए राजनीतिक पैरा मीटरों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर भारत गणराज्य की सरकार औरचीन की जनवादी गणराज्य सरकार के बीच करार	11.04.2005		11.04.2005
22.	भारत - चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास बनाने संबंधी उपायों को लागू करने के तौर तरीकों पर भारत की गणराज्य सरकार और चीन की जनवादी गणराज्य सरकार के बीच प्रोतोकॉल ।	11.04.2005		11.04.2005
23.	भारत की गणराज्य सरकार और चीन की जनवादी गणराज्य सरकार के बीच सीमाशुल्क संबंधी मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता और सहयोग पर करार	11.04.2005		
24.	भारत और चीन के बीच नागर विमानन पर समझौता ज्ञापन	11.04.2005		11.04.2005

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
25.	भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय और चीन के जनवादी गणराज्य के गुणता पर्यवेषण, निरीक्षण तथा संगरोध, सामान्य प्रशासन के बीच भारत से चीन तक अंगूर के निर्यात के लिए पादप सफाइ अपेक्षता प्रोतोकॉल ।	11.04.2005		11.04.2005
26.	भारग गणराज्य के कृषि मंत्रालय और चीन के जनवादी गणराज्य के गुणता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध, सामान्य प्रशासन के बीच भारत से चीन तक करेला निर्यात भी पादप सफाई अपेक्षता का प्रोतोकॉल ।	11.04.2005		11.04.2005
27.	भारत गणराज्य, भारतीय विश्व कार्यक्रम परिषद और चीन की जनवादी गणराज्य, चाइनीज पिपुल्स इन्स्टीट्यूट आफ फॉरेन अफेयर्स के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	11.04.2005		11.04.2005
28.	भारत की गणराज्य सरकार और चीन की जनवादी गणराज्य सरकार के बीच भारत-चीन वित्तीय वार्ता आरंभ करने पर समझौता ज्ञापन	11.04.2005		11.04.2005
29.	भारत की गणराज्य सरकार के जल संसाधन मंत्रालय और चीन की जनवादी गणराज्य सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के बीच चीन से भारत तक बाद के समय में सतलुज/लैंगेन जैंग्बों नदी के जल विज्ञानीय सूचना उपलब्ध कराने पर समझौता ज्ञापन	11.04.2005		11.04.2005
30.	भारत - चीन फिल्म सहयोग आयोग का प्रोतोकॉल	11.04.2005		11.04.2005
31.	वेस्टर्न साइड आफ दि वाइट हार्स टेंपल इन लुयोयांग, चीन पर भारतीय शैली के बौद्ध मंदिर के निर्माण का ज्ञापन	11.04.2005		
32.	भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और चीन के जनवादी गणराज्य के जन सुरक्षा मंत्रालय के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	08.09.2005	08.09.2005	
	कोलम्बिया			
33.	भारत की गणराज्य सरकार और कोलम्बिया की गणराज्य सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर ज्ञापन	11.06.2005		26.08.2005

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
	अल सल्वाडोर			
34.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और अल सल्वाडोर गणराज्य के विदेश संबंध मंत्रालय के बीच परामर्श पर समझौता ज्ञापन	12.02.2004		
	फीजी			
35.	भारत गणराज्य के संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और फीजी गणराज्य के वाणिज्य, व्यवस्था विकास तथा निवेश मंत्रालय के बीचसूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं में सहयोग पर समझौता ज्ञापन)	10.10.2005		10.10.2005
36.	भारत गणराज्य और फीजी गणराज्य के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	10.10.2005		10.10.2005
37.	भारत गणराज्य और फीजी गणराज्य के बीच व्यापार समिति की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	10.10.2005		10.10.2005
38.	भारत गणराज्य और फीजी गणराज्य के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	10.10.2005		10.10.2005
	फ्रांस			
39.	भारत गणराज्य और फ्रांस गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण करार	24.01.2003	15.04.2004	01.08.2005
40.	भारत सरकार और फ्रांस गणराज्य के बीच वायु सेवाओं से संबंधित समझौता ज्ञापन	21.2.2005	15.4.2004	
	ग्वेटेमाला			
41.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और ग्वेटेभाला गणराज्य के विदेश संबंध मंत्रालय के बीच परामर्श पर समझौता ज्ञापन	04.05.2005		04.05.2005
	हंगरी			
42.	भारत की गणराज्य सरकार और हंगरी की गणराज्य सरकार के बीच आर्थिक सहयोग पर करार	23.06.2005		23.06.2005
	आइसलैंड			
43.	भारत की गणराज्य सरकार और आइसलैण्ड की सरकार के बीच सांस्कृतिक करार	19.10.2005		
44.	भारत की गणराज्य सरकार और आइसलैंड की सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर करार	19.01.2005		

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
45.	भारत की गणराज्य सरकार और आइसलैण्ड की सरकार के बीच विदेश कार्यालय परामर्श पर करार	31.05.2005		31.05.2005
	इण्डोनेशिया			
46.	भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय और इंडोनेशिया गणराज्य के समुद्री तथा मात्ययिकी मंत्रालय के बीच समुद्री तथा मात्ययिकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	23.11.2005		23.11.2005
47.	भारत की गणराज्य सरकार और इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार की संभाव्यता की जाच करने के लिए संयुक्त अध्ययन समूह की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	23.11.2005		23.11.2005
48.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और इंडोनेशिया गणराज्य के विदेश कार्य विभाग के बीच प्रशिक्षण सहयोग पर समझौता ज्ञापन	23.11.2005		23.11.2005
	इजरायल			
49.	भारत की गणराज्य सरकार और इजरायल राज्य की सरकार के बीच अवैध व्यापार तथा स्वापक औषधि और मनो विकृति संबंधी पदार्थों में दुरूपयोग की रोकथाम में सहयोग पर करार	09.09.2003	25.06.2005	
	इटली			
	भारत गणराल्य की सरकार और इटली गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर करार	12.07.2004	20.01.2005	
50.	भारत गणराज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा इटली गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच मात्ययिकी और कृषि उत्पादों पर समझौता ज्ञापन	14.02.2005		14.02.2005
51.	भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा इटली गणराज्य के पर्यावरण और राज्य क्षेत्र मंत्रालय के बीच क्योटो प्रोतोकॉल के स्वच्छता विचार तंत्र के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन ।	07.12.2005		07.12.2005
	जापान			
52.	भारत के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा जापान के आन्तरिक कार्य और संचार मंत्री के बीच संयुक्त बयान	24.08.2005		24.08.2005
	कुवैत			
53.	भारत गणराज्य और कुवैत राज्य के बीच असैनिक और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायिक सहयोग पर करार	16.08.2005		

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
	माल्टा			
54.	माल्टा भारत सरकार और माल्टा सरकार के बीच विदेश सेवा विचार-विमर्श पर प्रोतोकॉल	07.03.2005		07.03.2005
	मारिशस			
55.	भारत की गणराज्य सरकार और मारिशस की गणराज्य सरकार के बीच आपाराधिक मामलों में पारस्परिक निविक सहायता पर करारा	24.10.2005	01.12.2005	
56.	भारत की गणराज्य सरकार और मारिशस की गणराज्य सरकार के बीच बंदियों के स्थानान्तरण पर करार	24.10.2005	21.12.2005	
	मैक्सिको			
57.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और संयुक्त मैक्सिको राज्य के विदेश मंत्रालय के बीच अकादमिक सहयोग पर करार	21.10.2005		21.10.2005
	मंगोलिया			
58.	भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और मंगोलिया सरकार के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	15.09.2005		15.09.2005
	मोरक्को			
59.	भारत की गणराज्य सरकार और कंगडम आफ मोरक्को सरकार केबीच वायु सेवाओं के संबंध में करार	07.12.2004	23.02.2005	
	मंगोलिया			
60.	भारत गणराज्य और मंगोलिया के बीच असैनिक वाणिज्य मामलों में विधिक सहायता और विधिक संवंध पर संधि के अनुसमर्थन के लिखतों के आदान-प्रदान पर प्रोतोकॉल	15.01.2004		
61.	भारत गणराज्य और मंगोलिया के बीच असैनिक और वाणिज्यिक मामलों के बारे में विधिक सहायता और विधिक संबंध पर संधि	03.01.2001	15.01.2004	14.02.2004
62.	भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और मंगोलिया सरकार के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	15.09.2005	15.09.2005	
	नार्वे			
63.	भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान और नार्वे के विदेश सेवा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन	17.06.2005		17.06.2005
	ओमान			
64.	भारत गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच पत्यर्पण संधि	26.12.2004	13.05.2005	14.10.2005

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
	पाकिस्तान			
65.	भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच मिसाइल प्रशिक्षण पर सूचना के आदान-प्रदान पर करार	04.10.2005		
66.	भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच कोस्ट गार्ड कार्य कलाप पर करार	04.10.2005		
	पेरू			
67.	भारत की गणराज्य सरकार और पेरू की गणराज्य सरकार केबीच एक राजनयिक मिशन अथवा कांसुलर पद के कौटुम्बिक सदस्यों के लिए लाभप्रद व्यवसाय पर प्रबंध	20.06.2005		20.06.2005
	पोलैंड			
68.	भारत सरकार और पोलैंड सरकार के बीच वर्ष 2005-07 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	17.06.2005		17.06.2005
	रोमानिया			
69.	भारत सरकार और रोमानिया सरकार के बीच तेल और गैस सेक्टर के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन			
70.	रोमानिया के तेल और गैस विश्वविद्यालय तथा के. डी मालवीय पेट्रोलियम खोज अनुसंधान देहरादून के बीच अनुसंधान और विकास पर समझौता ज्ञापन।			
71.	रोमानिकया के तेल और गैस विश्वविद्यालय तथा पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून के बीच तथा शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करार			
	सर्बिया तथा मांटेनेग्रो			
72.	भारत की गणराज्य सरकार और मांटेनेग्रो के मंत्रिमंडल के बीच वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सहयोग पर करार	28.10.2004	10.06.2005	
	सिंगापुर			
73.	भारत की गणराज्य सरकार और सिंगापुर की गणराज्य सरकार के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता के संबंध में करार	27.06.2005	26.07.2005	
74.	व्यापक आर्थिक सहयोग करार	29.06.2005		

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
75.	भारत की गणराज्य सरकार और सिंगापुर की गणराज्य सरकार के बीच दिनांक 24 जनवरी, 1994 को हस्तक्षारित आय पर करों के संबंध में दोहरे काराधान के परिहनऔर कर अपबंचन की रोकथाम के लिए करार को संशोधित करने वाला प्रोतोकॉल	29.06.2005		
	दक्षिण अफ्रीका			
76.	भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण पर संधि	16.10.2003		08.04.2005
	श्रीलंका			
77.	भारत की गणराज्य सरकार और श्री लंका की लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर आदान-प्रदान कार्यक्रम	10.06.2005		10.06.2005
78.	भारत गणराज्य की सरकार और श्रीलंका की लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार के बीच स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, धर्मार्थ ट्रस्टों तथा शिक्षा और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से लघु विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करने के लिए भारतीय अनुदान सहायता के बारे में समझौता ज्ञापन	10.06.2005		10.06.2005
	स्वीडन			
79.	भारत सरकार और स्वीडन सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	09.12.2005		
	सीरिया			
80.	भारत की गणराज्य सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सीरियाई अरब गणराज्य के उच्च शिक्षा मंत्रालय के बीच संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	15.11.2003		15.11.2003
	ताजिकिस्तान			
81.	भारत गणराज्य और ताजिकिस्तान गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि	14.11.2003	10.06.2005	
	थाईलैंड			
82.	भारत सरकार और थाईलैंड सरकार के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	10.10.2005		

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
	ट्यूनिशया			
83.	भारत की गणराज्य सरकार और ट्यूनिशिया की गणराज्य सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि	04.04.2000		
	ट्यूनिशिया			
84.	भारत की गणराज्य सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ट्यूनिशिया की गणराज्य सरकार के संचार, प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रालय के बीच संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	09.02.2004		09.02.2004
	यूक्रेन			
85.	भारत की गणराज्य सरकार और यूक्रेन सरकार के बीच बाहरी अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग में ढांचागत समझौता	02.06.2005		
86.	भारतीय मानक ब्यूरो और तकनीकी विनियमन तथा उपभोक्ता नीति के लिए यूक्रेन की राज्य समिति के बीच मानकी करण, मौसम विज्ञान, अनुरूपता मूल्यांकन और गुणवत्ता के क्षेत्र में समझौता	02.06.2005		
	यूनाइटेड किंगडम			
87.	भारत की गणराज्य सरकार और ग्रेट ब्रिटेन तथा नादर्न आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम की सरकार के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानान्तरण पर करार	18.02.2005	19.09.2005	
88.	भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के बीच एक संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समिति के स्थापना के लिए करार	13.01.2005		
	संयुक्त राज्य			
89.	भारत की गणराज्य सरकार और अमेरिका के संयुक्त राज्य की सरकार के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता करार	17.10.2001	01.07.2005	04.10.2005
90.	भारत की गणराज्य सरकार और अमरिका के संयुक्त राज्य की सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार ।	17.10.2005		
91.	भारत की गणराज्य सरकार और अमरिका की संयुक्त राज्य की सरकार के बीच असैनिक नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार ।	18.07.2005		

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
92.	भारत गणराज्य ओर स्टेट्स आफ सेंट्रल अमरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम के बीच राजनीतिक सहयोग और वार्तालाप के लिए एक तंत्र की स्थापना के लिए घोषणा	02.02.2004		
93.	**उजबेकिस्तान** भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय और उजेबेकिस्तान गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच सैन्य तथा सैन्य तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग पर करार	05.04.2005		05.04.2005
94.	भारत की गणराज्य सरकार और उजबेकिस्तान की गणराज्य सरकार के बीच शिक्षा के क्षेत्र में आदान - प्रदान कार्यक्रम	05.04.2005		05.04.2005
95.	भारत की गणराज्य सरकार और उजबेकिस्तान की गणराज्य सरकार के बीच 2005-2007 में सांस्कृतिक सहयोग के कार्यक्रम	05.04.2005		05.04.2005
96.	भारत की गणराज्य सरकार और उजबेकिस्तान की गणराज्य सरकार के बीच लघु तथा निजी उद्यम शीलता के समर्थन के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर करार ।	05.04.2005		05.04.2005
97.	**वेनेजुएला** भारत की गणराज्य सरकार और वेनेजुएला की बोल्वियाई गणराज्य सरकार के बीच राजनयिक, शासकीय तथा सेवा पासपोर्ट पर वीजा छूट संबंधी करार	31.08.2005		31.08.2005
98.	भारत गणराज्य और वेजेनुएला की बोल्विया गणराज्य के बीच एक उच्च स्तरीय संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन ।	05.03.2005		05.03.2005
99.	भारत गणराज्य और वेनेजुएला की बोल्वियाई गणराज्य के बीच हाइड्रोकार्वन सेक्टर में सहयोग पर करार	05.03.2005		
100.	भारत गणराज्य के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) तथा वेनेजुएला की बोल्वियाई गणराज्य के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच जैव - प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	05.03.2005		05.03.2005

परिशिष्ट IX

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार के शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	जमा/संशोधन/ अधिस्वीकृति/ स्वीकृति की तारीख	प्रवृत होने की तारीख
101.	भारत गणराज्य के अन्तरिक्ष विभाग तथा वेनेजुएला की बोल्वियाई गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	05.03.2005		05.03.2005
102.	भारत की गणराज्य सरकार और वेनेजुएला की बोल्वियाई गणराज्य सरकार के बीच बेनेजुएला में तेल तथा गैस खोज तथा उत्पादन परियोजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन	05.03.2005		05.03.2005

परिशिष्ट X

1 जनवरी, 2005 से दिसंबर, 2005 के दौरान जारी की गई पूर्ण शक्तियों के विवरण

क्र.सं.	अभिसमय/संधि	पूर्ण शक्तियों की तारीख
1.	भारत गणराज्य वेनेजुएला की बोल्वियाई गणराज्य के बीच हाइड्रोकार्बन सेक्टर में सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री मणि शंकर अय्यर, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री के पक्ष में	4.3.2005
2.	भारत की गणराज्य सरकार और कोलम्बिया की गणराज्य सरकार के बीच विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं महासागर विकास (स्वतंत्र प्रभाग) राज्य मंत्री के पक्ष में	6.6.2005
3.	भारत गणराज्य और कुवैत राज्य के बीच असैनिक एवं वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक तथा न्यायित सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री एच. आर. भारद्वाज, विधि और न्याय मंत्री के पक्ष में ।	2.8.2005
4.	रूस की संघीयसरकार और भारत की गणराज्य सरकार के बीच हवाई इंजिन ए. एल 551 के उत्पादन तथा इसके उत्पादन की स्थापना में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के करार पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री एस. बैनर्जी, अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय के पक्ष में ।	8.8.2005
5.	भारत की गणराज्य सरकार और यूक्रन सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री के पक्ष मे।	6.8.2005
6.	भारत गणराज्य और महान समाजवादी लोक लिथियाई अरब जमाहिरिया के बीच निवेश संवंर्धन तथा संरक्षण के करार पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री डी.पी. श्रीवास्तव, लिविधा में भारत के राजदूत के पक्ष में ।	9.9.2005
7.	वैश्विक विकास नेटवर्क की स्थापना संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अशोक झा, सचिव, आर्थिक कार्य, विभाग, वित्त मंत्रालय के पक्ष मे ।	19.9.2005
8.	भारत की गणराज्य सरकार तथा अमेरिका के संयुक्त राज्य की सरकार के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास (स्वंतत्र प्रभार), राज्य मंत्री के पक्ष में	4.10.2005
9.	भारत की गणराज्य और अमेरिकी के संयुक्त राज्य की सरकार के बीच विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं महासागर विकास (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री के पक्ष में	17.10.2005
10.	भारत की गणराज्य सरकार और आइसलैंड की गणराज्य सरकार के बीच सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं महासागर विकास (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री के पक्ष में ।	19.10.2005
11.	भारत की गणराज्य सरकार और कनाडा सरकार के बीच विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं महासागर विकास(स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री के पक्ष में ।	7.11.2005
12.	भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री निरूपम सेन के पक्ष में ।	9.12.2005

परिशिष्ट X

क्र.सं.	अभिसमय/संधि	पूर्ण शक्तियों की तारीख
13.	भारत की गणराज्य सरकार तथा किंगडम आफ स्वीडन की सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करार पर हस्ताक्षर करने के लिए श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री के पक्ष में।	8.12.2005
14.	भारत की गणराज्य सरकारऔर इटली की गणराज्य सरकार के बीच दिनांक 19 फरवरी, 1993 को हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दाहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए अभिसमय को संशोधित करने वाले प्रोतोकॉल हेतु श्री के. एम. चन्द्रशेखर, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के पक्ष में	9.01.2006

परिशिष्ट XI

1 जनवरी, 2005 से दिसंबर, 2005 के दौरन जारी किए गए अनुसमर्थन/सहमति के लिखत

क्र.सं.	अनुसमर्थन/स्वीकृति के लिखत	अनुसमर्थन / प्रवेश जारी करने की तिथि
1.	सी 108 समुद्री किरायाकों की पहचान दस्तावेजों का अभिसमय	10.1.2005
2.	भारत गणराज्य की सरकार और मोरक्को गणराज्य की सरकार के बीच मर्चेन्ट शिविंग और संबंधित समुद्री मामलों के संबंध में समझौता।	20.1.2005
3.	भारत गणराज्य की सरकार और इटली गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता।	20.1.2005
4.	भारत गणराज्य और बहरीन राज्य के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता पर समझौता।	23.2.2005
5.	भारत गणराज्य की सरकार और मोरक्को गणराज्य की सरकार के बीच वायु सेवा के संबंध में समझौता।	23.2.2005
6.	परमाणु सुरक्षा का अभिसमय	21.3.2005
7.	भारत गणराज्य की सरकार और बहरीन गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि।	08.4.2005
8.	भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि	8.4.2005
9.	पी. आई. सी. पर सेटरडैम अभिसमय	15.4.2005
10.	अति घातक माने जा सकने वाले अंधाधुंध प्रीव वाले कुछ अपारम्परिक शस्त्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध पर अभिसमय, 1980 के अनुच्छेद - I युद्ध की बची हुई विस्फोटक सामग्री पर प्रोतोकोल (प्रोतोकोल V)	15.4.2005
11.	भारत गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच प्रत्यर्पण संधि ।	13.5.2005
12.	भारत गणराज्य और बुल्गारिया गणराज्य के बीच प्रत्यपर्ण संधि	13.5.2005
13.	भारत गणराज्य की सरकार और इस्त्राइल राज्य की सरकार के बीच अवैध व्यापार और स्वापक व नशीले पदार्थों के दुरूपयोग का सामना करने के लिए सहयोग पर समझौता	4.6.2005
14.	आतंकवाद के दमन पर सार्क क्षेत्रीय अभिसमय का अतिरिक्त प्रोतोकोल।	6.6.2005
15.	भारत गणराज्य की सरकार और सर्बिया तथा मांटीनीग्रो को मंत्रिपरिषद के बीच वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग पर समझौता	10.6.2005
16.	भारत गणराज्य और ताजीकिस्तान गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि।	10.6.2005
17.	आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता पर भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच संधि।	1.7.2005
18.	भारत गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता के संबंध में समझौता	25.7.2005
19.	आतंकवाद के दमन पर सार्क क्षेत्रीय अभिसमय के लिए अतिरिक्त प्रोतोकोल।	26.7.05
20.	बच्चों की खरीद फरोक्त, बाल वेश्यावृत्ति और बाल अश्लीलता पर बाल अधिकारों के संबंध में अभिसमय हेतु वैकल्पिक प्रोतोकोल	2.8.2005

परिशिष्ट XI

क्र.सं.	अनुसमर्थन/प्रवेश दस्तावेज	अनुसमर्थन/प्रवेश जारी करने की तिथि
21.	सशस्त्र युद्ध में बच्चों को शामिल करने पर बाल अधिकारों के संबंध में अभिसमय हेतु वैकल्पिक प्रोतोकोल।	2.8.2005
22.	समूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु अभिसमय	12.8.2005
23.	भारत गणराज्य की सरकार ओर मारीशस गणराज्य की सरकार के बीच आपराधिक मामलों पर पारस्परिक विधिक सहायता पर समझौता	9.12.2005
24.	एशियाई राजमार्ग नेटवर्क पर अंतर-सरकारी समझौता	19.12.2005
25.	भारत गणराज्य की सरकार और मारीशस गणराज्य की सरकार के बीच बंदियों के स्थानातरण पर समझौता।	12.12.2005
26.	वैश्विक विकास नेटवर्क की स्थापना हेतु समझौता	21.12.2005
27.	भारत गणराज्य की सरकार और कोलम्बिया गणराज्य की सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौता	26.8.2005
28.	भारत गणराज्य की सरकार और ग्रेट ब्रिटेन के यूनायटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैण्ड की सरकार के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर समझौता	16.9.2005
29.	भारत गणराज्य की सरकार और ग्रेट ब्रिटेन के यूनायटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैण्ड की सरकार के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर समझौता	16.9.2005
30.	एशियाई आपदा तैयारी केंद्र	4.10.2005
31.	सीमा शुल्क प्रक्रिया और उसके परिशिष्टों I और II के सरलीकरण और अनुकूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संशोधन पर प्रोतोकोल।	18.10.2005
32.	समुद्र के कानून हेतु अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण के संशोधन का प्रोतोकोल।	28.10.2005
33.	अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों पर प्रोतोकोल ।	28.10.2005
34.	भारत गणराज्य और बेलारूस गणराज्य के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता पर संधि	9.1.2006
35.	चिर स्थायी जैव प्रदूषणकारी पदार्थों पर स्टाकहोम अभिसमय	9.1.2006

परिशिष्ट XII

संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित/किए जाने वाले सम्मेलन/सेमिनार/अध्ययन परियोजनाएं, जिनका आंशिक वित्तपोषण, नीतिगत नियोजन और अनुसंधान प्रभाग द्वारा किया गया।

क. वर्ष 2005-06 के दौरान आंशिक रूप से वित्तपोषित प्रस्ताव

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थान/लाभाथा
1.	डा0 श्यामली घोष द्वारा "चीन और दक्षिण एशियाः बंग्लादेश-चीन संबंध" नामक अनुसंधान परियोजना	द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एवं एनालाइसीस, नई दिल्ली
2.	3 मार्च, 2005 को "व्यापक सुरक्षा IIः आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा" पर सेमिनार	सेंटर फॉर एडवांस्ड स्ट्रैटेजिक स्टडीज (सीएएसएस), पूणे
3.	"नई वैश्विक चुनौतियाँ और चीन-भारत संबंध" पर 1 और 2 मार्च, 2005 को सेमिनार	सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस), नई दिल्ली
4.	वर्तमान आपातकालीन परिस्थितियों में दक्षिण एशिया में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए अध्ययन परियोजना : (नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान) -3 सितम्बर, 2005 को	द एशिया सेंटर, बंगलोर
5.	"अफ्रीका में भारत की आर्थिक कार्यनीति" पर अध्ययन	फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की), नई दिल्ली
6.	श्री उमाशंकर झा द्वारा राष्ट्रपति राबर्ट मुगावे के निर्देशन में जिम्बाबवे पर एक पुस्तक लिखने की परियोजना	द एसोसिएशन ऑफ इंडियन अफ्रीकनिस्ट्स, नई दिल्ली
7.	एडीलेड यूनिवर्सिटी में 3-6 जुलाई, 2005 को संपन्न "भारत-जापान संबंधों में सुधारः एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के लिए विवक्षा" में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आस्ट्रेलिया की जापानी अध्ययन एसोसिएशन की 14वीं द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लेना	स्कूल ऑफ इन्टरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
8.	भारतीय मूल के विदेशी छात्रों के लिए भारत में अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए भारत में फेलोशिप कार्यक्रम	अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टडीज, नई दिल्ली
9.	"21वीं सदी में युद्ध, शांति और विश्व आधिपत्य" पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार	बुक रिव्यू लिटरेरी ट्रस्ट, नई दिल्ली
10.	"हिस्पेनिज्म एंड ल्यूसो-ब्राजीलियन स्टडीज : फ्लैशवैक फ्रॉम द प्रेजेन्ट" पर पांच अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्रवाई का प्रकाशन	सेंटर फॉर स्पैनिश स्टडीज, जेएनयू, नई दिल्ली
11.	भारतीय विदेश नीति पर एक तिमाही जरनल	भारत राजनयिक संघ, नई दिल्ली
12.	भारत-श्रीलंका वार्ता ट्रेक-II का दूसरा दौर	भारत अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली
13.	शिप एंड ओशन फांउडेशन, टोक्यो से आए शिष्टमंडल के साथ 4-9 अप्रैल, 2004 को दूसरे दौर की वार्ता करना	सोसायटी फार इंडियन ओशन स्टडीज, नई दिल्ली
14.	सिंगापुर में 21-22 जून, 2005 को एशिया-मिडल इस्ट डायलॉग (एएमईडी) में श्री एच0एन0 अंसारी का भाग लेना	संयुक्त राष्ट्र में भूतपूर्व राजदूत श्री एच0एन0 अंसारी

परिशिष्ट XII

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थान/लाभाथा
15.	27-30 मई, 2005 को पाकिस्तान के साथ टैक-II वार्ता का 24 वां दौर	इंडिया पाकिस्तान नीमराना इनिसिएटिव (आईपीएनआई), नई दिल्ली
16.	नवम्बर, 2005 के पहले सप्ताह में पाकिस्तान के साथ ट्रैक-II वार्ता का 25वां दौर आयोजित कराना	-वही-
17.	श्री लीलाधर भंडारी एम0, आईएसआईएल का अनुसंधान सहायक, नई दिल्ली (दिल्ली-थिसालोनिकी-दिल्ली) का थिसासोनिकी, ग्रीस में 5-23 सितम्बर, 2005 को ईटरनेशनल लॉ इन्फोसिमेंट के 33वें वार्षिक सत्र में भाग लेना	इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नई दिल्ली
18.	5वीं भारत-कोरिया वार्ता	आईसीआरआईआर, नई दिल्ली
19.	डा0 कविता शर्मा द्वारा "भारत के विदेशी संबंधः शिक्षण अनुभाग की भूमिका" नामक अनुसंधान परियोजना	सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली
20.	डा0 पॉल का आस्ट्रेलिया एवं फिजी का अध्ययन दौरा	हेमचन्द्र आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन
21.	"पोखरन-II के बाद भारत की परमाणु कूटनीति : सरकार का यह आम चेहरा" नामक अनुसंधान परियोजना।	ओआरएफ इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज, नई दिल्ली
22.	"हिस्पैनिक हॉरिजन", जरनल का प्रकाशन	सेंटर ऑफ स्पेनिश, पोर्तगीज, इटालियन एंड लैटीन अमेरिकन स्टडीज (सीएसपीआईएलए), स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, जेएनयू, नई दिल्ली
23.	नवम्बर, 2005 को "भारत-यूरेशिया संबंध : आगे का मार्ग" पर सेमिनार	सेंटर फॉर कॉकेसियन स्टडी, सीसीआरआईडी (ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र) चड़ीगढ़
24.	"नए युग में भारत की विदेश नीति के लिए चुनौतियां" पर सेमिनार	एचएनबी गढ़वाल युनिवर्सिटी, श्रीनगर, उत्तरांचल
25.	मलेशिया के प्रधानमंत्री डाटो सेरी अब्दुल्ला अहमद बढ़ावी को सम्मानार्थ डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने के लिए दिसम्बर, 2004 को सम्मेलन	जामिया मिलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी, दिल्ली
26.	बीजिंग में 1-19 जून, 2005 को त्रिपक्षीय शैक्षिक सम्मेलन	विकासशील सोसाईटी का अध्ययन केन्द्र, इंस्टीट्यूट ऑफ चायनीज स्टडीज, नई दिल्ली
27.	भारत-चीन के संयुक्त अध्ययन समूह के चौथे दौर की बैठक 21-23 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में संपन्न।	पूर्वी एशिया, एमईए
28.	"एक्रॉस द हिमालयन ग्रुप-IIः ए चाइनीज क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिग इंडिया" नामक नए खंड का प्रकाशन	पूर्वी एशिया प्रभाग, एमईए
29.	"पूर्वोन्मुख" पर सेमिनार	जादवपुर युनिवर्सिटी, कोलकाता का डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स (डीआईआर)

परिशिष्ट XII

ख. प्रक्रियाधीन प्रस्ताव

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थान/लाभाथा
1.	"भारत-अफ्रीका संबंधी" पर नई दिल्ली में 7-8 अप्रैल 2005 को आयोजित सेमिनार	सोसायटी फॉर इंडियन ओशन स्टडीज, नई दिल्ली
2.	इण्डिया-इंडोनेशिया इमिनेंट पर्सन्स ग्रुप की स्थापना करना	दक्षिणी प्रभाग, एमईए
3.	कैनबरा में 11-12 अप्रैल,2005 को संपन्न ट्रैक-II, चौथा भारत-आस्ट्रेलिया सुरक्षा गोलमेज सम्मेलन	श्री मनोज जोशी, भारतीय पक्ष से संयोजक
4.	ताजिकिस्तान और कश्मीर के सांस्कृतिक समानताओं का पता लगाने के संबंध में अनुसंधान परियोजना	सेंटर फॉर सेंट्रल एशियन स्टडीज, युनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जम्मू-कश्मीर
5.	मुम्बई में 15-17 दिसम्बर को" भारत-अफ्रीका संबंधः द्विपक्षवाद और बहुपक्षवाद की चुनौतियां" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज (सीएएस), युनिवर्सिटी ऑफ मुंबई
6.	इंडो-यूएस संबंधों पर अनुसंधान परियोजना	सेंटर फॉर द एडवांस्ड स्टडी ऑफ इंडिया, युनिवर्सिटी ऑफ पेंसिलवानिया
7.	पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद के लिए अनुदान	आईएसआईएल, नई दिल्ली
8.	गोआ में 22-23 सितम्बर, 2005 को "भारत-लैटीन अमेरिकी सहयोग; अनुदर्शन और संभावना" पर सम्मेलन	सेंटर फॉर लैटीन अमेरिकन स्टडीज, गोआ युनिवर्सिटी, गोआ
9.	डा0 बालादास घोसाल द्वारा" भारत की पूर्वोन्मुख नीति पर एक नई नजर : सामरिक नीतिगत आयाम" नामक अनुसंधान परियोजना	सेंटर फॉर साउथ, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ-वेस्ट पैसिफिक, जेएनयू, नई दिल्ली
10.	"बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में दक्षिण एशिया क्षेत्र की सृजनात्मक वैचारिकता की ओर" पर 10-11 मार्च 2006 को सेमिनार आयोजित करना	इंडियन कौंसिल फॉर साउथ एशियन कोऑपरेशन (एसीएलएसी), दिल्ली
11.	नई दिल्ली में 13-15 दिसम्बर, 2005 को "परमाणविक ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग" पर संपन्न 8वां एशियन क्षेत्रीय सेमिनार	यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
12.	"भारत-चीन संबंध : एशियाई सदी के लिए एक एजेंडा" पर एक सेमिनार जनवरी, 2006 में संपन्न	विद्या प्रकाश मंडल्ज (वीपीएम) सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, मुम्बई
13.	"आर्थिक कूटनीति; भविष्य के लिए सामरिक नीति" पर सेमिनार मार्च, 2006 में आयोजित किया जाएगा।	एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, दिल्ली

परिशिष्ट XIII

अप्रैल, 2005 से जनवरी, 2006 तक की अवधि के लिए व्यय का विवरण (आईटैक एवं स्कैप कार्यक्रम)

मुख्य/लघु लेखा शीर्ष	2005-06 में आबंटित स्लाटों कुल संख्या	19.1.2006 की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षुओं की संख्या	31.12.2005 की तक किया किया गया कुल व्यय	2005-06 में बजट अनुदान
मुख्य शीर्ष - 3605, 17 - आइटेक कार्यक्रम, 17.00.32 - अंशदान	2862 (सिविलियन) + 319 (रक्षा) = 3181	1633	26.89 करोड़	बी ई 45 करोड़ आर ई 49 करोड़
मुख्य शीर्ष - 3605, 19-स्कैप कार्यक्रम, 19.00.32 - अंशदान	698	381	3.96 करोड़	बी ई 5.5 करोड़ आर ई 6.5 करोड़
	3879	**2014**	**30.85 करोड़**	**बी ई 50.50 करोड़ आर ई 55.50 करोड़**

परिशिष्ट XIV

भारत स्थित आइटेक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची

क्र संख्या	संस्थान का नाम	शहर
1.	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज	हैदराबाद
2.	ऐपटेक लिमिटिड	नई दिल्ली
3.	भारतीय मानक ब्यूरा	नई दिल्ली
4.	संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो	नई दिल्ली
5.	केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान	फरीदाबाद, हरियाणा
6.	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान	मैसूर, कर्नाटक
7.	केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान	हैदराबाद
8.	केन्द्रीय टूल डिजाइन संस्थान	हैदराबाद
9.	केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान	हैदराबाद
10.	केन्द्रीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान	बंगलौर, कर्नाटक
11.	केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन	नई दिल्ली
12.	सी-डैक	मोहाली (चंडीगढ़)
13.	सी एम सी लिमिटिड	नई दिल्ली
14.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	नई दिल्ली
15.	भारत का उद्यमिता विकास संस्थान	भाट, गुजरात
16.	द्रव नियंत्रण शोध संस्थान	पालाघाट, केरल
17.	मानव बसाव प्रबंधन संस्थान	नई दिल्ली
18.	भारतीय जन संचार संस्थान	नई दिल्ली
19.	भारतीय उत्पादन प्रबंध संस्थान	उड़ीसा
20.	भारतीय दूर संवेदी संस्थान	देहरादून
21.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रूड़की
22.	अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
23.	राजकीय लेखांकन एवं वित्त संस्थान	नई दिल्ली
24.	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान	नई दिल्ली
25.	अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान	नई दिल्ली
26.	अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र	कोलकाता
27.	जे आई एस इंजीनियरिंग महाविद्यालय	कोलकाता
28.	नरूला प्रौद्योगिकी संस्थान	कोलकाता
29.	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो	नई दिल्ली
30.	राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान	पूना

परिशिष्ट XIV

क्र संख्या	संस्थान का नाम	नगर (संस्थान)
31.	राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान	नई दिल्ली
32.	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान	नोएडा, उत्तर प्रदेश
33.	राष्ट्रीय भेषजी शिक्षा एवं शोध संस्थान	मोहाली, पंजाब
34.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान	हैदराबाद
35.	राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान	हैदराबाद
36.	एन आई आई टी लिमिटेड	नई दिल्ली
37.	डाक प्रशिक्षण केन्द्र	मैसूर, कर्नाटक
38.	गुट निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों हेतु शोध एवं सूचना प्रणाला	नई दिल्ली
39.	राइट्स	गुड़गांव, हरियाणा
40.	सीबिट	नई दिल्ली
41.	दक्षिण भारत वस्त्र शोध संघ	कोयम्बटूर
42.	टाटा इन्फोटेक लि	नई दिल्ली
43.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	चेन्नई
44.	टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट इंडियन लि. (टी सी आई एल)	नई दिल्ली
45.	वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान	नोएडा, उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट XV

आईटैक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिविलियन प्रशिक्षण स्लॉट (आबंटित/प्रयुक्त)

देश	स्लॉट	अनुमोदन शामिल हुए*	
		जारी हुए	19.1.06
अफगानिस्तान	100	102	80
अफगानिस्तान	200 (100+100)	213	98
अलबानिया	2	0	0
अल्जीरिया	9	9	2
अंगोला	15	3	0
एनगाइला	2	2	0
एंटीगुआ और बरमूदा	5	12	1
अर्जेन्टीना	3(जी-15)	1	0
आरमीनिया	60(50+10)	68	53
आजरबैजान	10	16	1
बहामास	02(एसएफटीसी)	2	2
बहरीन	03	0	0
बंगलादेश	125 (50+50 (बीआईएमएस टीईसी)+25)	114	38
बारबाडोस	5	2	1
बेलारूस	10	4	3
बेलीज	6	6	5
बेनिन	5	4	0
भूटान	80(50+30 बीआईएम एसटीईसी)	49	42
बोलीबिया	3	4	0
बोस्निया-हर्जोगोविना	2	0	0
ब्राजील	3(एस एफ टी सी)	0	0
ब्रुनेई दारूसलाम	10 (ए एस ई ए एन)	0	0
बुल्गारिया	10	16	6
बुर्किना फासो	10(5+5)	8	1
बुरूंडी	3	3	0
कम्बोडिया	75 (40+10(ए एस ई ए एन)+25)	78	53
केप वर्दे आइलैंड	2	0	0
केमैन आइलैंड	2	0	0
मध्य अफ्रीका गणराज्य	2	0	0
चाड	2	0	0
चिली	3(जी-15)	2	1
कोलम्बिया	20(15+5)	18	11
डोमिनिक राष्ट्रकुल	2(एस एफ टी सी)	4	2
कोमोरोस	2	3	0
कांगो	2	1	0
कोस्टारिका	10(5+5)	12	8
क्रोशिया	3	2	1
क्यूबा	35	45	24
चेक गणराज्य	5	1	1
जिबूती	5	1	0
डोमिनिक गणराज्य	5(एस एफ टी सी)	1	1
पूर्वी तीमोर	10	4	0
इक्वाडोर	10(5+5)	5	3
मिस्र	10(7+3(जी-15))	11	9
अल्सलवाडोर	7(2+5(एस एफ टी सी))	11	4
एक्वाटोरियल गिनीया	2	0	0
एरीट्रिया	10	11	5
एस्टोनिया	30(20+10)	32	20
इथोपिया	30	28	15
फिजी	30(25+5(एस एफ टी सी))	16	6
गाबोन	5	0	0
जार्जिया	40(30+10)	44	24
ग्रेनादा	7(5(एस एफ टी सी)+2)	10	7
ग्वाटेमाला	2	7	6
गिनीया	5	0	0
गिनीया बिसाउ	2	2	1
गुयाना	35(30+5(एस एफ टी सी))	44	24

परिशिष्ट XV

देश	स्लॉट	अनुमोदन शामिल हुए* जारी हुए	19.1.06
हैती	2	2	2
होन्डुरस	5	3	3
हंगरी	2	1	1
इण्डोनेशिया	88(50+3 (जी-15) +10 (ए एस ई ए एन)+25)	70	55
ईरान	15	20	10
इराक	100	117	54
आइवोरी कोस्ट	35	46	29
जमैका	13(5+8)	8	7
जार्डन	15(5+10)	16	4
कजाखिस्तान	40	46	26
किरिबाती	2	0	0
कोरिया (डी पी आर के)	10	16	10
किरगीजिस्तान	50	67	44
लाओस	60 (40+10(ए एस ई ए एन)+10)	63	49
लातविया	4	2	1
लेबनान	15(2+13)	28	11
लाइबीरिया	5	5	2
लीबिया	20	11	0
लिथवानिया	10	8	6
मेसीडोनिया	2	1	0
मेडागास्कर	10	24	15
मलेशिया	20(7+3(जी-15) +10(ए एस ई ए एन))	9	5
मालदीव	20	43	25
माली	3	0	0
मार्शल आइलैंड	2	1	1
मारीतानिया	2	1	0
मैक्सिको	13	12	3
माइक्रोनेशिया	5	3	1
मालदोवा	2	1	1
मंगोलिया	50(40+10)	58	35
मोंटसेरात	2	0	0
मोरक्को	5	7	5
म्यांमार	100(40+50(बी आई एम एस टी-ई सी)+10 (ए एस ई ए एन))	120	60
नाउरू	2	0	0
नेपाल	80(50+30)	47	29
निकारागुआ	5	7	2
नाइजर	2	1	0
ओमान	45	24	20
पलाऊ	2	2	2
फिलिस्तीन	30	68	30
पनामा	10	13	5
पापुआ न्यू गिनी	15(10+5)	40	14
परागुवे	2	1	0
पेरू	10(6+4)	12	6
फिलीपीन्स	25(15+10 (ए एस ई ए एन))	31	20
पोलैण्ड	3	3	3
कतार	2	0	0
साउटोम गणराज्य	2	5	5
रोमानिया	10	10	9
रूस	80	154	72
रवांडा	5	1	0
सामोआ	3(एस एफ टी सी)	0	0
सेनेगल	20(17+3 (जी-15))	8	4
सिंगापुर	10(ए एस ई ए एन)	0	0
स्लोवाक गणराज्य	10	15	4
सोलोमन द्वीप समूह	8(2+6)	8	4
श्रीलंका	100(50+50 (बी आई एम एस टी-ई सी))	99	51
सेंट क्रिस्टाफर और नेविस	2	1	1
सेंट लुसीया	2	0	0

परिशिष्ट XV

देश	स्लॉट	अनुमोदन शामिल हुए* जारी हुए	19.1.06	देश	स्लॉट	अनुमोदन शामिल हुए* जारी हुए	19.1.06
सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स	2	1	1	यमन	50	56	37
सूडान	100(60+40)	159	59	जायरे	3	0	0
सूरीनाम	30(20+10)	35	21	**योग**	**2862**	**3036**	**1633**
सीरिया	30	43	25				
ताजिकिस्तान	75	43	20	**(स्कैप देश)**			
थाईलैण्ड	60(10+50 (बी आई एम एस टी- ई सी))	76	38	बोत्सवाना	20	25	18
टोगो	5(2+3)	7	0	केमरून	5	4	4
टोंगा	5	6	5	गांबिया	10	11	4
त्रिनिदाद एवं टोबैगो	20	16	10	घाना	70(50+20)	78	52
ट्यूनिशिया	10	1	1	केन्या	53(50+3(जी-15))	33	11
तुर्की	50(40+10)	54	25	लिसोथो	20	28	11
तुर्कमेनिस्तान	30	32	26	मलावी	10(5+5)	17	6
तुर्कस् एवं कायकोस द्वीप समूह	2	0	0	मारीशस	75(30+45)	59	36
तुवालू	2	1	1	मोजाम्बीक	20	18	14
युक्रेन	15(10+5)	15	9	नामीबिया	55(40+15)	58	36
उरूग्वे	5	6	4	नाईजीरिया	50	51	30
उजबेकिस्तान	90	84	61	सेशेल्स	20	15	7
वनौतू	8(2(एस एफ टी सी)+6)	9	2	सीएरा लियोन	10	13	9
वेनेजुएला	10	13	6	दक्षिण अफ्रीका	75	39	23
वियतनाम	100 (40+10(ए एस ई ए एन)+20(एस और टी)+30)	91	57	स्वाजीलैण्ड	5	3	0
				तंजानिया	75(60+15)	111	56
				उगाण्डा	30	20	13
				जाम्बिया	50(35+15)	66	36
				जिबांबवे	45	40	15
				योग	698	689	381

संस्थानों द्वारा बिल के साथ टी सी प्रभाग को प्राप्त कार्यग्रहण रिपोर्ट के आधार पर आकड़ें दिये गए हैं । वास्तविक आकड़ें इससे ज्यादा हो सकतें हैं ।

परिशिष्ट XVI

वर्ष 2005-06 की अवधि के दौरान विभिन्न देशों को आबंटित सैन्य प्रशिक्षण स्लॉट की संख्या आईटैक/सैप के अन्तर्गत

क्र.सं.	देश	थल सेना	नौ सेना	वायु सेना	डीएसएससी	एनडीसी	योग
1	अफगानिस्तान	4	-	-	-	-	4
2	बंगलादेश	7	8	7	-	1	23
3	भूटान	-	-	-	1	1	2
4	बोत्सवाना	8	-	7	-	-	15
5	कम्बोडिया	5	3	5	-	-	13
6	एरीट्रिया	4	3	-	-	-	7
7	मिस्त्र	-	-	-	-	1	1
8	घाना	2	5	14	1	-	22
9	इण्डोनेशिया	3	3	14	1	1	12
10	कजाखिस्तान	4	2	-	1	-	7
11	किरगिजिस्तान	2	-	-	-	-	2
12	लाओस पी डी आर	2	-	3	-	-	5
13	लेबनान	3	-	-	-	-	3
14	लिसोथो	4	-	-	-	-	4
15	मलेशिया	2	6	5	-	-	13
16	मालदीव	-	-	-	1	1	2
17	मारीशस	18	12	9	-	-	39
18	मंगोलिया	4	-	-	1	-	5
19	म्यांमार	34	4	5	1	1	45
20	नेपाल	-	-	-	1	1	2
21	नाईजीरिया	3	9	6	-	-	18
22	सेशैल्स	7	19	-	-	-	26
23	श्रीलंका	-	-	-	1	2	3
24	सीरिया	2	-	-	1	1	4
25	ताजिकिस्तान	4	-	-	1	-	5
26	तंजानिया	3	1	-	1	-	5
27	थाइलैण्ड	2	-	-	-	1	3
28	उगाण्डा	2	-	-	1	-	3
29	उजबेकिस्तान	6	-	-	-	-	6
30	वियतनाम	6	7	-	1	1	15
31	जांबिया	5	-	5	1	-	11
32	जंजीबार	-	3	-	-	-	3
	योग	**146**	**85**	**70**	**15**	**12**	**328**

परिशिष्ट XVII

नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में तैनात आईटैक विशेषज्ञों की सूची

क्र.सं.	देश	विशेषज्ञ का नाम	क्षेत्र	दिनांक से	दिनांक तक
1	गुयाना	डा. ए. मुरूगन	दुग्ध विपणन	जुलाई,03	जुलाई,06
2	गुयाना	श्री मुकुल गुप्ता	शहर योजनाकार	अगस्त,03	अगस्त,05
3	गुयाना	श्री पी. के. मल्होत्रा	विधि अधिकारी	जनवरी,04	जनवरी,06
4	लाओस	ले. क. विवेक शर्मा	अंग्रेजी एवं सैन्य	मार्च,03	मार्च,06
5	लाओस	मेजर एस. एस. मैनी	रणकौशल शिक्षण	मार्च,03	मार्च,06
6	लाओस	मेजर अमित खबतियाल	अंग्रेजी एवं सैन्य	दिसम्बर,04	दिसम्बर,07
7	लाओस	मेजर मूर्ति	रणकौशल शिक्षण	दिसंबर, 04	दिसम्बर,07
8	नामीबिया	श्री आर. के. दुबे	अंग्रेजी एवं सैन्य	फरवरी,03	फरवरी,07
9	लिसोथो	सी एच एम सिमोन के जॉन	रणकौशल शिक्षण	सितंबर, 03	सितंबर,05
10	लिसोथो	सी एच एम विधान सिंह	अंग्रेजी एवं सैन्य	सितंबर,03	सितंबर,05
11	लिसोथो	सी एच एम के. लक्ष्मा रेड्डी	रणकौशल शिक्षण	नवंबर,03	नवंबर,05
12	लिसोथो	सी एच एम बी. देवराज	गणित प्राध्यापक	नवंबर, 03	नवंबर,05
13	लिसोथो	सी एच एम ए. के. भारती	भारतीय सेना प्रशिक्षण टीम	नवंबर,03	नवंबर,05
14	जांबिया	कर्नल यू. के. गुरूंग	सैन्य सलाहकार दल (आईमैट)	जनवरी, 04	जनवरी,06
15	जांबिया	ले. क. रघु श्रीनिवासन	सैन्य सलाहकार दल (आईमैट)	जनवरी,04	जनवरी,06
16	जांबिया	ले. क. आर. के. माथुर	सैन्य सलाहकार दल (आईमैट)	जनवरी,04	जनवरी,06
17	जांबिया	वि. कमांड. वी. आर. चौधरी	सैन्य सलाहकार दल (आईमैट)	जनवरी,04	जनवरी,06
18	उगांडा	डा. डी. सी. शेवडे	फार्माकोलाजी प्रध्यापक	फरवरी,04	फरवरी,06
19	मारीशस	डा. ए. लक्ष्मीनारायण	मात्स्यिकी विशेषज्ञ	मई,04	मई,06
20	मारीशस	श्री प्रवीण दीक्षित	सलाहकार नौकरशाही प्रशिक्षण	दिसंबर,04	दिसंबर,05
21	मारीशस	श्री आर. पी. दीनाराज	लेखा परीक्षा सलाहकार	दिसंबर,04	दिसंबर,07
22	मारीशस	श्री आई.डी.एस. धारीवाल	लेखा परीक्षा सलाहकार	दिसंबर,04	दिसंबर,07
23	मारीशस	श्री ए. के. रस्तोगी	सिविल इंजीनियर	सितंबर,04	सितंबर,06

परिशिष्ट XVII

क्र.सं.	देश	विशेषज्ञ का नाम	क्षेत्र	दिनांक से	दिनांक तक
24	लिसोथो	श्री कर्नल वी. जी. खंडारी	मुख्य अनुदेशक (आई ए टी टी)	जुलाई,05	जुलाई,07
25	लिसोथो	मुजर एस. ठुकराल	भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल	अगस्त,05	अगस्त,07
26	लिसोथो	मेजर आर. मिन्हास	भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल	अगस्त,05	अगस्त,07
27	लिसोथो	मे. ललित शर्मा	भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल	अगस्त,05	अगस्त,07
28	लिसोथो	मे. पी. वत्स	भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल	अगस्त,05	अगस्त,07
29	सेशेल्स	कमोडोर नवीन कुंद्रा	नौसेना सलाहकार	सितंबर,05	सितंबर,07
30	लिसोथो	मे. राहुल सरीन	भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल	सितंबर,05	सितंबर,07
31	लिसोथो	मे.अमित ओबराय	भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल	सितंबर,05	सितंबर,07
32	लिसोथो	मे. संदीप रातरा	भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल	सितंबर,05	सितंबर,07
33	लिसोथो	में बी. पी. एस. ठाकुर	भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल	सितंबर,05	सितंबर,07
34	लिसोथो	मे. एस.के.सेनगुप्ता	भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल	सितंबर,05	सितंबर,07
35	लिसोथो	मे. आई.वी.नागेश	भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल	सितंबर,05	सितंबर,07
36	ग्रेनाडा	श्री अनुराग सिन्हा	सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ	अक्तूबर,05	अक्तूबर,06
37	लिसोथो	ब्रि. रणवीर यादव	भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल	अक्तूबर,05	अक्तूबर,07
38	त्रिनिदाद एंड टूबैगो	श्री के. एस. गुलियानी	दूरसंचार विशेषज्ञ	नवंबर, 05	नवंबर, 06
39	सेशेल्स	ले.क.अनिल चंडेल	सैन्य सलाहकार	नवंबर, 05	नवंबर, 07
40	ग्रेनाडा	डा. अनिल.पी. सिंह	कृषि सलाहकार	नवंबर, 05	नवंबर, 06

परिशिष्ट XVIII

लिंग से संबंधित आंकड़े

काडर	कुल पद	महिला अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	कुल संख्या का प्रतिशत
भा. वि से	621	84	14%
भा. वि से (ख)	2433	332	14%
विधि एवं संधि	12	2	17%
दुभाषिये	19	6	32%
पुस्ताकलय	11	2	18%

परिशिष्ट XIX

आई सी डब्ल्यू ए द्वारा 01.04.2005 से 30.11.2005 के दौरान आयोजित संगोष्ठियां/सम्मेलन/गोल मेज वार्त्ता

क्र.	तारीख	विषय	सहभागी
1.	13 अप्रैल 2005	"चीन लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधान मंत्री श्री वेन जियाबाओ की यात्रा के परिणाम" पर चर्चा	प्रो. मीरा सिन्हा भट्टाचार्जी, आई सी एस,श्री पी. आर. चारी, आई पी सी एस,डा. अरविन्दर सिंह, आइ सी एस, प्रो. मनोरंजन, आई सी एस, डा. अलका आचार्या, जे एन यू, प्रो. जी. पी. देशपांडे, आई सी एस।
2.	29 अप्रैल 2005	"पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ की यात्रा का आकलन;" पर चर्चा	श्री निहाल सिंह, पूर्व संपादक, दी स्टेट्समैन, राजदूत जी. पार्थसारथी, लेफ्टि. जनरल (सेवानिवृत), डा. बी.एस. मलिक, डा. विवेक भारती, फिक्की, प्रो. कलीम बहादुर, जे एन यू।
3.	4 मई 2005	"हाल के अलगाव-विरोधी कानून तथा उसके निहितार्थ" पर संगोष्ठी	राज. रणजीत गुप्ता, राज. विनोद सी. खन्ना।
4.	5 मई, 2005	"जैवीय-आतंकवाद और जैवीय-प्रतिरक्षा" पर चर्चा	प्रो. पी. आर. चारी, रीयर एडमिरल राजा मेनन, रा. अरूंधती घोष, डा. के. संथानम, राज. ए. एन. राम।
5.	18 जुलाई 2005	"आतंकवाद को समाप्त करने से पूर्व क्या उसके मूल कारणों को समाप्त करना आवश्यक है" पर संगोष्ठी।	मे. ज. (सेनानिवृत्त) अफसीर करीम, (ए वी एस एम), संपादक, आक्रोश, डा. मनोज जोशी, संपादक (व्यूज), दी हिन्दुस्तान टाइम्स, श्री सिद्धार्थ वरदराजन, उप संपादक, दि हिन्दू, डा. अजय साहनी, आई सी एम, सुश्री स्वाति पराशर, ओ. आर. एफ., राज. ए. एन. राम।
6.	27 जुलाई 2005	"आई बी एस ए फोरम : संभावना एवं वायदे" पर चर्चा	डा. नागेश कुमार, डी जी, आर. आई. एस. डी सी, प्रो. अब्दुल नफे, जे एन यू., प्रो. अजय दुबे, जे एन यू, डा. सुरेश कुमार, डी यू, राज. शशांक, भूतपूर्व विदेश सचिव।
7.	17 अगस्त 2005	"श्रीलंका में शांति प्रक्रिया" : पर 8 वां दिनेश सिंह स्मारक व्याख्यान।	श्री रानिल विक्रमासिंघे, श्रीलंका, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री आई. के. गुजराल, राजदूत श्री आई.पी.खोसला।
8.	9 सितम्बर 2005	"ई यू-भारत संबंध एवं भावी सहयोग" पर व्याख्यान।	श्री हर्वी जुआनजीन, ब्रसेल्स, राज. सी. दासगुप्ता
9.	19 अक्तूबर 2005	21 वीं सदी में मेक्सिको की विदेश नीति की प्राथमिकताएं : भारत के साथ गहरी सहभागिता की ओर; पर व्याख्यान	मेक्सिको के विदेशी संबंधों के उपमंत्री महामहिम सुश्री लुर्डेस अरांडा बिजौरी, प्रो. आर. नारायणन, आई सी एस एस आर।
10.	16 नवंबर 2005	"एशिया पैसिफिक की सुरक्षा पर गैर-पारंपरिक खतरे" पर पैनल चर्चा	श्री धीरेन्द्र सिंह, पूर्व गृह सचिव, श्री पी. आर. चारी, प्रो. मारूफ रजा, प्रो. टी. श्रीधर, डा. विजय सखुजा।
11.	25 नवंबर 2005	"मोरक्को की आधुनिकता एवं धर्म निरपेक्ष परंपराओं पर आधारित नई संस्थाओं का निर्माण" तथा"मोरक्को के महामहिम स्व.महाराज मोहम्मद V के अज्ञातवास से वापसी की 50 वीं वर्षगांठ के आयोजन" पर व्याख्यान	मोरक्को के राजदूत श्री लार्बी मुखारीक, उ.प्र. के भूतपूर्व राज्यपाल तथा भूतपूर्व विदेशसचिव श्री रोमेश भंडारी।
12.	29 नवंबर 2005	"फिलीस्तीन के लोगों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय एटजूटता दिवस मनाना"	सूडान गणराज्य के राजदूत श्री अबडाल महमूद अबदाल्हालीम मोहम्मद, अरब मिस्र गणराज्य के राज. डा. खीर एल्डीन ए.लतीफ, फिलीस्तीन राज्य के राज. श्री ओसामा मूसा, सुश्री शालिनी दीवान, निदेशक, संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, प्रो, गुलशन, जे. एन. यू. प्रो. अचिन वनाइक, डी. यू. तथा राज. सी आर गरेखान

परिशिष्ट XIX

क्र.	तारीख	विषय	सहभागी
13.	9 दिसम्बर 2005	कजाकिस्तान में 205 के राष्ट्रपति चुनावःसुरक्षा,ऊर्जा सहयोग और विदेश संबंधों में भावी आयाम विषय पर गोलमेल चर्चा	महामहिम श्री कैरात उमारोव, कजाकिस्तान गणराज्य के राजदूत;प्रो. श्री प्रकाश, जे एम आई; श्री इन्द्रानिल बनर्जी सापरा इन्डियर काउन्डेशन; डा. रमाकान्त द्विवेदी,आई डी एस ए। प्रो. निर्मला जोशी।
14.	13 दिसम्बर 2005	"भारत-दक्षिण अफ्रीकाः अफ्रीका औरविश्व का सामरिक परिप्रेक्ष्य" पर चौथा अल्फ्रेड एन जेड ओ स्मारक व्याख्यान	महामहिम श्री अजीज पहाद, विदेश उप मंत्री, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य प्रो. अजय दुबे, जे एन यु
15.	18 जनवरी 2006	"ई यू विस्तारण का वैश्विक प्रभाव" चेक परिप्रेक्ष्य पर व्याख्यान	महामहिम श्री जिरि पराउबेक, चेक गणराज्य के प्रधान मंत्री माननीय श्री आई. के. गुजराल भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री
16.	25 जनवरी 2006	"लोकतांत्रिक अनुभव के विशेष में भारत-नेपाल संबंधों की उदीयमान प्रवृत्तियाँ" पर सेमिनार	डा. सी राजा मोहन, दी इन्डियन एम्सप्रेस; प्रो. लोकराज बराल,नेपाल; प्रो. प्रयाग राज शर्मा नेपाल, श्री तिल बिक्रम नेम्बांग, नेपाल; श्री तारा नाथ बराल, नेपाल; श्रीमती पुष्पा भुसाल, नेपाल; श्री प्रेम राज गौतम, नेपाल, श्री गणेश दत्ता भट्ट, नेपाल
17.	8 फरवरी 2006	"पूर्वी यूरोप, विशेषकर स्लोवाकियाकी वर्तमान स्थिति और विदेश नीति परिस्थिति" पर व्याख्यान	श्री ग्रीगोरिज मेसेजनिकोव, स्लोवाकिया लोक मामले संस्थान के अध्यध; राजदूत बी आर मुपुकुमार

परिशिष्ट XX

आर आई एस द्वारा आयोजित सम्मेलन

- स्तरीय हांगकांग सम्मेलन के लिए" 11 फरवरी, 2005
- उभरता पूर्वी एशियाई क्षेत्रवाद : भारत के लिए विकल्प, 10 फरवरी, 2005
- आईबीएसए में आर्थिक सहयोग की शक्यता, 24 मार्च, 2005
- व्यापरिक मुद्दों पर भारत-यूएस वार्ता- एक एजेंडा : एयूएसटीआर विजिट आरआईएस, 10 मई, 2005
- वाशिंगटन,डीसी में 16 जून, 2005 को एशियाई आर्थिक समुदाय पर सेमिनार
- उत्पत्ति नियम के विभिन्न विकल्पों पर समझ को ठोस रूप देने तथा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत सरकार को समय पर निवेश उपलब्ध कराने के लिए आरआईएस ने 25 नवम्बर, 2005 को एक बैठक आयोजित की ।
- 23 दिसम्बर, 2005 को "पूर्वी एशिया में मौद्रिक एवं वित्तीय सहयोग का जायजा : भारत के लिए निहितार्थ " पर 23 दिसम्बर, 2005 को सेमिनार

आरआईएस प्रकाशन

पुस्तकें

- एशियाई आर्थिक समुदाय की ओर : पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एक एजेंडा,आईएसईएएस, सिंगापुर द्वारा प्रकाशित, 2006
- भारत-आशियान आर्थिक संबंध : भूमंडलीकरण की चुनौतियों को पूरा करना, नागेश कुमार, राहुल सेन और मुकुल अशेर (संपादक), आईएसईएएस, सिंगापुर द्वारा प्रकाशित, 2005
- रोजगारोन्मुख निर्यात नीति की ओर, 2006
- दक्षिण एशिया में पर्यावरणीय अपेक्षाएं और बाजार पहुंच, 2006

नीति संक्षिप्तियां

#14 यूएस ब्याज दरों में चक्रीय अपटर्न और तेल भंडार : एशिया के लिए निहितार्थ सितम्बर, 2004

#15 एशिया में गरीबी उन्मूलन और आहार सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय सहयोग, जुलाई, 2005

#16 वैश्विक असंतुलन के उच्च जोखिम : एशिया में अवसंरचनात्मक निवेश की भूमिका, अगस्त, 2005

#17 विश्व और एशिया में क्षेत्रीय व्यापार करार : भारत के लिए विकल्प, अगस्त, 2005

#18 जैव सुरक्षा प्रोतोकोल, प्रीकाशनरी एप्रोच और व्यापार : महत्वपूर्ण नीति विकल्पों की पहचान, सितम्बर,2005

#19 दोहा चक्र का विकास प्रभाव : सिमटते अभिलाभ और वास्तविक लागत, नवम्बर, 2005

#20 दोहा को वस्तुतः विकास चक्र बनाना, दिसम्बर, 2005

#21 व्यापार सुविधा : सिद्धांत और सतर्कता के बीच संतुलन लाने की आवश्यकता, दिसम्बर, 2005

चर्चा कागजात

#106 मशनोरी कोंडो द्वारा जापान और एशियाई आर्थिक समुदाय, 2006

#105 राजेश मेहता द्वारा भारत-वियतनाम व्यापार : वर्तमान संबंध एवं भविष्य, 2005

#104 प्रवीर डे द्वारा आईबीएसए आर्थिक सहयोग में व्यापार : संचार सेवाओं की भूमिका, 2005

#103 संजय कुमार और नुपुर चौधरी द्वारा डब्ल्यूटीओ में व्यापार और पर्यावरण : विकासशील देशों के लिए सौदेबाजी के विकल्प, 2005

#102 एस. के. मोहंती और सचिन चतुर्वेदी द्वारा दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय प्रक्रिया के तहत पर्यावरण व्यापार का भविष्य : एसएपीटीए से साक्ष्य तथा साफ्टा के लिए प्रस्ताव, 2005

#101 एस.के. मोहंती और सचिन चतुर्वेदी द्वारा नई सहस्राब्दि में भारत और चीन का उद्भव : क्या यह एलडीसी और विकासशील देशों में बाजार पहुंच को सुकर बनाएगा, 2005

#100 नागेश कुमार द्वारा विस्तृत एशियाई समुदाय की ओर : पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा, 2005

#99 सचिन चतुर्वेदी और लियां चौबी द्वारा जैवसुरक्षा प्रोतोकोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कृषि जैव प्रौद्योगिकी : भारत के लिए नीति संदर्भ, 2005

#98 पिलमज आकुज द्वारा औद्योगिक टैरिफ पर डब्ल्यूटीओ वार्ता : विकासशील देशों के लिए क्या दाव पर है? 2005

#97 राजेश मेहता द्वारा भारत के निर्यात को प्रभावित करने वाले गैर-टैरिफ बाधाएं, 2005

#96 आंग केंग योंग द्वारा नई सहस्राब्दि में आशियान- भारत साझेदारी की प्रगति, 2005

#95 जिजमन एस सिमानजुंतुक द्वारा क्षेत्रीय वास्तु शिल्प की तलाश : विचित्र आकर्षक के रूप में आशियान की भूमिका, 2005

#94 भारत-मध्य एशिया आर्थिक संबंधः आरआईएस/ सीआईआई सेमिनार की रिपोर्ट, 2005

परिशिष्ट XX

#93 कोकिची इटो, लि झिदोंग और रियोचि कोमियामा द्वारा 2020 के प्रति एशियाई ऊर्जा दृष्टिकोण : क्षेत्रीय सहयोग के रूझान, पैटर्न एवं अनिवार्यताएं, 2005

#92 टिजीयाना बोनापेस द्वारा एशिया-प्रशांत में क्षेत्रीय व्यापार और निवेश वास्तुशिल्प : अभरते रूझान और अनिवार्यताएं, 2005

#91 मुकुल जी अशेर और राहुल सेन द्वारा भारत-पूर्वी एशिया एकीकरण : एशिया के लिए विजय, 2005

#90 इरिक टीआ चू चेवोव द्वारा एशियाई आर्थिक समुदाय का रणनीतिक महत्व, 2005

#89 याओ चाओ चेंग द्वारा एशियाई आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया में चीन की भूमिका, 2005

#88 केजे जोसफ द्वारा ज्ञान आधारित उद्योग : इलैक्ट्रानिक उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण, 2005

#87 सचिन चौधरी द्वारा दक्षिण एशिया में गरीबी उपशमन और भोजन सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय सहयोग, 2004

पत्रिकाएं

1. साऊथ एशिया इकोनामिक जर्नल (खंड 6 अंक 1) जनवरी-जून, 2005

   साऊथ एशिया इकोनामिक जर्नल (खंड 6 अंक 2) जलाई-दिसम्बर, 2005

2. एशियन वायोटेक्नालाजी एवं डवलपमेंट रिब्यू, खंड 7 (1), नवम्बर, 2005

   एशियन वायोटेक्नालाजी एवं डवलपमेंट रिब्यू, खंड 7 (2), मार्च, 2005

   एशियन वायोटेक्नालाजी एवं डवलपमेंट रिब्यू, खंड 8 (1), नवम्बर, 2004

3. न्यू एशिया मानीटर, खंड 2, अंक 2, अप्रैल, 2005
   न्यू एशिया मानीटर, खंड 2, अंक 3, जुलाई, 2005
   न्यू एशिया मानीटर, खंड 2, अंक 4, अक्तूबर, 2005
   न्यू एशिया मानीटर, खंड 3, अंक 1, जनवरी, 2005

सूचनापत्र

आरआईएस डायरी खंड 3 अंक 2, अप्रैल, 2005

आरआईएस डायरी खंड 3 अंक 3, जुलाई, 2005

आरआईएस डायरी खंड 3 अंक 4, अक्तूबर, 2005

आरआईएस डायरी खंड 4 अंक 1, जनवरी, 2006

संक्षिप्त रूप

एसीएएफडी	विदेशी राजनयिकों के लिए एशिया पर उच्च पाठ्यक्रम
एसीडी	एशियाई सहयोग वार्ता
एजीपीएल	वास्तविक भू स्थिति रेखा
एआरएफ	आसियान क्षेत्रीय मंच
एएसईएएन	दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ
एएसआई	भारतीय पुरातत्व
बीडीआर	बंगलादेश राइफल
बीआईएमएसटी	बंगलादेश, भारत, म्यांमा, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग
बीआरपीपीए	द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार
बीओओटी	बिल्ड आने आपरेट ट्रांसफर
बीएसएफ	सीमा सुरक्षा बल
सीएएन	एंडीयन देशों का समुदाय
सीएआरआईसीओएम	केरिबियाई समुदाय
सीबीएम	विश्वासोत्पादक उपाय
सीडी	निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध सम्मेलन
सी ई सी ए	व्यापक आर्थिक सहयोग करार
सीईएल	केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक लि.
सी ई पी	सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम
सीएफवाय	चालू वित्तीय वर्ष
सीएचओजीएम	राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक
सीआईसीए	एशिया में अन्योन्यक्रिया और विश्वासोत्पादक उपायों से सम्बद्ध सम्मेलन
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सी आई एस	स्वतंत्र देश का राष्ट्रमण्डल
सीएलएमवी	कम्बोडिया, लाओस, म्यांमा, वियतनाम
सीओएमईएसए	पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका समुदाय
सीपीआईएफ	चीन लोक विदेशी मामले संस्थान
सीएससीएपी	एशिया प्रशांत में सुरक्षा और सहयोग परिषद
सीयूएनपीके	संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यवाहियों हेतु केन्द्र
सी डब्ल्यू सी	रासायनिक हथियार अभिसमय
डीपीसी	जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ
डीपीआरके	कोरिया प्रजातांत्रिक लोक गणराज्य
इकोवास	पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय
ईयू	यूरोपीय संघ
फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ
एफआईईओ	भारतीय निर्यात संगठनों का परिसंघ
एफओसी	विदेश कार्यालय परामर्श
एफएसआई	विदेश सेवा संस्थान
एफटीए	मुक्त व्यापार करार
जीसीसी	खाड़ी सहयोग परिषद
जी सी आई एम	अंतराष्ट्रीय उत्प्रवास पर सार्वभौम आयोग
जीओआई	भारत सरकार
जी एस एल वी	जिओसिंक्रोन सेटेलाइट लांच वेकल
एचएएल	हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड
एचआईपीसी	अत्याधिक ऋण ग्रस्त गरीब देश
एच ओ एम	मिशन प्रमुख
एच ओ पी	केन्द्र प्रमुख
एचटीसीजी	उच्च प्रौद्योगकी सहयोग दल
आईबीएसए	भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका
आईसीसीआर	भारतीय सांस्कृतिक सम्बद्ध परिषद
आईसीडब्ल्यूए	इंडियन कांउसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स
आईएफएस	भारतीय विदेश सेवा
इग्नु	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

संक्षिप्त रूप

आई एल ओ	अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन
आई एम ओ	अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन
आईआरआईजीसी	भारत-रूस अंतर - सरकारी आयोग
आईटीईसी	भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग
आईटीपीओ	भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन
जेसीई	संयुक्त विशेषज्ञ समिति
जेईसी	संयुक्त आर्थिक आयोग
जेएसजी	संयुक्त अध्ययन दल
जेटीजी	संयुक्त व्यापार समिति
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्य बल
एलएसी	वास्तविक नियंत्रण रेखा
एलसीडीएस	अल्प विकसित संविदाकारी पक्ष
एलओसी	नियंत्रण रेखा
एलटीटीई	लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम
मार्कोसुर	दक्षिण कोण्य देशों का बाजा
एमएनए	म्यांमा न्यूज एजेंसी
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एनएएम	गुट निरपेक्ष आंदोलन
नाटो	उत्तरी प्रशांत संधि संगठन
एनडीसी	राष्ट्रीय रक्षा कालेज
एनआईडीएम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एनआरआई	अप्रवासी भारतीय
एनएससीएस	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
एमएसएसपी	सामारिक भागीदारी में अगला कदम
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
पीसीएफडी	विदेशी राजनयिकों के लिये व्यवसायिक पाठ्यक्रम
पीआईएफ	प्रशांत द्वीप समूह मंच
पीकेओ	शांति कार्यवाहियां
पीआइओ	भारतीय मूल के लोग
पी आई एस	कार्मिक सूचना प्रणाली
पीएलए	पीपील्स लिबरेशन आर्मी
पीटीए	अधिमानी व्यापार करार
आरआईटीईएस	रेल इंडया टेक्नीकल इक्नोमिक्स सर्विस
आरओक	कोरिया गणराज्य
एसएएआरसी	क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संघ
साफ्ता	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र
साप्ता	दक्षिण एशिया अधिमानी व्यापार करार
स्काप	अफ्रीकी योजना के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता
एससीपीडी	फिलीस्तीनी राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम
एसआईसीए	मध्य अमरीकी एकीकरण प्रणाली
एसपीडीसी	राज्य शांति और विकास परिषद
टीसीआईएल	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड
टीम - 9	अफ्रीका भारत आंदोलन के लिए तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण
यूजीजी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएमएफसीसीआई	म्यांमार संघ वाणिज्य एवं उघोग परिसंघ
उनकोपुओस	बाह्य अंतरिकक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति
यूएनडीसी	संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग
यूएनजीए	द्दसंयुक्त राष्ट्र महासभा
यूएनएचसीआर	विस्थापितों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त
युएनएमईई	इथियोपिया और एरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन
यूएनएससी	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद
यूपीए	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
डब्ल्यूएमडी	सामूहिक विनाश के हथियार
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन